FINAL REPORT OF MAJOR RESEARCH PROJECT

F.No. 5-50/2014(HRP)FD III DIARY NO 9859

SUBMITTED TO

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NEW DELHI

नेपाल में चीन की संलिप्तता एवं भारत के सुरक्षा आयाम

INVOLVEMENT OF CHINA IN NEPAL AND INDIA'S SECURITY DIMENSIONS

Submitted by:

Dr. R.S.Pandey
Principal Investigator
Department of Defence Studies
Shri Lal Bahadur Shastri Degree College,
Gonda U.P.

फोन नं0 : 05262-232994 कार्यालय
website : lbsdc.org.in
e-mail : principal@lbsdc.org.in

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा - 271003 (उ.प्र.)
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI DEGREE COLLEGE, GONDA - 271003 (U.P.)

दिनांकः दिसम्बर , 2020

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ0 आर0 एस0 पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर, (से0नि0) रक्षा अध्ययन विभाग ने इस महाविद्यालय केन्द्र से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट (F.No. 5-50/2014(HRP), FD III Diary No. 9859) पूरी कर ली है। इनके रिसर्च प्रोजेक्ट का शीर्षक– **''नेपाल में चीन की संलिप्तता एवं भारतीय सुरक्षा आयाम''** (INVOLVEMENT OF CHINA IN NEPAL AND INDIA'S SECURTY DIMENSIONS) है।

मैं इस शोध परियोजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अग्रसारित करते हुए डॉ0 पाण्डेय के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।

(डॉ0 वन्दना सारस्वत)
प्राचार्य

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	1-IV
	प्रस्तावना	1-16
1	नेपाल का ऐतिहासिक, आर्थिक व भू–रणनीतिक स्वरुप	17-38
2	भारत–नेपाल सम्बन्धों के विस्तृत आयाम	39-80
3	चीन–नेपाल सम्बन्धः ऐतिहासिक व राजनैतिक पक्ष	81-112
4	चीन–नेपाल सम्बन्धों के आर्थिक व रणनीतिक आयाम	113-129
5	नेपाल–केन्द्रित भारत व चीन की सामरिक–आर्थिक विनियोजन नीति	130-173
6	चीन की एशियाई महान स्त्रातेजी एवं भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ–	174-223
7	भारत के स्त्रातेजिक प्रयत्न व भावी सुरक्षा आयाम	224-262
	परिशिष्ट एवं संदर्भ ग्रन्थ की सूची	263-287

प्राक्कथन

राष्ट्रीय अखण्डता, सम्प्रभुता एवं राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा व इसका सतत अभिवर्धन ही किसी राष्ट्र की विदेश नीति का परम लक्ष्य होता है जिसके निर्धारण में उस राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रबोध, विचारधारा, संसाधन, जनसंख्या का स्वरूप, भू–सामरिक अवस्थिति व रणनीतिक–संस्कृति जैसे तत्वों की निर्णायक भूमिका होती है। स्वतन्त्र भारत ने तत्कालीन वैश्विक व क्षेत्रीय शक्ति–संरचना की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही न केवल असंलग्नता की नीति को अपनी विदेश नीति का मूलाधार बनाया तथा साम्राज्यवाद का विरोध, पंचशील–भावना, विश्वशान्ति, अहस्तक्षेप एवं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व जैसे सुसंगत तत्वों द्वारा नीति संचालन की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की उसकी तार्किक परिणति शनैः शनैः निस्तेज होती रही। अपने सभी पड़ोसियों के प्रति सद्भाव, मैत्री व सहयोग भावनाओं के बावजूद जहाँ एक ओर भारत को पाकिस्तान व चीन के आक्रमण का शिकार होना पड़ा वहीं शीत युद्ध के वातावरण में भारत की नीतियों के आदर्शवादी स्वरूप के कारण उसकी सुरक्षा आहत व संकटापन्न होती दिखाई पड़ी। फलतः, बांग्ला मुक्ति–संघर्ष काल में गठित बेमेल चीन–पाक–अमेरिका धुरी से आहत भारत को अन्ततः सोवियत संघ से शन्ति व मैत्री सन्धि सम्पन्न करके बदल रही भू–राजनीतिक परिस्थितिवश रक्षा तैयारियों व वैश्विक शक्ति–संतुलन में सक्रिय भूमिका के मार्ग की तलाश हेतु विवश होना पड़ा। कालान्तर में सोवियत विघटन के पश्चात अमेरिकी नेतृत्व में स्थापित नवीन विश्व व्यवस्था, चीन का शान्तिपूर्ण अभ्युदय, एशिया के नाभिकीकरण एवं चीन से प्रगाढ़ होती पाकिस्तानी रणनीतिक–आर्थिक मैत्री के विविध दबावों के फलस्वरूप भारत का स्त्रातेजिक परिदृश्य निरन्तर संवदेनशील आयाम ग्रहण करता रहा।

यद्यपि प्रारम्भ से ही भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक सम्बन्धों को सौहार्दपूर्ण बनाने हेतु प्रयत्नरत रहा तथापि अफगान–संकट के मूल से उत्पन्न आतंकवाद एवं पाक–अमेरिकी गठबन्धन से उत्पन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों से भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ जटिल होती गयी। उधर, चीन–पाक

सहयोग तथा भारत के निकटस्थ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका व मालदीव आदि के साथ प्रत्यक्ष निवेश–सहायता तथा सामरिक सहयोग को निरन्तर बढ़ाते हुए भारत की सामरिक घेरेबन्दी में चीन ने किंचित संकोच. नहीं किया। 21वीं शताब्दी में अमेरिका को स्थानापन्न कर वैश्विक महानतम शक्ति बनने की लालसा की पूर्ति हेतु चीन ने न केवल अपने सुरक्षा–क्षितिज को विस्तृत करने का प्रयत्न जारी रखा अपितु भारत को अपना प्रमुख स्पर्धी राष्ट्र मानकर 'स्ट्रिंग आफ पर्ल' व 'बी0आर0आई0' जैसी महत्वाकाँक्षी योजनाओं में भारत के सभी पड़ोसियों को शामिल कर जो चुनौतियाँ उत्पन्न की वे आज भारत के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय हैं। इन्हीं चुनौतियों का ही यह परिणाम है कि भारत को अपनी पुरानी रणनीतिक–संस्कृति से पृथक होकर बालाकोट जैसी कार्यवाहियाँ करनी पड़ी। भारत के इस परिवर्तित स्वरूप एवं प्रकट रक्षा–पुरूषार्थ से चीन भी हतप्रभ रह गया। गुटनिरपेक्षता की नीति से हटकर भारत द्वारा अमेरिका, जापान, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन व आस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देशों के साथ रणनीतिक सम्बन्धों का विस्तार यह सिद्ध करता है कि वर्तमान परिवेश में भारत बहु–संलग्नता नीति के आधार पर विदेश नीति का संचालन करके अपने हितों के रक्षार्थ प्रत्येक स्तर पर तैयार हो रहा है।

चीन की विशाल अर्थव्यवस्था एवं सैन्य सामर्थ्य तथा सीमा–विवाद के समाधान में कोई सार्थक प्रगति न होना भारत के लिए चिन्ता का विषय है। पहले डोकलाम तथा बाद में गलवान घाटी में भारत व चीन के मध्य हुई हिंसक झड़प यह सिद्ध करती है कि सीमा–विवाद समाधान सम्बन्धी उदासीनता उसकी सुविचारित नीति का ही अंग है। चीन इस विवाद को बनाये रखकर नेपाल–पाकिस्तान गठबन्धन के माध्यम से भारत के उत्तरी सीमान्त को सदैव अशान्त रखते हुए भारत को दक्षिण एशिया में ही उलझाए रखना चाहता है जिससे चीन–विरोधी वैश्विक रणनीति में सहभागिता हेतु उसे परिसीमित किया जा सके। नेपाल में निरन्तर बढ़ रही चीन की सामरिक–आर्थिक संलिप्तता एवं भारत–नेपाल सीमाओं पर प्रभुत्व–स्थापना सम्बन्धी उसके विविध प्रयत्न यह सिद्ध करते हैं कि चीन, भारत के हिमालयी सीमान्त को असुरक्षित, तनावपूर्ण व भेदनीय बनाने की महानस्त्रातेजी पर चल रहा है तथा नेपाल की कम्युनिस्ट

सरकार इस समय भारत–विरोधी यन्त्र के रूप में कार्य कर ही है। इतना ही नही, भारत की विकसित हो रही अर्थव्यवस्था, सुदृढ़ सामरिक सामर्थ्य, एक्ट ईस्ट पालिसी, क्वाड में सहभागिता तथा एशियान क्षेत्र में वियतनाम व म्यांमार से भारत की प्रगाढ़ होती सामरिक मैत्री से चीन व्यथित व क्षुब्द्ध है, क्योंकि भारत के उक्त सभी कदम एशिया में उसके हितवर्धन में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। यह एक विडम्बना ही है कि कभी नेपाल को अपनी 'फाइव फिंगर पालिसी' का अंग बताने वाले चीन के साथ भारत–विरोधी रूख की पृष्ठभूमि में नेपाल चीनी व्यामोह में इतना अन्धा हो गया है कि न तो उसे तिब्बत की दुर्दशा की ही स्मृति है और न ही अपने सम्प्रभुता की ही चिन्ता। दो बड़े चट्टानों के मध्य फँसा नेपाल यह भी नहीं समझ पा रहा है कि भारत पर उसकी निर्भरता किस स्तर की है। नेपाल को यह कदापि विस्मृत नहीं करना चाहिए कि भारत का विरोध करके न तो वह अपना विकास ही कर सकता है और न ही स्थायित्व व शान्ति के वातावरण का सृजन ही। वास्तव में, चीन, भारत व नेपाल के मध्य गतिरोध को उग्र कर अपने हितों की पूर्ति हेतु एक उसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर ऐसे ऋण जाल में फँसाना चाहता है, जिससे भारत–चीन के मध्य नेपाल रूपी अन्तस्थ राज्य को निस्तेज व निष्क्रिय किया जा सके। इन परिस्थितियों में नेपाल का यह परम दायित्व है कि वह कूटनीतिक कौशल द्वारा भारत व चीन के साथ संतुलन बनाते हुए अपने हितों की सुरक्षा पर केन्द्रित विदेश–नीति को ओर उन्मुख हो अन्यथा उसकी स्थिति निरन्तर न केवल दयनीय होती जायेगी अपितु वह भारत–चीन संघर्ष का अखाड़ा बन जायेगा। यदि ऐसा हुआ तो क्षेत्रीय सुरक्षा व भू–राजनीतिक परिस्थितियाँ न केवल भारत अपितु नेपाल व चीन के लिए भी कल्याणकारी नहीं होगी। प्रस्तुत शोध परियोजना में उक्त तथ्यों के प्रकाश में भारत–नेपाल व चीन के उभयपक्षीय हितों, रणनीतिक–आर्थिक आयामों के साथ–साथ भारत की सुरक्षा चिन्ताओं एवं उनके समाधान हेतु विकल्पों का विस्तृत विवेचन किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित इस शोध परियोजना की स्वीकृति हेतु मैं आयोग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति हार्दिक

कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस शोध परियोजना को मूर्त रूप देने में मैंने जिन विद्धानों की साहित्यिक–कृतियों को आधार बनाया है उनके प्रति हार्दिक–शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। इसी क्रम में मैं अपने महाविद्यालय की कर्मठ, ईमानदार व उदारमना प्राचार्य, डॉ0 वन्दना सारस्वत, समस्त विभागीय सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ तथा कोविड–19 के असुरक्षित वातावरण में भी टंकण कार्य हेतु श्री राजकुमार माथुर एवं श्री आशुतोष श्रीवास्तव के सद्प्रयास हेतु धन्यवाद देते हुए सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अन्त में, शोध परियोजना को मूर्त रूप देने में अपने परिजनों व मित्रों से प्राप्त प्रोत्साहन व सहयोग हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए इस शोध कार्य को राष्ट्रीय रक्षा में सदैव प्राणोत्सर्ग हेतु तत्पर वीर भारतीय जवानों को समर्पित करते हुए उन्हें सादर नमन करता हूँ।

जय हिन्द–जय भारत

02 अक्टूबर, 2020

(डॉ0 आर0एस0 पाण्डेय)
रक्षा अध्ययन विभाग
श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज,
गोण्डा (उ0प्र0)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय हितों की प्रभावी सुरक्षा व इसका सतत अभिवर्धन सुदृढ़ राष्ट्रीय शक्ति के माध्यम से ही सम्भव है। यही कारण है कि विश्व के सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा व सम्प्रभुता के रक्षार्थ अपने समस्त संसाधनों, चाहे व मूर्त हो अथवा अमूर्त (Tangible and Intangible) के द्वारा अहर्निश तत्परता के साथ क्षेत्रीय व वैश्विक, भू–राजनीति, स्त्रातेजिक परिदृश्य, निकटस्थ पड़ोसियों की सामरिक–संस्कृति व उभयक्षीय सम्बन्धों की प्रकृति को दृष्टिगत रखकर सुरक्षा व विदेशनीति का निर्धारण करते हैं। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में देश की रक्षा का प्रमुख दायित्व शासकों व सेनाओं तक ही सीमित था [1] किन्तु सामाजिक परिवर्तन, तकनीक व वैज्ञानिक अनुसंधान, राष्ट्र–राज्य की संकल्पना, राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न पारस्परिक निर्भरता व विश्व–समाज के मध्य आई सन्निकटता के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं तथा अब यह अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता व चिन्तन का केन्द्रीय–तत्व बन गया है। वास्तव में, सक्रिय विदेश नीति का निर्धारण कर अपने आन्तरिक नीतियों, उसकी स्वायत्तता व सम्प्रभुता को अक्षुण्य रखना ही सभी राष्ट्रों का सबसे बड़ा व प्राथमिक राष्ट्रहित है। विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य राष्ट्रहित का संरक्षण ही है और विदेश नीति व राजनय के सामरिक पक्ष पर बल देने का तात्पर्य है कि देश की एकता व अखण्डता को सुरक्षित रखकर उस क्षेत्र की स्पष्ट पहचान और अलग निजी अस्तित्व कोएक ऐसे क्षेत्र के रूप में दर्शाया जा सके जहां उसकी सम्प्रभुता में कोई राज्य हस्तक्षेप न कर सके। अन्य शब्दों में, ''किसी भी देश की विदेश नीति उसकी आन्तरिक नीतियों का ही अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रतिबिम्बित प्रक्षेप होती है।''[2] विदेशनीति व राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे से जुड़े ऐसे विषय हैं जिन्हें पृथक करना कदापि सम्भव नहीं है क्योंकि सुरक्षा के अन्तर्गत समाहित विभिन्न कारक यथा–भौगोलिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, अनुसंधान, तकनीक, सैन्य–सामर्थ्य, विचारधारा, नेतृत्व, राष्ट्रीय मनोबल, राष्ट्रीय चरित्र, नेतृत्व व सांस्कृतिक पक्ष आदि सम्मिलित रूप से एक प्रभावशाली

राष्ट्रीय शक्ति का सृजन करके अन्ततः राष्ट्र की विदेशनीति के निर्धारण, प्रकृति व स्वरूप को तय करते हैं। आर0ई0ओसगुड का अभिमत है कि, ''अनिवार्य रूप से और प्रत्येक कीमत पर राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के दृढ़ संकल्प को ही राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं। राष्ट्रीय हितों में निहित राष्ट्र की प्रादेशिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सरकार की मूल संस्थाओं के समस्त अवएव एवं न केवल राष्ट्र का अस्तित्व अपितु उसकी सामर्थ्य भी समाहित होती है।[3] वाह्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न खतरों के अतिरिक्त बदल रही सामाजिक व आर्थिक, सामरिक व अन्य परिस्थितियों के फलस्वरूप राष्ट्रों के आन्तरिक सुरक्षा की अवधारणा न केवल जटिल स्वरूप ग्रहण कर रही है अपितु उसकी संकल्पना व आयाम भी त्वरित गति से परिवर्तन–प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं। समाज में होने वाले आन्तरिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी, शहरीकरण का विस्तार, रोग, पर्यावरणीय ह्रास, भ्रष्टाचार, राजनैतिक–अस्थिरता, अप्रभावी शासन, ऊर्जा व संसाधनों का क्षरण आदि कारणों से राष्ट्रों का सुरक्षा तंत्र न केवल अस्थिर हो रहा है अपितु वैश्वीकरण, नाभिकीय शस्त्र–प्रसार, इंसरजेन्सी, आतंकवाद, मादक द्रव्यों की तस्करी एवं छोटे हथियारों के प्रसार जैसी गतिविधियाँ वैश्विक सुरक्षा के लिए गम्भीर चुनौती बनती जा रही हैं।[4] कहने का तात्पर्य है कि शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिकी नेतृत्व में स्थापित तथाकथित एक ध्रुवीय विश्व प्रणाली के विभिन्न पक्षों पर दृष्टिपात से यह पुष्ट हो रहा है कि सम्पूर्ण विश्व में असुरक्षा व अस्थिरता में पूर्व की तुलना में निरन्तर वृद्धि से राष्ट्र अपनी अखण्डता व सुरक्षा हेतु निरन्तर व्यग्र होते जा रहे हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली से संलग्न बड़े राष्ट्रों का उत्तरदायित्व न केवल बढ़ता जा रहा है अपितु नवीन शीतयुद्ध की सम्भावनाओं को भी नया आयाम मिलने की प्रबल सम्भावनाएं है।

दक्षिण एशिया में भारत व चीन के हितों के द्वन्द–

भौगोलिक , सांस्कृतिक , आर्थिक, राजनैतिक व सामरिक विशिष्टताओं के कारण दक्षिण एशिया सदैव वाह्य शक्तियों के आकर्षण का क्षेत्र रहा है। जहां एक ओर हिमालय की महान पर्वतमालाएं इस क्षेत्र को उत्तर–पश्चिम व

उत्तर पूर्व के अन्य क्षेत्रों से पृथक करती है वहीं ''सातों समुद्रों की कुंजी'' के रूप में सुप्रसिद्ध विशाल हिन्दमहासागर इस क्षेत्र की व्यापारिक, भू–राजनैतिक व सामरिक महत्ता में अद्‌भुत अभिवृद्धि करता है।[5] लगभग बीस ऐसे देश हैं जिनके तटों का प्रक्षालन और उनकी जीवनचर्या काफी अंश तक इस जल क्षेत्र से प्रत्यक्षः जुड़ी है तथा जो राष्ट्र इसके तट पर नहीं भी है, उनका विकास व व्यापार इसी महासागर से जुड़ा हुआ है। दक्षिण एशिया एक भौगोलिक व्यक्तित्व व सांस्कृतिक समन्वय की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया के सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि राजनैतिक व भौगोलिक दृष्टि से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान बांग्लादेश श्रीलंका व मालद्वीव इस इकाई के देश हैं किन्तु कुछ पश्चिमी विचारक म्यांमार व अफगानिस्तान को भी इसी भू–भाग का अंग मानते हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता सुगताता बोस ने भारतीय उपमहाद्वीप को ही दक्षिण एशिया की मान्यता दी है जबकि ब्रिटिश विचारक इसे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप (South Asian Subcontinent) की संज्ञा देते हैं।[6] प्रमुख मानववैज्ञानिक जॉन आर0ल्यूकेस (John R. Lukacs) के विचार से भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया के एक बड़े भू–क्षेत्र को समाहित (The Indian Subcontinent occupies the major landmass of South Asia) करता है।[7] कहने का अभिप्राय यह है कि मुख्यतः दक्षिण एशिया अन्य ऐशियाई भू–भागों को राजनैतिक दृष्टि से पृथक करने हेतु चिन्हित व निर्धारित किया गया क्षेत्र है जबकि सामान्यतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप की ही संज्ञा दी जाती रही है। सांस्कृतिक पक्ष इनके मूल में निहित मार्मिक तत्व है। हिमालय की पर्वतमालाएं तथा हिन्दमहासागरीय समुद्रोन्मुखता इस क्षेत्र के भौगोलिक व सांस्कृतिक विशिष्टता के प्रमुख कारक हैं। दक्षिण एशिया के भौगोलिक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए भूगोलवेत्ता डॉ0के0एन0सिंह ने लिखा है कि, ''मध्यपूर्व, मध्य एशिया, केन्द्रीय एशिया तथा द0पू0 एशिया से उच्च पर्वत श्रेणियों द्वारा अलग और शेष दिशाओं से हिन्दमहासागर में घंसा–बढ़ा लिपटा यह प्रदेश एक विलग प्रदेश बन जाता है। इस भौगोलिक स्थिति ने उसके इतिहास, संस्कृति और भू–राजनीतिक परिवेश को प्रचुर रूप से प्रभावित किया है।''[8]

लगभग 44,68,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत दक्षिण एशिया का भू–क्षेत्र राजनैतिक, सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व नृजातीय तत्वों की दृष्टि से न केवल विविधताओं से युक्त है अपितु शीतयुद्ध काल व शीतयुद्धोत्तरकालीन शक्ति–स्पर्धा की दृष्टि से बड़ी शक्तियों का संघर्ष स्थल रहा है और आज भी है। यह क्षेत्र सम्पूर्ण यूरोप के क्षेत्रफल के लगभग समतुल्य होने के साथ–साथ सम्पूर्ण विश्व की जनंसख्या का लगभग 1/5 हिस्सा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में निवास करता है।[9] सामरिक व आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र के विशाल बाजार बड़ी शक्तियों के आर्थिक–स्पर्धा के स्थल तो हैं ही साथ ही फारस की खाड़ी से संलग्न इस क्षेत्र से तेल आयात व मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ सामुद्रिक मार्ग सम्बन्धी सन्निकटता के फलस्वरूप तेल–राजनीति भी इस क्षेत्र की शक्ति–संरचना व स्पर्धा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। अमेरिका, जापान व चीन जैसी महत्वपूर्ण शक्तियाँ इस क्षेत्र की अपार खनिज सम्पदा, सस्ते श्रमिकों की उपलब्ध्ता, मध्यम वर्गीय नागरिकों की उपस्थिति, आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ व प्रजातांन्त्रिक संरचना आदि कारणों से प्रत्यक्ष निवेश व व्यापार हेतु ललचाई दृष्टि से देख रही हैं।[10] वास्तव में, इस क्षेत्र में प्रकृति ने आधुनिक औद्योगीकरण हेतु अपेक्षित कृषि, पशु–प्राप्ति व कच्चे पदार्थों के अतिरिक्त लोहा कोयला, अभ्रक व मैगनीज आदि खनिज पदार्थों को तो उपलब्ध कराया ही है साथ ही रेल, सड़क, नदी मार्ग, समुद्री मार्गों व बन्दरगाहों की उपलब्धता एवं घनी जनसंख्या के कारण इसे विश्व के एक बड़े बाजार का दर्जा भी दिया है। यद्यपि, यह औद्योगिक ईकाई सम्बद्ध रुप से आत्मनिर्भर है फिर भी विभिन्न राजनैतिक ईकाइयों के मध्य संघर्ष व टकराव के कारण यह क्षेत्र अपेक्षित विकास से बहुत दूर है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह सम्पूर्ण क्षेत्र सुसम्बद्ध है तथा पाकिस्तान, नेपाल, बॉग्लादेश व भूटान आदि देशों की मुस्लिम व बौद्ध–ईसाई जनता भारतीय रक्त, रीति–रिवाज, जीवन–वृत व समन्वयवादी दर्शन से काफी हद तक प्रभावित है। भाषा, धर्म व सामाजिक मान्यताओं आदि की दृष्टि से भी दक्षिण एशिया के सभी देशों में पारस्परिक सम्बद्धता व समानता के भी विलक्षण तत्व दिखाई देते हैं, जो दक्षिण एशिया को वास्तविक दृष्टि से एक पृथक व सुसम्बद्ध ईकाई के रुप में मान्यता देने हेतु

पर्याप्त हैं। पाश्चात्य देशों द्वारा अपने आर्थिक व सामरिक हितों की पूर्ति हेतु पहले तो विभाजन व शासन (Divide and Rule) तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात साम्प्रदायिक आधार (Two-Nation Theory) पर भारत के विभाजन के घिनौने खेल द्वारा पाकिस्तान निर्माण का ऐसा कुकृत्य किया गया जिसके फलस्वरुप न केवल दक्षिण एशिया अपितु सम्पूर्ण एशिया समेत वैश्विक शान्ति निरन्तर आहत हो रही है। अमेरिका, रुस, चीन व अन्य पश्चिमी देश भी पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद से किसी न किसी रुप में पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। पाक–प्रायोजित आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित भारत अपनी संतुलित विदेश नीति व रक्षा नीति के माध्यम से उक्त चुनौती का सामना करने हेतु तत्पर है। यह बात दूसरी है कि इससे भारत के सर्वागीण विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते प्रतीत हो रहे हैं। चीनी प्रोत्साहन के कारण भारत–पाक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहीं हो पा रहा है जबकि दोनों देश सार्क के सदस्य हैं।

भारत का रणनीतिक वर्णक्रम–

द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त शीतयुद्ध काल मे भारत ने गुटनिरपेक्षता व पंचशील के पुनीत सिद्धान्तों के आधार पर विदेशनीति का निर्धारण करके शान्ति, समृद्धि व विकास सम्बन्धी मूलाधारों पर अपने राष्ट्रीय हितों के रक्षार्थ जिस राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया वह पड़ोसियों द्वारा भारत–विरुद्ध संचालित आक्रामक नीतियों से निरन्तर आहत होती रही है। जहॉ तक भारत की विदेश नीति का प्रश्न है भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रीय विस्तार, जनसंख्या, आर्थिक क्षमता, वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान, कूटनीतिक व सैन्य शक्ति आदि बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में उसने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय व विश्वशान्ति को केन्द्र में रखकर यह कामना की थी भविष्य में वह अपने सर्वांगीण विकास के साथ–साथ क्षेत्रीय व वैश्विक शान्ति, विकास व स्थिरता हेतु उत्प्रेरक का कार्य करते हुए निरस्त्रीकरण के माध्यम से एक अनूठा आर्दश प्रस्तुत करेगा किन्तु यह मार्ग अन्यन्त कंटकाकीर्ण सिद्ध हुआ। चीन व पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपे गये युद्ध एवं दक्षिण एशिया में महाशक्तियों की हस्तक्षेप नीति से प्रेरित व प्रभावित भारत अपने महत्वपूर्ण भू–राजनैतिक व स्त्रातेजिक वातावरण को ध्यान में रखकर धीरे–धीरे शक्ति–संरचना के निर्माण

को त्वरित करने हेतु विवश हुआ। जहॉ तक भारत के भू–सामरिक वर्णक्रम का प्रश्न है, विश्व में उसकी स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लगभग 32,80,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत भारत पूरब से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर व उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले प्रमुख सामुद्रिक मार्ग भी भारत से होकर गुजरते हैं। स्वेज नहर, होरमुज की खाड़ी व मलक्का जलडमरुमध्य जैसे अवरोधक स्थलों (Choke Points) के कारण भारत का विशिष्ट सामुद्रिक महत्व है। जहॉ तक भारत के स्थलीय सीमान्त का प्रश्न है, इसकी लम्बाई 14,100 किलोमीटर है जो छः देशों को स्पर्श करती है। बॉग्ला देश के साथ 4,351 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, चीन के साथ 2,410 किलोमीटर तथा पाकिस्तान के साथ (जम्मू–कश्मीर व नियन्त्रण रेखा सहित) 3,244 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत से संलग्न है।[11] भारत का स्थलीय सीमान्त 15,200 किमी0 जबकि सामुद्रिक सीमा 7,516 किमी0 है।

भारत के सीमा व सीमान्त क्षेत्रों की भू–आकृति, भू–राजनीतिक दशा व सुरक्षा परिदृश्य निम्नवत है–

(अ) उत्तरी–पश्चिमी सीमान्त–

जम्मू–कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की सीमाएं इसके अन्तर्गत आती हैं। भू–रणनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र पर्याप्त संवेदनशील है क्योंकि इससे संलग्न भारत–पाक सीमा से भारत में घुसपैठ प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। इस सीमान्त की औसत ऊचाई 6,000 मीटर है तथा कश्मीर की तीन प्रमुख पवर्त श्रेणियॉ– जास्कर, पीरपंजाल व पंजी यहीं स्थित हैं। इस सीमान्त क्षेत्र में प्रमुख दरें निम्नलिखित हैं–

1. बुर्जिल, बैलन, खैर, मालकन्द, जेलेप्ला
2. भुजतांग
3. जोजीला
4. शिपकी ला

5. पीरपंजाल

6. चांग ला

7. नीति दर्रा

इस क्षेत्र में पाक–अधिकृत कश्मीर के अन्तर्गत गिल्गित की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा गिल्गित–बालिस्तान क्षेत्र से स्पर्श करती अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के अतिरिक्त इस क्षेत्र में बढ़ रही चीन की सैन्य सक्रियता, काराकोरम मार्ग की रणनीतिक उपादेयता[12] व चीन–पाक स्थलीय सम्पर्क (सीपीईसी व काराकोरम मार्ग) के कारण यह सीमान्त रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील व भारत की रक्षा व्यवस्था की दृष्टि से नितान्त महत्वपूर्ण है। भारत–पाक के मध्य तानव की स्थिति यहाँ का स्थायी चरित्र है।

(ब) उत्तरी पर्वतीय सीमान्त–

इस सीमान्त पर भारत की सीमाएं चीन व म्यांमार से मिलती हैं तथा भारत के असम, अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा व नागालैण्ड जैसे भारत के सीमावर्ती राज्य स्थित हैं। यहॉ पर तुगां, थांगला, कोगटी नाटू, कार्पोबूमला व दीपू दर्रें स्थित हैं तथा चीन (तिब्बत) से इसका सम्पर्क व मैकमोहन सीमा रेखा विवाद के फलस्वरुप भारत व चीन के मध्य यह क्षेत्र तनावपूर्ण व संवेदनशील बना रहता है। म्यांमार के रास्ते राष्ट्र–विरोधी तत्वों की घुसपैठ कम चिन्ताजनक नहीं है। भारत–म्यांमार के मध्य लगभग 1,670 किमी0 लम्बी सीमा रेखा द्वारा मादक द्रव्यों की तस्करी, शस्त्र–तस्करी, घुसपैठ एवं बांगला देशी तत्वों की अवैध घुसपैठ से यह सम्पूर्ण क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से सम्वेदनशील है। भारत–नेपाल की खुली सीमाओं का लाभ उठाकर आई0एस0आई0 के तत्वों के भारत में प्रवेश से उसके आन्तरिक सुरक्षा आयाम भी जटिल होते जा रहे हैं।[13]

(स) पूर्वी सीमान्त–

यह असम के पूर्वी किनारे–किनारे फैली हुई पर्वतीय सीमा है जिस पर नागा, पटकोई, पीगूयामा व अराकानयोमा की पर्वत श्रेणियॉ हैं। यह क्षेत्र दलदली, जंगली व असमतल है जहॉ से भारतीय क्षेत्र में सरलता से घुसपैठ सम्भव है। इस क्षेत्र में मानव गतिविधियॉ कम हैं तथा घने आच्छादित जंगलों से युक्त इस क्षेत्र में तांगुप, तेजोगम व मणिपुर आदि दर्रें हैं। इस क्षेत्र में

नागा–कूकी, मीजो व असम के विद्रोही तत्व सक्रिय हैं तथा चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद के फलस्वरुप भारत हेतु खतरे भी पर्याप्त है। इस क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही आई0एस0आई0 की गतिविधियों के फलस्वरुप 'सिलीगुडी गलियारे' पर रणनीतिक दवाब बढ़ गया है। इसी गलियारे से संलग्न चोपरा गॉव (Chopra Village), जिसे गैरकानूनी शस्त्र, मादक द्रव्य व नकली नोटों का 'स्नायु–केन्द्र' (Nervs Centre) कहा जाता है, में विदेशी मुद्राएं व हानियों, पुश्तो व बलूचों की उपस्थिति तथा आई0एस0आई0 से स्थापित उनके नेटवर्क से[14] इस क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ गयी हैं।

यद्यपि आज भी हिमालय व काराकोरम पर्वत श्रृंखलांए भारत के लिए सुरक्षा प्रहरी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथापि सैनिक आक्रमण के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उत्तर के अनेक प्रमुख व छोटे दर्रों से सैनिक प्रवेश सम्भव है। भारत–तिब्बत सीमा पर भी सन् 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद रक्षा–व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किए गये है तथापि सैन्य संतुलन चीन के ही पक्ष में है। भारत व चीन दोनों के पास लम्बी दूरी के प्रक्षेपास्त्र व नाभिकीय वारहेड होने के फलस्वरुप इस क्षेत्र में सीमित व परम्परागत युद्ध के ही खतरे हैं। इसी प्रकार भारत–पाकिस्तान सीमा व भारत–बांग्ला देश सीमाओं पर बाड़ लगाकर तथा बाग्लादेश के साथ सीमा–समझौता करके सुरक्षा–ढाँचे को सुदृढ़ करने के प्रभावी उपाय भारत द्वारा किये गये है तथापि घुसपैठ की समस्या पर पूर्णतः अकुश नहीं लगाया जा सका है। इन क्षेत्रों का भू–विन्यास इसमें सबसे प्रमुख अवरोध है। हिन्दमहासागर भी भारत की सुरक्षा व विकास का प्रमुख तत्व है जहाँ वाह्य शक्तियों विशेषकर चीन व अमेरिका की बढ़ती स्पर्धा, व चीन द्वारा संचालित बी0आर0आई0 जैसी महत्वाकाँक्षी योजना व चीन–पाक के मध्य विकसित हो रहे 'आर्थिक गलियारे' से भारत की चिन्ता बढ़ना स्वाभाविक है। यद्यपि भारत ने बिम्सटेक (BIMSTEC) के माध्यम से अपने रणनीतिक व आर्थिक हितों के रक्षार्थ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं तथापि शक्ति–स्पर्धा के भावी आयामों को देखते हुए रणनीतिक, आर्थिक व कूटनीतिक दृष्टि से भारत को दीर्घकालिक एवं प्रभावी नीति निर्धारण कर उसके क्रियान्चयन की दिशा में

मुखरता के साथ क्षेत्रीय व वैश्विक भू–राजनीतिक समीकरणों में अपनी उपादेयता को रेखांकित करना ही होगा।

भारत–नेपाल–चीन केन्द्रित क्षेत्रीय रणनीतिक आयाम

केन्द्रीय हिमालय क्षेत्र में भारत व चीन के मध्य स्थित स्थलबद्ध व विश्व का एक मात्र हिन्दू राष्ट्र (अब प्रजातान्त्रिक व धर्मनिरपेक्ष) नेपाल भारत व चीन के मध्य ऐसा अन्तस्थ क्षेत्र है जो शीतयुद्धोत्तरकालीन क्षेत्रीय रणनीतिक व भू–राजनैतिक दृष्टि से भारत की सुरक्षा में एक ज्वलन्त तत्व बना हुआ है। लगभग 1,47,141 वर्ग किमी0 क्षेत्र में विस्तृत नेपाल का अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित है तथा मात्र काठमाण्डू घाटी व नदियों की घाटियाँ ही कृषि योग्य हैं। नेपाल की लगभग 92 प्रतिशत आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। यहाँ की आबादी लगभग पचास प्रतिशत हिन्दुओं की तथा शेष लगभग बौद्ध धर्मविलम्बियों की है। भारत व चीन के मध्य स्थित अन्तस्थ राज्य (Buffer State) की अवस्थिति ही उसका उत्तरदायित्व एवं सम्पत्ति (Liability And Asset) है।[15] एस0डी0 मुनि के शब्दों में, ''आर्थिक, राजनैतिक व सैन्य मामलों में नेपाल अपनी अवस्थिति के कारण भारत पर निर्भर तो है ही साथ ही दोनों के सामाजिक–सांस्कृतिक बन्धन उन्हें पास्परिक सन्निकटता हेतु विवश करते हैं।''[16] स्वाधीनता के बाद से ही हिमालयी सीमान्त क्षेत्र की भू–राजनीतिक परिस्थितियॉ भारत के लिए चिन्ता का विषय रही हैं। इस क्षेत्र के भू–राजनैतिक महत्ता को रेखांकित करते हुए सन् 1963 में पं0 नेहरु ने स्पष्ट कहा था कि–

" If it is breached, the way to the Indian plains and Ocean beyond would lie exposed, and the threat to India, would then, likewise, be a threat to the other countries of South and South-East Asia. India's determination to resest aggressions and retain her territoral integrity is, therefore, a vital factor in the safeguarding of peace and stability this whole area."[17]

हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा भारत की प्राथमिकता रही है जिसमें भूटान, नेपाल व सिक्किम (अब भारत का अभिन्न अंग) प्रमुख रहे हैं। ध्यातव्य है कि फरवरी 1951 में नार्थ– ईस्टर्न बार्डर डिफेंस कमेटी, जिसका गठन भारत के

रक्षा मन्त्रालय के अनुरोध पर किया गया था, से प्राप्त रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने इस क्षेत्र में आधारभूत रक्षा ढ़ाचें के निर्माण पर विशेष बल दिया।[18] उत्तरी व पूर्वोत्तर सीमान्त की सुरक्षा में चीनी प्रभुत्व विस्तार की शंकाओं से चिन्तित पं0 नेहरु ने न केवल नेपाल की यात्रा की अपितु भारतीय संदर्भ में 17 मार्च 1950 को यह भी घोषणा की कि नेपाल के साथ भारत एक सैन्य संधि करने की दशा में कदम उठा रहा है क्योंकि भारत के उत्तरी सीमान्त की सुदृढ़ रक्षा हेतु एक सुदृढ़ व सशक्त नेपाल महत्वपूर्ण कारक है। पं0 नेहरु का मत था कि हम नेपाल सहित भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी विदेशी आक्रमण को सहन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होने पर भारत की सुरक्षा पर उसने दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।[19] इस क्षेत्र में तिब्बत मसले पर चीन की आक्रामक मनोवृत्ति से चिन्तित पं0 नेहरु का मत था कि–

"We can not risk on own security by any thing not does in Nepal which permits either that barrier to be crossed or otherwise leads to the weakenning of our forntiers."[20]

यही कारण है कि भारत ने 31 जुलाई 1950 को नेपाल के साथ ''शान्ति व मैत्री सन्धि'' पर हस्ताक्षर करके दोनों देशों ने एक दूसरे की सम्प्रभुता का सम्मान करते हुए पारस्परिक सुरक्षा की अवहेलना न करने का संकल्प लिया। वास्तव में, 'रोटी व बेटी' सम्बन्धों की सांस्कृतिक व आर्थिक सुसमृद्धता के आधार पर स्वाधीन भारत ने सदैव अपने पड़ोसी नेपाल के साथ सम्बन्धों की स्थापना व उनका आदर पूर्वक निर्वहन करने की हर सम्भव कोशिश की किन्तु नेपाल ने बड़ी ही चतुराई व सतर्कता के साथ भारत के विरुद्ध 'चीन–कार्ड' का इस्तेमाल करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। यद्यपि नेपाल की भू–राजनीतिक विवशता इसके लिए उत्तरदायी हो सकती है किन्तु जिस तरह चीनी–प्रभाव में आकर नेपाल ने भारत–नेपाल की खुली सीमाओं को भारत–विरोधी तत्वों, विशेषकर आई0एस0आई0 व चीनी विचारधारा को अपने भू–भागों में विस्तृत होने दिया वह भारत के लिए चिन्ताजनक है। नेपाल भी इन अराजक तत्वों से कम आहत नहीं हुआ है। उसे भारतीय सहायता, सहयोग व संकट की घड़ी में प्राप्त सहायता को विस्मृत नहीं करना चाहिए।

शीतयुद्धोत्तर दक्षिण एशिया की भू–राजनीतिक व रणनीतिक यथार्थता को स्वीकार करते हुए नेपाल को भारत के साथ अपनी विदेश नीति का व्यावहारिक संचालन सर्वथा उसके हित में है साथ ही क्षेत्रीय शान्ति, विकास व स्थिरता के लिए भी अनिवार्य है।

अपनी उभरती हुई विशाल अर्थव्यवस्था व रणनीतिक दृष्टि से महान शक्ति का दर्जा प्राप्त चुके चीन व नेपाल के मध्य स्थापित ''अच्छे पड़ोसी की साझेदारी (Good Neighbourhood Partnership) [21] वास्तव में उसकी एशियाई नीति का ही अंग है जिसे वह 'चार वृत्तीय कूटनीति' (Four Circle Diplomacy) की संज्ञा दे रहा है।[22] इस महत्वपूर्ण कूटनीति का प्रमुख लक्ष्य उभयपक्षीय हितों वाले राष्ट्रों के साथ अपने राजनयिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करके अपने सुरक्षा–आवृत को सुरक्षित करते हुए आर्थिक व राजनीतिक सहयोग हेतु ठोस आधार निर्मित करना है। वास्तव में, चीन की उक्त ''परिधि–कूटनीति'' एशियाई क्षेत्र में अपना प्रभाव–वृद्धि करते हुए न केवल वैश्विक शक्ति–राजनीति में व्यापक व दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति सुनिश्चित करनी है अपितु भारत के सुरक्षा–क्षितिज पर दबाव डालकर उसकी विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था व एशियाई क्षेत्र में बढ़ रहे उसके प्रभाव–विस्तार पर अंकुश लगाना भी है। अक्टूबर 2013 के पश्चात चीन अपनी उक्त कूटनीति के माध्याम से हिमालयी क्षेत्र की भू–राजनीतिक संरचना को अपने पक्ष करते हुए विशाल–बाजारों वाले राष्ट्रों को पारस्परिक विकास हेतु अभिप्रेरित करने की दिशा में तीव्रता से अग्रसर हैं। यही कारण है कि वामपंथी आदोलन से अभिप्रेरित नेपाल में चीन ने अपने पैर पसारने शुरु कर दिये हैं। इतना ही नहीं, तिब्बत का प्रश्न, चीन के लिए ऐसी संवेदनशील पहेली है जिसमें सहायक के रुप में वह नेपाल को अपने पक्ष में लाने हेतु 'चेक बुक कूटनीति' के बजाय विविध प्रकार के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक ढ़ाचों के निर्माण सम्बन्धी प्रलोभन देकर उसे अपने पक्ष में करने हेतु प्रयत्नशील है।[23]

चीन को इस बात का पूर्ण आभास है कि नेपाल उसके लिए तिब्बत–प्रश्न व व्यापार क्षेत्र में मित्र बनकर कुछ सीमा तक सहायता देने की स्थिति में है। दोनों की पारस्परिक मित्रता से जहॉ एक ओर तिब्बती–विद्रोहियों

हेतु नेपाल के भूमि के इस्तेमाल की आशंका निर्मूल होगी वहीं उसके साथ वाणिज्यिक निकटता से भारत पर उसकी निर्भरता को भी शनैः शनैः शिथिल करके हिमालयी क्षेत्र में भू–राजनीतिक परिवेश को भी अपने पक्ष में किया जा सकेगा। नेपाल में चीन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 423 बिलियन रुपये का विशाल पूँजी निवेश इस बात का प्रमाण है कि नेपाल की हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं में भागीदार बनकर वह भारत के लिए जल–संकट उत्पन्न करना चाहता है। ब्रहमपुत्र नदी पर चीन द्वारा 27 बांधों का निर्माण उसकी उक्त रणनीति का ही अंग है। उधर, नेपाल भी अपनी विशिष्ट भू–सामरिक स्थिति का लाभ उठाते हुए सुरक्षा सम्बन्धी तत्वों की आड़ में अपने दोनों ही पड़ोसियों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बड़ी कुशलतापूर्वक दोनों नैसर्गिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों को इस्तेमाल करने की कूटनीतिक पैंतरेबाजी में संलग्न है किन्तु बदल रही क्षेत्रीय भू–राजनैतिक परिस्थितियों में नेपाल में चीन से अभिप्रेरित भारत–विरोधी गतिविधियाँ गम्भीर आयाम ले रही हैं''।

भारत का निकटस्थ पड़ोसी नेपाल अपनी भू–राजनीतिक अवस्थिति के कारण भारत के उत्तरी सीमान्त की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि दोनों के मध्य सांस्कृतिक व आर्थिक आधार पर निर्मित व विकसित द्विपक्षीय सम्बन्धों में भौगोलिक निकटता, सुरक्षा कारक, व्यापारिक पहलू व खुली अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण पारगमन सुगमता जैसे विविध कारणों से पारस्परिक सम्बन्धों का आधार अत्यन्त सुदृढ़ है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (NAM) व बिम्सटेक (BIMSTEC) का सदस्य होने के कारण नेपाल न केवल भारत के अत्यन्त निकट है अपितु भारतीय सेनाओं में आज भी गोरखा सैनिकों की भर्ती व उनका भारत के प्रति लगाव व श्रेष्ठ शौर्य प्रदर्शन उक्त सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने के साथ–साथ दोनों को ही गौरवान्वित करता है। दोनों देशों के मध्य पारगमन हेतु न तो बीजा व पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है और न ही कोई अन्य विशेष अवरोध उत्पन्न होते हैं। सीमा पर कुछ निर्धारित पारगमन स्थलों से यह आवाजाही निर्वाध रुप से सम्पन्न होती है। जहाँ तक व्यापारिक गतिविधियों का प्रश्न है, 1950 में सम्पन्न–''शान्ति व मैत्री सन्धि'' ही उसका आधार है तथा

भारत के कलकत्ता बन्दरगाह से ही उसके व्यापार का अधिकांश कार्य सुचारु रुप से संचालित होता है। यद्यपि नेपाल में सम्पन्न जन आदोलन के पश्चात राजशाही व 'हिन्दू–राष्ट्र' के दर्जे की समाप्ति के पश्चात भारत–नेपाल सम्बन्धों में कुछ गतिरोध अवश्य पैदा हुए हैं किन्तु भारत की सरकार ने कूटनीतिक प्रयत्नों से इसे दूर करने का गम्भीर प्रयत्न किया है। वैश्विक–शक्ति संतुलन में उत्पन्न हो रहे परिवर्तन चीन के शान्तिपूर्ण अभ्युदय, चीन द्वारा भारत की रणनीतिक घेरेबन्दी व 'सामुद्रिक सिल्क मार्ग परियोजना' में नेपाल की भागीदारी से भारत–नेपाल सम्बन्धों में गतिरोध तो अवश्य परिलक्षित हुए हैं तथापि दोनों की आर्थिक–सामाजिक–भौगोलिक सन्किटता द्वारा इसे न्यून किया जा सकता है। दक्षिण एशिया में पाक–प्रायोजित आतंकवाद के प्रसार व भारत–केन्द्रित उसकी नीतियों के संचालन में आतंकवादियों व आई0एस0आई0 द्वारा नेपाल की भूमि व भारत–नेपाल खुली सीमा रेखा को प्रवेश मार्ग के रुप में इस्तेमाल करना अवश्य चिन्ताजनक है किन्तु अब नेपाल भी आतंकवाद को समर्थन व प्रोत्साहन देने के विरुद्ध है तथा स्वयं को ऐसी गतिविधियों का केन्द्र न बनने देने हेतु प्रयत्नशील है। नवम्बर 2016 में इस्लामाबाद के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) में भारत के समर्थन में नेपाल द्वारा किये गये बहिष्कार निर्णय उक्त दृष्टि से एक सकरात्मक लक्षण है। भारत व चीन के मध्य स्थित नेपाल को भी अब यह समझना होगा कि भारत के साथ निकटता उसके विकास व सुरक्षा के लिए एक 'कवच' है तथा उसे दोनों ही पड़ोसियों के साथ संतुलित व सकारात्मक विदेश नीति के अनुपालन की आवश्यकता है। निःसन्देह, इसी संतुलित व व्यावहारिक नीति से ही उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, समृद्धि व स्थायित्व का पथ प्रशस्त हो सकेगा।

References

1. K.K. Nayyar and others (ed.) , National Security : MilitaryAspects, Rupa & Co. New Delhi, P.1.
2. Pushpesh Pant : India's foreign policy, Tata Mcgraw Hill, New Delhi, 2010, p.3
3. National Security necessarily denotes a nation's determination to preserve certain interest at all cost. Foremost among these national interests -- are the nations territorial integrity, political independence and fundamental governmental institutions. It expresses not only survival of nations but its ability to surve. - Quoted in strategic Analysis , Vol. xiv, No. 9 December 1991, P. 1073.
4. K.K. Nayyar, No. 1. P.2
5. Whoever controls the Indian Ocean will dominate Asia , the destiny of the world will be decided on its waters- A.T., Mahan.
6. B.D.Singh, Indian Subcontinent And China's New Defence Strategy, Sumit Enterprises, New Delhi, 2016, p.6.
7. Ibid P.7
8. K.N.Singh, Asia ka Pradeshik Swaroop. P.94.
9. Deb Brata Goswami, "The Crisis in South Asia, Indian in the context" in V.N. Vora et. atl (eds) New Dimensions of Security Challenges in South Asia : Diagnosis and Prognosis, Mohit Publications, New Delhi, 2012. p.58
10. Monir Hussain Moni, 'Japan and South Asia : Towards a Strengthened Economic Cooperation', Asia Pacific Social Science Review, Vol. VII, No. 1 P.6.

11. K.K.Nayyar: National Security: Military Aspects, Rupa & Co New Delhi, 2003,p 164.
12. Virendra Gupta & Alok Bansal, Pakistan Occupied Kashmir: The Untold Story, Manas Publications, New Delhi, 2008 p 142-43.
13. Strategic Analysis, Nov. 2000, p 65.
14. This village (Chopra), the nerve centre for illegal border trade and fake currency, has some 2000 Pushto and Baluch settlers from Afganistan engaged in money lending and suspected I.S.I. activities. Anand Kumar, "Illegal Bangladeshi Migration to India: Impact on Internal Security"- Strategic Analysis, Vol. 35, No.1, 2011, p 107.
15. S.S.Bindra, India And Her Neighbours,New Delhi 1984,p. 20.
16. S.D. Muni(ed), An Assertive Monarchy, New Delhi, 1977,p. 127.
17. Jawahar Lal Nehru, "Changing India", Times of India, New Delhi, 31 March 1963.
18. L.J.Kavic, India's Quest for Security : Defence Policies, 1947-1965, EBD Publishers, Dehradun 1967, p. 46.
19. Ibid, p. 55
20. Ibid, p. 56.
21. World focus, June 2015, p. 44.
22. Ibid.
23. For China "Tibet is a necessary evil because of which China needs to woo Nepal..... China, yet considering Chinese pragmatism it can not be doubted that Chinese do not play "Cheque 'Book diplomacy' until and unless economic gains are around the corner. This can only be happen if Nepal offers more than its market. China is wooing Nepal both through its

soft power strategies as well as hardcore investment", Prachi Agrawal, The Nepal Factor in Sino-Indian Relations, World Focus, June 2015 p. 45.

24. Hussain Wasbir (2014). "India China and MOU on Brahmputra-Analysis" Eurasia Review Date of access 12 September,2014. http:www.eurasiareview.com/05072014

अध्याय–1

नेपाल का ऐतिहासिक, आर्थिक व भू–रणनीतिक स्वरुप

एशिया के दो महान व शक्तिशाली पड़ोसियों, भारत व चीन के मध्य स्थित अन्तस्थ (Buffer State) व स्थलबद्ध (Landlock) राष्ट्र नेपाल अपनी भू–राजनीति व सामरिक विशिष्टता के कारण हिमालयी सुरक्षा सीमान्त का ऐसा राष्ट्र है जो दक्षिण एशिया में चीनी हितों की पूर्ति का एक यन्त्र व साधन बनने के कारण ही दोनों बड़े राष्ट्रों के मध्य स्पर्धा व आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है। लगभग 1,47,516 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत नेपाल विश्व का एक मात्र हिन्दू राष्ट्र था जो माओवादी इसरजेन्सी के परिणामस्वरुप राजशाही शासन के पतन के उपरान्त 'संघीय गणतन्त्र राष्ट्र' के रुप में अस्तित्व में आया। 'जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' नेपाल का ध्येय वाक्य (Motto) तथा ''सयों थुंगा फूलका'' इसका राष्ट्र गीत है। नेपाल की जनसंख्या लगभग 28 मिलियन है तथा काठमांडू इसकी राजधानी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान 41 वाँ है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 93 वाँ बड़ा देश है। हिमालयी क्षेत्र में स्थित नेपाल के उत्तर में चीन तथा दक्षिण, पश्चिम व पूर्व में इसकी सीमाएं भारत से निर्धारित होती हैं। भारत के उत्तराखण्ड, उत्तर–प्रदेश, बिहार, सिक्किम व प0 बंगाल राज्य नेपाल के दक्षिणी–पूर्वी व पश्चिमी सीमाओं पर स्थित हैं। चिकेन नेक (Chicken Neck) के ''सिलीगुड़ी गलियारा[1]' (Silliguri Corridor) नेपाल को भारत के प0 बंगाल राज्य से पृथक करता है तथा सामरिक दृष्टि से यह गलियारा अत्यन्त संवेदनशील है। नेपाल का उत्तरी सीमान्त क्षेत्र दुर्गम पर्वतमालाओं से आच्छादित है जहॉ विश्व की आठ सबसे ऊँची पहाडियॉ स्थित हैं जिनमें माउण्ट एवरेस्ट (29,028 फिट), कंचनजंगा (28,169 फिट), लोत्से (27,940 फिट), मकालू (27,762) व धौलागिरि (26,625 फिट) उल्लेखनीय हैं।[2] पूरे नेपाल में समुद्र के तल से लगभग 20,000 फिट ऊँची लगभग 250 पर्वत चोटियाँ फैली हुई हैं। नेपाल का दक्षिणी तराई भू–भाग अत्यन्त उपजाऊ व कृषि योग्य है।

Area Illegally Ceded to China by Pakistan
SINKIANG
Karakoram Range
Kunlun Range
Karakoram Pass
Daulat Beg Oldi
AKSAI CHIN (Area illegally occupied by China)
Indian Claim Line
Siachen Glacier
POK
Saser La
NJ9842
Rubra R.
Partapur
LAC
Western Highway
SSW
LOC
Turtuk
Shyok R.
Kargil
Hanif Sector
Kardung La
Ladakh Range
Tangtse
Leh
TIBET
River Indus
LADAKH
Chushul
Tashi Gong
Demchok
Himachal Pradesh
Shipki Pass
Map not to scale

तिब्बत के साथ नेपाल की लगभग 800 किलोमीटर लम्बी सीमा मिलती है जो चीन से सम्पर्क स्थापित करने का महत्वपूर्ण मार्ग है जबकि स्थलबद्ध राष्ट्र होने के कारण अपने वैश्विक व्यापार हेतु नेपाल पूर्णतः समुद्री मार्गों पर ही निर्भर है। 80^0 एफ व 88^0 $12'$ पूर्वी देशान्तर तथा 26^0 $22'$ व 30^0 $37'$ अक्षांश के मध्य विस्तृत नेपाल पूर्व से पश्चिम की ओर 800 किलोमीटर व दक्षिण से उत्तर की ओर 160 किलोमीटर तक फैला हुआ है।[3] यद्यपि विभिन्न राजनीतिक व ऐतिहासिक कालों में नेपाल का भौगोलिक सीमान्त परिवर्तित होता रहा है तथापि मौसम, तापमान, उर्वरता व आवागमन आदि की सुविधाओं के कारण काठमाण्डू की घाटी सदैव व्यापार का केन्द्र रही है।[4]

ऐतिहासिक स्वरुप–

जहॉ तक नेपाल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सन्दर्भ है यह महत्वपूर्ण पवित्र भूमि समृद्ध परम्पराओं व गौरव–सम्पन्न भू–भाग रहा है। स्कन्द पुराण के अनुसार सतयुग में नेपाल का प्राचीन नाम सत्यवती (The Land of Truth), त्रेता युग में तपोवन (The Land of Penance), द्वापर युग में मुक्तिसोपान (The Ladder of Salvation) तथा कलियुग में नेपाल के नाम से सुविख्यात रहा है।[5] ऐतिहासिक प्रमाणों से यह भी पुष्ट होता है कि राजा दुष्यन्त व उनके पुत्र भरत द्वारा शासित इस क्षेत्र को महाभारत की भी संज्ञा दी जाती है। नेपाल में स्थित महाभारत नामक पर्वत श्रृंखला से इसकी पुष्टि भी होती है। इतना ही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि हिमालय की पुत्री पार्वती के संदर्भ भी नेपाल से जुड़े हुए हैं, जहाँ की पवित्र भूमि पर विश्वामित्र, अगस्त्य, बाल्मीकि व यज्ञवालक्य जैसे महान ऋषियों द्वारा की गयी तपस्या व साधना के कारण वस्तुतः यह भूमि न केवल पवित्र अपितु सभ्यता के विकास का मुख्य केन्द्र रही है। गोपाल, लिच्छवी, मल्ल व शाह वंशजों से शासित इस क्षेत्र में नेपाली सभ्यता को विकसित होने का सुअवसर मिलता रहा है। कालान्तर में लगभग 250 ई0पू0 में नेपाल का दक्षिण भूक्षेत्र उत्तर भारत में स्थापित मौर्य साम्राज्य के अधिपत्य में आ गया तथा चौथी शताब्दी में नेपाल के कुछ हिस्सों पर गुप्त साम्राज्य का भी नियन्त्रण रहा। यद्यपि तीसरे ई0पू0 काल में काठमाण्डू घाटी तथा केन्द्रीय नेपाल से संलग्न कुछ क्षेत्रों पर लिच्छवी शासकों का अधिपत्य रहा

किन्तु इस साम्राज्य के पराभव के उपरान्त दक्षिण के चालुक्य वंश ने इस पर अधिकार कर लिया। इस शासन काल (चालुक्य वंश) के शासकों ने नेपाल के बौद्ध धर्म के स्थान पर हिन्दू धर्म की स्थापना की। तदुपरान्त, 12वीं शताब्दी में मल्ल राजाओं ने अपनी शक्ति में अद्‌भुत वृद्धि कर नेपाल पर नियन्त्रण करके लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। सन् 1484 ई0 में यह साम्राज्य तीन खण्डों में विभक्त हो गया जिसके परिणामस्वरुप काठमाण्डू, पाटन व भक्तपुर राज्यों का आर्विभाव हुआ। तदुपरान्त, 18वीं शताब्दी के मध्य में शक्तिशाली गोरखा राजा नारायण शाह ने उक्त सभी राज्यों को मिलाकर जो साम्राज्य स्थापित किया वही नेपाल के नाम से जाना जाता है।[7] ध्यातव्य है कि सन् 1769 में कीर्तिपुर की लड़ाई में नारायण शाह ने न केवल काठमाण्डू घाटी पर नियन्त्रण कर लिया अपितु उन्होंने बल पूर्वक इसका विस्तार करते हुए पूर्व में स्थित तिस्ता नदी से कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी के साथ–साथ दक्षिण के तराई के विशाल भू–भाग तक राज्य की सीमाओं को विस्तृत करने में सफलता प्राप्त की नेपाल की सीमाओं पर स्थित छोटे–मोटे राज्यों पर नियन्त्रण हेतु ईस्ट इण्डिया कम्पनी व नेपाल के मध्य हुए एग्लो–नेपाली युद्ध (1815–16) के पश्चात दोनों के मध्य सम्पन्न 'सुगौली संधि' के फलस्वरूप सिक्किम व तराई के अधिकृत भू–भागों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा नेपाल को उपहार में देना पड़ा। बाद में, एक सुनियोजित षड़यत्र के फलस्वरुप घटित भीषण रक्तपात के पश्चात जंग बहादुर राना ने नेपाल में राणा साम्राज्य की आधारशिला रखी। नेपाल का राणा परिवार न केवल अंग्रेजों का समर्थक था अपितु सन् 1857 के भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम व दोनों महायुद्धों में नेपाल ने अंग्रेजों की हर सम्भव सहायता की। यही कारण है कि 1816 में सम्पन्न 'सुगौलीसन्धि' के बावजूद सन् 1923 में नेपाल व अंग्रेजों के मध्य एक मैत्री संधि सम्पन्न हुई।

इस बीच सन् 1950 के दशक में चीन द्वारा तिब्बत पर अधिपत्य हेतु किये जा रहे सैन्य–कूटनीतिक प्रयत्नों से अपने उत्तरी सीमान्त की सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न भावी चुनौतियों का पूर्वानुमान कर भारत ने नेपाल की नयी सरकार व महाराजा त्रिभुवन (1911–55), जिन्होंने राणा साम्राज्य को समाप्त

China
Nepal
India
Maquan R.
Bramaputra R.
P'eng-ch'u Ho R.
Darchula
Simikot
Seti R.
Baitadi
Dandeldhura
Jumla
Silgarhi
Karnali R.
Mustang
Bheri R.
Dhangadhi
Birendranagar
Sarda R.
Salyan
Baglung
Pokhara
Tulsipur
Nepalganj
Pyuthan
Trisuli R.
Rasua Garhi
Gurkha
Kali R.
Nawakot
Kodari
Butawal
Kathmandu
Bhadgaon
Arun R.
Siddharthanagar
Patan
Hetauda
Bhimphedi
Ramechhap
Okhaldhunga
Amlekhganj
Sindhulimadi
Sun Kosi R.
Dhankuta
Birganj
Dharan
Ilam
Janakpur
Rajbiraj
Biratnagar
Rapti R.
Ghaghara R.
Ganges R.
Gandak R.
Baghirair Nadi R.
0 100 km
0 75 mi
30°
81°
84°
87°
N
©1997 MAGELLAN Geographix
(805) 685-3100 www.maps.com

कर नेपाल में नेपाली कांग्रेस के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी, से द्विपक्षीय रिश्तों को सुदृढ़ बनाने की हर सम्भव कोशिश की। नेपाल में व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता व नेपाल के महाराजा व सरकार के मध्य सत्ता–संघर्ष से उत्पन्न राजनैतिक अस्थिरता के कारण 1959 में नेपाल के राजा महेन्द्र ने (1955–72) पार्टीविहीन पंचायत पद्वति की स्थापना की। 1989 में नेपाल में प्रारम्भ जन–आंदोलन (People's Movement) के फलस्वरूप वहाँ शासन की प्रजातांत्रिक प्रणाली के शुभारम्भ के पूर्व तक नेपाल में पंचायत शासन प्रणाली के ही आधार पर शासन व्यवस्था कायम रही।

नेपाल विश्व का ऐसा राष्ट्र है जिसकी निम्नांकित विशेषताएं सर्वथा उल्लेखनीय हैं–

1. नेपाल विश्व का एकमात्र देश है जो कभी विदेशी आक्रान्ताओं/शक्तियों का गुलाम नहीं रहा।
2. यहाँ की सम्पूर्ण आबादी में 81% हिन्दुओं की है तथा यह पूर्व में (1991 तक) विश्व का एक मात्र हिन्दू देश रहा हैं।
3. भारत से बाहर स्थित एक मात्र पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग नेपाल में स्थित है, शेष ज्योतिर्लिंग भारत में ही हैं।
4. भारतीय पर्यटकों को नेपाल जाने हेतु पासपोर्ट/वीजा की आवश्कता नही पड़ती है।
5. यह भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है।
6. नेपाल के गोरखा सन् 1816 से ही ब्रिटिश सेना के अंग रहे हैं तथा कायरता के वजाय शहीद होना उनका मूल ध्येय है। (Better to die than be coward is their motto).
7. नेपाल 80 नृजातीय समूहों व 123 भाषाओं वाला देश है।
8. हिमालय का अधिकांश हिस्सा नेपाल में है।
9. नेपाल धार्मिक व नृजतीय दंगों से सदैव मुक्त रहा है जबकि यहाँ हिन्दू व बौद्ध धर्म के लोग तथा अन्य नृजातीय समूहों की जीवन शैली में पर्याप्त अन्तर है।

10. विश्व में एकमात्र नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज की आकृति गैर चतुभुजीय (Non- quardrilateral) है।

11. 2018 के एक आंकड़े के अनुसार नेपाल की कुल आबादी 28,095,714 है।

प्राकृतिक–प्रभाग– प्राकृतिक दृष्टि से नेपाल निम्नांकित चार भागों में विभक्त है–

1. हिमालयन क्षेत्र (The Himalaya Region)
2. पर्वतीय क्षेत्र (The Hilly Region)
3. घाटी क्षेत्र (The Vally Region)
4. तराई क्षेत्र (Terai Region)

नेपाल की निम्नांकित तीन नदियाँ प्रमुख हैं–

1. सप्तकोसी–

यह नदी पूर्व की ओर बहती हुई गंगा में मिलती है तथा इस प्रणाली के अन्तर्गत तामा कोशी, लिक्खू, सन कोशी, दूध कोशी, अरूण, तमोर व इन्द्रवती नदियाँ सम्मिलित हैं।

2. करनाली–

यह मानसरोवर से निकलकर गंगा में मिलती है। वेरी, सेती व महाकाली इसकी सहायक नदियाँ हैं।

3. गण्डकी–

नेपाल के उत्तरी क्षेत्र से नारायणी नदी के नाम से बहती हुई यह भी गंगा में मिलती है। बुद्धी, गण्डकी, त्रिशूली, काली गण्डकी व मार्सियान्दी इसकी सहायक नदियाँ हैं।

राजनैतिक–प्रभाग–

प्रशासनिक कार्यों के सुगम संचालन हेतु नेपाल 14 क्षेत्रों (7 उपक्षेत्रों) व जिलों में विभक्त है जिसके विस्तृत–विभाजन को निम्नांकित तालिका से समझा जा सकता है[9]–

Subdivisions

TAJIKISTAN
CHIN
AFGHANISTAN
Kabul
IRAN
Kandahār
Islamabad
Line of Actual Control
Kashmir
Indian claim
Faisalābād
Quetta
Lahore
Baluchistan
Punjab
Ludhiāna
PAKISTAN
Tibet
Himalayas
Lhasa
New Delhi
NEPAL
BHUTAN
THAR DESERT
Thimphu
Karāchi
Lucknow
Kathmandu
Kanpur
Patna
Tropic of Cancer
Central Indian Plateau
Varanasi
BANGLADESH
Dhaka
Arabian Sea
Surat
Bhopal
Kolkata
Chittagong
INDIA
Mumbai
Pune
DECCAN
Hyderābād
Western Ghats
Eastern Ghats
Bay of Bengal
PLATEAU
Bengaluru
Chennai
LAKSHADWEEP (INDIA)
Cochin
Jaffna
ANDAMAN ISLANDS (INDIA)
SRI LANKA
Laccadive Sea
Colombo
MALDIVES
Male
Equator
NICOBAR ISLANDS (INDIA)

Province No.1

1. Taplejung District
2. Panchthar District
3. Ilam District
4. Sankhuwasabha District
5. Terathum District
6. Dhankuta District
7. Bhojpur District
8. Khotang District
9. Solukhumbu District
10. Okhaldhunga District
11. Udaypur District
12. Jhapa District
13. Morang District
14. Sunsari District

Province No. 2

1. Saptari District
2. Siraha District
3. Dhanusha District
4. Mahottari District
5. Sarlahi District
6. Rautahat District
7. Bara District
8. Parsa District

Province No.3

1. Dolakha District
2. Ramechhap District
3. Sindhuli District
4. Kaverpalanchowk District

5. Sindhuplchowk District
6. Rasuwa District
7. Nuwakot District
8. Dhading District
9. Chitwan District
10. Makwanpur District
11. Bhaktapur District
12. Lalitpur District
13. Kathmandu District

Provnce No. 4

1. Gorkha District
2. Lamjung District
3. Tanahu District
4. Kaski District
5. Manang District
6. Mustang District
7. Prabat District
8. Syangdi District
9. Myagdi District
10. Baglung District
11. Nawalparasi District (East of Bardaghat Susta)

Province No. 5

1. Nawalparasi District (West of Bardaghat Susta)
2. Rupandehi District
3. Kapilbastu District
4. Palpa District
5. Arghakhanchi District
6. Gulmi District
7. Rukum District (Eastern part)

8. Rolpa District
9. Pyuthan District
10. Dang District
11. Banke District
12. Bardiya District

Province No. 7

1. Bajura District
2. Bajhang District
3. Doti District
4. Achham District
5. Darchula District
6. Baitadi District
7. Dadeldhuara District
8. Kanchanpur District
9. Kailali District

नेपाल की राजधानी काठमाण्डू घाटी आयताकार व पवर्त श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। कहा जाता है कि पूर्व में यह क्षेत्र एक झील के रुप में था जिसे मंजुश्री ने जल निष्कासन कराकर इसे आबादी हेतु तैयार किया।[10] पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, व स्वयंभूनाथ इस क्षेत्र के पवित्र स्थल हैं तथा काठमाण्डू के अतिरिक्त पाटन, भदगॉव, कीर्तिपुर व अन्य कई सुप्रसिद्ध स्थल स्थापत्य कला, पुरातत्व व व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

कृषि नेपाल क आर्थिक प्रगति का प्रमुख क्षेत्र है जो लगभग 65 प्रतिशत आबादी को रोजगार प्रदान करती है तथा यह क्षेत्र जी0डी0पी0 का 31.7 प्रतिशत अंश उपलब्ध कराता है। नेपाल के कुल क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत ही खेती योग्य है तथा 40.7 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र है। शेष भाग पहाड़ी है। तराई का क्षेत्र ही अपने उत्पादन द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों को खाद्यान्न आपूर्ति करता है।, फल, सब्जियाँ, चावल व गेहूँ ही यहाँ की प्रमुख खाद्य फसलें हैं।

अर्थव्यवस्था–

नेपाल की अर्थव्यवस्था पर उसके भौगोलिक कारक विशेषकर अवस्थिति (Location), जलवायु एवं तकनीकी कौशल का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। यद्यपि सन् 2019 के आकड़ों के अनुसार नेपाल का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 29.813 बिलियन डालर रहा है जबकि 2018 के आकड़ों से स्पष्ट है कि यह कृषि क्षेत्र में 27 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 59.5 प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्र में जी.डी.पी. का 13.5 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि कृषि व उद्योगों की तुलना में सेवा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा शनैः शनैः बढ़ रहा है। नेपाल का तराई क्षेत्र ही मुख्यतः कृषि योग्य है तथा भारत से सटे इस क्षेत्र में चाय, चावल, गेंहू, मक्का, गन्ना, दुग्ध व मॉस आदि का उत्पाद सन्तोषजनक है जबकि नेपाल की आबादी के लगभग 76 प्रतिशत लोग कृषि में, सेवा क्षेत्र में 18 प्रतिशत व उद्योगों में मात्र 6 प्रतिशत लोग ही कार्य करते हैं। रोजगार दर 34.2 प्रतिशत है।

यद्यपि नेपाल में कुशल मजदूरों व कामगारों की कमी व राजनैतिक अस्थिरता के कारण यहॉ का उद्योग जगत अपेक्षाकृत प्रगति नहीं कर पा रहा है तथपि नेपाल के 2010–11 की तुलना में 2018–19 में 3.5 प्रतिशत के स्थान पर जी.डी.पी. में 7.1 प्रतिशत की बृद्धि से पुष्ट होता है कि वह इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक प्रयत्नशील है। विकास की यह दर मुख्यतः कृषि, निर्माण, आर्थिक व अन्य क्षेत्र में हुई है। धन–प्रेषण जैसे कारक के अभाव व मुद्रास्फीति (6.1 प्रतिशत) आदि के कारण नेपाल की विकास दर अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रही है फिर भी नेपाल में गरीबी–उन्मूलन जैसी नीतियों के कारण सत्र 2003 के बाद गरीबी अपेक्षाकृत कम हुई है जो 2010–11 में घटकर 37 प्रतिशत व 2018 में 21.6 प्रतिशत तक आ पहुँची है। विकास गति का ही शायद यह परिणाम है कि अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नेपाली नागरिकों का प्रतिशत 2003–04 में 53.1 प्रतिशत की तुलना में 2015 में गिरकर 20 प्रतिशत तक पहुँच गया है। नेपाल में प्रति व्यक्ति आय 1.25 डालर प्रतिदिन से भी कम है। आशा है कि नेपाल की आयात–निर्यात व उत्पादन में शनैः शनैः हो रही

वृद्धि के कारण आगामी बीस वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में कमी आयेगी।

नेपाल में कार्य योग्य नागरिकों की लगभग आधी आबादी बेरोजगारी से ग्रस्त है। नेपाल में कुशल श्रमिकों की भारी कमी है तथा रोजगार दार 2017 के आंकड़ों के अनुसार 34.2 प्रतिशत है। बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत है। पर्यटन ही नेपाल की विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुख उद्योग है जिसमें 2012 में जी.डी.पी. के 3 प्रतिशत अंश की वृद्धि देखी गयी जो एक सकारात्मक लक्षण है। गरीबी से संत्रस्त नेपालियों का भारत, अमेरिका, कतर, थाईलैण्ड, यू0के0, सउदी अरब, जापान, ब्रुनोई, आस्ट्रेलिया व कनाडा आदि देशों में रोजगार करने के फलस्वरुप नेपाल को 50 मिलियन डालर की आय होती है। इसमें भारत व इग्लैण्ड में सेवारत गोरखा सैनिकों का भी पर्याप्त योगदान है। नेपाल लगभग 822 मिलियन डालर मूल्य का निर्यात करता है जिसमें कालीन, कपड़े, चमड़े के सामान, जूट के सामान व अनाज आदि सम्मिलित हैं जबकि लगभग 2 बिलियन डालर मूल्य के सोना, मशीन व इसके उपकरण, पेट्रोलियम उत्पाद व फर्टिलाइजर आदि का नेपाल आयात करता है। यूरोपीय यूनियन (46.13%), अमेरिका (17.4%) व जर्मनी (7.1%) आदि नेपाल के प्रमुख निर्यातक सहयोगी है। यूरोपीय यूनियन सिले सिलाये नेपाली कपड़ों का 46.13 प्रतिशत सामान खरीदता है। नेपाल के आयात के क्षेत्र में भारत (70.2%), चीन (7.5%), संयुक्त अरब (4.9%) व सिंगापुर (4%) का सामान नेपाल को भेजते हैं। नेपाल की स्थलवद्ध अवस्थिति, दुर्गम धरातलीय संरचना तथा शिथिल आधारभूत सुविधाएं आदि ऐसे प्रमुख कारक हैं जो नेपाल के व्यापारिक नीतियों व उत्पादन आदि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सन 2017 में नेपाल का सार्वजनिक ऋण जी0डी0पी0 का 26.4 प्रतिशत तथा विदेशी मुद्रा भण्डार 9.091 बिलियन डालर रहा है। नेपाल का वित्तीय वर्ष 16 जुलाई–15 जुलाई है।

ऊर्जा–संसाधन–

ऊर्जा ऐसा प्रमुख कारक है जिसे 21 वीं शताब्दी में हो रहे वैश्विक–विकास की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि अर्थव्यवस्था, विद्युत–उत्पादन, यातायात के क्षेत्र, उर्वरक उद्योग व तेल–उद्योग आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो

ऊर्जा–संसाधनों पर पूर्णतः निर्भर हैं तथा इनकी कमी से किसी देश का समग्र विकास पथ अवरुद्ध सा हो जाता है। ऊर्जा कारक न केवल देश की समृद्धि से संलग्न है अपितु विदेशी सम्बन्धों के निर्धारण व राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मूलभूत तत्वों पर इनका निर्णायक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।[11] जहाँ तक नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र का प्रश्न है, वहाँ तेल, गैस व कोयले के भण्डारों का पूर्णत अभाव है, या अभी तक उनकी खोज नहीं हो पायी है। नेपाल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्णतः भारत, चीन व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर है तथा यह आयात भी भारत अथवा चीन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मार्गों द्वारा ही करता है। आकड़ों से यह पुष्ट है कि ईंधन आयात पर उसे अपनी विदेशी मुद्रा आय का लगभग एक चौथाई अंश व्यय करना पड़ रहा है। नेपाल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की मात्र एक प्रतिशत पूर्ति विद्युत से पूरा करता है जबकि विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक समस्त अनुकूल परिस्थितियॉ नेपाल में उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि लगभग 20 बड़े हाइड्रोपावर व अन्य छोटे–मोटे संयन्त्रों से उत्पादित बिजली का लगभग 730.47 मेगावाट ही उपयोग नेपाल कर पा रहा है। यद्यपि नेपाल में 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की व्यावहारिक क्षमता है तथापि तकनीक के अभाव के कारण वह विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अत्यन्त दयनीय स्थिति में है। नेपाल की मात्र चालीस प्रतिशत आबादी ही विद्युत सुविधाओं से लाभान्वित है तथा शहरी क्षेत्रों में तो लगभग 97 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा मात्र 72 प्रतिशत तक ही पहुँच पायी है। अभी भी नेपाल में उच्च–माँग की अवधि में लगभग 22 घण्टे की विद्युत कटौती की जाती है। ऊर्जा–सुविधा की दृष्टि से नेपाल की दशा दयनीय है जिसके लिए उच्च आयात–शुल्क, भारी विद्युत क्षति, उत्पादन की उच्च कीमत एवं घरेलू क्षेत्रों में आपूर्ति की न्यूनतम मॉग जैसे कारण मुख्यतः उत्तरदायी हैं। वर्तमान में नेपाल में बिजली की 8–10 प्रतिशत माँग बढ़ रही है जिसके लिए उसने भारत से समझौते करके आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु गम्भीर कदम उठाये हैं।

यातायात–

पर्वतीय व स्थलबद्ध हिमालयी देश होने के कारण नेपाल में यातायात व्यवस्था का सुचारु ढ़ग से संचालन अत्यन्त कठिन है जिसके कारण विश्व के हवाई, जल व स्थल मार्गों में उसकी पहुॅच सुगम नहीं है। समुद्र तट से नेपाल की पृथक अवस्थिति उसके व्यापारिक व विकास गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यद्यपि नेपाल में 47 हवाई अड्डे हैं किन्तु इनमें मात्र 11[12] अड्डे ऐसे हैं जिनका रनवे कंक्रीट व ईंट से बना है। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा नेपाल का प्रमुख व एक मात्र अन्तर्राष्ट्रीय वायु अड्डा है। नेपाल का उत्तरी भू–भाग क्षेत्र अत्यन्त दुर्गम होने के कारण इन क्षेत्रों में यातायात हेतु मार्गों का निर्माण दुष्कर कार्य है। सन् 2007 में नेपाल में 10,142 किलोमीटर पक्की व 7,140 किलोमीटर कच्ची सड़कें व दक्षिण क्षेत्र में मात्र 59 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी।[13] काठमाडू घाटी में प्रवेश हेतु प्रमुख मार्ग भारत होकर ही जाते हैं। नेपाल के सभी जिलों में से 15 जिला मुख्यालय अभी तक सड़कों से जुड़ नहीं पाये हैं। नेपाल का समुद्री यातायात कलकत्ता बन्दरगाह से ही संचालित होता है तथा यही उसके सामुद्रिक मार्ग का मुख्य विकल्प है। दुगर्म भू–संरचना के फलस्वरुप नेपाल के बाजारों, स्कूलों व चिकित्सालयों आदि को सड़क मार्गों से जोड़ना पर्याप्त कठिन कार्य है।

जनसांख्यिकी–

अर्थव्यवस्था, शिक्षा व स्वास्थ की दृष्टि से नेपाल एक निर्धन देश है तथा नेपाली नागरिकों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं व प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन हेतु संघर्ष करने के लिए विवश होना पड़ता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार नेपाल की सम्पूर्ण आबादी के लगभग 38.17 प्रतिशत घरों में शौचालय जैसी मूलसुविधाओं का अभाव रहा है तथा जीवन यापन हेतु अपेक्षित आवश्यकताओं की दृष्टि से विश्व में इसका 139 वॉ स्थान है। सन् 2010 के एक आकड़े के अनुसार नेपालियों की औसत आयु 65.8 वर्ष है जबकि स्वास्थ की दृष्टि से मानक विकास सूचकांक (H.D.I.) 0.77 प्रतिशत तथा विश्व में 126 वें स्थान पर है। वास्तव में, नेपाल बहुसांस्कृतिक व बहु–नृजातीय लोगों का ऐसा देश है जहॉ कश्मीर, तिब्बत, वर्मा व केन्द्रीय एशिया के प्रवासी

मूल नागरिक भी पर्याप्त संख्या में बसे हुए हैं। मंगोल मूल के किरान्त, जो उत्तरी नेपाल में बसे हुए हैं, यहाँ के प्राचीन निवासी हैं।

जुलाई 2018 के एक अनुमान के अनुसार नेपाल की जनसख्या 28,095,714 है जिसको विस्तृत संरचना निम्नवत है–[14]

Structure of Population-

01–14 वर्ष	:	30.93%, (पुरुष–4,646,048 स्त्री– 4,333,105)
25–54 वर्ष	:	21.86%, (पुरुष–3,176,186 स्त्री– 3,169,721)
55–64 वर्ष	:	06.22%, (पुरुष–0,877,288 स्त्री– 0,927,202)
65 से ऊपर	:	05.02%, (पुरुष–0,723,523 स्त्री– 0,732,620)

Net Migration Rate-

1.9 Migrants/ 1000 Population

Sex Ratio-

At - Birth

00 -14	Years	- 1.04 - Male/Female
15 -24	Years	- 1 - Male/Female
25 -54	Years	- 0.82 - Male/Female
55 -64	Years	- 0.95 - Male/Female
65 -Years and over		- 0.86 - Male/Female

Total Fertility Rate-

2-18 Children born/woman (2016est.)

Urbanization-

Urban Population:- 18.6% of Total Population (2015)

Rate of Urbanization : 3.18 Annual Rate of Change.

Population Growth-

1.24% (2016 estd.)

Birth Rate -

19.9 Birth/ 1000 Population(2016est.)

Death Rate-

5.7 Death/ 1000 Population(2016est.)

Caste and Ethenic Groups.(2011 census)

Groups	Population	% of Total
Khas-Chhetri	4,398,053	16.6%
Khas/ Bahum	2,226,903	12.2%
Magar	1,887,733	7.1%
Tharu	1,737,470	6.5%
Tamang	1,539,830	5.8%
Newar (taken as a single communal group)	1,321,933	5.0%
Khas-Kami	1,258,554	4.7%
Muslim(Taken as a single religious group)	1,164,255	4.4%
Yadav	1,054,458	4.0%
Rai	0,620,004	2.3%
Gurung	0,522,641	1.9%
Damai/ Dholi	0,472,862	1.8%
Khas-Thakuri	0,425,623	1.6%
Limbu	0,387,300	1.4%
Sarki	0,374,816	1.4%
Teli	0,369,688	1.4%
Chamar/ Harijan/ Ram	0,335,893	1.3%
Koiri/ Kushwaha	0,306,393	1.1%
Musahar	0,234,490	0.88%
Kurmi	0,231,129	0.87%
Sanyasi/ Dasnami	0,227,822	0.86%
Dhanuk	0,219,808	0.82%
Dusadh/ Paswan	0,208,910	0.79%
Sherpa	0,112,946	0.42%
Sunuwar	0,100,000	0.38%
Other(More than 100 caste/ ethenic group)	4,229,290	15.96%

शिक्षा–

नेपाल में साक्षरता दर 2001 में 54.1% से बढ़कर 2011 में 65.9% हो गयी है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 75.1 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 57.4 प्रतिशत है। काठमाण्डू की साक्षरता दर देश में सर्वाधिक 86.3 प्रतिशत तथा राउतहाट की सबसे न्यून 41.7 प्रतिशत है नेपाल में निम्नांकित विश्वविद्यालय हैं–

1. त्रिभुवन विश्वविद्यालय

2. पोखरा विश्वविद्यालय

3. पूर्वांचल विश्वविद्यालय

4. महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय

5. फार–ईस्टर्न विश्वविद्यालय

6. कृषि व वन विश्वविद्यालय

7. काठमाण्डू विश्वविद्यालय

नेपाल की सरकार ने प्राथमिक व महाविद्यालय/ शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है क्योंकि नेपाली विद्यार्थी विविध कारणों से बीच में ही शिक्षा ग्रहण करना बन्द कर देते हैं। लुम्बिनी में बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ उच्च–शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु नेपाल ने कई स्कालरशिप के भी कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं जिससे तकनीकी शिक्षा को समृद्ध करके विकास कार्यक्रमों को प्रभावी व समृद्ध बनाया जा सके। गरीबी व अशिक्षा नेपाल की सबसे बड़ी चुनौतियाँ है जिससे तकनीकी कौशल व कृषि उत्पादन आदि के क्षेत्र में नेपाल को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भाषा–

नेपाल की भाषाई धरोहर अति प्राचीन है जिसमें इण्डो–आर्यन व तिब्बत–बर्मीज भाषाओं के लोगों में भी पर्याप्त विभेद पाया जाता है। सन् 2018 की जनगणना के अनुसार नेपाल की भाषाई संरचना निम्नवत है–

- नेपाली –(44.6%)
- मैथिली –(11.7%)
- भोजपुरी –(06.0%)
- थारु (05.8%)
- तमांग (05.1%)
- नेपाल भाषा (03.2%)
- मगार (03.0%)
- दोतेली –(03.0%)
- उर्दू (02.6%)

- सुनुआर –(00.9%)
- नेवार (03.2%)
- वाजिका –(03.0%)
- अवधी (01.9%)
- लिम्बू (01.3%)
- गुरुंग (01.2%)
- अन्य (10.6%)

खास भाषा (Khas Bhasa) से व्युत्पन्न नेपाली भाषा मूलतः इण्डो–यूरोपियन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यद्यपि 18 वीं शताब्दी में नेपाली भाषा मूलरुप से गोरखाओं की भाषा थी जिसे कालान्तर में राष्ट्रीय भाषा का दर्ज मिल गया। दक्षिणी तराई क्षेत्र में मैथिली, अवधी व भोजपुरी भाषाओं का विशेष प्रभाव है। यद्यपि नेपाली वहाँ की सरकारी भाषा है किन्तु तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा व वैज्ञानिक समुदाय, सरकारी कार्यों व व्यापार में अब अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है।

धर्म–

नेपाल की आबादी में अधिकांश लोग हिन्दू धर्म के अनुयाई हैं तथा भगवान शिव को वे अपने देश के संरक्षक के रुप में मानते हैं। पशुपति नाथ मन्दिर नेपाल का सुप्रसिद्ध व पवित्र मन्दिर है जहाँ विश्व के विविध देशों के लोग दर्शन करने हेतु नेपाल की यात्रा करते हैं। नेपालियों के जीवन में धर्म की विशिष्ट भूमिका है। काठमाण्डू घाटी में ही मात्र 2700 धार्मिक स्थलों की उपस्थिति से सहज ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कपिलवस्तु जिले में स्थित लुम्बिनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए ऐसा प्रसिद्ध स्थल है जिसे यूनेस्को (UNESCO) ने विश्व की महत्वपूर्ण धरोहर के रुप में संरक्षित करने का निर्णय लिया है। 563 ई0 पू0 में शाक्य वंश में जन्में गौतम बुद्ध की यह जन्मस्थली है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार धर्म की दृष्टि से नेपाल की संरचना निम्नवत है–

Religion	Percent
Hindu	81.3%
Buddist	09.0%
Muslim	04.4%
Folk	03.0%
Christian	01.42%
Other	00.9%

यद्यपि नेपाल में जनसंख्या का घनत्व उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में दक्षिणी तराई में अधिक है तथापि काठमाण्डू की घाटी व इसके आस–पास आबादी का घनत्व विविध व्यापारिक, पर्याटन तकनीकी संस्थानों आदि के कारण अधिक है। नेपाल की अधिक आबादी वाले शहरों/नगरों का स्वरुप निम्नवत है–

- Kathmandu 975,453
- Pokhara 255,465
- Lalitpur 220,802
- Biratnagar 201,125
- Bhratpur 143,836
- Birganj 135,904
- Butwal 118,462
- Dharan 116,181
- Bhim Datta 104,599
- Dhangadhi 101,970
- Janakpur 097,776
- Hetanda 084,671
- Madhyapur Thimi 083,036
- Bhakatpur 081,748
- Ghorahi Dang 062,938

नेपाल की विदेशनीति–

भारत व नेपाल जैसे विशाल देशों के मध्य स्थित नेपाल ने अपनी भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक–प्रारुप, सुरक्षा, तकनीकी पक्ष एवं औद्योगीकरण सम्बन्धी तत्वों को ध्यान में रखकर जहाँ एक ओर अपने दोनों एशियाई पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति निर्धारण में सतर्कतापूर्ण ढ़ग से अपने राष्ट्रीय हितों को केन्द्र में रखकर द्विपक्षीय सम्बन्धों के निर्धारण व संचालन में राजनयिक कौशल का परिचय दिया है वहीं अपने अस्तित्व व अस्मिता की रक्षा करते हुए विकास–गति को त्वरित आयाम प्रदान करने की कोशिश की है। नेपाल द्वारा बदलते क्षेत्रीय व वैश्विक शक्ति पर संरचना व शक्ति–राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सदैव संतुलित रणनीतिक नीतियों के आधार पर गुटनिरपेक्षता की नीति के मूलाधारों पर ही अपने सभी पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों के निर्धारण व संचालन के अतिरिक्त पंचशील, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विश्वशान्ति व यू0एन0 चार्टर द्वारा निर्देशित सिद्धान्त ही नेपाल की विदेशनीति के आधार हैं। अपने विकास व समृद्धि हेतु 'एशियन डेबलपमेण्ट बैंक' (A.D.B.), आई0एम0एफ0 (IMF), सार्क (SAARC) बिम्सटेक (BIMSTEC), यू0एन0ओ0 (UNO) व ग्रुप–77 आदि के माध्यम से संचालित बहुपक्षीय सम्बन्धों द्वारा अपनी स्वायतता की रक्षा व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना उसके मूल लक्ष्य रहे हैं। आर्थिक व सैन्य सहायता देने वाले विश्व के प्रमुख देशों, अमेरिका, फ्रांस, जापान व यू0के0 के साथ–साथ अर्जेन्टिना, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, फिनलैण्ड, भारत, इसराइल, मलेशिया, नार्वे, पाकिस्तान, रुस, दक्षिण कोरिया आदि देशों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करके नेपाल ने कुशल विदेशनीति की स्त्रातेजी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना (सन् 2000 ई0) करके नेपाल समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों के उन्मूलन के साथ–साथ मानव अधिकारों की सुरक्षा व अन्य अवैध व्यापारों पर नियन्त्रण की कोशिश भी कर रहा है। भारत के साथ चल रहे लिपूलेख व धारचूला स्थित कालापानी व सुस्ता विवादों के हल हेतु भी नेपाल विधिक प्रक्रिया हेतु सक्रिय है।

सैन्यबल—

नेपाल की सेना में लगभग 95,000 सक्रिय जवान हैं। सेना का प्रमुख सेनापति नेपाल का राष्ट्रपति होता है जिसे संविधान की धारा 144 में विशेष अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, रुस, श्रीलंका व उत्तरी कोरिया नेपाल के प्रमुख शस्त्र निर्यातक देश हैं। 2011 के एक आकड़ों के अनुसार नेपाल का रक्षा बजट 207 मिलियन अमेरिकन डालर था जो जी0डी0पी0 का 1.4 प्रतिशत है। नेपाल की सेना मीर कासिम के साथ युद्ध (1763 ई0), अग्लों—नेपाल युद्ध (1814 ई0) तथा तिब्बत के साथ (1888 ई0) युद्ध में भाग ले चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रथम महायुद्ध (1914—18), अफगान युद्ध (1919), द्वितीय महायुद्ध (1939—45) व सन् 1948 के हैदराबाद कार्यवाही में भी रॉयल नेपाल सेना ने सक्रिय भूमिका का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है। इतना ही नहीं, मध्यपूर्व, लेबनान, सोमालिया, सूडान, हैती व तिमोर आदि मे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाये गये शान्ति अभियानों/मिशनों में भी नेपाली सेना की सक्रिय भागीदारी रही है। गोरखा सैनिकों की कर्तव्यनिष्ठा, वीरता व अदम्य शौर्य—प्रदर्शन का ही यह परिणाम है कि आज भी भारतीय सेनाओं में इनकी भर्ती की जा रही है तथा ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हितार्थ बलिदान में कदापि पीछे नहीं रहते।

नेपाल की विशिष्ट भू—राजनीतिक स्थिति एवं भारत के साथ उसके विशिष्ट सम्बन्धों का प्रवाह, जिसकी कुछ धाराएं दृश्य व कुछ अदृश्य हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा व सहयोग में विशिष्ट महत्व रखते हैं। यद्यापि भारत—नेपाल के राजनैतिक सम्बन्धों ने निश्चय ही पर्याप्त उतार—चढ़ाव देखे हैं तथापि संस्कृति, समुदाय, इतिहास, भूगोल व पारिवारिक रिश्तों के अटूट बन्धनों के फलस्वरुप दोनों राष्ट्र कभी पृथक नहीं रह सकते।[15] भारत—नेपाल सम्बन्धों का यही अटूट बन्धन चीन को स्वीकार्य नहीं। भारत की निरन्तर विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था, विश्व पटल पर बढ़ती उसकी महत्ता व नवीन वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका, जापान, रुस सहित एशिया, अफ्रीका व यूरोप के प्रमुख देशों के साथ भारत की राजनैतिक—रणनीतिक निकटता ऐसा पक्ष है जिसे चीन अपने वर्चस्व—वृद्धि, विशेषकर एशियाई नेतृत्व के सन्दर्भ में अवरोधक मानता है। यही कारण है कि

वह न केवल भारत–चीन के मध्य स्थित बफर–राज्य नेपाल को अपने प्रभाव में लेने हेतु व्यग्र है अपितु भारत के सीमान्त पड़ोसियों को भी अपने संजाल में लाकर भारत के शक्ति–ध्रुव बनने की राह को अवरुद्ध करने की दूरगामी रणनीति पर अग्रसर है। दूसरी ओर, अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्री व सद्भावनापूर्ण सम्बन्धों के स्थापन व संचालन हेतु प्रतिबद्ध भारत अपनी सुरक्षा,[16] विकास व स्थायित्व हेतु नेपाल के साथ बराबरी के दर्जे के आधारभूत सिद्धान्तों के आधार पर अपनी विदेशनीति में उसे प्रमुख स्थान दे रहा है, यही भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहर है।

References

1. It shares, borders with three countries-Bangladesh, Bhutan and Nepal. Important highways and railways passes through this area. Vital installations, such as the airfeilds of Bagdogra and Hashimara and oil pipelines are located here Strategic Analysis, Vol. 35, No 1, 2011, p.113.
2. P.P. and Jenkins W.M; The Himalyan Kingdoms-Bhutan, Sikkim and Nepal, Princetion, 1969.
3. S.B.Singh, Nepal: Struggle for Democracy, New Delhi 2007, p.3.
4. Saha R; Modern Nepal: A political History, 1769-1955, Vol. I, New Delhi, 1990, p03.
5. I.R.Aryal & T.P. Dungyal; A New History of Nepal, Kathmandu, Nepal, 1975, p.2.
6. Ibid.
7. S.B.Singh, No. 3, p.17.
8. Ibid. p.5
9. K.N.Sanwal, 'Resetling Indo-Nepal Ties And China', Sumit Enterprises, New Delhi, 2016, p15-17.
10. I.R.Aryal others No.5, p.7
11. Strategic Analysis, Vol. 35, No 4, July 2011, p. 595
12. World factbook : Retrieved 30 July, 2012
13. Ibid
14. Nepal Vikipedia, https://en.m.wikipedia.org
15. A.S. Bhasin; Documents On Nepal's Relation with India and China, Academics, New Delhi, p 25.
16. Since Nepal occupies an important strategic position between India and China, New Delhi considered Nepal as an integeral

part of its defence machenism and tried to keep her within its area of influence so that any inimical power did not get its upperhand in the Himalayan region. M.D. Dharamdasani, Nepal's Foreign Policy, Anmol Publications, New Delhi, 2005 ,p. 30.

अध्याय–2

भारत–नेपाल सम्बन्धों के विस्तृत आयाम

किसी भी राष्ट्र की विदेशनीति उसकी आन्तरिक नीतियों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबिम्ब होती है जिसके निर्धारण में उसकी भौगोलिक स्थिति ऐतिहासिक–अनुभव, संस्कृति, सामर्थ्य, ज्ञान–विज्ञान का स्तर व रणनीतिक–संस्कृति आदि तत्वों का समावेश होता है। उल्लेखनीय है कि विदेश नीति का मूल लक्ष्य कुशल राजनय के सदुपयोग से देश की एकता, अखण्डता व सम्प्रभुता की रक्षा करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति एवं उसका सतत संवर्धन करना होता है।[1] जहाँ तक भारत का प्रश्न है, सरदार के0एम0पन्नीकार की पुस्तक ''द सर्वे आफ इण्डियन हिस्ट्री'' व कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में भारत की भौगोलिक स्थिति, परम्पराओं, भू–राजनैतिक स्थिति, जातीय संस्कृतियों व सीमा निर्धारण आदि के दिग्दर्शन उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के विश्लेषणों से यह पुष्ट होता है कि जहाँ एक ओर राजनैतिक एकता के अभाव के फलस्वरूप भारत आन्तरिक शक्ति–संघर्ष से प्रभावित हुआ वहीं इन परिस्थितियों के कारण यह देश वाह्य आक्रमणों का सतत शिकार भी होता रहा। इन विषम परिस्थितियों में भी भारत भूमि से ध्वनित ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की नीति ने विश्व के ध्यान–आकर्षण को बार–बार अभिप्रेरित किया। विश्व शान्ति की स्थापना पर बल, अहिंसा, पंचशील, निरस्त्रीकरण, गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद का विरोध, एवं अफ्रीका–एशियाई एकता आदि भारतीय विदेशनीति के वे मूलाधार हैं जो आज भी वैश्विक–राजनीति व शक्ति–संरचना के केन्द्रक बने हुए हैं।

भारत–नेपाल सम्बन्धों का स्वरुप व प्रकृति–

भारत के उत्तरी सीमान्त पर हिमालयांचल में स्थित नेपाल व भारत के सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन हैं, जिन पर धर्म, समुदाय, सामाजिक पक्ष, भौगोलिक तत्व, भू–राजनीतिक अर्थव्यवस्था व भू–रणनीतिक तत्वों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। पृथक भौगोलिक ईकाइयाँ होते हुए भी भाषा–बोली, उपासना, सामाजिक साम्यता आदि के कारण दोनों में आज भी सम्बन्धों का स्वरूप अत्यन्त घनिष्ठ है। भारत व चीन जैसे विशाल राष्ट्रों के मध्य स्थित नेपाल की भू–राजनीति एवं अर्थव्यवस्था जैसे पक्ष उसकी विदेशनीति के ऐसे निर्धारक तत्व हैं जिनकी अवहेलना कर वह शान्ति, स्थायित्व व सुरक्षा की

भावनाओं की अनुभूति कर ही नहीं सकता। फिर भी क्षेत्रीय सुरक्षा आयामों, भारत–चीन सम्बन्धों की प्रकृति एवं वैश्विक शक्ति–राजनीति आदि ऐसे कारक हैं जिनका लाभ उठाकर यद्यपि नेपाल ने भारत व चीन दोनों को ही एक दूसरे के विरूद्ध प्रयोग व भ्रमित कर हर सम्भव लाभ प्राप्त करने की कुशल रणनीति का यथोचित लाभ तो अवश्य उठाया है किन्तु भारत पर उसकी निर्भरता का कोई भी प्रभावी विकल्प अभी तक उसकी विदेशनीति में दृष्टिगत नहीं होता है।[2] वास्तव में, भूगोल नेपाल की विदेश नीति को निर्धारित करने वाला ऐसा प्रभावी पक्ष है जिसकी अवहेलना उसके लिए सम्भव नही है।[3] उत्तर में चीन अधिकृत तिब्बत (TAR) एवं दक्षिण–पश्चिम व पूर्व से भारत द्वारा घिरे नेपाल की अवस्थिति के कारण वह दोनों एशियाई पड़ोसियों की स्पष्ट अवहेलना व विरोध करके अपनी विकास–प्रक्रिया को द्रुत गति नही दे सकता। भारत–नेपाल की खुली सीमाएं व सामुद्रिक व्यापार हेतु नेपाल की भारत पर निर्भरता ही उसके विकास गति को त्वरित स्वरूप उपलब्ध करती हैं जबकि हिमालयी श्रृखंला की दुरूह व्यापारिक गतिविधियाँ उसे चीन के निकट ले तो गयी हैं किन्तु इससे व्यापारिक गतिविधियाँ अत्यन्त सीमित हैं साथ ही शीत ऋतु में यह कार्य और ही दुष्कर हो जाता है। काठमाण्डू व तिब्बत के मध्य स्थापित रेल नेटवर्क से शनैःशनैः चीन–नेपाल व्यापार को यद्यपि नवीन ऊर्जा प्राप्त हो रही है तथापि चीन के उद्देश्य व्यापारिक काम सामरिक अधिक हैं।

सम्बन्धों का ऐतिहासिक पक्षः

धर्म एवं प्रभावी सामाजिक विमर्श की दृष्टि से नेपाल व भारत के सम्बन्धों की जड़े पर्याप्त गहरी हैं। दोनों ही राष्ट्र गहन हिन्दू आस्था के सूत्रों से ऐसे बंधे रहे हैं और आज भी हैं, जिन्हें पृथक राजनैतिक इकाई के बावजूद पृथक करना असम्भव हैं। अयोध्या–जनकपुर के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों के अतिरिक्त पशुपतिनाथ, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, काशी व बौद्ध धर्म के विभिन्न तीर्थस्थलों के परिदृश्य में भारत–नेपाल के मध्य जो सम्बन्ध स्थापित हैं वे दोनों के अटूट सम्बन्धों को महान ऊँचाई पर स्थापित करते हैं।[4] रत्ना मल के शाासन काल में (लगभग 400 वर्ष पूर्व) दक्षिण भारत के पण्डित सोम शेखरानन्दन को पशुपति का प्रमुख पुजारी नियुक्त करना तथा नेपाल के राजा को अकेले जगन्नाथपुरी

के मन्दिर (बिना किसी पुजारी के) मुख्य भाग में प्रवेश अधिकार जैसे धार्मिक सम्बन्ध इसके पुष्ट प्रमाण हैं कि भारत–नेपाल के सम्बन्धों का धार्मिक आधार कितना सुदृढ़ है।[5] दोनों देशों के नागरिकों का एक दूसरे में क्षेत्रों में प्रवास के अतिरिक्त नेपाली गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती उनके अटूट रिश्तों की पुष्टि करती हैं। धार्मिक पक्षों के अतिरिक्त विशाल भारत व छोटे देश नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्ध यद्यपि असमान आधार पर दिखाई देते हैं किन्तु उक्त के बावजूद भौगोलिक आयाम, जनसांख्यिकी आकर्षण व प्रभाव, आर्थिक संसाधन एवं उत्पादन–संरचना जैसे कारक दोनों देशों के सम्बन्धों की स्थापना में निःसन्देह निष्पक्ष व महत्वपूर्ण हैं।[6]

प्राचीन काल से ही भारत–नेपाल सम्बन्धों का स्वरूप इतना व्यवस्थित व सुदृढ़ रहा है जिससे दोनों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक सम्बन्धों में पर्याप्त समरूपता प्रकट होती है। वी0पी0 दत्त का मत है कि, ''दुनिया में दो देशों के मध्य इतने प्रगाढ़ सम्बन्धों के उदाहरण कम ही मिलते हैं''।[7] रामायणकालीन सम्बन्धों के बाद आज भी भारत व नेपाल दोनों के मध्य न केवल जनता के वैवाहिक सम्बन्ध कायम हैं अपितु रीति–रिवाज, त्यौहार व जाति प्रथा में भी पर्याप्त समानता है। ऐतिहासिक व प्रमाणिक रूप से भारत–नेपाल सम्बन्धों की तथ्यात्मक जानकारी छठी शताब्दी ई0पू0 से प्रमाणित होती है। पाली साहित्य में इसके स्पष्ट प्रमाण हैं कि भगवान बुद्ध के समकालीन कौशल के राजा प्रसेनजित ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर अपना अधिपत्य स्थापित किया तथा भगवान बुद्ध राज्य त्यागकर भारत के बिहार राज्य आये। इस अवधि में भारत–नेपाल के सांस्कृतिक सम्बन्धों में पर्याप्त सुदृढ़ता उत्पन्न हुई। महात्मा बुद्ध ऐसी पहली कड़ी माने जाते हैं जिन्होने भारत–नेपाल को सांस्कृतिक सूत्र में बँधने का ठोस आधार प्रदान किया।[8] यही कारण है कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बनी के अतिरिक्त बौद्ध गया व सारनाथ आदि पवित्र स्थलों के प्रति आज भी नेपालियों की गहन श्रद्धा है। सम्राट अशोक की कपिलवस्तु यात्रा व उनके पुत्र महेन्द्र व पुत्री संघमित्रा की बौद्ध–धर्म प्रचार हेतु की गयी यात्राओं, चारूमित्रा की नेपाल के राजकुमार देवपाला (Devpala) के साथ किए गये विवाह तथा काठमाण्डू के निकट 'पाटन व चाबीहिल' नामक

उपनगरों की स्थापना[9] से भारत–नेपाल सम्बन्धों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। उक्त सम्पर्कों के बावजूद चौथी ई0पू0 में नेपाल गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के अधीन रहा। प्रयागराज में स्थापित एक स्तम्भ पर सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशंसा में उल्लिखित प्रार्थनाओं में नेपाल के राजा के नाम उल्लेख से इसकी पुष्टि होती है।[10] तदुपरान्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सम्पन्न नेपाल यात्रा एवं वहाँ विक्रमी सम्वत का शुभारम्भ तथा नेपाल में शैववाद का विस्तार यह पुष्ट करते हैं कि दोनों पड़ोसी देशों के सम्बन्धों का आधार पर्याप्त सुदृढ़ रहा है। इतना ही नहीं, गुप्त वंशज से सम्बद्ध लिच्छवियों द्वारा नेपाल में राजतन्त्र की स्थापना, वशुवध नामक महान तपस्वी की नेपाल यात्रा एवं सूर्यवंशी सम्राट वृषदेव वर्मा के शासनकाल में हिन्दू धर्म के पुनर्जीवन हेतु शंकराचार्य की नेपाल यात्रा से यह पुष्ट होता है कि नेपाल पर भारत का विशेष प्रभाव रहा है। 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के एक राजपूत राजा नान्यादेव ने सम्पूर्ण नेपाल पर बलपूर्वक अधिकार कर अपने सैनिकों हेतु एक विस्तृत बस्ती की स्थापना की। नेपाल की आबादी इन्ही की बंशज मानी जाती है तथा वहाँ के मल्ल वंशज भी दक्षिण भारतीय मूल के माने जाते हैं।[11]

भारत पर मुस्लिमों के हुए आक्रमण के फलस्वरूप भारत की कई जनजातियों के नेपाल पलायन से दोनों देशों के सम्बन्धों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 14वीं शताब्दी में भारत के राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी से संत्रस्त होकर हिमालय की पहाड़ियों में शरण ली तथा धीरे–धीरे वहाँ गोरखा गाँव के आस–पास छोटी जागीर स्थापित कर लिया। सन् 1457 में नेपाल के राजा यक्षमल द्वारा अपने राज्य को मटगाँव, काठमाण्डू व पाटन नामक तीन राज्यों में विभक्त कर देने से नेपाल की स्थिति कमजोर हो गयी तथा अगले तीन शताब्दियों तक नेपाल में किसी शक्तिशाली राज्य की स्थापना सम्भव न हो सकी। तत्पश्चात् आधुनिक नेपाली साम्राज्य के निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में नेपाल घाटी, काठमाण्डू, पाटन व मटगाँव के राजाओं को पराजित कर सन् 1769 में एक सुदृढ़ और एकीकृत राज्य की स्थापना की गयी। पृथ्वी नारायण शााह के वंशज भारत के राजस्थान के सिसौदिया वंशज से सम्बन्धित थे जिनके पूर्वजों ने मुगलों के दमनकारी कुचक्र से पीड़ित होकर नेपाल की

बागमती घाटी में शरण ली थी। उल्लेखनीय है कि नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह की बढ़ रही शक्ति व प्रभाव को भारत के ब्रिटिश शासकों ने अपनी विस्तारवादी अभियान द्वारा नियन्त्रित करने का गम्भीर प्रयत्न किया किन्तु वे नेपाल को अपने प्रभाव में लाने में निष्फल रहे। उधर, तिब्बत में बढ़ रहे चीनी प्रभाव व ब्रिटिश भारत के मध्य फँसा देखकर नेपाल ने संतुलन बनाते हुए अपनी स्वतन्त्र स्थिति को अक्षुण्य रखने का हर सम्भव प्रयत्न तो किया ही साथ ही महाराजा पृथ्वी नारायण शाह के उत्तराधिकारियों ने भी नेपाली साम्राज्य–विस्तार गतिविधियों को जाारी रखा। सन् 1803 में नेपाल ने आक्रामक रूख अपनाते हुए नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, गढ़वाल, शिमला, सिक्किम तथा कुछ तराई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया किन्तु बाद में ब्रिटिश भारत द्वारा प्रारम्भ किए सैन्य अभियान के फलस्वरूप गोरखा सेना को पराजित होने के फल्स्वरूप दोनों के मध्य 'सुगौली सन्धि' सम्पन्न हुई जिससे नेपाल द्वारा भारत के अधिकृत क्षेत्रों को वापस करना पड़ा।

सुगौली सन्धि–

सन् 1814–16 तक चले ब्रिटिश–नेपाली युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों के (नेपाल सरकार व ईस्ट इंडिया कम्पनी) मध्य यह सन्धि सम्पन्न हुई जिस पर नेपाल की ओर से राजगुरू गजराज मिश्र (सहायक चन्द्रशेखर उपाध्याय) और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से ले0कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ ने हस्ताक्षर करके 4 मार्च, 1816 को इस सन्धि को दोनों पक्षों ने अनुमोदित किया।[12] सन्धि में वर्णित व्यवस्था के आधार पर नेपाल के कुछ भू–भागों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने, काठमाण्डू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति और ब्रिटिश सेवाओं में गोरखाओं के भर्ती की अनुमति तो मिल गयी किन्तु नेपाल को अपनी सेवाओं में अमेरिकी अथवा यूरोपीय कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी पूर्व प्राप्त सुविधा से वंचित होना पड़ा जबकि पहले नेपाली सेनाओं के प्रशिक्षण हेतु फ्रांसीसी कमाण्डरों की नियुक्ति की सुविधा उसे प्राप्त थी। उल्लेखनीय है कि काठमाण्डू में नियुक्त ब्रिटिश प्रतिनिधि मल्ल युग के बाद नेपाल में रहने वाला पहला पश्चिमी व्यक्ति था जबकि 18वीं शताब्दी के मध्य में गोरखाओं ने नेपाल पर अधिकार करने के उपरान्त ईसाई, धर्म प्रचारकों को नेपाल से बाहर कर

दिया था। नेपाल में ब्रिटिश प्रथम प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनर को काठमाण्डू के उत्तरी हिस्से में तैनात किया गया था। इसी क्षेत्र में आज ब्रिटिश व भारतीय दूतावास स्थित हैं। सुगौली सन्धि में की गयी व्यवस्थाओं के फलस्वरूप नेपाल ने अपने भू–भाग का लगभग तिहाई हिस्सा गवाँ दिया जिसके अन्तर्गत नेपाल के राजा द्वारा विजित पूर्व में सिक्किम, दार्जिलिंग, द0पश्चिम में नैनीताल, कुमाँऊ व गढ़वाल राजशाही वाशहर क्षेत्र तथा दक्षिण में तराई का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित था। सन्धि के अनुसार तराई भू–भाग का कुछ हिस्सा पहले 1816 में तथा एक बड़ा भू–भाग 1860 में 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु प्राप्त नेपाल की सहायता के फलस्वरूप उसे उपहार स्वरूप अंग्रेजों ने वापस कर दिया। सुगौली सन्धि में निम्नांकित व्यवस्था थी–

1. ईस्ट इण्डिया कम्पनी व नेपाल के राजा के मध्य सदैव शन्ति व मित्रता रहेगी।
2. नेपाल के राजा उन सभी–भूमि दावों का परित्याग कर देंगे जो युद्ध से पहले दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय थे तथा उस भूमि पर कम्पनी की सम्प्रभुता को नेपाल के राजा स्वीकार करेंगे।
3. नेपाल के राजा शाश्वत रूप से निम्नलिखित भू–भाग ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सौंप देंगे–
   - अ. काली व राप्ती नदियों के बीच का सम्पूर्ण तराई क्षेत्र।
   - ब. बुटवल को छोड़कर व राप्ती का गण्डकी नदी के बीच का सम्पूर्ण तराई क्षेत्र।
   - स गण्डकी व कोसी के बीच का सम्पूर्ण तराई क्षेत्र, जिस पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अधिकार स्थापित कर लिया है।
   - द. मेंची और तीस्ता नदी के बीच का सम्पूर्ण तराई क्षेत्र।
   - य. मेंची नदी के पूर्व के भीतरी प्रदेशों का सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र जिसे गोरखा सैनिकों द्वारा इस तिथि से चालीस दिन के भीतर खाली कर दिया जायेगा।
4. नेपाल के उन सरदार प्रमुखों, जिनके हित पूर्वगामी अनुच्छेद–3 के अनुसार उक्त हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होते हैं, की क्षतिपूर्ति के लिए

ईस्ट इण्डिया कम्पनी 2 लाख रूपये की राशि पेंशन प्रतिवर्ष के रूप में देने को तैयार है जिसका निर्णय नेपाल के राजा द्वारा लिया जा सकता है।

5. नेपाल के राजा उनके वारिस और उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में स्थित देशों पर अपने दावों का परित्याग करेंगे और उन देशों या उनके निवासियों से सम्बन्धित किसी भी मामले में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेंगे।

6. नेपाल के राजा सिक्किम के राजा को उनके द्वारा शासित प्रदेशों के कब्जे के सम्बन्ध में कभी परेशान करने या सताने की किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे। यदि नेपाल व सिक्किम के मध्य कोई विवाद पैदा होता है तो उसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मध्यस्थता के लिए भेजा जायेगा।

7. नेपाल के राजा ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी भी ब्रिटिश, अमेरिकी व यूरोपीय नागरिकों को अपनी किसी भी सेवा में न तो नियुक्त करेंगे और न ही उनकी सेवाओं को बनाए रखेंगे।

8. नेपाल व ब्रिटेन (ईस्ट इण्डिया कम्पनी) के बीच स्थापित शान्ति व सौहार्द के सम्बन्धों की सुरक्षा और उनमें सुधार के उद्देश्य से यह सहमति बनती हैं कि एक का मान्यता प्राप्त मन्त्री, दूसरे की अदालत में रहेगा।

9. इस सन्धि का अनुमोदन नेपाल के राजा द्वारा इस तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा, जो उसे अगले 20 दिनों में या उससे पहले (यदि साध्य तो) गर्वनर जनरल से अनुमोदित कराकर राजा को सुपुर्द करेंगे।

अंग्रेजों को इस बात की आशंका थी कि चन्द्रशेखर उपाध्याय द्वारा 4 मार्च, 1816 को हस्ताक्षरित उक्त–सन्धि को नेपाल शायद ही स्वीकार करें। इसीलिए गर्वनर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने ब्रिटिश सरकार की ओर से सन्धि की पुष्टि उसी दिन करके अपने समकक्ष उपाध्याय को दस्तावेज सौंप दिया। अब नेपाल द्वारा यह कहा जा रहा है कि चूँकि यह सन्धि नेपाली

राजशाही व अंग्रेजों के मध्य हुई थी अतएव नेपाल गणराज्य भारत गणराज्य के मध्य इसे लागू करना अवैधानिक व औचित्यहीन है। सन्धि के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिसीमन के अस्पष्ट होने का ही यह परिणाम हैकि आज भी भारत व नेपाल के मध्य 60,000 हेक्टेअर भूमि विवादित है तथा कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता–मेंची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर व हिले थोरी आदि क्षेत्रों में लगभग 54 स्थलों पर अतिक्रमण व सीमा–विवाद भारत व नेपाल के मध्य यदाकदा उग्र रूप लेते रहते हैं जिससे भारत व नेपाल सीमा पर बसे दोनों ही देशों के स्थानीय नागरिकों के मध्य तनाव व क्षेत्रीय विवादों को ऊर्जा मिलती रहती है।

सुगौली सन्धि के फलस्वरूप नेपाल ब्रिटिश–भारत के प्रभाव क्षेत्र में आने के साथ–साथ दोनों के मध्य सही अर्थो में राजनैतिक सम्बन्धों की शुरूआत हुई। इसी बीच 'कोट–हत्याकाण्ड' (15 सितम्बर, 1846) के पश्चात राणा जंग बहादुर द्वारा नेपाल की सत्ता सँभालने के उपरान्त उन्होंने अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति व रक्षा हेतु अंग्रेजों से मैत्री स्थापित करने के हर अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया। सन् 1857 के भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में उनके उत्तराधिकारियों ने अंग्रेजों को गोरखा सैनिक तो उपलब्ध कराये ही साथ ही ब्रिटिश सेना में गोरखाओं की भर्ती की सुविधा भी प्राप्त कर ली। फलतः, नेपाल के सहयोग से अंग्रेजों को तिब्बत से व्यापार की सुविधा भी मिलने लगी तथा अंग्रेजों ने प्रत्युत्तर में नेपाल को हर सम्भव आर्थिक व सामरिक सुविधाएं प्रदान कर क्षेत्रीय प्रभाव में अपनी वृद्धि हेतु प्रत्येक परिस्थिति का लाभ उठाया। सन् 1933 में लन्दन में नेपाली दूतावास की स्थापना एवं द्वितीय विश्वयुद्ध में अंग्रेजों की ओर से धुरी राष्ट्रों के विरूद्ध गोरखाओं द्वारा युद्ध में भाग लेना इसके स्पष्ट उदाहरण हैं।

भारत–नेपाल शान्ति व मैत्री सन्धि–

भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व संस्कृति आदि क्षेत्रों में सहयोग प्रदान कर एक स्वतन्त्र, सम्प्रभु, सुरक्षित व विकसित नेपाल का निर्माण भारतीय विदेश की प्राथमिकता सदैव रही। नेपाल में व्याप्त भय के प्रतिकूल स्वतन्त्र भारत की सरकार ने ब्रिटिश–भारत व नेपाल

के मध्य स्थापित सम्बन्धों को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय भू–राजनीति को स्थिर बनाने के परम लक्ष्य से द्विपक्षीय सम्बन्धों में विश्वास व सद्इच्छा उत्पन्न करने की सतत कोशिशें की। नेपाल की भू–राजनैतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल व गोविन्द बल्लभ पन्त आदि पं0 नेहरू की चीन के प्रति आशाजनक नीति के बावजूद इस बात पर चिन्तित थे कि भविष्य में चीन द्वारा नेपाल जैसे अन्तस्थ राज्य के माध्यम से भारतीय सुरक्षा को संकटापन्न करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है।[13] नेपाल के तत्कालीन महाराजा त्रिभुवन व प्रधानमन्त्री राणा के मध्य चल रहे सत्ता–संघर्ष, महाराजा त्रिभुवन का दिल्ली पलायन तथा भारतीय सहयोग से पुनः सत्तारूढ़ होने से उत्पन्न परिस्थितियों में अन्ततः नेपाल ने 31 जुलाई, 1950 को भारत के साथ 'शान्ति व मैत्री सन्धि' तथा दूसरी 'व्यापार वाणिज्य तथा पारगमन सन्धि' सम्पन्न की जो आज भी दोनों देशों की विदेश नीति के मूलाधार माने जाते हैं।[14]

नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर राणा व नेपाल में भारत के राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस सन्धि में 10 धारायें हैं। एक दूसरे की समग्र सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता व स्वाधीनता के सम्मान पर आधारित इस सन्धि में जहाँ एक दूसरे के नागरिकों व सामानों की स्वतन्त्र आवाजाही का संकल्प निहित है वहीं रक्षा व विदेशी मामलों में पारस्परिक सहयोग की भावनाएँ भी पुष्ट की गयी। सन्धि की धारा–2 में दोनों देशों के अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को संकटापन्न करने वाली किसी भी पड़ोसी की नीति व गम्भीर मतभेदों को परस्पर सूचित करने का संकल्प लिया वहीं धारा–5 में कहा गया है कि नेपाल अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक अस्त्र–शस्त्र, गोलाबारूद्ध व यौद्धिक सामग्रियों का आयात भारत से पारस्परिक सहमति द्वारा करने में स्वतन्त्र होगा। धारा–6 व 7 के अन्तर्गत यह व्यवस्था निहित हैं कि वे अपने नागरिकों की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति, व्यापार व वाणिज्य, निवास, सम्पत्ति व स्वामित्व तथा आवागमन आदि के संदर्भ में पारस्परिक सहयोग से समस्त सुविधाएं व प्राथमिकताएं उपलब्ध करायेंगे। सन्धि की धारा–8 के अन्तर्गत दोनों देशों ने ब्रिटिशकालीन भारत व नेपाल के मध्य सम्पन्न सभी सन्धि व समझौतों को निरस्त करने का निर्णय लिया। अन्तिम 10वीं धारा में इस सन्धि को रद्द करने

की प्रक्रिया का उल्लेख है।[15] यद्यपि शीतयुद्ध की समाप्ति, चीन–नेपाल सम्बन्धों में निरन्तर उत्पन्न हो रही सुदृढ़ता, नेपाल में साम्यवादी तत्वों की बढ़ रही शक्ति, भारत–चीन सम्बन्धों में उत्पन्न विवाद एवं बदल रही क्षेत्रीय भू–राजनीतिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में नेपाल में 1950 की नेपाल–भारत मैत्री सन्धि की समीक्षा की आवाजें उठती रही हैं किन्तु इस पर दोनों देशों ने अभी तक गम्भीर प्रयत्न नहीं किये हैं। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेपाल यात्रा के अवसर पर उन्होंने सन्धि की समीक्षा हेतु सहमति अवश्य प्रकट की थी किन्तु उन्होंने नेपाल को आगाह करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रश्न का राजनीतिकारण कदापि नही होना चाहिए।[16]

भारत–नेपाल शान्ति व मैत्री सन्धि के पश्चात दोनों देशों के मध्य विकसित मधुर रिश्तों का ही परिणाम था कि भारतीय विभाजन के फलस्वरूप भारत में उत्पन्न साम्प्रदायिक हिंसा पर नियन्त्रण हेतु नेपाल के अपने सैन्य बल उपलब्ध कराये।[17] उधर, तिब्बत पर पड़ रहे चीनी दबाव एवं नेपाल की प्रजातान्त्रिक शक्तियों द्वारा राणा कुलीन तन्त्र के प्रबल विरोध के फलस्वरूप नेपाल की आन्तरिक राजनीति में उत्पन्न अन्तर्द्वन्द से भारत के हिमालयी सीमान्त की सुरक्षा में नकारात्मक परिदृश्य के लक्षण प्रतीत होने लगे। इस अवसर पर पं0नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत–विरोधी शाक्तियों द्वारा वे किसी भी दशा में अपने हिमालयी सीमान्त में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होने देंगे।[18] स्पष्ट है कि हिमालय से संलग्न भारत के उत्तरी स्त्रातेजिक सीमान्त की सुदृढ़ता, स्पष्टता एवं सुरक्षा हेतु भारत की नीति में किसी भी प्रकार का असमंजस न कभी था और न आज भी है। वास्तव में, 1950 की भारत–नेपाल सन्धि ही नेपाल के साथ स्थापित भारत के विशिष्ट सामरिक व आर्थिक सम्बन्धों का मूलाधार है।[19]

भारत–नेपाल की खुली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा

भारत व नेपाल के मध्य लगभग 1850 किमी0 लम्बी सीमा का निर्धारण ब्रिटिश भारत व नेपाल के मध्य सम्पन्न सुगौली सन्धि के फलस्वरूप हुआ था[20] जिसमें हिमालय क्षेत्र के साथ–साथ भारत–गंगा का मैदान सम्मिलित है। यह

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पूर्णतः खुली है जिसे विभिन्न सीमा स्तम्भों के माध्यम से पृथक किया गया है तथा यह भारत के उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, व सिक्किम को नेपाल से पृथक करती है जिनकी लम्बाई निम्नवत् है–[21]

उत्तराखण्ड–303 किमी

उत्तर प्रदेश–651 किमी0

बिहार– 601 किमी

पश्चिम बंगाल–96 किमी

सिक्किम–98 किमी

उक्त अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को सन् 1950 में भारत–नेपाल के मध्य सम्पन्न शान्ति व मैत्री सन्धि के प्रावधानों द्वारा पुष्ट करके दोनों देशों के नागरिकों कोआने–जााने की छूट प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि जहाँ एक ओर इस खुली सीमा से भारत व नेपाल के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक सम्बन्ध पर्याप्त प्रगाढ़ हुए हैं वहीं सीमा पर अपराध, तस्करी व आतंकवाद जैसे तत्वों से नवीन चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। सीमा से सटे नेपाली क्षेत्रों में स्थित व निरन्तर स्थापित किए जा रहे मदरसे जहाँ एक ओर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के शरणस्थल बने हुए हैं वहीं आई0एस0आई0 ने तराई क्षेत्र में अपना प्रबल नेटवर्क स्थापित कर क्षेत्रीय असुरक्षा को बढ़ावा दिया है। तिब्बत के शरणार्थियों का भारत में प्रवेश तथा नेपालियों का म्यांमार पलायन इसी खुली सीमा के परिणाम हैं। मानव तस्करी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है जिनमें संलिप्त तस्कर खुली सीमा पर स्थित कई अदृश्य ग्रामीण–मार्गों का लाभ उठाकर सीमा सुरक्षा बल से बचते हुए अपनी गतिविधियों के संचालन में संलिप्त है।

भारत–नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की मानव–विहीन भूमि (No Man's Land) पर हो रहा अतिक्रमण गम्भीर चिन्ता का विषय है। उत्तर प्रदेश से संलग्न खुली सीमा पर स्थित नेपालगंज, बढ़नी व सोनौली क्षेत्रों के साथ–साथ बिहार के पश्चिमी चम्पारण व मधुबनी जिलों की सीमा पर गम्भीर अतिक्रमण हुआ हैं। कहीं–कहीं तो पक्के निर्माण भी कर लिए गये हैं जहाँ से नियमित

व्यवसाय सम्पन्न हो रहा है। बिहार के रक्सौल क्षेत्र में घुसपैठ, कब्जा व माओवादियों से मिल रहे प्रोत्साहन के फलस्वरूप अराजकता, हिंसा व तस्करी को व्यापक प्रोत्साहन मिल रहा है। बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले में दोनों देशों की सीमा गंडक नदी के जरिये निर्धारित होती है किन्तु अब गण्डक की धारा भारतीय सीमा से मुड़ जाने के फलस्वरूप नेपाल लाभ की स्थिति में है। नेपाल ने इस क्षेत्र के बाल्मीकी नगर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गाँवों की लगभग छः हजार एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। खेतों में गये किसानों को खदेड़ना, सुस्ता को नेपाल का अंग बताना, सीमा बन्द कर भारत विरोधी प्रदर्शन करना यहाँ की सामान्य घटनाएं बन गयी हैं। सीमामढ़ी जिले के मेजरगंज, सोनबरसा, बैरगानियाँ व सुरसंड के कई भागों में नौमैन्स लैण्ड, जिसे यहाँ 'दसगजा' भी कहा जाता है, की अन्तर्राष्ट्रीय अवधारणा ही समाप्त हो चुकी है। कन्हौली, भासर व लालबड़ी आदि स्थानों में सक्रिय अपराधी दोनों देशों के नियमों की खुली अवहेलना करते पाये जाते हैं। बेरोकटोक आवा–जाही का यह दुष्परिणाम है कि भारत के अर्धसैनिक बल भी इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थापना में कभी–कभी असहाय हो जाते हैं। इस सीमा क्षेत्र में नेपालियों द्वारा जबरन भारतीय भूमि का अतिक्रमण व कब्जा पर्याप्त चिन्ता का विषय है। कई बार तो यहाँ भारतीय सुरक्षा बलों पर भी आक्रमण करने की घटनाएं हो चुकी हैं। बाल्मीकि थाना क्षेत्र में स्थित रामपुरवा गाँव में तस्करों का प्रमुख अड्डा है जहाँ से बहुमूल्य वन सम्पदा की तस्करी की जाती है। रमपुरवा गाँव के पास तो नेपाली पुलिस चौकियाँ भी स्थापित की गयी है जिन्हें नेपाल सेना हेलीकाप्टरके माध्यम से हथियारों की आपूर्ति करती रहती है। इस क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि इस सीमा पर तैनात एस0एस0वी0 की 12वीं बटालियन के गश्तीदल के जवानों को रमपुरवा में रोक दिया जाता है जबकि पहले वे सुस्ता तक गश्त कार्यवाहियाँ करते थे। एस0एस0बी0 के कमाण्डेंट रह चुके आदित्य मिश्र का कथन है कि जबसे गण्डक का बैराज बना तब से कुछ भारतीय भूमि नेपाल में चली गयी। सुगौली सन्धि में यह माना गया था कि गण्डक नदी ही भारत–नेपाल की सीमा होगी किन्तु वैराज निर्माण के बाद सीमा निर्धारण नही हुआ। यह संयुक्त सर्वेक्षण से ही तय हो पायेगा कि कौन

सी जमीन किसकी है। इस विवादित मामले पर दोनों देशों की सरकारों की दृष्टि है। अधिकारिक सूत्रों से इसकी पुष्टि हो चुकी है कि इस क्षेत्र के 15 किलोमीटर भूमि पर नेपाल ने कब्जा कर लिया है तथा अब नेपाली सेना की चौकियाँ भी स्थापित हो चुकी हैं। सुस्ता विवाद इस सीमान्त की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक चिन्ताजनक है। भारत सरकार की उदासीनता का ही परिणाम है कि नेपाल के अराजक तत्व इस क्षेत्र में 5423.94 एकड़ वन भूमि पर कब्जा कर चुके हैं तथा भारत के भगोड़े अपराधी भी नेपाल के अराजक तत्वों की सहायता कर रहे हैं। नेपाली सेना के पक्ष में यहाँ गठित 'प्रतिकार समिति' भारत के किसानों के प्रबल विरोधी बनकर उभरे हैं। सुस्ता क्षेत्र में 90 किलोमीटर भूमि को लेकर भारत–नेपाल के मध्य गम्भीर विवाद पैदा हो गया है तथा सीमांकन के प्रति भारत व नेपाल सरकार की उदासीनता के परिणामस्वरूप सीमावर्ती ग्रामीण निवासी स्वयं ही देशों की सीमाओं का निर्धारण कर रहे हैं।

मानव विहीन भू–पटटी पर उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महराजगंज जनपदों में 250 किलोमीटर भू क्षेत्र पर स्थानीय लोगों ने झुग्गी झोपड़ी डालकर कब्जा कर लिया है। यह क्षेत्र स्तम्भ संख्या 32 से 33, 61 से 65, 66 से 68 तथा 84 से 86 के बीच की है। इसके अलावा मुर्तिहा वन क्षेत्र में भी स्तम्भ संख्या 61 से 63 के मध्य भी पर्याप्त अतिक्रमण हुआ है। इस वन क्षेत्र में सटे 'नो–मैन्स लैण्ड' पर हजारों परिवारों ने स्थायी निवास स्थान निर्मित कर लिए है जो वनों की अवैध कटान व तस्करी में संलिप्त है। इतना ही नहीं, झुलनीपुर, ठूठीबारी, सोनौली, खुनवा, बढ़नी, मल्हीपुर आदि क्षेत्रों से संलग्न नोमैन्स लैण्ड पर भी पर्याप्त अतिक्रमण हुआ है। इन क्षेत्रों में लगभग 25 हजार की आबादी कब्जा जमाये हुए है। कहीं कही तो पक्के मकान तक बन गये है। पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के मध्य असामंजस्य के कारण यहाँ स्थितियाँ जटिल बनी हुई है।

उत्तरांचल राज्य के ऊधमसिंह नगर जिले से सटी नेपाल की सीमाओं पर भी नौमेन्स लैण्ड पर अतिक्रमण हुआ है। कई स्थानों से सीमांकन स्तम्भ गायब हैं। यह क्षेत्र माओवादियों की अति सक्रियता के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। राष्ट्र विरोधी तत्व व तस्करों की यहाँ अतिसक्रियता चिन्ताजनक

है। नेपाल के माध्यम से आतंकवादियों, तस्करों, अराजकतत्वों आदि की घुसपैठ से भारत–नेपाल सीमान्त क्षेत्र दिन प्रतिदिन असुरक्षित होता जा रहा है। यद्यपि भारत सीमा पर स्थापित तमाम चेक पोस्टों पर एस0एस0वी0 व नेपाल प्रहरी की कड़ी निगरानी के कारण अवांछनीय तत्वों का प्रवेश व तस्करी पर काफी हद तक नियन्त्रण स्थापित कर लिया गया है किन्तु इन क्षेत्रों में दोनों राष्ट्रों को जोड़ने वाली तमाम पगडंडियों के रास्ते से हो रही तस्करी पर नियंत्रण दुष्कर कार्य हैं। यद्यपि भारत व नेपाल के बीच यू0पी0 व उत्तरांचल के बीच 45 चौकियाँ व 113 सीमा चौकियों द्वारा निरन्तर सतर्कता बरती जा रही है तथापि सुरक्षा व नियन्त्रण सम्बन्धी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। नेपाल से लौंग, इलायची, डली, टार्च, साबुन आदि सामान तस्करों द्वारा सीमा पार कराया जाता है साथ ही जाली नोट, मवेशियों व अन्य मादक पदार्थों की भी तस्करी सीमान्त क्षेत्र के स्थित गाँवों व टेढ़े–मेढ़े तथा वनाच्छादित मार्गो द्वारा जारी है। उ0प्र0 के श्रावस्ती जिले व नेपाल की सीमा पर स्थित विभिन्न गाँवों– भचकाही, कटककुइयाँ, कानीबोझी व सोनपथरी आदि से तस्कर सरलता से अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। नोमैन्स लैण्ड से सटे इन गाँवों में तस्कर नेपाली वस्तुओं को लाकर काफी मात्रा में इकठ्ठा कर लेते हैं तथा मौका पाकर वे इन्हें नेपाल व भारत के विभिन्न नगरों में भेज देते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत की केन्द्र सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर रूपईडीहा, सोनौली, जोगवनी व रक्सौल में 'इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट' स्थापित करने के कार्य को त्वरित ढंग से पूरा कर लिया है तथा इन चेक पोस्टों पर 'कस्टम पुलिस' व 'इमीग्रेशन सीमा सुरक्षा बल' जैसी एजेन्सियों के साथ ही इन्टेलीजेन्स एजेन्सियाँ भी सक्रिय है। भारत की 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' ने अभीष्ट सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं नेपाल की ओर से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखकर 'केन्द्रीय राजमार्ग परिवहन विभाग' और 'हाईवेज एथोरिटी आफ इण्डिया' को नेपाल सीमा को जोड़ने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रान्तीय राजमार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग में आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने का निर्देश दिया है। यह कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

भारत–नेपाल के मध्य नदी जल–प्रबन्धन–

200 बिलियन क्यूबिक मीटर जल क्षमता से युक्त नेपाल में बहने वाली लगभग 600 नदियों के जल संसाधन का 45–71 प्रतिशत जलांश गंगा नदी में मिलने के कारण ब्रिटिश भारत की सरकार ने जल संसाधन से सम्बन्धित सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित महाकाली नदी पर शारदा कैनाल प्रोजेक्ट से सम्बन्धित एक समझौता नेपाल के साथ सन् 1920 में किया था। सन् 1947 में आजादी मिलने के पश्चात नेपाल के साथ स्वतन्त्र भारत ने 1954 में 'कोसी प्रोजेक्ट', 1959 में 'गण्डक सिंचाई व शक्ति–परियोजना' तथा 1996 में टनकपुर बाँध, शारदा बाँध व पंचेश्वर परियोजना के निर्माण हेतु समझौता किया। ये समझौते सिंचाई, बाढ़ विभीषिका के नियन्त्रण तथा शक्ति–उत्पादन की दृष्टि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

कोसी समझौता–

जहाँ तक कोसी समझौते का प्रश्न है, बिहार के शोक (Sorrow of Bihar) के नाम से प्रसिद्ध कोसी नदी की बाढ़ से होने वाली जन–धन की आपार क्षति को देखते हुए ब्रिटिश शासकों ने सन् 1779 में बाराह क्षेत्र में सर्वेक्षण कर कुछ उपाय करने हेतु प्रयास अवश्य किया किन्तु उसका कोई सार्थक लाभ नही मिल सका। तदुपरान्त, भारत व नेपाल के मध्य 1954 में सम्पन्न समझौते के फलस्वरूप बाढ़ नियन्त्रण व सिंचाई हेतु 1962 में हनुमानगढ/भीमनगर में एक बाँध का निर्माण किया। इस बाँध की लम्बाई 1.1 किमी है। इसे नेपाल की भूमि पर निर्मित किया गया है। कोसी परियोजना नेपाल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है जिससे 1,64,000 हेक्टेअर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। इसी से संलग्न चतारा नहर परियोजना को भी विश्व बैंक की सहायता से विस्तृत व उच्चीकृत किया गया है जो नेपाल के सनसारी व मोरंग जिलों की सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कोसी समझौते में कुल 18 अनुच्छेद हैं जिनमें कुछ पर नेपाल की गहरी आपत्ति रही है। सन्धि के अनुच्छेद 5 के आधार पर इस परियोजना हेतु नेपाल की अधिकृत भूमि पर भारत का स्वामित्व था किन्तु कतिपय विरोध व अवरोधों के बाद भारत ने उक्त भूमि पर नेपाल की सम्प्रभुता स्वीकार कर ली तथा इस पर 199 वर्ष

हेतु भारत के लीज सम्बन्धी अधिकार रह गये। इसी प्रकार कोसी परियोजना से कुछ रॉयल्टी भी नेपाल सरकार को प्राप्त हो रही है जिसका उपयोग वह ऊर्जा–उत्पादन व बाँध की मरम्मत में करता है। पूर्वी व पश्चिमी नेपाल को जोड़ने वाली यह परियोजना नेपाल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। काठमाण्डू के उत्तर स्थित नुआकोट जिले में बनी त्रिशुली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लाण्ट का निर्माण भारत द्वारा रॉयल्टी से ही पूरा किया गया। नेपाल के तराई क्षेत्र में निर्मित कई नहरें भी कोसी परियोजना के ही परिणाम हैं। कोसी नदी पर भारत के सहयोग से ही निर्मित उच्च बाँध से जुड़ी सुनकोसी–कमला डाइवरजन–प्रोजेक्ट से ऊर्जा के साथ–साथ नेपाल की सिंचाई व्यवस्था को पर्याप्त लाभ मिल रहा है।[22]

गण्डक सन्धि–

गण्डक नदी का जल ब्रिटिश भारत व नेपाल में सिंचाई हेतु सन् 1871 से ही प्रयोग में लाया जाता रहा है किन्तु दिसम्बर, 1959 में भारत व नेपाल ने गण्डक नदी के जल संसाधन के व्यवस्थित व अधिक सिंचाई उपयोग हेतु एक सन्धि पर हस्ताक्षर किया किन्तु सन्धि में अपेक्षित परिवर्तनोपरान्त यह सन 1964 से क्रियान्वित हुई। गण्डक–परियोजना के अन्तर्गत 1968–69 में गण्डक बाँध निर्मित किया गया। गण्डक नदी पर निर्मित इस बाँध की लम्बाई 2,749 फिट है जो कोसी के बाद नेपाल की द्वितीय सबसे बड़ी परियोजना है। इसके द्वारा नेपाल के 63,000 हेक्टेअर व भारत के 1,850,520 हेक्टेअर भूमि की सिंचाई की जा रही है।[23] गण्डक परियोजना पर सम्पूर्ण धन का व्यय भारत ने ही किया है जबकि नेपाल को भी सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। इस सन्धि में 13 धारायें हैं जिनके अन्तर्गत नेपाल को विशेष सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। जहाँ एक ओर गण्डक व इसकी सहायक नदियों के जल को सिंचाई हेतु नेपाल को जल वापस लेने का अधिकार प्राप्त है वहीं उसने 'एशियन डेवलपेण्ट बैंक' (ADB) व विश्व बैंक से सहायता लेकर क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी नेपाल में गण्डक नहर परियोजना को विस्तार देकर अपनी सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने का सफल प्रयास भी किया है। यह नेपाल को सन्धि में प्राप्त विशेष अधिकार व व्यवस्था के ही परिणाम हैं।

महाकाली सन्धि–

नेपाल की सहमति प्राप्त कर सन् 1928 में ब्रिटिश–भारत सरकार द्वारा महाकाली नदी के निकट बनबसा क्षेत्र में शारदा बाँध का निर्माण करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु इसके जल का उपयोग किया जाता रहा हैं। इसी बाँध से जहाँ एक ओर भारत लोहिया शक्ति–संयन्त्र से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु सक्रिय रहा वहीं सिंचाई हेतु नेपाल को भी 460 क्यूसेक जल इसी नदी से मिलता रहा है। इतना ही नहीं, नदी में जल उपलब्धता के फलस्वरूप नेपाल को 15 मई–15 अक्टूबर के मध्य 1000 क्यूसेक पानी तथा 15 अक्टूबर–15 मई की अवधि में 150 क्यूसेक जल प्राप्त करने की अतिरिक्त सुविधा[24] भी प्राप्त थी जो 1997–98 में विश्व बैंक की सहायता से 'महाकाली सिंचाई परियोजना' के पूर्ण होने के पश्चात ही सम्भव हो सकी। ध्यातव्य है कि 12 फरवरी, 1996 को नई दिल्ली में शेर बहादुर देउवा (नेपाल के तत्कालीन प्रधानमन्त्री) व पी0वी0 नरसिम्हा राव के मध्य महाकाली सन्धि सम्पन्न हुई जिसमें महाकाली के समग्र विकास योजना के ही अन्तर्गत शारदा बाँध, टनकपुर बाँध व पंचेश्वर परियोजना का निर्माण होना था। 6000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की पंचेश्वर परियोजना के निर्माण व विकास हेतु 4 बिलियन डालर की धनराशि आवंटित थी जिसमें दोनों देशों में कृषि–सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण की व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान निहित थे। 11 सितम्बर को नेपाली संसद द्वारा उक्त सन्धि की पुष्टि करके 5 जून, 1997 से इसे लागू कर दिया गया। यह सन्धि 75 वर्ष की अवधि तक वैध है। इस सन्धि का समर्थन नेपाली कांग्रेस, सी0पी0एन0–यू0एम0एल0, राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी एवं नेपाल सद्भावना पार्टी आदि ने दृढ़ता व खुले मन से किया।[25]

इस सन्धि में महाकाली नदी के दोनों ओर समान क्षमता वाले शक्ति–केन्द्रों की स्थापना एवं ऊर्जा के बराबर अंश एक दूसरे देशों द्वारा उपयोग करने का निर्णय लिया तथा परियोजना में अधिक धन व्यय होने के कारण महाकाली नदी आयोग (Mahakali River Commision) का गठन कर तकनीकी व आर्थिक मूल्यांकन पर पारस्परिक सहमति व्यक्त की। भारत व नेपाल का सीमांकन करने वाली महाकाली के विस्तार के एक स्थान पर

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण पर वे सहमत हुए तथा दोनों देश जल विद्युत व जल प्राप्ति हेतु समानता के सिद्वान्त–आधार पर धन व्यय हेतु भी सहमत तो हुए ही साथ ही नेपाल के महेन्द्र नगर में 'पंचेश्वर विकास प्राधिकरण' (PDA) की स्थापना करके इस उपयोगी परियोजना के निर्माण व विकास की भी सद्इच्छा प्रकट की। उल्लेखनीय है कि अधिक व्ययशील इस परियोजना में नागरिकों के विस्थापन (21,621 नागरिकों का), पुनर्स्थापना एवं विविध पर्यावरणीय मुद्दों के कारण इसके निर्माण में कई अवरोध उत्पन्न हो गये। यद्यपि सड़क, संचार, सिंचाई, पर्यटन, विद्युत–मूल्य, शिक्षा व स्वास्थ्य विकास जैसे क्षेत्रों हेतु अत्यन्त उपयोगी इस परियोजना से क्षेत्रीय–विकास के साथ–साथ भारत–नेपल के आर्थिक सहयोग की दृष्टि से पंचेश्वर परियोजना क्षेत्रीय विकास हेतु मील का पत्थर सिद्ध हो सकती थी किन्तु दोनों देशों के मध्य मतैक्य के अभाव में आशाजनक प्रगति सम्भव न हो सकी।

भारत व नेपाल के मध्य उक्त सान्धियों के माध्यम से जल–संसाधन वितरण, सिंचाई, बाढ़, नियन्त्रण व जल विद्युत उत्पादन हेतु किये गये सभी समझौतों के प्रति नेपाल की सरकार व जनता में भारत के प्रति अविश्वास एवं चीन के प्रति निरन्तर उत्पन्न होने वाली उसकी सकारात्मक भावनाएं ही भारत–नेपाल विवाद हेतु मूलतः उत्तरदायी हैं। वैसे भारत की सभी सरकारों ने उक्त सन्धियों में वांछित संसोधन हेतु नेपाल द्वारा जो भी प्रश्न उठाये गये भारत ने सक्रियता के साथ सबका त्वरित समाधान करने हेतु राजनैतिक व कूटनीतिक प्रयत्न किए हैं तथापि नेपाल आज भी भारत के प्रति शंकालु बना हुआ है। नेपाल में आज भी यह आशंका बनी हुई है कि भारत को प्राप्त जल–संसाधन का भाग नेपाल से अधिक है किन्तु उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोसी व गण्डक परियोजनाओं पर पूरा व्यय भारत ने ही किया है, नेपाल ने तो मात्र भूमि ही उपलब्ध कराई है। जहाँ तक पंचेश्वर परियोजना का प्रश्न है, इस पर दोनों ही देशों को बराबर धनराशि व्यय करना है तथा लाभ भी बराबर मात्रा में मिलना है। जो भी देश अपने हिस्से में अधिक सुविधाएं चाहेगा उसे अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी होगी। नेपाल को यह भी याद रखना चाहिए कि इन परियोजनाओं के फलस्वरूप विकसित सड़क व विद्युत

जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी उसे प्राप्त हो रही हैं जो उसकी विकास योजनाओं हेतु अत्यन्त उपयोगी हैं। भारत व नेपाल के मध्य भविष्य में भी होने वाले जल–संसाधन सम्बन्धी समझौते तभी सफल होंगे जब तक दोनों ही देशों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए भारत व नेपाल दोनों को ही खुली व सकारात्मक मानसिकता कर परिचय देना होगा।

भारत व नेपाल के मध्य पारगमन–

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार स्थल–बद्ध देशों के लिए दो पारगमन सुविधाओं का विधिक अधिकार दिया गया है जिनके माध्यम से वे व्यापार व आवगमन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। भारत व नेपाल के मध्य खुली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आवागमन हेतु न तो बीजा और न ही पासपोर्ट की अनिवार्यता भारत व नेपाल के नागरिकों पर लागू होते हैं क्योंकि इन दोनों की सामाजिक, व्यापारिक व सांस्कृतिक समरूपता पर्याप्त घनिष्ठ है। सन् 1950 में भारत व नेपाल के मध्य सम्पन्न 'शान्ति व मैत्री सन्धि' दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्धों को न केवल सुविधाजनक स्वरूप उपलब्ध कराती है अपितु उनकी पारस्परिक निर्भरता की भी पुष्ट करती है। नेपाल की सुरक्षा, व्यापार व स्थिरता की दृष्टि से उक्त सन्धि ही उसे रक्षा कवच प्रदान करके विकास हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करती रही है। उल्लेखनीय है कि भारत व नेपाल के मध्य 11 सितम्बर, 1960 को व्यापार व पारगमन सन्धि सम्पन्न हुई जो दोनों के मध्य व्यापार व आर्थिक सम्बन्धों के आधार को सुदृढ़ करती है। इस समय दोनों देशों के मध्य पारगमन व व्यापार हेतु निम्नांकित स्थलों का उपयोग किया जा रहा है–

Agreed routes for Mutual Trade		**Transit points to Calcutta Port**	
1.	Pashupatinagar/Sukhia Pokhari	1.	Sukhia Pokhari
2	Kakarbhitta/Naxalbari	2	Naxalbari (Panitank)
3	Bhadrapur/Galgalia	3	Galgalia
4	Biratnagar/Jogbani	4	Jogbani
5	Setobandha/Bhimnagar	5	Bhimnagar
6	Rajbiraj/Kunauli		

7	Siraha, Janakpur/Jayanagar	6	Jayanagar
8	Jaleswar/Bhitamore(Sursand)	7	Bhitamore
9	Malangawa/Sonabarsa		
10	Gaur/Bairgania		
11	Birgunj/Raxaul	8	Raxaul
12	Bhairahawa/Nautanwa	9	Nautanwa(Sonuali)
13	Taulihawa/Khunwa		
14	Krishnanagar/Barhni	10	Barhni
15	Koilabas/Jarwa	11	Jarwa
16	Nepalganj/Nepalganj Road	12	Nepalganj Road
17	Rajapur/Katerniyaghat		
18	Prithivipur/Sati (Kailali/Tikonia)	13	Tikonia
19	Dhangadhi/Gauriphanta	14	Gauriphanta
20	Mahendranagar/Banbasa	15	Banbasa
21	Mahakali/Jhulaghat(Pithoragarh)		
22	Darchula/Dharchula		

Source : Department of Customs, HMG/Nepal

भारत–नेपाल सीमा पर पारस्परिक व्यापार व पारगमन हेतु निर्धारित उक्त स्थलों पर स्थित 'कस्टम पोस्ट' के अतिरिक्त 143 छोटी भन्सार (कस्टम पोस्ट) स्थापित की गयी हैं। नेपाल ने अपने क्षेत्र में तीन ऐसे स्थलीय बन्दरगाहों की स्थापना भी की हैं जहाँ से वह सीधे कलकत्ता बन्दरगाह से आयात व निर्यात का कार्य त्वरित ढंग से कर सकता है। ये तीनो शुष्क बन्दरगाह (Dry Ports) विराटनगर, सिरसिया (वीरगंज के पूर्व स्थित उ0प्र0) एवं भैरहवां (उ0प्र0) में स्थित हैं। रक्सौल के मार्ग से इनका कलकत्ता से सीधा रेलवे सम्पर्क हैं जिसके माध्यम से नेपाल भारत के अतिरिक्त अन्य देशों से सामानों की आपूर्ति करता है। नेपाल व भारत के मध्य रेलवे समझौता सन् 2004 में हुआ था। दोनों देशों ने पारस्परिक सहमति के आधार पर भारत–नेपाल के अतिरिक्त अन्य किसी देश के नागरिकों के आवागमन हेतु निम्नांकित स्थलों को निर्धारित किया है–

1. बनवासा
2. धनगढ़ी

3. नेपालगंज
4. भैरहवा (सोनौली)
5. वीरगंज
6. ककरभिटा

भारत के उक्त समस्त अप्रवास–स्थल सड़क मार्ग द्वारा भारत व नेपाल को जोड़ने हैं जबकि नेपाल व चीन के मध्य मात्र दो ही अप्रवास स्थल हैं–

1. कोदारी सड़क मार्ग
2. नारा नांगला

व्यापारिक समृद्धि एवं आवागमन हेतु भारत ने नेपाल सीमा पर रक्सौल–वीरंगज एवं जोगवती–विराट नगर में दो एकीकृत चेक पोस्ट भी स्थापित किया है। इन व्यापारिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार व यात्रियों की आवाजाही को न केवल बेहतर बनाया जा रहा है अपितु आधुनिक व्यापार सुविधा के कारण अर्थव्यवस्थाा को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। 'नेशनहुड फर्स्ट पालिसी' (Nationahood first Policy) के अन्तर्गत जोगवनी–विराटनगर चेक पोस्ट का उद्‌घाटन प्रधानमन्त्री मोदी ने किया जिसके निर्माण में 140 करोड़ रूपये का प्रावधान है। यह केन्द्र 260 एकड़ में विस्तृत है। भारत सरकार ने नेपाल हेतु विशाखापत्तनम में अतिरिक्त परागमन बिन्दु स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

जहाँ तक भारत व नेपाल के मध्य व्यापारिक सम्बन्धों का प्रश्न है इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं स्वयं नेपाल की भू–आकृतियाँ इसे नियन्त्रित करती हैं। दोनों के आर्थिक व व्यापारिक सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन व प्रगाढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों के मध्य भौगोलिक सुगमता सतत् इसे प्रोत्साहित करती रही है। ऐतिहासिक तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं कि भारत व चीन के मध्य व्यापार नेपाल मार्ग से ही होता था। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' व ह्वेसांग के यात्रा–वृत्तान्त में इसका विस्तृत उल्लेख है। यद्यपि ब्यापार में उत्पन्न होने वाली विविध विसंगतियों को दूर करने हेतु भारत–नेपाल के मध्य सम्पन्न सन्धि में कई संसोधन हो चुके हैं तथापि नेपाल 1950 की मैत्री सन्धि को ही दोनों के मध्य व्याप्त व्यापार–असंतुलन को मुख्य कारक मान रहा है जबकि ऐसा है नहीं। उल्लेखनीय है कि नेपाल के सम्पूर्ण व्यापार का लगभग 70 प्रतिशत अंश भारत से ही सम्पन्न होता है तथा भारत की विकसित होती जा रही

अर्थव्यवस्था से उसे पर्याप्त लाभ मिल रहा है। फिर भी चीन के साथ उसके निरन्तर सुदृढ़ हो रहे व्यापारिक सम्बन्ध शनैःशनैः इसे प्रभावित तो अवश्य कर रहें हैं। यह क्षेत्रीय भू–राजनीतिक महत्ता का ही परिणाम है कि सन 1990 के दशक से नेपाल की अस्थिर राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर भारत ने सन् 2009 में 'व्यापारिक–सन्धि' में संसोधन कर नेपाल के व्यापारिक हितों को सुदृढ़ व निष्कष्टक करने का गम्भीर प्रयत्न किया जिससे न केवल उसके व्यापारिक घाटे में अपेक्षित सुधार के लक्षण प्रतीत हुए अपितु नेपाल के औद्योगिक क्षमता में पर्याप्त सुधार सम्भव हो सका। 27 अक्टूबर, 2009 को भारत–नेपाल व्यापार सन्धि में हुए संसोधन एवं साप्टा (SAPTA) से प्राप्त व्यापारिक सुविधाओं के फलस्वरूप नेपाल की उत्पादन क्षमता के साथ–साथ आर्थिक प्रगति को नयी दिशा प्राप्त हुई है। फिर भी उल्लेखनीय है कि भारत व नेपाल के मध्य खुली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से हो रही तस्करी व अवैध व्यापार से भी द्विपक्षीय व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि यहाँ सक्रिय तस्कर 'कस्टम चेक–पोस्ट' से बचते हुए कर की चोरी कर अवैध सीमा–पार व्यापार में अति सक्रिय हैं जिससे अंतुलन उत्पन्न होना स्वाभाविक है। औपचारिक व अनौपचारिक वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार से दोनों देशों की व्यापारिक स्थिति गम्भीर रूप से प्रभावित हो रही है। निम्नांकित तालिका से इसे समझा जा सकता है–

List of commodities traded between India and Nepal

	India to Nepal		Nepal to India	
	Informal	Formal	Informal	Formal
Food	50	59	13	61
Primary including	08	23	07	27
intermediate goods Textiles	28	18	40	12
Electronics	04	00	70	00
Other consumer	30	33	43	48
goods				
Machinery	06	33	00	03
Other	00	07	00	03

Source : ICRIER Survey Report 2006

यद्यपि सन् 1996–2016 तक राजनैतिक उथल–पुथल के कारण नेपाल के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा किन्तु 2015 में नये गणतन्त्र संविधान की घोषणा एवं 2018 में बहुमत की सरकार स्थापित होने के पश्चात भारत–नेपाल व्यापारिक गतिविधियों में नये अवसर प्रारम्भ हुए। भारत व नेपाल के मध्य द्विपक्षीय ब्यापार घाटा भारत के पक्ष में ही झुका रहा है क्योंकि इस अवधि में भारत ने नेपाल को 6.38 बिलियन डालर का माल निर्यात किया जबकि नेपाल से आयात 437 मिलियन डालर ही था। वहीं 2009–10 में द्विपक्षीय व्यापार 2.71 बिलियन डालर का रहा है। निम्नांकित तालिका से दोनों देशों के व्यापार व असंतुलन को समझा जा सकता है–

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009=10
EXPORT	3077.71	3891.69	4071.47	4172.88	3855.57	4100.59	3999.37
IMPORT	7873.93	8867.55	10714.31	11587.23	14237.65	16243.73	21711.43
BALANCE	4796.24	4975.86	6642.84	7414.35	10382.08	12143.17	17712.00
VOLUME	10951.66	12759.24	14785.78	15760.11	18093.22	20344.35	25710.80
SHARE	57.58	61.29	63.18	62.03	64.34	57.77	57.08

- Economic Survey 2011, Ministry of Finance, Nepal
- Ammout in Ten Million Nepalese Rupees.

नेपाल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत नेपाल को मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन और कल पुर्जे, दवाइयाँ, विभिन्न मशीनरी, विद्युत उपकरण, तार, सीमेण्ट, कृषि उपकरण, रासायनिक उपकरण, रसायन, धागा, जूट, कपड़े, पोलिस्टर धागे, इलायची, टूथपेस्ट, आदि का अधिकांश अंश आपूर्ति करता है। 2017–18 मे भारत का निर्यात 7.7 बिलियन डालर व नेपाल का आयात 446.5 मिलियन डालर (कुल 8.2 बिलियन डालर) था। भारतीय कम्पनियाँ नेपाल के बैंकिग, बीमा, बिजली व पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में निवेश कर रही हैं। भारत की सरकार नेपाल के बुनियादी ढांचे में निवेश कर उसके विकास हेतु सक्रिय है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, व ग्रामीण विकास में नेपाल को भारत का अद्भुत विकास सहयोग प्राप्त है। सार्क, बी0बी0आई एन0(BBIN) व बिम्सटेक (BIMSTEC) जैसे

बहुपक्षीय साझेदारी मंचों से भी नेपाल को सहायता पहुँचाने में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अगले सम्बन्धित अध्याय में इसका अद्यतन विवेचन किया गया है।

नेपाल की माओवादी जनक्रान्ति एवं भारत–

सन 1996 से 2006 तक नेपाल में चले माओवादी इन्सरजेन्सी से नेपाल की शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, विकास कार्यक्रम, व आन्तरिक जन भावनाओं पर व्यापक प्रभाव तो पड़ा ही साथ ही क्षेत्रीय भू–राजनीति एवं भारत–नेपाल–चीन के त्रिपक्षीय सम्बन्ध भी इससे अछूते नहीं रहे। पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना के उद्देश्य से सी0पी0एन0 (एम) द्वारा नेपाल राजशाही के विरुद्ध किये गये इस संघर्ष में नेपालियों के हुए व्यापक नरसंहार, जन–धन का विनाश, अपहरण एवं नेपालियों के हुए विस्थापन से भारत के इस निकटस्थ पड़ोसी को जो घाव मिले उसके प्रभाव अभी भी वहाॅ महसूस किये जा रहे हैं। चीनी माओवादी प्रणाली के प्रतिरुप की भाॅति नयी जन प्रजातान्त्रिक (New people's Democracy) की स्थापना के उद्देश्य से सम्पन्न यह इन्सरजेन्सी स्त्रातेजी की दृष्टि से साम्यवादी विचारधारा पर ही केन्द्रित रही। नेपाल के राणा शासन की समाप्ति के उद्देश्य से गठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (CPN) को ही शनैःशनैः विस्तारित करते हुए विघटन के प्रभाव सहन करके भी पुष्प कुमार दहल न केवल इसके प्रमुख नेता रहे अपितु चीन से इन्हें पर्याप्त वैचारिक, राजनैतिक समर्थन व संरक्षण भी सतत प्राप्त होता रहा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी आन्दोलन में उत्पन्न दरार एवं सी0पी0एन0 में हुए विखण्डन के फलस्वरुप पुष्प कुमार दहल व बाबू राम भट्टराई की वैचारिक असमानता के बावजूद दोनों के सम्मिलन से माओवादी आन्दोलन को नई गतिशीलता प्राप्त हुई। सन 1990 में नेपाल में सम्पन्न पंचायत चुनाव का दोनों नेताओं द्वारा गठित 'यूनिटी सेन्टर' (Unity Center) ने बहिष्कार करने के वाबजूद 1991 के प्रथम संसदीय चुनाव में हिस्सा लिया। चुनाव के पश्चात तीव्रता से घटित राजनैतिक घटनाक्रम में प्रचण्ड–भट्टराई ने मिलकर सी0पी0एन0 (माओवादी) का गठन करके माओवादी आन्दोलन को तीव्र करने हेतु गम्भीर कदम उठाये।

नेपाल की माओवादी आन्दोलन की पृष्ठभूमि में मुख्यतः निम्नांकित कारक उत्तरदायी थे–

1. नेपाल में गरीबी, सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा व बेरोजगारी।
2. राजशाही की आड़ में जमींदारों द्वारा गरीब किसानों का शोषण।
3. जमीन का असमान वितरण एवं कृषि योग्य भूमि पर अवैध नियन्त्रण।
4. स्वास्थ, सड़क, बिजली व स्कूलों का पिछड़े क्षेत्रों में अभाव।
5. नेपाली समाज में महिलाओं का शोषण एवं लिंग पक्षपात।
6. चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति का नेपाल की घरेलू राजनीति पर प्रभाव।
7. नेपाल की माओवादी विचारधारा को तुर्की, ईरान, फिलीपीन्स, श्रीलंका व बॉग्लादेश के क्रान्तिकारी आन्दोलन से प्राप्त अभिप्रेरणा।
8. भारत के साम्यवादियों, 'पीपुल्स वार ग्रुप' (P.W.G.) एवं से जन–युद्ध सम्बन्धी विचारधारा से प्राप्त प्रेरणा।
9. दक्षिण एशिया में सक्रिय माओवादी दलों व संगठनों के मध्य स्थापित CCOMPSA (Coordination Committee of the Maoist Parties and Organisation of South Asia) से सहायता व समर्थन की प्राप्ति।
10. नेपाल की घरेलू राजनीति में माओवादियों की राजनैतिक शक्ति का तिरस्कार।
11. माओवादियों को कुचलने हेतु सरकार द्वारा चलाया गया सैन्य दमन–चक्र।

उक्त परिस्थितियों से माओवादी आन्दोलन को न केवल सामाजिक–वैचारिक ऊर्जा प्राप्त हुई अपितु नेपाल में आंतकवादी कृत्यों का अन्तहीन दौर प्रारम्भ हुआ। इन आन्दोलनकारियों के निशाने पर मुख्यतः भारत ही था। प्रचण्ड–भट्टराई ने नेपाल सरकार के समक्ष निम्नांकित मॉगें रखी थीं–

1. भारत व नेपाल के मध्य हुई सन 1950 की 'शान्ति व मैत्री सन्धि' समाप्त कर दी जाय।
2. महाकाली व टनकपुर समझौते रद्द कर दिये जाँय।

3. नेपाल में भारतीय नम्बर प्लेट की सभी गाड़ियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।
4. गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द किये जाँय।
5. विदेशी सहायता से चल रहे एन0जी0ओ0 व आई0एन0जी0ओ0 तत्काल बन्द कर दिये जाँय।
6. राजा व उनके परिजनों को प्राप्त सभी अधिकार रद्द करते हुए सेना, पुलिस व प्रशासन को जनता के नियन्त्रण में लिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त माओवादियों द्वारा नेपाल से गरीबी व भ्रष्टाचार उन्मूलन, स्वास्थ व रोजगार सृजित करने, जातीय भेदभाव व असमानता समाप्त करने, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, प्रेस की स्वतन्त्रता, बौद्धिक स्वतन्त्रता, लड़कियों को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार देने तथा प्रजातान्त्रिक राज्य की स्थापना आदि बिन्दु सम्मिलित थे। विचारणीय है कि नेपाल में संचालित जन युद्ध जहाँ एक ओर राजशाही के उन्मूलन पर केन्द्रित था वहीं भारत का विरोध भी माओवादियों की कार्ययोजना के केन्द्रक में था। संवैधानिक परिवर्तन (Constitutional Transformation), आजीविका व आर्थिक उत्तरजीविता (Livelihood and Economic Survival) तथा नेपाल के राष्ट्रीय सम्मान (National Pride of Nepal) केन्द्रित माओवादी हिंसा से सम्बद्ध तत्वों ने गुरिल्ला युद्ध के वैचारिक आधार व युद्ध तकनीक का सहारा लेकर सम्पूर्ण नेपाल को अस्त–व्यस्त कर दिया। नेपाल के इस आन्दोलन से जहॉ एक भारत–नेपाल के तराई क्षेत्र के नागरिकों को व्यापक क्षति पहुंची वहीं भारत के माओवादी तत्वों ने इस आन्दोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु हर सम्भव सहायता प्रादन की। नेपाल के माओवादी तत्वों को चीन का समर्थन प्राप्त था क्योंकि उसकी आड़ में वह राजशाही समाप्त कर वहॉ ऐसी सरकार की स्थापना हेतु उत्सुक था जो उसकी विस्तारवादी नीतियों का हिमालयी क्षेत्र में हित–वर्धन कर सके। वास्तव में, चीन नेपाल रुपी 'बफर राज्य' पर आर्थिक–वैचारिक नियन्त्रण कर भारत–नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक अपनी पहुॅच को सुगम करना चाहता था जिससे भारत को सतत परेशान कर उसके विस्तृत हो रहे आर्थिक–सामरिक प्रभाव को शिथिल व न्यून किया जा सके। माओवादी क्रान्ति

के सफल होने से नेपाल अब एक प्रजातान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो अवश्य बन गया किन्तु उसकी चुनौतियॉ अभी समाप्त नहीं हुई हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के0पी0शर्मा ओली की चीन के प्रति प्रतिबद्धता एवं भारत का नैसर्गिक विरोध नेपाल की प्रगति पथ का ऐसा शूल है जो उसे आज भी पीड़ा दे रहा है। अपनी विनियोजन नीति (Policy of Engagement) के माध्यम से चीन शनैःशनैः नेपाल के सत्ता प्रतिष्ठान, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र पर नियन्त्रण हेतु गम्भीर रुप से प्रयत्नशील है तथा यदाकदा वह नेपाल व भारत के मध्य विवाद व तनाव को प्रोत्साहित करने का कोई भी अवसर गवाँ नहीं रहा है। विचारणीय है कि नेपाल की वर्तमान सरकार को अपने राष्ट्रीय हित, सम्प्रभुता व अखण्डता के मार्मिक पक्ष पर चिन्तन करते हुए ही विदेशनीति का निर्धारण व संचालन करना चाहिए। भारत का निरर्थक विरोध उसके लिये कदापि शुभ नहीं होगा। उसे 2015 की घटनाओं को (आर्थिक–प्रतिबन्ध) विस्मृत नहीं करना चाहिए।

मधेशी समस्या एवं भारत–नेपाल सम्बन्ध–

नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले मधेशी समूहों समूहों द्वारा सन् 2007 से किये जा रहे विरोध व हिसंक आन्दोलन से भारत–नेपाल के सद्भावनापूर्ण सम्बन्धों पर नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि नेपाल, पर्वतीय (The Himalayan Region), पहाड़ी (The Shivalik Range) एवं तराई अथवा मधेस (The Southern Plains) भू–क्षेत्रों मे विभक्त है तथा मधेसियों को मध्य–देश (Madhya-desh) का निवासी माना जाता है। नेपाल में यह भी मान्यता है कि मधेश समस्या मात्र भौगोलिक न होकर सांस्कृतिक कारणों से अत्यन्त मार्मिक पहलू है। तराई का मधेसी क्षेत्र लगभग बीस जिलों में विस्तृत है जिसकी सीमाएं प्रत्यक्षतः भारत से मिलती हैं। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह पुष्ट होता है कि घने जंगलों से आच्छादित इस क्षेत्र में मलेरिया की आंशका, जंगली जानवरों के आधिक्य एवं गर्म व आर्द्र जलवायु के कारण यह क्षेत्र लोगों के निवास हेतु अनुपयुक्त था। यद्यपि मधेस क्षेत्र में मूलतः नेपाल की थारु जनजातियाँ ही निवास करती थीं किन्तु 16 वीं व 17 वीं शताब्दी में भारत पर हुए मुगल आक्रमण के फलस्वरुप राजस्थान से थारुओं के पलायन

से नेपाल का यह क्षेत्र शनैःशनैः आबादी हेतु उपयुक्त होता गया। तराई के इस क्षेत्र में मुख्यतः निम्नांकित तीन प्रकार की मधेसी जनसंख्या निवास करती हैं–

1. जन जातिया (Tharus)
2. पहाड़ी मधेसी (Pahadi Madhesis)- ये लोग सन 1960 व 1970 के दशक में पहाड़ी क्षेत्रों से आकर यहा बस गये।
3. भारतीय मधेसी (Indian Madhes)- ये लोग सन 1950 के दशक में पूर्वी बिहार व उत्तर प्रदेश से आकर बसे।

भारतीय मूल के मधेसियों के भारत से प्रगाढ़ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नृजातीय रिश्ते हैं तथा एक अध्ययन के अनुसार मधेसियों की आबादी तराई क्षेत्र में लगभग 57 प्रतिशत है जो नेपाल की सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 31. 70 प्रतिशत है। मधेसी समूह के अन्तर्गत सम्मिलित जातियों व नृ–जातीय समूहों का विवरण निम्नवत है–

Sr. No.	**Recognised Terai Caste/ Enthnic Group**	**Total**	**Terai**
1	Tharu	1533879	21.13
2	Muslim	971056	13.38
3	Yadav	895423	12.33
4	Teli	304536	4.19
5	Chamar/Harijan/Ram	269661	3.71
6	Koiri	251274	3.46
7	Kurmi	212842	2.93
8	Dhanuk	188150	2.59
9	Musahar	172434	2.37
10	Dusadh/Paswan/Pasi	158526	2.18
11	Sonkar	145088	1.99
12	Kewat	136953	1.88
13	Brahman	134496	1.85

14	Bania	126971	1.74
15	Mallah	115986	1.60
16	Kalwar	115606	1.59
17	Hajam/Thakur	98169	1.35
18	Kanu	95826	1.32
19	Rajbansi	89846	1.24
20	Sudi	82637	1.14
21	Lohar	76512	1.05
22	Tatma	74972	1.03
23	Katma	73413	1.01
24	Dhobi	66873	0.92
25	Nuniya	54413	0.74
26	Kumhar	53229	0.73
27	Danuwar	50583	0.69
28	Haluwai	48454	0.66
29	Rajput	46071	0.63
30	Kayasth	45975	0.63
31	Badhae	43971	0.60
32	Marwadi	42698	0.58
33	Santhal/Sattar	41764	0.57
34	Jhangar/Dhagar	35839	0.49
35	Bantar	35434	0.48
36	Barae	34531	0.47
37	Kahar	31318	0.43
38	Gangai	24738	0.34
39	Lodha	24263	0.33
40	Rajbhr	19537	0.26
41	Dhimal	18720	0.25
42	Bing/Binda	17729	0.24

43	Bhediyar/Gaderi	17522	0.24
44	Nurang	13215	0.18
45	Tajpuriya	12296	0.16
46	Chidimar	11390	0.15
47	Mali	9860	0.13
48	Bengali	8931	0.12
49	Dom	8761	0.12
50	Kamar	3763	0.05
51	Meche	3621	0.04
52	Halkhor	3054	0.04
53	Kisan	2876	0.03
54	Koche	1429	0.02
55	Dhunia	1231	0.02
56	Jain	1015	0.01
57	Munda	660	0.00
58	Kuswadia/Patharkata	552	0.00

नेपाल के पूर्वी, मध्य व पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय मधेसी भाषाई आधार पर मैथिली, भोजपुरी व अवधी में विभक्त हैं तथा मैथिली नेपाल की द्वितीय भाषा (11 प्रतिशत) है जबकि भोजपुरी बोलने वाले 8 प्रतिशत एवं अवधी भाषा 4 प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है। मधेसियों की धारणा है कि नेपाल की सरकार विविध भाषाई, जन्म व भू–स्वामित्व प्रमाण पत्रों के अभाव के कारण उन्हें नेपाल की नागरिकता से वंचित करने के षड़यन्त्र में संलिप्त है। नेपाल के सन 1964 के नागरिकता कानून व 1990 के संविधान में निहित प्रावधानों के कारण मूल अधिकारों का लाभ भी मधेसियों को नहीं मिल पा रहा है। भाषा व सांस्कृतिक दृष्टि से उनकी भारतीय सन्निकटता के कारण वे शोषण, दमन व पक्षपात के शिकार हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल की सम्पूर्ण आबादी के एक तिहाई भाग होने के बावजूद जहाँ एक ओर मधेसियों को मात्र 9.9 प्रतिशत ही सरकारी सेवाओं में स्थान मिल रहा है वहीं ब्राह्मण व क्षत्रियों को 71.6 प्रतिशत,

नेवार को 14.2 प्रतिशत, जन जातियों को 3.3 प्रतिशत व दलित को 0.9 प्रतिशत लोगों को उक्त लाभ मिल रहा है। निम्नांकित तालिका से इसकी पुष्टि होती है–

Caste/Ethenic Group	**Special Class**	**First Class**	**Second Class**	**Third Class**	**Total Number**	**%**
Brahman	24	230	1161	3306	4721	58.3
Chhetri	6	63	283	728	1080	13.3
Dalit	0	3	11	60	74	0.9
Newar	7	68	374	703	1152	14.2
Janajati (Excluding Newar)	1	3	70	190	264	3.3
Mashesi, Muslim and Marwari	0	30	237	538	805	9.9
Total	38	397	2136	5525	8096	100
Percentage	0.5	4.9	26.4	68.2	100.00	-

नेपाल का तराई क्षेत्र खनिज संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता एवं उपजाऊ होने के कारण अत्यन्त समृद्ध है किन्तु यहाँ के निवासी आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त हैं। यद्यपि नेपाल के सम्पूर्ण कृषि उत्पादन का 70 प्रतिशत, जी0डी0पी0 का 65 प्रतिशत एवं राष्ट्र के सम्पूर्ण राजस्व का 65 प्रतिशत अंश तराई क्षेत्र से ही प्राप्त होता है तथापि अच्छे स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालयों, स्वास्थ सेवाओं के अभाव तथा विकास सम्बन्धी निम्नस्तरीय ढाँचे के कारण यहाँ पर्याप्त विकास का अवसर अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। उक्त संदर्भ में सुखदेव प्रसाद का अभिमत है कि –

"Peoples from Tarai are a conquered people ..... Conquered people have got no right because they are as second-class citizens or non-citizens for that matter."

मधेसी आन्दोलन–

आर्थिक–विपन्नता, सामाजिक भेदभाव व सरकारी उपेक्षा से संत्रस्त मधेसियों ने अपने अधिकारों व हित संवर्धन के उद्देश्य से सन 1950 व 1960 के दशक में प्रजातान्त्रिक मूल्यों पर आधारित आन्दोलन तो अवश्य प्रारम्भ किया किन्तु नेपाली शासकों ने उन्हें भारतीय एजेण्ट मानने के साथ–साथ प्रजातान्त्रिक–आस्था से उनकी संलग्नता से भयाक्रान्त होकर दमन–चक्र प्रारम्भ कर दिया। सन 1951 में वन्दना झा एवं 1956 में रघुनाथ झा के नेतृत्व में क्रमशः 'नेपाल तराई कांग्रेस' व 'मधेसी मुक्ति–आन्दोलन' द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने हेतु मधेसियों ने आन्दोलन प्रारम्भ किया। नेपाल में तराई क्षेत्र की स्वायत्ता एवं राज्य की एजेन्सियों में समान प्रतिनिधित्व हेतु चलाया जा गया यह आन्दोलन मूलतः यू0एन0 चार्टर की धारा 73 के सिद्धान्तों पर केन्द्रित था। आन्दोलनकारियों की भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गॉधी से हुई भेंट के कारण जहाँ एक ओर नेपाल सरकार ने इसे भारत–प्रेरित आन्दोलन की संज्ञा दी वहीं 29 जून 1971 को भारतीय संसद ने मधेसी आन्दोलन को नेपाल का आन्तरिक मामला कहकर इसके न्यायिक समाधान की अपील की। मेधशी आन्दोलन के प्रथम चरण की असफलता के पश्चात सन 1983 में गजेन्द्र नारायण शाह ने 'नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस' (NNC) से त्यागपत्र देकर नेपाल 'सद्भावना परिषद' (NSP) नामक 'सांस्कृतिक फोरम' की स्थापना करके मधेसियों के हितों के रक्षार्थ आन्दोलन प्रारम्भ तो अवश्य किया किन्तु विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ मधेसियों की संलग्नता के फलस्वरुप यह आन्दोलन निष्प्रभावी ही रहा। नेपाल में प्रारम्भ 'जन युद्ध' काल में सी0पी0एन0 माओवादी ने सन 2000 में जय कृष्ण गोइल के नेतृत्व में 'मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा' (MRMM) का गठन करके तराई क्षेत्र में अपना विस्तार करते हुए मधेसियों की स्वायत्तता हेतु व्यापक संघर्ष प्रारम्भ किया। यद्यपि राजशाही के विरुद्ध प्रारम्भ संघर्ष की पृष्ठभूमि में माओवादियों ने 'मधेस फेडरल राज्य' की स्थापना एवं आत्मनिर्णय के अधिकार का वादा करते हुए मधेसी आन्दोलन में आशा की किरण का त्वरित संचार तो अवश्य किया किन्तु जन आन्दोलन के द्वितीय चरण में 2007 में अस्तित्व में आये 'अन्तरिम

संविधान' में मधेसियों की माँगों को स्थान न मिलने के कारण उनके हितों को गहरा आघात पहुँचा।

तदनन्तर, अपने को ठगा महसूस करते हुए मधेसियों ने 'सशस्त्र–संघर्ष' प्रारम्भ कर दिया जिससे सन 2008 के चुनाव के बाद मधेसियों व माओवादियों के मध्य मतभेद गहरे होते गये। उल्लेखनीय है कि अपने चुनाव घोषणा–पत्र में माओवादियों ने वादा किया था कि यदि उन्हें सफलता मिली तो वे भाषा, सांस्कृतिक व नृजातीयता के आधार पर मधेस क्षेत्र को पाँच स्वाशासित क्षेत्रों (थारुवन, अवध, भोजपुरा, मिथिला व कोचिला) की स्थापना करेंगे जबकि मधेसी मूल के लोग अपने लिए मात्र एक ही 'स्वशासित–क्षेत्र' की मॉग पर संकल्पबद्ध थे। यद्यपि सन 2009 में माओवादियों ने थारुवन व मधेस क्षेत्र की स्थापना की इच्छा तो अवश्य प्रकट की किन्तु मधेसी इससे सन्तुष्ट नहीं हुए। सन 2008 में नेपाल में हुए चुनाव में विभिन्न मधेसी दलों के मध्य एकता व वैचारिक साम्यता के अभाव में उन्हें अपेक्षित सफलता तो नहीं मिली तथापि इस चुनाव में उनकी स्थिति निम्नांकित रही–

Sl.No.	**Madhesi Political Parties**	**Seats**
1	MJF- Nepal (Upendra Yadav)	12
2	MJF- Ganatantrik	13
3	MJF- Loktantrik (Gachhadar)	28
4	Terai Madhes Democratic Party (Thakur)	11
5	Terai Madhes Democratic Party-Nepal (Raya Yadav)	09
6	MJF- Madhesh (Bhagyanath)	00
7	Nepal Sadhvawana Party (Mahto)	09
8	Nepal Sadhvawana Party-A (Sarita Giri)	02
Total		84

मधेसी आन्दोलन का सर्वाधिक सफल व सशक्त समूह 'मधेसी जनाधिकार फोरम' (MJF) था किन्तु नेतृत्व के टकराव के फलस्वरुप यह भी

कई खण्डों में विभक्त हो गया। उक्त राजनैतिक दलों के अतिरिक्त तराई क्षेत्र में लगभग 58 'सशस्त्र–समूह' सक्रिय हैं जिनमें 'जनतान्त्रिक तराई मुक्ति–मोर्चा' (JTMM) व तराई कोबरा (Tarai Cobra) सर्वाधिक चर्चित हैं।

मधेसी आन्दोलन के राजनैतिक व सामाजिक आयामों से यह प्रकट होता है कि तराई के निवासियों के साथ भारत के 'रोटी–बेटी' सम्बन्धों के बावजूद भारत ने इसे नेपाल का आन्तरिक मामला मानते हुए किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से स्वयं को पृथक ही रखा हैं। यद्यपि भारत का यह प्रबल तर्क है कि नेपाल की नई सरकार संविधान के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समायोजन कर इसका हल कर सकती है। उधर नेपाल के पूर्व प्रधानमन्त्री जी0पी0 कोइराला का अभिमत रहा है कि भारत के सक्रिय सहयोग के बिना मधेसी समस्या का समाधान मुश्किल है। उन्हीं के शब्दों में–

"The ongoing Madhesh crisis can be solved within a minute if Nepal and India jointly work together for it."

दूसरी ओर माओवादी नेता प्रचण्ड का मत है कि ''यदि मधेसी समस्या का राजनैतिक हल नहीं हो पाता है तो नेपाल में भारत–विरोधी प्रवृत्ति को नया आयाम मिलेगा जिसके राजनैतिक लाभ उठाने हेतु चीन व पाकिस्तान को सुअवसर मिलेगा यह स्थिति प्रजातान्त्रिक व धर्मनिरपेक्ष नेपाल की स्थिरता, सुरक्षा व विकास हेतु शुभ नहीं होगी। नेपाल में नेपाल व पहाड़ियों के मध्य व्याप्त संघर्ष–भावना तथा पहाड़ियों द्वारा मधेसियों को भारत का एजेन्ट मानने की प्रवृत्ति से स्थिति निरन्तर जटिल व अस्थिर होती जायेगी। इसलिए नये संविधान की परिधि में वार्ता व विचार–विमर्श द्वारा इस समस्या का समाधान निकालने हेतु सभी पक्षों को प्रयत्नशील होना चाहिए।'' मधेशी क्षेत्र में बसे अथवा बसाये गये पहाड़ियों में व्याप्त असुरक्षा व मधेसियों द्वारा की जा रही हिंसा से यह सम्पूर्ण क्षेत्र अस्थिर व अशान्त है। दूसरी ओर भारत से वॉछित सहयोग व समर्थन न मिलने के कारण मधेसी भी भारत के प्रति उग्र भावना से ग्रसित होते जा रहे हैं जो अन्ततः नेपाल की स्थिरता हेतु शुभ नहीं है। मधेसी नेता उपेन्द्र यादव का मत है कि,

" We are people of Indian origin but remember we are Madhesis and Nepalis. This is our struggle. India can give us support, which is not forthcoming at the moment. The people of Bihar and UP are with us, but the government of India is not taking any notice. If the situation in Madhesh worsens, India will be badly affected. The implication could be terrible."

स्पष्ट है कि यू0सी0पी0एन–माओवादी के नेताओ एवं नेपाल के सामान्य नागरिकों द्वारा भारत पर लगाये जा रहे नेपाल–विरोधी आरोप यद्यपि निराधार प्रतीत होते हैं तथापि नेपाल में भारत के ऊर्जा हित व पंचेश्वर जलविद्युत परियोजना से सम्बन्धित बाँध के निर्माण में हो रहे विलम्ब से संकट गहरा होता जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री के0पी0शर्मा ओली के नेतृत्व में यद्यपि नेपाल भारत के साथ सम्बन्धों को मधुर बनाने हेतु प्रयत्नशील है तथापि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 'जयमधेस' भावना की सक्रियता व बढ़ रही हिंसात्मक प्रवृत्ति से दोनों देशों के सम्बन्धों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारत, चीन व नेपाल के त्रिपक्षीय सम्बन्धों की प्रवृत्ति एवं चीन के प्रति नेपाल की बढ़ रही सदाशयता ऐसा कारक है जिसमें नेपाल पाकिस्तान की भॉति निरन्तर चीनी–संजाल में उलझता जा रहा है। यह स्थिति नेपाल के विकास व स्थिरता हेतु कदापि शुभ नहीं है।

भारत–नेपाल के मध्य भू–क्षेत्र विवाद–

4 मार्च, 1816 को ब्रिटिश भारत व नेपाल के मध्य सम्पन्न सुगौली सन्धि, द्वारा काली नदी को भारत–नेपाल की सीमा रेखा के रुप में स्वीकार किया गया था किन्तु कालापानी क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य आज भी भू–क्षेत्र सम्बन्धी विवाद चल रहा है। जहाँ एक ओर भारत का मत है कि कालापानी के पूर्व बहने वाली ही मुख्य काली नदी है जो नेपाल के पश्चिमी भू–क्षेत्र एवं भारत के उत्तराखण्ड राज्य को स्पर्श करती है तथा यही विभाजक नदी है किन्तु नेपाल को यह मान्य नहीं है। इस क्षेत्र में लगभग 400 वर्ग किमी0 विवादास्पद क्षेत्र है जहॉ से कालीनदी प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र पर सन 1962 के भारत–चीन युद्ध के समय से ही भारत का नियन्त्रण है जिसकी सुरक्षा हेतु 'भारत–तिब्बत

सीमा सुरक्षा बल' तैनात है। नेपाल में माओवाद के उदय, प्रसार तथा निरन्तर बढ़ रहे उसके वर्चस्व के फलस्वरुप यह विवाद यदाकदा गम्भीर रुप लेता रहता है। वास्तव में, कालापानी क्षेत्र में लगभग 37000 हेक्टेयर भू–क्षेत्र एवं सुस्ता क्षेत्र में 14500 हेक्टेयर नेपाली भू–क्षेत्र पर सन 1962 से ही भारत द्वारा भूमि हड़पने जैसे नेपाली आरोपों के कारण सीमाओं पर तनाव के लक्षण व्याप्त रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त मेची, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर व हील थोरी क्षेत्र में भी दोनों देशों के मध्य भू–क्षेत्र विवाद है।[26] जबकि 18 फरवरी, 2009 को भारत के तत्कालीन विदेश सचिव के कहा था कि भारत व नेपाल के मध्य भू–क्षेत्र व सीमा सम्बन्धी विवादों का 98 प्रतिशत तक समाधान निकाल लिया गया है।[27] 1974 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाने के बाद नेपाल की चिन्ताएं अभी यथावत बनी हुई है क्योंकि इससे भूटान के साथ अब नेपाल का सीमा सम्पर्क समाप्त हो गया है। उधर 5 अक्टूबर, 1961 को नेपाल व चीन के मध्य सम्पन्न सीमा समझौते से दोनों के मध्य 35 स्थलों पर व्याप्त सीमा विवाद का हल द्विपक्षीय वार्ताओं एवं समानता व पंचशील सिद्धान्तों के आधार पर ढूढ़ लिया गया। यद्यपि 15 नवम्बर, 1981 को गठित भारत–नेपाल 'संयुक्त तकनीकी स्तरीय सीमा कमेटी' भारत व नेपाल के मध्य व्याप्त सीमा विवादों के समाधान हेतु तत्पर व प्रयत्नशील है तथापि अभी तक इसके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सके हैं। हॉ, इतना अवश्य हुआ कि मेंची नदी (Mechi River), डुण्डुआरोन्ज विवाद, रामनगर जमींदारी क्षेत्र सम्बन्धी विवाद एवं शारदा बॉध सम्बन्धी भू–विवादों का हल तो निकाल लिया गया है किन्तु मूल रुप से नेपाल के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र के स्थलीय भू–भागों में सीमा–विवाद यथावत बना हुआ है। इस सीमा पर 54 ऐसे स्थल हैं जहॉ अतिक्रमण आदि के फलस्वरुप सीमा–स्तम्भों के निर्धारण का मामला विवादास्पद है। इस पूरी सीमा रेखा पर दोनों देशों की जनता का दबाव, नो मैन्स लैण्ड पर अतिक्रमण एवं घने जंगलों के कारण समस्या का हल दोनों देशों के लिए गम्भीर चुनौती है। ये क्षेत्र निम्नांकित है–

कालापानी– लिम्पियाधुरा

सुस्ता क्षेत्र

मेंची नदी क्षेत्र

वाल्मीकि नगर

थोरी

सन्दकपुर

मेनीभंजयांग

चिवाभंजयांग

भण्टावारी

जोगवनी

सखदा–लालपत्ती

कुनौली

सोनौली–बेल्ही

कृष्णानगर

सन्तालिया

भदनाला

बीरानाला

लुना नदी क्षेत्र

लक्ष्मणपुर बॉध क्षेत्र

रसियावल खुर्दालोटन

उक्त सभी क्षेत्र भारतीय सीमा पर स्थित नेपाल के लगभग 21 जिलों से संलग्न हैं जिनके समाधान हेतु दोनों देशों की 'संयुक्त सीमा कमेटी' एवं उच्चस्तरीय कूटनीतिक व राजनैतिक प्रतिनिधि निरन्तर प्रयत्नशील तो अवश्य हैं किन्तु अभी तक इनका सम्यक समाधान नहीं हो सका है। भारत–नेपाल सीमाओं से सम्बद्ध भू–क्षेत्रों में नदियों का भीषण कटाव, बॉध निर्माण एवं स्थानीय कृषकों द्वारा खेती हेतु किये जाने वाले अतिक्रमण आदि के फलस्वरुप क्षेत्रीय भूमि अतिक्रमण सम्बन्धी चुनौतियॉ यदाकदा गम्भीर रुप भी ले लेती हैं।

लिपुलेख–कालापानी विवाद

समुद्र तल से लगभग 5200 मीटर ऊँचाई पर भारत के उत्तराखण्ड राज्य, चीन के तिब्बत क्षेत्र व नेपाल की सीमा के त्रिमुहाने पर स्थित लिपुलेख

Rakshastal
Mansarovar
CHINA
10 km
China
India
Limpiyadhura
Kuti
Nabi
Kalapani
Lipulekh Pass
Gunji
China
Nepal
INDIA
India
Nepal
NEPAL
N

एक हिमालयी दर्रा है जो कालापानी क्षेत्र में स्थित है। यह दर्रा तिब्बत के व्यापारिक शहर टकलाकोट के पास में है जिसका प्रयोग भारत व तिब्बत के मध्य व्यापार हेतु प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। लिपुलेख क्षेत्र चीन के चांग लोबोचेला शहर से जुड़ा हुआ है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह दर्रा 1992 में चीन के साथ होने वाले व्यापार हेतु खोला गया था, बाद में 1994 में शिपकी ला दर्रा (हिमाचल प्रदेश) एवं नाथू ला (सिक्किम) 2006 में व्यापार हेतु खोले गये। लिपुलेख दर्रा भूटिया लोगों द्वारा व्यापार और तीर्थयात्रा के उद्देश्य से बनाया गया एक प्राचीन मार्ग है जिस पर नेपाल ने उस समय भी आपत्ति की थी जब चीन व भारत ने मानसरोवर की यात्रा हेतु इसे खोला था। ध्यातव्य है कि लिपुलेख दर्रा गुँजी गॉव से खुलता है जिसे नेपाल अपना भू–भाग बता रहा है जबकि भारत व चीन ने सन 1954 में ही लिपुलेख दर्रे को भारतीय प्रवेश द्वार घोषित करते हुए एक 'व्यापार–सन्धि' सम्पन्न की थी। पुनः 2015 में इस दर्रे के माध्यम से व्यापार हेतु भारत व चीन ने एक और सन्धि पर हस्ताक्षर किया किन्तु तभी से नेपाल कालापानी क्षेत्र पर भारतीय गतिविधियों पर आपत्ति प्रकट करता रहा है।

भारत के रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह द्वारा 8 मई, 2020 को कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुगमता हेतु धारचुला से लिपुलेख तक 80 किमी0 लम्बी सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल सरकार ने गहरी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा है कि कालापानी, लिंपियाधुरा व लिपुलेख का क्षेत्र विवादित है जिसपर भारत अपना नियन्त्रण बता रहा है। उल्लेखनीय है कि इस संघर्ष की उत्पत्ति के परिपेक्ष्य में ब्रिटिश भारत व नेपाल के मध्य सम्पन्न सुगौली सन्धि का उद्धरण महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया था कि काली नदी के पश्चिम का इलाका भारत का है तथा पूर्वी क्षेत्र नेपाल का। कालीनदी ही भारत व नेपाल के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। नेपाली विशेषज्ञों की मान्यता है कि 1827 व 1856 में ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा कालापानी क्षेत्र को नेपाली क्षेत्र के रुप में दर्शाया गया है। नेपाल का दावा है कि कालीनदी का स्रोत लिम्पियाधुरा में है इसलिए कालीनदी के पूर्व स्थित कालापानी व लिपुलेख नेपाल के अन्तर्गत आते हैं। दूसरी ओर भारत का मत है कि कालापानी के

Limpiyadhura
लिम्पियाधुरा
CHINA
हरे रंग वाला क्षेत्र (लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा) जिस पर नेपाल दावा करता है
कालापानी
Kalapani
लिपुलेख
कालापानी
वैली
लिपुलेख
Lipulekh
INDIA
NEPAL
Kalapani, Lipulekh
Kuti
CHINA
Gunji
INDIA
NEPAL

दक्षिण में पंखगढ़ नामक छोटी नदी और कालापानी क्षेत्र के पूर्व की ओर की सीमा ही असली सीमा है तथा कालापानी का क्षेत्र भारत का है। उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले के प्रशासनिक व कर सम्बन्धी रिकार्डों के अनुसार कालापानी पर भारत के ही दावों की पुष्टि होती है। वास्तव में, यह विवाद नया नहीं है। सन 1962 के युद्ध के बाद से ही इस क्षेत्र में न केवल भारत तिब्बत सीमा पुलिस तैनात है अपितु सन 2000 व 2002 में भारत व नेपाल ने सीमा विवाद हल करने पर सहमति व्यक्त की थी। नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला व भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य नई दिल्ली में 2002 में हुई वार्ताओं में दोनों देश विवाद के समाधान हेतु 'द्विपक्षीय संयुक्त सीमा समिति' के गठन हेतु सहमत हुए थे। सन 2014 में भी दोनों देशों ने विदेश सचिव स्तर की वार्ताओं द्वारा कालापानी व सुस्ता–विवाद के हल का प्रयास भी किया किन्तु यह वार्ता निष्फल रही। सन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार हेतु दोनों देशों द्वारा लिपुलेख दर्रा, शिपकीला व नाथू–ला दर्रे के उपयोग पर हुई सहमति पर भी नेपाल ने गहरी आपत्ति करते हुए, इसे अपनी सम्प्रभुता पर आक्रमण कहकर प्रचारित किया था। भारत–नेपाल–चीन त्रिमुहाने पर स्थित लिपुलेख–कालापानी क्षेत्र भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा इस क्षेत्र में किये जाने वाले आक्रमण व अतिक्रमण की स्थिति में भारत चीन पर रणनीतिक दबाव बनाने हेतु लाभदायक स्थिति में है। सन 2015 में काठमाण्डू की 'आर्थिक नाकेबन्दी' के उपरान्त भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की 'पड़ोसी–प्रथम' की विदेशनीति के अन्तर्गत यद्यपि भारत–नेपाल सम्बन्धों में मैत्री–भावना के सुदृढ़ होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे किन्तु इस नये विवाद ने पुनः दोनों को कूटनीतिक रुप से आमने–सामने खड़ा कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री के0पी0शर्मा ओली द्वारा नेपाली संसद में इस प्रश्न को उठाने व इस क्षेत्र से सम्बन्धित नया मानचित्र प्रकाशित करने (Map Diplomacy) से स्थिति तनावपूर्ण हो गयी है। कोविड–19 के सन्दर्भ में चीन की वैश्विक शक्ति–राजनीति के विविध पक्षों पर दृष्टिपात से ऐसा लगता है कि नेपाल का भारत–विरोधी यह कृत्य चीन द्वारा उत्प्रेरित लगता है। भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने भी आशंका प्रकट की है कि

लिपुलेख–धारचूला मार्ग पर नेपाल की प्रतिक्रिया चीन से प्रेरित लगती है। नरवाणे ने 15 मई, 2020 को 'मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फार डिफेंस स्टडीज एण्ड एलालिसिस' (IDSA) के एक वेबीनार में कहा कि ''लिपुलेख–धारचूला मार्ग पर पड़ोसी की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली हैं काली नदी के पूरब की तरफ नेपाल का हिस्सा है। हमने जो सड़क बनाई वह नदी के पश्चिम में है। इसमें कोई विवाद नहीं है।''[28]

लिपुलेख–कालापानी विवाद के सन्दर्भ में यह सर्वदा उल्लेखनीय है कि भारत व नेपाल दोनों ही राष्ट्रों के हित–वर्धन हेतु यह सर्वथा आवश्यक है कि वे एक महत्वपूर्ण पड़ोसी व सहयोगी के रुप सभी द्विपक्षीय विवादों के समाधान में कूटनीतिक उपायों को ही माध्यम बनायें। अपनी भू–राजनैतिक व सामरिक–आर्थिक अवस्थिति के कारण नेपाल की आर्थिक समृद्धि, शान्ति व स्थिरता भारत से मैत्री–भाव सुदृढ़ करने में ही निहित है। दोनों ही पड़ोसी देशों को चीन से सावधान व सतर्क रहकर पारस्परिक विवादों के समाधान हेतु सहयोग व सार्थक सम्वाद का परिचय देना चाहिए।

References:

1. J.Bandyopadhyaya, The Making of India's foreign Policy; Allied Publishers Ltd. Bombay, 1970, P-5.
2. Shusheel Raj Pandey and Pushpa Adhikarki (ed.), Nepalese Foreign Policy at the Crossroads, Sangam Institute, Kathmandu 2009, P-15.
3. Monika Mandal; India-Nepal Relations, KW Publishers Pvt. Ltd. New Delhi, 2014, P-3.
4. Ibid P-8
5. M. D. Dharamdasani, "Common Heritage and Cultural Ties. "India and Nepal: A Publication of the Embassy of India, 2002.
6. S.D.Muni, India and Nepal : A Changing Relationship, Konark Publishes Pvt. Ltd. 1996.
7. V.P.Dutt, India;s Foreign Policy, Vikas Publishing House, New Delhi, P-252.
8. Ramashankar Tripathi, History of Ancient India, P-92
9. Ramakant; Indo-Nepalese Relations,1616-1877,p.1
10. Lt. Col. E. Vansittart, Gurkhas, Calcutta, 1906, P-67.
11. Col. W, Kirkpatrick, An Account of Kingdom of Nepal, London, 1811, P- 184.
12. Pushpesh Pant, 'Bharart Ki Videsh Neeti,Tata Megraw Hill Education Pvt. Ltd. New Delhi, 2010, P-2.3. see Appendex-I
13. "---------much as we appreciate the independence of Nepal, we cannot risk our own security by anything going wrong in Nepal which either that barrier to be crossed or otherwise weakens our frontier."

    -A.S. Bhasin, Documents on Nepal's Relations with India and China,Academics Book (1970) Bombay, P-5

14. T.R.Ghoble, China-Nepal Relations and India, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1991, P-121.
15. Op. Cit, No.13, P-32.
16. "_______'The issue of the 1950 treatly is being raised time and again, please speak frankly what you want, but refrain from politicizing it." Strategic Analysis, July-August 2015 p.402-03
17. John whelpton, A History of Nepal, Combridge university Press, Cambridge, 2005, P-46.
18. J. L. Nehru, India's Foreign Policy : Selected speeches (Sept.-1946-April 1961), Government of India, Publication Division, New Delhi, 1971, p.436
19. R.K.Jha, The Himanlyan Kingdom in Indian Foreign Policy, Maitryee Publication,s Ranchi, 1986, P-346.
20. Strategic Analysis Vol. 39 No-2, March-April 2015, P-197.
21. The actual length of the Nepal-India border is yet to be determined because the demarcation is not yet complete- Strategic Analysis, July-August, 2015. p.415
22. Dwarika N. Dhungel and Santa B.Pun (eds.), The Nepal-India water Relationship : Challenges, Springer, 2009, P-11.
23. Hari Bansh Jha, The Economy of Terai Region in Nepal : Prospects for its Sustainable Development, Centre for Economic and Technical Studies, Kathmandu, 2010, P-50.
24. Dwarika Nath Dhungel, No.22, P-14
25. Strategic Analysis, Vol.37, N0.2, March-April. 2013, P-226.
26. K. N. Sanwal, Resetling Indo-Nepal ties and China, Sumit Enterprises, New Delhi, 2016, P-75.
27. Ibid, P-76.
28. Dainik Jagran, Lucknow, 20 May, 2020.

अध्याय–3

चीन–नेपाल सम्बन्धः ऐतिहासिक व राजनैतिक पक्ष

एशिया के दो शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य 'नन्हा राष्ट्र' (Tiny Nation) नेपाल अपनी भू–राजनीतिक व भू–सामरिक अवस्थिति के फलस्वरुप दोनों ही पड़ोसियों के साथ संतुलित सम्बन्धों का संचालन करते हुए निरन्तर अपने हितों के रक्षार्थ प्रयत्नशील अवश्य रहा है तथापि भारत पर उसकी निर्भरता चीन से सर्वथा महत्वपूर्ण व अनिवार्य पक्ष है। जहॉ तक चीन व नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्धों का सन्दर्भ है, नेपाल के उत्तर स्थित तिब्बत के साथ व्यापारिक, राजनैतिक व नृजातीय समानता के फलस्वरुप चीन के प्रति उसके सम्बन्धों का इतिहास अत्यन्त पुरातन रहा है।[1] 18वीं, 19वीं व 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरणों में जहॉ एक ओर नेपाल व भारत के मध्य विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक अनेकता एवं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण सम्बन्धों का कोई विशेष महत्वपूर्ण आधार नहीं रहा वहीं तिब्बत के साथ उस समय भी नेपाल के सम्बन्ध अच्छे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल व थाईलैण्ड ऐसे दो एशियाई देश हैं जो यूरोपीय उपनिवेशवाद से सदैव मुक्त रहे हैं।[2] ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह पुष्ट होता है कि भौगोलिक व नृजातीय सन्निकटता के फलस्वरुप नेपाल व चीन (तिब्बत) के सम्बन्धों का आधार न केवल पुरातन अपितु प्रगाढ़ रहे है। उक्त तथ्यों के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं कि पॉचवी शताब्दी में (406 ई0) चीन के प्रमुख बौद्ध अध्येता फाह्यान ने नेपाल स्थित गौतम बुद्ध की जन्मस्थली व उनके निर्वाण स्थल की यात्रा सम्पन्न की थी तथा 406 ई0 में ही कपिलवस्तु निवासी बुद्धभद्र ने तत्कालीन चीन की राजधानी झैगंन (Zhangan) की यात्रा की। तांग राजवंश (618–907 ई0) की शासनावधि के अर्न्तगत चीन के बौद्ध शिक्षक युयान झुयांग (Yuan Zhuang)[3] की कश्मीर व तुर्किस्तान मार्ग सें सम्पन्न नेपाल यात्रा से यह पुष्ट होता है कि नेपाल व चीन के मध्य पूर्व में भी व्यापारिक आदान–प्रदान रहा है।[4]

इतना ही नहीं, Li-I-biao के नेतृत्व में Turfani- Nepal मार्ग से चीन के प्रथम औपचारिक व शासकीय प्रतिनिधिमण्डल की नेपाल यात्रा के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं।[5] इस प्रतिनिधिमण्डल का नेपाल के तत्कालीन महाराजा नरेन्द्रदेव ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। कालान्तर में लगभग दो दशकों तक नेपाल व चीन के कई यात्रियों द्वारा उक्त मार्ग से ही भारत व चीन की यात्राओं का उल्लेख भी ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। सन् 647 ई0 में, चीन के दस्तावेजों में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह पुष्ट होता है कि चीनी यात्रा पर गये विभिन्न नेपाली दलों का चीन में भव्य स्वागत किया गया। इन यात्राओं के दौरान नेपाल की परम्पराओं, रीति–रिवाजों, धर्म, संसाधनों व विभिन्न पुरातात्विक कलाओं से प्रभावित होकर चीनी व नेपाली तीर्थ यात्रियों के पारस्परिक आवागमन में निरन्तरता बनी रही।[6] वास्तविकता तो यह है कि चीन व नेपाल के पारस्परिक सम्बन्धों का सूत्रधार तिब्बत ही था जहॉ सातवीं शताब्दी में एक अत्यन्त प्रभावशाली शासन का अभ्युदय हो चुका था जिसकी राजधानी ल्हासा (Lhasa) थी तथा इस प्रभावशाली परिवर्तन अथवा शक्ति–अभ्युदय ने काठमाण्डू को भारत व केन्द्रीय एशिया के मध्य एक प्रमुख व्यावसायिक व चिन्तन–प्रधान गतिविधियों के केन्द्रक के रुप में स्थापित होने का गौरव व सुअवसर प्राप्त हुआ। तांग (Tang) शासनकाल में तिब्बत–नेपाल मार्ग से सम्पन्न Yuan Zhuang की भारत यात्रा के दौरान काठमाण्डू घाटी की समृद्धि व वाणिज्यिक महत्ता से प्रभावित होकर उन्होंने नेपाल के साथ पारस्परिक सम्बन्धों को मधुर बनाने की इच्छा तो अवश्य प्रकट की किन्तु सातवीं शताब्दी तक कतिपय राजनैतिक उथल–पुथल के फलस्वरुप ऐसा सम्भव न हो सका।[7] तिब्बती दस्तावेजों से पुष्ट होता है कि वहॉ के शासक Srongtsan Gambo ने दो दशक पूर्व नेपाल के एक प्रभावशाली मन्त्री अंशु वर्मा (Amshu Verma) द्वारा सत्ताच्युत शासक राजा नरेन्द्रदेव व उनके परिवार की सहायता करके उन्हें पुनः शासनारुढ़ होने में पर्याप्त सहायता की।[8] नेपाल की वंशावली के अभिलेखों से यह पता चलता है कि कालान्तर में (640 ई0) तिब्बत के शासक (Srongtsan Gambo) ने

नेपाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया तथा बाद में इन सम्बन्धों से तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रविस्तार हेतु पर्याप्त अवसर मिला।[9] तदुपरान्त, तिब्बत के शासक (Gambo) की मृत्यु के (650 ई0) पश्चात चीन व तिब्बत के मध्य उत्पन्न तीव्र मतभेदों के फलस्वरुप नेपाल व तिब्बत के पारस्परिक सम्बन्धों की निरन्तरता लगभग अवरुद्ध सी हो गयी। फलतः, तिब्बत व चीन के मध्य उत्पन्न शत्रुता के फलस्वरुप दक्षिण व पूर्वी एशिया के मध्य ट्रांस–हिमालय भाग कई शताब्दियों तक अवरुद्ध रहा किन्तु बाद में तिब्बत में चीन के प्रभावशाली विस्तार व प्रभुत्व स्थापित करने के फलस्वरुप नेपाल व चीन के मध्य भी सम्बन्धों को गहरा आघात पहुॅचा जिसे सामान्य बनने में पर्याप्त समय लगा।

मंगोलों को सत्ताच्युत कर चीन में स्थापित मिंग साम्राज्य (Ming Dynasty- 1368-1644) के दौरान यद्यपि तिब्बत में उसका प्रभुत्व शिथिल रहा किन्तु चीन ने नेपाल की काठमाण्डू घाटी के प्रभावशाली राजा परिवार से कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना में सफलता अवश्य प्राप्त कर ली। तिब्बत, नेपाल व चीन के सम्बन्धों के ऐतिहासिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सन 1384–1427 की कालावधि में नेपाल व चीन के मध्य सात प्रतिनिधिमण्डलों की यात्राएं सम्पन्न हुई किन्तु नेपाल के मल्ल राजवंश द्वारा सन 1427 में सम्पूर्ण काठमाण्डू घाटी को एकीकृत कर नियन्त्रण स्थापित करने के पश्चात उसने मिंग साम्राज्य के साथ पूर्व में स्थापित सभी कूटनीतिक सम्पर्कों को समाप्त कर दिया[10] तथा कई वर्षों तक नेपाल व चीन के मध्य सम्पर्कों की स्थापना अवरुद्ध रही। सोलहवीं व सत्रहवीं शताब्दी का काल भी नेपाल व चीन के द्विपक्षीय सम्बन्धों की दृष्टि से अत्यन्त नाजुक था। इस अवधि में जहॉ एक और बौद्ध पंथ के अनुयाइयों के मध्य उत्पन्न मतभेदों के फलस्वरुप तिब्बत आन्तरिक संघर्षों व उथल पुथल से प्रभावित था वहीं नेपाल के गोरखा राजा रामाशाह (1606–33) व काठमाण्डू के राजा प्रताप मल्ल (1624–74) ने तिब्बत की उक्त परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए सीमा से संलग्न हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख सम्वेदनशील व्यापारिक मार्गों पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया। इतना ही नहीं, 1625 से 1630 की अवधि में राजा शाह ने

तिब्बत में घुसपैठ कर पूर्वी क्षेत्र में स्थित कुकुरघाट क्षेत्र में तिब्बत व गोरखा के मध्य सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय सीमा सन्धि का नायायज लाभ उठाकर किरोंग मार्ग क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण संचार मार्ग पर भी बलपूर्वक नियन्त्रण स्थापित कर लिया। इस घटनाक्रम से काठमाण्डू के राजा प्रताप मल्ल ने व्यापारिक असुविधा को ध्यान में रखकर गोरखा राजा से विरोध करने के बजाय कुटी व्यापारिक मार्ग पर नियन्त्रण स्थापित कर तिब्बत के साथ एक समझौता कर लिया जिससे कुटी व किरांग जैसे सीमावर्ती कस्बों पर तिब्बत ने काठमाण्डू को संयुक्त आधिपत्य के अधिकार की अनुमति दे दी। यह समझौता 25 वर्षों तक ही कायम रहा तथा तिब्बत के पॉचवे दलाई लामा, (जिनकी मृत्यु सन् 1683 में हुई) ने प्रताप मल्ल को दिये गये सीमावर्ती क्षेत्रों को पुनः वापस तिब्बत में मिला लिया।[11]

अठरहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में यद्यपि क्विंग (मंचू) राजवंश ने तिब्बत के ल्हासा में दो रेजीडेण्ट्स नियुक्त कर दिये तथा सन 1773 में काठमाण्डू ने भी तिब्बत में अपने दूतों को अवश्य भेजा किन्तु उनके मध्य व्याप्त गतिरोधों के परिणामस्वरुप नेपाल व चीन के मध्य सम्बन्धों का न तो नवीनीकरण सम्भव हुआ और न ही दोनों के मध्य कूटनीतिक आदान–प्रदान। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि अट्ठारहवीं शाताब्दी के अन्तिम चरण मे भारत, नेपाल व तिब्बत में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के फलस्वरुप पहली बार हिमालयी क्षेत्र की राजनीति में चीन एक प्रमुख सक्रिय कारक के रुप में उभारकर सामने आया।[12] सन 1788 व 1793 की महत्वपूर्ण व निर्णायक कालावधि में क्षेत्रीय राजनैतिक उथल–पुथल में चीन की निरन्तर बढ़ती सक्रियता के कारण ब्रिटिश भारत, नेपाल व तिब्बत के साथ उसकी राजनैतिक अभिरुचि को नया आयाम मिला। ध्यातव्य है कि पंचेन लामा की मृत्यु, नेपाल में बहादुर शाह के हाथों में नेपाल की राजनैतिक सत्ता का संकेन्द्रण एवं ब्रिटिश भारत में लार्ड हेस्टिंग्स के स्थान पर गर्वनर जनरल के रुप में लार्ड कार्नवालिस की नियुक्ति से उत्पन्न परिस्थितियों का निश्चय ही चीन को राजनैतिक लाभ मिला। सन 1780 में तिब्बत के धार्मिक व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नेता नवें करमापा लामा (Shamar Trulkn) के काठमाण्डू

आगमन से जहाँ एक ओर तिब्बत –नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्धों में आई कटुता को अपेक्षाकृत शिथिल करने में सहायता मिली वहीं नेपाल व तिब्बत के संयुक्त सद्प्रयासों से तिब्बत पर क्विंग राजवंश के अधिराज्यीय आधार को भी शनैःशैनः शिथिल करने की भी आशा का संचार हो तो अवश्य हुआ किन्तु तिब्बत पर नेपाल के प्रभाव में शिथिलता के लक्षण प्रतीत नहीं हुए। उधर चीन की गतिविधियों से गोरखा राजा बहादुर शाह की यह आशंका पुष्ट होती गयी कि वह तिब्बत मार्ग से हिमालयी अवरोध को पार कर उस पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। यही कारण है कि सन 1788 में काठमाण्डू यात्रा पर आये एक तिब्बती भिक्षु के माध्यम से तिब्बत राज्य को एक पत्र भेजकर मल्ल राज्य की मुद्रा के अवमूल्यन का प्रयास करने के साथ–साथ रन बहादुर शाह ने कुटी व किरंग सीमान्त क्षेत्र में स्थित तिब्बत के चार व्यापारिक मार्गों नयानांग (Nyanang), रोंशार (Ronshar), किरांग (Kirong) व जॉग्का (Dzongka) पर नियन्त्रण की धमकी दी। तिब्बत पर गोरखाओं के उक्त अतिक्रमण से वहाँ की परिस्थितियॉ पर्याप्त जटिल होती गयीं जिससे इस क्षेत्र में चीन के प्रभाववृद्धि के अवसर दिखाई देने लगे। उधर, दलाईलामा द्वारा अंग्रेजों से सहायता प्राप्ति की अपील को लार्ड कार्नवालिस द्वारा ठुकराने के पश्चात सन् 1789 में चेंग डी के नेतृत्व में लगभग 2000 सैनिकों व अन्य चीनी प्रतिनिधियों को भेजकर तिब्बत में व्याप्त अस्थिरता को दूर करने का प्रयास किया गया। तदुपरान्त, दलाईलामा व नेपाली प्रतिनिधियों के मध्य सम्पन्न वार्ताओं के फलस्वरूप 2 जून, 1789 को नेपाल व तिब्बत के मध्य एक सन्धि सम्पन्न हुई जिसमें तिब्बत ने नेपाल को 57,000 रूपये प्रतिवर्ष उपहार स्वरूप धनराशि देने पर सहमति व्यक्त की। इस सन्धि पर चीन की प्रतिक्रिया से भयभीत नेपाल ने तिब्बत से प्राप्त होने वाले उपहार को लगान की संज्ञा देते हुए चीन के साथ सम्बन्धों में उत्पन्न हो रही कटुता की दूर करने के फलस्वरूप 1989–90 में चीन में एक प्रतिनिधिमण्डल भेजकर मावी अनिष्ट को टालने का हर सम्भव प्रयत्न किया। नेपाली प्रतिनिधिमण्डल का चीन में भव्य स्वागत किया गया तथा चीन के शासक ने भी नेपाल के

महाराजा हेतु बहुमूल्य उपहार के साथ–साथ महाराजा को प्रतिभाशाली व कुशाग्र राजा (Erdeni Wang) के अलंकरण से सुशोभित किया। उधर, तिब्बत द्वारा नेपाल के साथ 2 अक्टूबर, 1789 को सम्पन्न एक सन्धि (Treaty of Betrawati) की अवहेलना के पश्चात नेपाल ने तिब्बत पर 1791 में पुनः आक्रमण कर उसके सीमावर्ती चार जिलों पर अधिकार करने के साथ–साथ शिगस्ते (Shigaste) व शिलहिम्पों (Tashilhumpo) क्षेत्रों तक अपनी सैन्य कार्यवाही विस्तृत कर आक्रामक रूख प्रदर्शित किया। तिब्बत के विरूद्ध नेपाल के इस सैन्य अभियान से आक्रोशित होकर चीन के मंचू न्यायालय के निर्देशानुसार सन् 1792 में चीन ने नेपाल पर प्रबल आक्रमण कर न केवल नेपाली सेनाओं को पराजित कर दिया अपितु तिब्बत के साथ सम्पन्न सन्धि का समादर करने हेतु नेपाल को विवश होना पड़ा। यद्यपि सन् 1866 के पश्चात नेपाल ने 1877, 1886, 1894, 1906 व 1908 में चीन में अपने प्रतिनिधिमण्डल भेजकर द्विपक्षीय सम्बन्धों में पर्याप्त सुधार की कोशिश की किन्तु तिब्बत की भाँति नेपाल–चीन सम्बन्धों में मैत्रीपूर्ण भावनाओं के लक्षण दृष्टिगत नही हुए। सन् 1866 में चीन व तिब्बत के सम्बन्धों में उत्पन्न शिथिलता का ही यह परिणाम था कि वह नेपाल पर अपने अधिराज्य अधिकार (Suezerainty) को बलपूर्वक थोपने की स्थिति में नहीं था। चीन को यह भी भय था कि यदि उसने नेपाल पर अनावश्यक दबाव डालकर उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयत्न किया तो ब्रिटिश शासन चीन के विरूद्ध कठोर कदम उठा सकता है। यही कारण है कि चीन ने तत्कालीन भू–राजनैतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों एवं दक्षिण एशिया के घटनाक्रमों में अहस्तक्षेप की नीति पर चलना ही श्रेयस्कर माना। यद्यपि चीन ने ब्रिटिश सरकार की सामरिक–राजनैतिक महत्कांक्षाओं का विश्लेषण करते हुए जहाँ एक ओर तिब्बत–नेपाल क्षेत्र में छोटी–छोटी सैन्य टुकड़ियों को भेजकर अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश की वहीं नेपाल के प्रति ब्रिटिश सरकार की भावनाओं का अनुमान करने के फलस्वरूप नेपाल के प्रति चीन ने आक्रामक भावनाओं को प्रकट नहीं होने दिया। नेपाल व ब्रिटिश के मध्य सम्पन्न युद्ध

(1814) व काठमाण्डू में ब्रिटिश रेजीडेन्सी की स्थापना भी चीन के लिए चिन्ता का विषय था जबकि ब्रिटिश सरकार तिब्बत व पश्चिमी चीन तक अपनी व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार हेतु नपे–तुले कदम उठाने हेतु प्रयत्नशील थी। इन घटनाओं से चीन व ब्रिटिश सरकार के मध्य सम्बन्धों में कटुता के लक्षण यत्र–तत्र दिखाई देने लगे तथा तिब्बत से संलग्न अपनी सीमान्त सुरक्षा हेतु वह अत्यन्त व्यग्र हो उठा।[13] 17 वीं, 18वीं व 19वीं शताब्दी में तिब्बत पर नेपाल का वर्चस्व स्थापित रहा।

वास्तव में, नेपाल व चीन सम्बन्धों के केन्द्र में तिब्बत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेपाल ने तिब्बत–केन्द्रित अपने व्यापारिक हितों की दृष्टि से न केवल महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर नियन्त्रण बनाये रखा अपितु तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के बावजूद तिब्बत के साथ उसके व्यापारिक सम्बन्ध निर्बाध गति से चलते रहे। किन्तु कालान्तर में तिब्बत के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में आयी शिथिलता एवं तिब्बत पर ब्रिटिश वर्चस्व के फलस्वरूप नेपाल ने अपनी व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन करके चीन के तिब्बत–वर्चस्व को चुनौती देते हुए 1792 व 1854 में तिब्बत पर आक्रमण किया। इस युद्ध में पराजित तिब्बत को अन्नतः नेपाल के साथ 2 मार्च, 1856 को थपाथली सन्धि (Treaty of Thapathali) हेतु विवश होना पड़ा। इस सन्धि के अन्तर्गत नेपाल के राजा जंग बहादुर ने तिब्बत के विजित क्षेत्रों को वापस करने हेतु क्षतिपूर्ति के रुप में एक करोड़ रुपये की मॉग की। तिब्बत को अपना राज्य मानते हुए चीन द्वारा नेपाल को आक्रमण की धमकी देने के फलस्वरुप दोनों देश निम्नांकित बिन्दुओं पर सहमत हुए–

1. तिब्बत की सरकार नेपाल की सरकार को प्रतिवर्ष 10,000 नेपाली रुपये की धनराशि देगी।
2. नेपाल व तिब्बत दोनों ने चीन के राजा का सम्मान करते हुए यह संकल्प लिया कि तिब्बत पर होने वाले विदेशी आक्रमण के समय नेपाल सरकार उसकी सहायता करेगी। तिब्बत ने भी नेपाल पर होने वाले आक्रमण की स्थिति में उसके धन व सम्पत्ति की सुरक्षा का आश्वासन दिया।

3. दोनों देशों के मध्य व्यापार–प्रक्रिया को सुगम बनाया जायेगा।

4. नेपाली व्यापारी सुगमता से तिब्बत में व्यापार कर सकेंगे तथा नेपालियों का तिब्बत आवागमन निष्कंटक रहेगा।

5. नेपाली प्रतिनिधि तिब्बत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा द्विपक्षीय विवादों का समाधान नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जायेगा।

उधर तिब्बत–नेपाल संघर्ष, तिब्बत के स्त्रातेजिक महत्व एवं हिमालयी क्षेत्र की सामरिक–आर्थिक सम्वेदना के प्रति ब्रिटिश सरकार के मनोभावों का आंकलन करते हुए चीन ने नेपाल के भू–राजनैतिक महत्व पर ध्यान केन्द्रित कर उसे चीन व ब्रिटिश भारत के बीच एक अन्तस्थ–क्षेत्र के रूप में मान्यता देकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की चेष्टा की। यही कारण है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर चीन–नेपाल सम्बन्धों में मधुरता के लक्षण प्रतीत होने लगे वहीं नेपाल द्वारा अपनी भूमि से ब्रिटिश सरकार के तिब्बत प्रवेश के विरोध के फलस्वरूप सिक्किम व भूटान होकर तिब्बत प्रवेश सम्बन्धी ब्रिटिश की वैकल्पिक मार्ग की नीति से क्षेत्रीय तनावों को नया आयाम मिला। तिब्बत व नेपाल के संदर्भ में ब्रिटिश नीतियों के गम्भीर विश्लेषण के फलस्वरूप चीनी नीति निर्धारकों को यह स्पष्ट हो गया कि ट्रांस–हिमालयन क्षेत्र में नेपाल की भूमि एक ऐसे अन्तस्थ राज्य (Buffer State) की है जिसके साथ सुदृढ़ सम्बन्धों की स्थापना करके वे ब्रिटिश–प्रवाह पर अंकुश लगा सकते हैं। ध्यातव्य है कि तिब्बत–नेपाल के भू–स्त्रातेजिक महत्व का ही यह परिणाम था कि चीन ने इस क्षेत्र में अपने कूटनीतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया वहीं ब्रिटिश सरकार न केवल सिक्किम मार्ग से चुम्बी घाटी में प्रवेश हेतु सड़क निर्माण पर सक्रिय रही अपितु भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती का भी अभियान प्रारम्भ करने को प्राथमिकता दी। लार्ड कर्जन द्वारा तिब्बत में प्रकट आक्रामक रूख से व्यथित चीन की सहायता हेतु जहाँ रूस ने सक्रियता दिखाई वहीं अंग्रेजों ने नेपाल में देव शमसेर को पदच्युत कर सन् 1901 में सत्ता में आये चन्द्र शमशेर की सहायता तो अवश्य की किन्तु चीन–रूस विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को अपनी आक्रामक तिब्बत– नीति को शिथिल करके वहाँ से पीछे

हटना पड़ा। तिब्बत में नेपाल के व्यापारिक हितों, नेपाल–ब्रिटिश रिश्तों एवं तिब्बत के भू–सामरिक अवस्थिति के विश्लेषणोंपरान्त 31 अगस्त, 1907 को सेण्ट्स पीटर्सवर्ग में सम्पन्न एक सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन एवं रूस ने तिब्बत पर चीन के अधिराज्य अधिकार (Suzerain Right) की मान्यता प्रदान कर दी, जिसमें निम्नांकित तत्व समाहित थे[14]

1. चीन, तिब्बत की प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करते हुए उसके आन्तरिक प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।
2. तिब्बत के साथ सम्बन्धों के संचालन में मात्र चीन की सरकार ही मध्यस्थता की भूमिका निभायेगी।

नेपाल व तिब्बत के मध्य सम्पन्न शक्ति–राजनीति के उक्त घटनाक्रमों से यह स्पष्ट होता है कि इसमें ब्रिटेन व रूस के स्थान पर मात्र चीन को ही प्रत्यक्ष लाभ मिला तथा उसने तिब्बत पर पर्याप्त वर्चस्व स्थापित करके क्षेत्रीय भू–राजनीतिक व भू–सामरिकी पर स्थायी प्रभाव बनाकर अपने हितों के अनुरक्षण व उनके सतत अभिवर्द्धन हेतु पृष्ठभूमि निर्मित कर ली। वास्तव में, हिमालयी क्षेत्र में सफल चीन की अग्रवती नीति (Forward Policy) एक ऐसी अविश्वसनीय घटना थी जिसकी उम्मीद उसे भी नहीं थी किन्तु घटनाक्रमों के विविध आयामों का उसने बड़ी सतर्कता व धैर्यपूर्वक लाभ उठाया। तदुपरान्त, नेपाल व भूटान के साथ स्थापित ब्रिटिश सम्बन्धों की उपादेयता को ध्यान में रखकर ल्हासा स्थित चीन के प्रतिनिधि ने अपनी सरकार को पत्र लिखकर उनके साथ सम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण बनाने की सलाह दी। यद्यपि ब्रिटिश शासन ने चीन को सम्पूर्ण तिब्बत पर व्यावहारिक नियन्त्रण हेतु अनुमति तो दे दी किन्तु तिब्बत के दक्षिणी हिमालयी चोटियों के क्षेत्र में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप के दुःसाहस न करने का अल्टीमेटम भी दिया। 26 फरवरी, 1910 को ब्रिटिश सरकार ने बीजिंग सरकार का उक्त आशय का पत्र भी भेजा, जिसके प्रत्युत्तर में बीजिंग ने नेपाल को अपना सामन्ती अधिकार क्षेत्र (feudatory) बताकर लिखे पत्र में दृढ़ता से यह स्पष्ट किया कि नेपाल काफी समय से उसे उपहार व सम्मान आदि देता रहा है। प्रतिक्रिया स्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने दृढ़तापूर्वक

बीजिंग को 17 जनवरी, 1911 को एक पत्र लिखकर नेपाल में किसी प्रकार के हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी किन्तु इसी बीच सन् 1911 में चीन में प्रारम्भ क्रान्ति एवं तिब्बत से उसके पीछे हटने की पृष्ठभूमि में चीन–नेपाल सम्बन्धों में उत्पन्न हो रहे विवाद अव्यावहारिक हो गये। इसी बीच जहाँ एक ओर चीन ने नेपाल की स्वतन्त्रता पर कोई सवाल खड़े किये बिना परिस्थितिवश उसे स्वीकार कर लिया वहीं नेपाल पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव पर भी कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। उधर, तिब्बत–चीन सम्बन्धों की प्रकृति व विभिन्न घटनाक्रमों पर नेपाल द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने से बीजिंग ने यह अनुमान लगा लिया कि वह ब्रिटिश सरकार को संतुलित करने हेतु तिब्बत में चीन की उपस्थिति का पक्षधर है। जहाँ तक क्षेत्रीय भू–राजनैतिक सन्तुलन का प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने नेपाल के साथ सदाशयता प्रकट करते हुए तिब्बत में उसके हितों को ध्यान में रखकर हथियार व अन्य आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति नीति में आंशिक शिथिलता अवश्य प्रदान की। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने सम्भावित नेपाल–चीन यूनियन के गठन की सम्भावनाओं पर भी सतर्कतापूर्वक दृष्टि रखते हुए इस पर विराम लगाने के कई कूटनीतिक प्रयत्न भी किये।

नेपाल व चीन के राजनैतिक सम्बन्धों के आयाम–

सन् 1911 में तिब्बत से चीन के निष्कासन एवं आन्तरिक उथल पुथल से ग्रस्त होने के कारण नेपाल–चीन सम्बन्धों पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। सन् 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना से पूर्व चीन द्वारा नेपाल में भेजे गये क्रमशः सन् 1930, 1932, 1934 व 1946 में प्रतिनिधिमण्डलों के प्रत्युत्तर में नेपाल द्वारा 1946 में मात्र एक ही प्रतिनिधिमण्डल भेजने के ऐतिहासिक साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं कि नेपाल के शासक बड़ी सतर्कतापूर्वक चीन की साम्यवादी क्रान्ति एवं भारत में भी ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरण की सम्भावनाओं पर दृष्टि रखते हुए संतुलित नीति संचालन हेतु अत्यन्त सतर्क थे। इस क्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक राजनैतिक घटनाओं का ही परिणाम था कि नेपाल जहाँ एक ओर चीन व भारत के साथ

संतुलित नीति का संचालन कर रहा था वहीं अपनी पृथक्कीकरण नीति (Isolation Policy) को गतिशीलता प्रदान करते हुए ब्रिटिश–भारत–तिब्बत नीति से ऊपर उठकर अमेरिका व राष्ट्रवादी चीन के साथ सम्बन्धों को नयी ऊर्जा देने हेतु भी प्रयत्नरत था। यद्यपि नेपाल ने मार्च 1946 में चीन में अपना एक शान्ति मिशन अवश्य भेजा किन्तु चीन में साम्यवादियों को प्राप्त सफलता के पश्चात उसकी विदेश नीति में व्यापक परिवर्तन प्रक्रिया को नयी दिशा व ऊर्जा प्राप्त हुईं क्योंकि 15 अगस्त, 1947 में प्राप्त भारतीय स्वाधीनता से पूर्व स्थापित क्षेत्रीय भू–राजनैतिक समीकरण ही परिवर्तित हो गये। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति एवं महाशक्तियों के मध्य प्रारम्भ शीत युद्ध का भी नेपाल की राजनीति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

जहाँ तक नेपाल व चीन के पारस्परिक सम्बन्धों का प्रश्न है, यद्यपि यह विविध उतार–चढ़ावों से निरन्तर प्रभावित होता रहा है किन्तु इन पर भौगोलिक कारकों का स्थायी प्रभाव परिलक्षित होता है। दोनों राष्ट्रों की भौगोलिक सन्निकता एवं भू–रणनीतिक महत्ता से प्रभावित उभयपक्षीय सम्बन्धों में तिब्बत की प्रमुख भूमिका रही है।[15] पूर्व, पश्चिम व दक्षिण की ओर भारत से तथा उत्तर की ओर से तिब्बत द्वारा घिरे हुए नेपाल की भौगोलिक विशिष्टता का स्पष्ट प्रभाव उसकी विदेश नीति पर परिलक्षित होता है।[16] इसी भौगोलिक विशिष्टता एवं भारत व चीन के साथ उसकी क्षेत्रीय सन्निकटता ने ही नेपाल को दोनों बड़े देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों के निर्धारण में जहाँ एक ओर सुविधाएं प्रदान की वहीं उसके लिए चिन्ताजनक स्थिति का परिवेश उत्पन्न करने में भी ये निर्धारक तत्व रहे हैं।[17] हिमालय की ऊँची पहाड़ियों एवं लगभग 15000 फिट ऊँचे तिब्बत के दुर्गम भू–भागों से चीन द्वारा पृथक नेपाल ऐसा दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ के अधिकांश उत्तरी भू–भागों की धरातलीय संरचनाएं यातायात व संचार हेतु दुष्कर वातावरण का निर्माण करती हैं। मात्र कुछ दुर्गम पर्वतीय दर्रों से ही चीन व नेपाल के मध्य यातायात सम्पर्क सम्भव हैं वह भी मौसम व जलवायु की प्रतिकूलता उन्हें समय–समय पर अवरूद्ध करती रहती है। दोनों राष्ट्रों के मध्य लगभग 18 ऐसे पर्वतीय दर्रे हैं जो उनके मध्य पारस्परिक सम्पर्क के माध्यम हैं। सबसे सुगम व सरल मार्ग तिब्बत–नेपाल की

सीमा पर स्थित किरोंग व कुटी दर्रें ही ऐसे हैं जिनसे व्यापार व यातायात अपेक्षाकृत सहज है किन्तु ये दोनों मार्ग नेपाल व चीन के मध्य प्राचीन काल से ही संघर्ष व विवादों को जन्म देते रहे हैं। महान हिमालय पर्वत में लगभग 13000–14000 फिट ऊँचाई पर भैरव लांगर (Bhairab Langur) श्रृंखला पर स्थित ये दर्रे भी शीत काल में अवरूद्ध हो जाते हैं तथापि ये सीमित रूप में व्यापारिक कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाते हैं वह भी मात्र स्थानीय नागरिकों द्वारा। यही कारण है कि अपने व्यापारिक व सामारिक हितों के रक्षार्थ नेपाल के शासकों द्वारा तिब्बत–नेपाल सीमा पर स्थित किरोंग व कुटी मार्गों पर सदैव अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने सम्बन्धी राजनयिक प्रयत्न किये जाते रहें है। विगत तीन शताब्दियों में इस क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के परम लक्ष्य से तिब्बत व नेपाल के मध्य हुए संघर्ष इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। दूसरी ओर नेपाल–चीन सीमावर्ती भागों की दुर्गम प्राकृतिक जटिलता के प्रतिकूल भारत व नेपाल क्षेत्रों की सन्निकटता एवं विशिष्ट अवरोध न होने के कारण भारत–नेपाल के मध्य सम्बन्धों की स्थापना अपेक्षाकृत पर्याप्त सुगम है। प्राकृतिक अवरोध–मुक्त भारत–नेपाल की सीमाएं खुली हैं तथा पहाड़ व यहाँ बहने वाली पश्चिम में काली नदी व पूर्व में तीस्ता नदियाँ भारतीय क्षेत्र में बहती हैं। नेपाल के दक्षिणी भाग का तराई क्षेत्र न केवल भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक दृष्टि से भारतीय भू–भागों से सन्निकट है अपितु इस सीमावर्ती क्षेत्र में कोई दुर्गम अवरोध न होने के फलस्वरूप चीन की अपेक्षा नेपाल व भारत के द्विपक्षीय सम्बन्धों के निर्धारण की दृष्टि से सुगमता उपलब्ध कराता है। भारत–नेपाल सीमा की अरोधमुक्त विशिष्टता एक ऐसा मुख्य कारण है जिनसे दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार व आवागमन को सदैव प्रोत्साहन मिलता रहा है। स्थलबद्ध नेपाल का अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार भी भारत के कलकत्ता बन्दरगाह के माध्यम से ही सम्पन्न होता है जिससे दोनों देशों की प्राकृतिक मैत्री को निरन्तर ऊर्जा मिलती रहती है।

नेपाल : एक सामरिक प्रतिरोधक क्षेत्र–

जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि चीन व भारत जैसे विशाल राष्ट्रों के मध्य नेपाल दबा अथवाा फँसा हुआ (Sandwitch)[18] एक ऐसा देश है जो दोनों के मध्य एक अन्तस्थ राज्य अथवा प्रतिरोधक की भूमिका के निर्वहन हेतु विवश है। ध्यातत्व है कि ब्रिटिश शासन काल में हिमालयी क्षेत्र तक उसके प्रभुत्व विस्तार की अवधि में तिब्बत का स्वायत्तशासी क्षेत्र चीन व भारत के मध्य एक बफर–क्षेत्र की भूमिका हेतु उपलब्ध था किन्तु एक शक्ति केन्द के रूप में चीन के अभ्युदय व तिब्बत पर उसके अधिकार के फलस्वरूप नेपाल तक विस्तृत उसके सीमान्त से नेपाल की भू–सामरिक महत्ता में निर्णायक अभिवृद्धि होती गयी। तिब्बत पर चीन के नियन्त्रण से लगभग 800 किमी तिब्बत–नेपाल सीमा सम्पर्क से जहाँ एक ओर चीन का नेपाल से प्रत्यक्ष सीमा सम्पर्क स्थापित हो गया वहीं भारत का भू–स्त्रातेजिक परिदृश्य भी इससे प्रभावित हुआ। इस क्षेत्र में भारत की सीमा–सुरक्षा व्यवस्था न केवल सम्वेदनशील हो गयी अपितु नेपाल में प्रवेश हेतु चीन को तिब्बत क्षेत्र स्थित विभिन्न दर्रों की उपलब्धता के कारण भारत का हिमालयी सीमान्त क्षेत्र पर्याप्त सम्वेदनशील हो गया। नेपाल के साथ भारत की खुली सीमाएं एवं तिब्बत क्षेत्र तक विस्तृत नेपाल के सीमान्त क्षेत्रों में चीन की भेदनीयता की आशंकाओं के कारण भारत का यह सम्पूर्ण क्षेत्र चीन की पहुँच के अन्तर्गत आने सम्बन्धी आशंकाओं को भी पर्याप्त बल मिला। यही कारण है कि 6 दिसम्बर, 1950 को भारतीय संसद में पं0 नेहरू ने चीन व नेपाल के अर्न्तसम्बन्धों एवं भारत के उत्तरी सीमान्त पर पड़ने वाले उसके सम्भावित प्रभावों को दृष्टिगत रखकर यह स्पष्ट किया कि ''हम इस अवरोध पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देंगे क्योंकि प्रत्यक्षतः यह प्रश्न भारत की सुरक्षा व अखण्डता से संलग्न है।''[19] निर्विवाद रूप से भारत व चीन के मध्य स्थित नेपाल की रणनीतिक महत्ता कम नही है किन्तु तिब्बत व भारत के मध्य व नेपाल के उत्तरी सीमान्त पर विस्तृत हिमालय की पर्वत मालाएं एक ऐसा अवरोध हैं जो नेपाल की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इतना ही नहीं, नेपाल की भौतिक अथवा क्षेत्रीय गहराई की सीमित प्रकृति सम्भवतः दो विशाल

ये है चीन का असली नक्शा। आप सभी से अनुरोध है की इसको इतना विरल करें की एक बार फिर ये नक्शा ग्लोबल टाइम्स की मुख्य खबर बन जाए।

This is the real map of china. Request to all of you please make it viral across the world by sharing this picture on different types of social sites like Facebook WhatsApp etc.

देशों के मध्य उसे एक महत्वपूर्ण अन्तस्थ क्षेत्र अथवा प्रमुख अवरोधक स्थल का दर्जा नहीं दे सकतीं। नेपाल व भारत की अभिन्न भौगोलिक संलग्नता तथा भारत पर उसकी निर्भरता सम्भवतः उसे चीन व भारत के मध्य संतुलन हेतु ही सक्रियता व सर्तकता का आभास कराती रहती हैं।

यह सच है कि भौगोलिक कारक किसी भी देश की विदेश नीति व रणनीतिक संस्कृति पर स्थायी प्रभाव डालते हैं किन्तु बदलती भौगोलिक अवधारणाएं, तकनीक, विचारधारा एवं भू–राजनैतिक परिवेश से राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण व उनका संचालन अछूता नहीं रह सकता। यही कारण है कि चीन व नेपाल के पारस्परिक सम्बन्ध भी भौगोलिक सन्निकटता के बावजूद बहुत सामान्य ढंग से संचालित न हो सके। चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना और उसकी नेतृत्व–संस्कृति से प्रभावित अवधारणा का ही परिणाम था कि माओत्सेतुंग ने नेपाल को अपने आश्रित राज्य (Dependent State)[20] का दर्जा देते हुए कहा कि अंग्रेजों ने इस पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है। चीन के उक्त अधिकार प्रदर्शन की छाया एवं 1950–51 में तिब्बत पर ऐतिहासिक दावों सम्बन्धी चीनी नीतियों[21] से नेपाल का भयभीत होना स्वाभाविक था। यद्यपि चीन का उद्देश्य नेपाल पर मनौवैज्ञानिक दबाव डालकर उसे अपने विस्तारवादी नीति के प्रभाव में लाना था किन्तु स्वतन्त्र भारत से स्थापित नेपाल के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के कारण चीन की आक्रामक मनोवृत्ति का उसकी नीतियों पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा।[22] सन् 1949 में नेपाल के विपक्षी नेता डी0आर0रेग्मी ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि यदि भारत द्वारा नेपाल को विखण्डित कर अधिकार करने का प्रयास किया गया तो भारत समर्थित राणा परिवार के विरूद्ध चीन द्वारा न केवल कठोर कार्यवाही की जायेगी अपितु उत्तरी नेपाल के असन्तुष्ट नागरिकों को हर सम्भव व अपेक्षित सहायता प्रदान कर वह राणा परिवार के विरूद्ध संघर्ष को ऊर्जा देकर प्रत्यक्ष कार्यवाही करने में चीन जरा सा संकोच नही करेगा।[23] यद्यपि नेपाल उस समय चीन के साथ सम्बन्धों की स्थापना हेतु बहुत उत्सुक नहीं था किन्तु नेपाल में भारत के राजदूत सी0पी0एन0सिंह द्वारा नेपाल की सेना को

पुर्नगठित व प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक सैन्य प्रतिनिधिमण्डल भेजने के निर्णय, नेपाल सचिवालय में भारतीय सलाहकारों की विविध गतिविधियों तथा नेपाल नरेश त्रिभुवन व अन्य नेपाली उच्च अधिकारियों से मन्त्रणा हेतु भारत यात्रा से उत्पन्न आशंकाओं से काठमाण्डू की जनता में भारत के विरूद्ध उत्पन्न जनमत से द्विपक्षीय सम्बन्धों में गतिरोध होना स्वाभाविक था। उल्लेखनीय है कि नेपाल में व्याप्त जन–असन्तोष पर नियन्त्रण हेतु सन् 1951–1953 में भारतीय सैन्य व पुलिस बल नेपाल भेजने की भारतीय गतिविधियों से द्विपक्षीय सम्बन्धों को गहरा आघात पहुँचा तथा भारत व नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्धों में उत्पन्न गतिरोध के फलस्वरूप नेपाल में चीनी हस्तक्षेप की महत्वाकाँक्षाओं को नयी ऊर्जा मिली। फलतः, हिमालयी क्षेत्र में उसके आर्थिक–सामरिक अभिरूचि की अभिवृद्धि को तवरित आयाम देने हेतु नेपाल के असन्तुष्ट तत्वों ने सरकार पर दबाव बनाकर इस मार्ग को सुगम कर दिया कि चीन के साथ भी नेपाल को कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना कर अपनी विदेशनीति के क्षितिज को विस्तृत करना वर्तमान भू–राजनैतिक व सामरिक दृष्टि से अपरिहार्य है।[24] सन् 1951–54 की कालावधि में तिब्बत की त्वरित घटनाओं से व्यथित नेपाल ने जहाँ एक ओर चीन की आक्रामक मनोवृत्ति से प्रभावित होकर उसके साथ उभयपक्षीय सम्बन्धों के निर्धारण में सर्तकतापूर्ण रूख अपनाया वहीं डॉ0के0आई0 सिंह व अन्य समर्थकों की तिब्बत यात्रा से नेपाल में इस आशंका का बल मिला कि इनके माध्यम से चीन तिब्बत पर आक्रमण के साथ–साथ नेपाल के विरूद्ध भी छापामार युद्ध की शुरूआत कर सकता है।[25] सन् 1856 में नेपाल व तिब्बत के मध्य पूर्व में सम्पन्न सन्धि व अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में नेपाल का चीन के प्रति शंकालु होना स्वाभाविक भी था। उल्लेखनीय है कि सन् 1953 में तिब्बत से नेपाल को प्राप्त होती रही वार्षिक धनराशि के भुगतान को निषिद्ध करने हेतु चीन द्वारा दलाईलामा को निर्देश देना एवं तिब्बत में नेपाली अधिकार सम्बन्धी विवादों के समाधान हेतु ल्हासा में नेपाली वकीलों को प्राप्त विधिक अधिकारों के स्थगन सम्बन्धी नेपाल–विरोधी चीनी कदमों से नेपाल–चीन सम्बन्धों में अविश्वास की भावनाओं को पर्याप्त बल मिला। ध्यातव्य है कि सन् 1954 में भारत व चीन में मध्य सम्पन्न पंचशील समझौते के कुछ सप्ताह पूर्व ही एम0पी0

कोइराला ने घोषणा की थी कि उनका देश सन् 1856 की सन्धि के आधार पर तिब्बत में प्राप्त अपने अधिकारों का समर्पण किसी भी दशा में नहीं करेगा[26] किन्तु भारत द्वारा 1954 में चीन के साथ किए गये समझौते एवं इसमें तिब्बत पर चीनी अधिराज्य (Suzerainty)[27] की स्वीकृति के फलस्वरूप तिब्बत में प्राप्त नेपाल के पूर्व अधिकारों के भाग्य का निर्धारण स्वतः तो हो ही गया वहीं भारत ने भी नेपाल को तिब्बत के साथ सम्बन्धों के पुनर्निर्धारण की सलाह देते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब उसे 1954 के भारत–चीन सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में ही भावी सम्बन्धों का निर्धारण करना चाहिए।[28] हिमालयी क्षेत्र में त्वरित गति से परिवर्तित हो रहे भू–राजनैतिक घटनाक्रमों का गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण करते हुए यद्यपि नेपाल के महाराजा ने चीन के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना हेतु प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया किन्तु अक्टूबर 1954 में पं0 नेहरू की चीन मात्रा के दौरान चाऊ एल लाई से हुई उनकी वार्ता एवं 13 मार्च, 1955 को नेपाल नरेश त्रिभुवन की मृत्यु से वार्ता–प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। नेपाल में सत्तारूढ़ नये महराजा महेन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने राष्ट्र की भूमिका हेतु अत्यन्त सतर्क थे किन्तु साम्यवादी चीन व नेपाल के साथ सम्बन्धों की स्थापना में चीन की शासन प्रणाली, दिशा निर्देशों, संकल्प एवं विदेशनीति सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण, तिब्बत–संघर्ष व कोरियाई युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों व परिणामों के साथ–साथ शीतयुद्ध की प्रकृति सम्बन्धी विभिन्न आयामों के परिप्रेक्ष्य में नेपाल के साथ चीन आक्रामक रूख अपनाने की स्थिति में नहीं था।[29] उधर, नेपाल पर स्थापित भारतीय प्रभाव के कारण नेपाल के प्रति आक्रामक होकर चीन भारत को क्रुद्ध करना भी नहीं चाहता था। यही कारण है कि नेपाल के साथ सम्बन्धों की स्थापना में चीन ने बहुत संयम व कूटनीतिक चातुर्य से अपना कदम आगे बढ़ाया।

नेपाल–चीन के कूटनीतिक सम्बन्ध–

चीन व नेपाल के मध्य कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थाापना के परिप्रेक्ष्य में 1954 के अन्तिम अवधि में नई दिल्ली में सम्पन्न राजदूत स्तर की असफल बैठक के उपरान्त नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूत General Yuan

Zhuangxuan के नेतृत्व में एक छः सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल की काठमाण्डू यात्रा सम्पन्न हुई। लगभग पाँच दिनों के गहन विचार–विमर्श के उपरान्त अन्ततः शान्तिपूर्ण–सहअस्तित्व के पाँच–सिद्धान्तों के आधार पर 1 अगस्त, 1955 को दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना पर सहमति हुई। यद्यपि उस बैठक में काठमाण्डू में चीनी दूतावास की स्थापना हेतु कोई निर्णय नहीं हो सका किन्तु सम्बन्धों में प्रगाढ़ता लाने के उद्‌देश्य से 3 फरवरी, 1956 को चीन ने नेपाल को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की इच्छा अवश्य प्रकट की। इस अवसर पर नेपाल के महाराजा ने न केवल चीन की सद्‌इच्छाओं के प्रति सम्मान व आभार प्रकट किया अपितु इस पृष्ठभूमि में उन्होंने नेपाल–तिब्बत सम्बन्धों के सुदृढ़ीकरण एवं अपने उत्तरी सीमान्त क्षेत्र की सीमा निर्धारण का महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य लिया। उक्त परिप्रेक्ष्य में नेपाल व चीन के मध्य मई 1956 में प्रतिनिधिमण्डलों के माध्यम से दोनों देश कूटनीतिक दृष्टि से निकट आते हुए प्रतीत हुए। हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण जैसे मुद्‌दों पर उत्पन्न कतिपय नेपाली प्रतिक्रिया के बावजूद नेपाली प्रधानमन्त्री टी0प्रसाद आचार्य की सम्पन्न दस दिन की चीनी यात्रा के दौरान गहन मन्त्रणा के पश्चात 7 अक्टूर, 1956 को दोनों देशों के मध्य एक आर्थिक समझौता सम्पन्न हुआ। यद्यपि इस विचार–विमर्श के दौरान चीनी प्रतिनिधियों ने हिमालयी क्षेत्र में स्थापित भारतीय प्रभुत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे भारतीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े किन्तु 25–28 फरवरी, 1957 की अवधि में चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ एन लाई की सम्पन्न नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल में रह रहे मंगोलियाई मूल के नृजातीय समूहों के प्रति प्रकट सद्‌भावना एवं नेपाल–चीन के मध्य 'रक्त–सम्बन्धों' (Blood ties between China and Nepal) पर विशेष बल देने से निश्चय ही भारत का सतर्क होना स्वाभाविक था क्योंकि इससे नेपाल–भारत के सांस्कृतिक व राजनयिक समबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भावी आशंकाओं को नई ऊर्जा मिलने के प्रबल आसार थे। चीन के उक्त निर्णय से नेपाल व भारत के मध्य पूर्व स्थापित सुदृढ़ सांस्कृतिक आधार पर चोट पहुँचने के आसार बनते दिखाई दे रहे थे। उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा नेपाल में भोटिया राज

(Bhotia Raj) सम्बन्धी प्रचार से जहाँ एक ओर घाटी स्थित नेवर समुदाय व पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिम्बू व किराती समुदाय की भारत सम्बन्धी भावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था वहीं चीन द्वारा बौद्ध धर्म के आधार पर नेपाल में प्रभाव–विस्तार से भी भारतीय हितों पर गहरा आघात पड़ने के प्रबल आसार बनते दृष्टिगत होने लगे। काठमाण्डू में बौद्ध होटल की स्थापना हेतु चीन द्वारा पचास हजार रूपये की सहायता एवं 'नेपाली बौद्ध संगठन' के सदस्यों को चीनी आमन्त्रण जैसी गतिविधियों से इन आशांकाओं को बल मिला।

भारत के धुर–विरोधी नेपाल के तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंका प्रसाद आचार्य द्वारा चीन के प्रति निर्धारित नीतियों के भावी परिणामों से आशंकित राजा महेन्द्र ने अन्ततः उन्हें पदच्युत कर संतुलित विदेशनीति सम्बन्धी कदम उठाये, जिससे भारत व चीन दोनों को संतुलित किया जा सके। तदुपरान्त, नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमन्त्री के0आई0सिंह ने भारत–नेपाल सम्बन्धों के मैत्री भावनाओं की सुदृढ़ता व प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि चीन व सोवियत संघ के दूतावासों की स्थापना हेतु नेपाल कदापि अनुमति नहीं देगा। फलतः, राजा महेन्द्र ने यद्यपि 14 नवम्बर, 1957 को के0आई0सिंह को पदच्युत कर सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया किन्तु निम्नांकित कारकों का नेपाल की विदेशनीति पर गम्भीर प्रभाव पड़ा–

1. बी0पी0कोइराला के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार की स्थापना।
2. सन् 1959 में तिब्बत में चीनी नेतृत्व के विरूद्ध व्यापक स्तर पर विद्रोह।
3. भारत–चीन के मध्य सीमा विवाद का वातावरण।

यही कारण है कि नेपाल की तत्कालीन कोइराला सरकार ने प्रजातान्त्रिक मूल्यों में विश्वास प्रकट कर भारत के साथ सदियों से स्थापित मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्राथमिकता देते हुए साम्यवादी विचारधारा का प्रबल विरोध किया जिससे नेपाल–चीन सम्बन्धों में गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। वास्तव में, कोइराला की न केवल प्रजातन्त्र में प्रबल आस्था थी अपितु वे साम्यवाद की विचारधारा को व्यक्तिगत रूप से पसन्द नहीं करते थे।

तिब्बत में विद्रोह–

सन 1959 में तिब्बत में प्रारम्भ खम्पा विद्रोही गतिविधियॉ (Khampa Rebellion)[30] एवं चीन द्वारा तिब्बत में निर्मम दमन एक ऐसा प्रमुख कारक था जिसने नेपाल व चीन सम्बन्धों को पर्याप्त क्षति पहुँचाई। नेपाल में सम्पन्न आम चुनाव एवं वी0पी0 कोइराला द्वारा सत्ता संभालने के दौरान 30 अप्रैल 1959 को नेपाली कांग्रेस के दो महासचिवों, एस0पी0 उपाध्याय व गणेशमान सिंह द्वारा तिब्बत में चीनी गतिविधियों की न केवल आलोचना की गयी अपितु चीन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने 1951 की तिब्बत–चीन सन्धि का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, नेपाल द्वारा आरोप लगाते हुए चीन को यह सुझाव दिया कि उसे तिब्बत में आत्म–निर्णय सम्बन्धी लेनिनवादी सिद्धान्तों का आदर करना चाहिए। वास्तव में, यह नेपाल की तत्कालीन नई सरकार की विदेश नीति का ऐसा पक्ष था जिससे यह स्पष्ट हो गया कि तिब्बत में बर्बर व अमर्यादित गतिविधियों के प्रति उसके दृष्टिकोण की दिशा क्या होगी। वी0पी0 कोइराला ने स्वयं यह पुष्ट कर दिया कि तिब्बत घटना से अपने बडे पड़ोसी चीन से उसके परम्परागत सम्बन्धों पर प्रभाव निश्चय ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, चीन की तिब्बत नीति की आलोचना करते हुए नेपाल ने इसे 19 वीं सदी की साम्राज्यवादी परम्पराओं की संज्ञा तो दी ही साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि उनका देश तटस्थता व गुटनिरपेक्षता की नीति के आधार पर अपनी नीति का संचालन करेगा। नेपाल व भारत के प्रधानमन्त्रियों ने 14 जून 1959 को एक संयुक्त–घोषणा पत्र जारी किया जिससे यह पुष्ट हो गया कि भारत व नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्धों का भावी स्वरुप किस प्रकार निर्मित होगा। जहॉ एक ओर तिब्बत पर चीन की कार्यवाहियों पर नेपाल का दृष्टिकोण विक्षोभकारी था वही चीनी राजदूत बैन जिली (Ban Zili) ने मई व अक्टूबर 1954 में नेपाल व भारत की दो बार यात्राएं करके नेपाल को आर्थिक सहायता देने की लालच देकर तिब्बत प्रश्न पर द्विपक्षीय सम्बन्धों के सामान्यीकरण की कूटनीतिक कोशिशें की। उधर, तिब्बत में अपने व्यापार से व्यथित नेपाल की आर्थिक दशा पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव व तिब्बत में केवल चीनी मुद्रा के

प्रचलन से स्थिति गम्भीर होती गयी किन्तु द्विपक्षीय वार्ताओं के परिणामस्वरुप तिब्बत में नेपाली व्यापार हेतु चीन द्वारा प्रारम्भ की गयी कुछ सुविधाओं से अन्ततः गतिरोध को शिथिल किया जा सका। यही कारण है कि नेपाल–चीन के मध्य व्यापार सन्धि करने हेतु प्रारम्भ द्विपक्षीय वार्ताओं के कारण न केवल नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता हेतु चीन का समर्थन किया अपितु तिब्बत में चीनी गतिविधियों सम्बन्धी विवाद में भी चीन के पक्ष में मतदान का बहिष्कार भी किया। इसी पृष्ठ भूमि में नेपाल के छः सदस्यीय बौद्ध प्रतिनिधिमण्डल ने चीन की यात्रा भी की। यह यात्रा चीन के 'बौद्ध संगठन' के आमन्त्रण पर सम्पन्न हुई। इतना होने के बावजूद वी0पी0 कोइराला के अभिन्न सहयोगी डॉ0 तुलसीगिरी एवं मार्च 1960 में वी0पी0 कोइराला की चीन यात्रा के बाद भी तिब्बत व भारत के सन्दर्भ में चीनी दृष्टिकोण की नेपाल ने आलोचना करते हुए कहा कि इन मुद्दों पर चीन का दृष्टिकोण अविश्वसनीय व अस्पष्ट है। उधर, नेपाल की प्रतिक्रिया पर ध्यान न देते हुए चीन ने कूटनीतिक कौशल व पड़ोसी–धर्म की पृष्ठभूमि में न केवल नेपाल के प्रति नरम दृष्टिकोण अपनाया अपितु नेपाल–चीन सीमा निर्धारण करने सम्बन्धी एक सन्धि करने के अतिरिक्त बीस किलोमीटर सीमान्त क्षेत्र के विसैन्यीकरण पर सहमति व्यक्त की। इतना ही नहीं, नेपाल को अपने निकट लाने हेतु चीन ने उसे 1956 के समझौते के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त 100 मिलियन डालर की धनराशि देने का भी संकल्प प्रकट किया।

माउण्ट एवरेस्ट का प्रश्न–

द्विपक्षीय सम्बन्धों में सामान्यीकरण प्रक्रिया के बावजूद चीन द्वारा माउण्ट ऐवरेस्ट पर अपना दावा प्रस्तुत करने से नेपाल–चीन सम्बन्धों को गहरा आघात पहुॅचा तथा प्रतिक्रियास्वरुप काठमाण्डू में चीन विरोधी प्रदर्शन हुए। नेपालियों की प्रतिक्रिया से हतप्रभ चीन ने द्विपक्षीय सम्बन्धों पर पहुॅचे आघात के निर्वारण हेतु सन 1960 में चाऊ एन लाई ने नेपाल यात्रा के दौरान इस विवाद के समाधान हेतु इस मुद्दे को संयुक्त सीमा आयोग (Joint demarcation Commission) [31] के माध्यम से हल हेतु नेपाल के समक्ष एक प्रस्ताव की

रुपरेखा अवश्य प्रस्तुत की किन्तु चीन के पर्वतारोही दल द्वारा अभियान की सफलता से एवरेस्ट पर चीनी दावे के कारण इस आशंका को पर्याप्त बल मिला कि वह इस महत्वपूर्ण पर्वत चोटी पर नेपाल के साथ नियन्त्रण सम्बन्धी संयुक्त दावों की ओर ही अग्रसर है।[32] तदुपरान्त, 28 जून 1960 को नेपाल–तिब्बत सीमान्त क्षेत्र पर स्थित मुस्तांग के विसैन्यीकृत क्षेत्र में चीनी सैन्य टुकड़ियों द्वारा नेपाल के निःशस्त्र पुलिस दल पर बिना किसी कारण किये गये फायर से नेपाल की भावनाओं को गहरा आघात पहुॅचा। इस घटना में सत्रह पुलिस कर्मियों की हत्या के विरोध में नेपाल ने आक्रोश व्यक्त किया तथा 'गण्डक मुद्दे' पर भी भारत के विरुद्ध नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में व्यापक प्रदर्शन हुए। नेपाल की सरकार ने न केवल चीन अपितु भारत को अपने विरुद्ध मानते हुए अपनी प्रतिक्रिया में संतुलित विदेशनीति संचालन का संकल्प लिया किन्तु इसी बीच 15 दिसम्बर 1960 को कोइराला मन्त्रिमण्डल को भंगकर दिया गया। उल्लेखनीय है कि कोइराला सरकार द्वारा अगस्त 1960 में नेपाल में चीनी दूतावास स्थापित करने की अनुमति तथा 21 मार्च 1960 को दोनों के मध्य सम्पन्न 'सीमा समझौते' के आलोक में सितम्बर 1960 में संयुक्त सीमा–आयोग द्वारा नेपाल–चीन सम्बन्धों में नये वातावरण का सूत्रपात हुआ तथा दोनों देशों के मध्य पंचशील के मूलाधार पर 28 अप्रैल 1960 को एक 'शान्ति व मैत्री सन्धि' सम्पन्न हुई। तत्पश्चात, राजा महेन्द्र शासन के शासन काल में नेपाल ने चीन के साथ सीमाओं के निर्धारण हेतु गम्भीर प्रयास किया तथा 25 सितम्बर, 1961 को सम्पन्न चीन की यात्रा के दौरान न केवल राजा महेन्द्र का भव्य स्वागत हुआ अपितु दोनों के मध्य 5 अक्टूबर 1961 को एक सीमा समझौता [33] हुआ तथा 15 अक्टूबर को तिब्बत व काठमाण्डू के मध्य सड़क निर्माण हेतु द्विपक्षीय सहमति भी बन सकी।[34] उक्त दोनों समझौतों से नेपाल व चीन के मध्य सन्निकटता व मैत्रीपूर्ण भावनाओं के फलस्वरूप रणनीतिक दृष्टि से चीन ने नेपाल के साथ सम्बन्ध स्थापित कर भारतीय सुरक्षा पर निर्णायक दबाव बनाने हेतु सुगमता प्राप्त कर ली जिसका प्रभाव भारत चीन सीमा–विवाद में स्पष्टतः परिलक्षित भी हुआ।

भारत–चीन सीमा विवाद एवं नेपाल–

नेपाल के महाराजा महेन्द्र की चीन यात्रा के पश्चात अक्टूबर 1962 में भारत–चीन सीमा संघर्ष का भारत, चीन व नेपाल के पारस्परिक सम्बन्धों पर व्यापक प्रभाव परिलक्षित हुआ। काठमाण्डू–कोदारी मार्ग निर्माण से सम्बन्धित चीन–नेपाल समझौते से जहॉ एक ओर भारत की रणनीतिक प्रक्रिया व उत्तरी सीमान्त क्षेत्रों के सुरक्षा परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा वहीं संघर्ष की परिस्थितियों में भारत द्वारा तिब्बत में प्रवेश हेतु सिक्किम व भूटान मार्गों के अवरुद्ध करने पर चीन उक्त वैकल्पिक मार्ग द्वारा सरलतापूर्वक तिब्बत की आपूर्ति व्यवस्था को नेपाल मार्ग से बनाये रखने में भी सक्षम हो गया। उधर, भारत में शरण लिए नेपाली कांग्रेस के नेताओं द्वारा राजा महेन्द्र के विरुद्ध किए जा शान्तिपूर्ण विरोधों से वे व्यथित थे। राजा महेन्द्र ने पं0 नेहरु से अपील कर भारत भूमि से उनके विरुद्ध संचालित गतिविधियों को रोकने की अपील की किन्तु पं0 नेहरु ने सन 1950 की भारत–नेपाल मैत्री सन्धि की मूल भावनाओं के आलोक में यह स्पष्ट कर दिया कि वे भारत में निर्वासित रुप से रह रहे नेपाली कांग्रेस नेताओं द्वारा चलाए जा रहे शान्तिपूर्ण प्रयत्नों पर अंकुश नहीं लगा सकते।[35] पं0 नेहरु की उक्त प्रतिक्रिया के परिणामस्वरुप नेपाल ने भारत के विरुद्ध चीनी प्रभाव का प्रयोग करते हुए न केवल भारतीय प्रयत्नों को गैरकूटनीतिक व अशोभनीय[36] बताया अपितु तिब्बत विद्रोहियों को मुस्तांग क्षेत्र में हवाई मार्ग से शस्त्र गिराये जाने का लॉछन भी भारत पर लगाया। इतना ही नहीं, खम्पा विद्रोहियों का सफलतापूर्वक दमन करने में अशक्त नेपाली सेनाओं की गतिविधियों से चिन्तित नेपाल ने चीनी सेनाओं के आमन्त्रण की इच्छा प्रकट की तथा नेपाली प्रेस व रेडियो ने नेपाल में भारत की छवि को धूमिल करने व चीन की छवि में सकारात्मक वृद्धि हेतु व्यापक अभियान भी चलाया। नेपाल द्वारा चीन के प्रति प्रकट मैत्रीपूर्ण भावनाओं व भारत–विरोधी प्रयत्नों के फलस्वरुप भारत द्वारा नेपाल को दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबन्ध लगाने से स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण हो गयी। उक्त परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीन ने नेपाल के साथ अपनी मैत्री की सुदृढ़ता व निरन्तरता का आश्वासन देते हुए कहा कि ''यदि कोई विदेशी सेना नेपाल पर

आक्रमण का प्रयत्न करती है तो चीन नेपाल का ही पक्ष लेगा''[37] किन्तु विभिन्न कूटनीतिक प्रयत्नों के फलस्वरुप भारत ने नेपाल के विरुद्ध लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्धों को हटाने के साथ–साथ नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने भी राजा महेन्द्र के विरुद्ध किए जा रहे प्रदशनों को स्थगित तो अवश्य कर दिया किन्तु उक्त घटनाओं में चीन के प्रति नेपाल की नीतियों से भारत–नेपाल सम्बन्धों पर दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

सन 1962 के भारत–चीन युद्ध से नेपाल–चीन सम्बन्धों मे नव प्रवर्तन युग की शुरुआत हुई जिसका नेपाल ने पर्याप्त राजनीतिक लाभ उठाने का हर सम्भव प्रयत्न किया। नेपाल के भू–सामरिक महत्व को देखते हुए भारत व चीन दोनों ही देशों ने अपनी राजनैतिक व आर्थिक नीतियों में अपेक्षित परिमार्जन तो अवश्य करने की कोशिश की किन्तु इससे स्पर्धात्मक कूटनीति के नये परिवेश का सृजन हुआ। फलतः, भारत के साथ अपने विविध सम्बन्धों की भेदनीयता एवं चीन के बढ़ रहे क्षेत्रीय प्रभाव को देखते हुए नेपाल ने अपने दोनों पड़ोसियों के साथ 'तटस्थ–नीति' पर ध्यान केन्द्रित किया। यही कारण है कि परिस्थितियों की जटिलता व गम्भीरता को देखते हुए भारत व चीन दोनों ने नेपाल को आर्थिक सहायता हेतु सुनिर्धारित व दीर्घकालीन नीति का अनुकरण करना उचित समझा। सन 1962 में चीन के हाथों भारत की हुई पराजय एक ऐसा कारक था जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व भू–राजनैतिक सम्बन्धी प्रकट भारतीय शिथिलता के फलस्वरुप नेपाल में चीन के प्रभाव में अभिवृद्धि के लक्षण प्रतीत हुए। चीन–नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्धों में उत्पन्न हो रही मैत्रीवत भावना के बावजूद नेपाल के साम्यवादियों के साथ चीनी सन्निकटता एवं चीन की आक्रामक मनोवृत्ति से चिन्तित नेपाल ने 1962 के पश्चात दोनों पड़ोसियों के साथ संतुलन स्थापना पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया।[38] उधर चीन ने नेपाल के प्रति किसी प्रकार का आक्रामक रुख तो नहीं अपनाया अपितु जून 1963 में चाऊ एन लाई ने यह अवश्य इच्छा प्रकट की कि नेपाल को चीन की अपेक्षा भारत से अच्छे सम्बन्धों की स्थापना व विकास पर बल देना चाहिए।[39] इस कालावधि में चीन ने न तो नेपाल के राजवंश की आलोचना की और न ही कम्युनिस्ट पार्टी को कोई प्रत्यक्ष सहयोग ही किया। यह चीन की परिपक्व

कूटनीति का ही परिणाम था कि नेपाल को आर्थिक सहायता देते हुए भी उसने नेपाल–भारत के आर्थिक व राजनैतिक आचारण पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। वास्तव में, चीन का मन्तव्य नेपाल को भारतीय प्रभाव–क्षेत्र से पृथक कर हिमालयी क्षेत्र में अपने सामारिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए मार्च 1965 व अगस्त 1966 में क्रमशः 'सीमा समझौते' व नये सड़क मार्ग के निर्माण सम्बन्धी समझौतों पर हस्ताक्षर कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का सद्प्रयास किया। फलतः नेपाल के युवराज वीरेन्द्र की सन 1966 के गर्मियों में नेपाल की यात्रा सम्पन्न हुई। इतना ही नहीं, इस अवधि में नेपाल व चीन के मध्य राजनैतिक, वाणिज्यिक व सामारिक पक्षों से सम्बन्धित प्रतिनिधि मण्डलों के पारस्परिक विमर्श से दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों की मधुरता का आधार निरन्तर सुदृढ़ होता गया। सन 1963–67 की कालावधि में नेपाल के प्रधानमंत्री तुलसीगिरि ने जनवरी 1963 में, 1963 में विश्वबन्धु थापा, व 30 मार्च 1965 से 3 मार्च 1965 तक चीन के विदेशमन्त्री एवं 1966 में राजा वीरेन्द्र की चीन यात्राएं उक्त परिप्रेक्ष्य में विशेषरुप से उल्लेखनीय हैं। इन यात्राओं से न केवल दोनों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सम्बन्धों में सद्भावना को बढ़ावा मिला अपितु क्षेत्रीय भू–राजनैतिक आयाम भी इनसे अप्रभावित न रह सके। इस काल में भारत के परिप्रेक्ष्य में चीन–नेपाल के मध्य बढ़ रहे द्विपक्षीय सम्बन्ध निश्चय ही महत्वपूर्ण व संवेदनशील माने जा सकते है।

चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति एवं नेपाल–

सन 1966 की चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति का चीन व नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्धों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। नेपाल में सक्रिय चीनी प्रतिनिधियों ने प्रचार का सहारा लेते हुए न केवल नेपालियों के मन–मस्तिक पर चीनी विचारधारा सम्बन्धी प्रभाव डालने की हर सम्भव कोशिश की अपितु काठमाण्डू–कोदारी मार्ग, सुनकोई विद्युत परियोजना एवं काठमाण्डू–पोखरा राजमार्ग परियोजनाएं चीनी प्रचार का प्रमुख केन्द्र थीं। तदनन्तर, माओ की लाल किताब (Red Book of Mao) का नेपाली भाषा में अनुवाद करके चीनियों ने नेपाल में व्यापक स्तर पर बॉटने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के छात्र–संघ में

चीन को सक्रिय भागीदारी [41] एवं नेपाल स्थित चीनी दूतावास के कर्मचारियों को चीन द्वारा वापस बुला लेने जैसी गतिविधियों से चीन–नेपाल सम्बन्धों में गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था।[42] चीन की बढ़ रही राजनीतिक महत्वाकाँक्षाओं का ही यह परिणाम था कि चीनी छात्रों व अधिकारियों ने कई अवसरों पर अमेरिकी पूंजीवाद, सोवियत परिशोधन एवं भारतीय प्रतिक्रियावादी नीतियों की कटु आलोचना करते हुए माओ को महिमामण्डित कर उन्हें न केवल चीन अपितु विश्व के सभी शोषित वर्गों का नेता बताया।[43] चीन की उक्त गतिविधियाँ एवं नेपाल में चीन के साम्यवादी तत्वों द्वारा अमेरिका, सोवियत संघ व भारत के विरुद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार एवं नेपालियों के मस्तिष्क–प्रक्षालन से आक्रोशित नेपाली छात्रों ने चीन के विरुद्ध काठमाण्डू में उग्र प्रर्दशन किया।[44] अन्ततः, चीन के विरुद्ध नेपाल में बढ़ रहे असन्तोष को दूर कर सम्बन्धों के सामान्यीकरण के उद्देश्य से मई 1968 में नेपाल के उप प्रधानमन्त्री कीर्ति निधि विष्ट की सम्पन्न बीजिंग यात्रा के अवसर पर माओ व चाऊ–एन–लाई से उनकी वार्ताओं के फलस्वरुप गतिरोध को शान्त व सामान्य किया जा सका।[45] वास्तव में, भारत–चीन युद्ध की प्रतिछाया से अभिप्रेरित होकर चीन द्वारा नेपाल के साथ सम्बन्धों का विस्तार करते हुए जहाँ एक ओर नेपाल को आर्थिक सहयोग देकर नेपाल की सरकार को स्थिरता प्रदान करने का उद्देश्य निहित था वहीं मूलतः भारत पर नेपाल की निर्भरता को शनैःशनै शिथिल कर नेपाल को अपने प्रभाव में लाने हेतु चीन अत्यन्त आतुर भी था। यही कारण है कि नेपाल–चीन मैत्री सन्धि 1960 की 9 वीं वर्षगॉठ के अवसर पर दोनों देशों ने वैचारिक व राजनैतिक वैषम्यता के बावजूद मैत्री–भावना को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया तथा जुलाई 1969 में राजदूत नियुक्ति से (1967 से नेपाल में कोई राजदूत नियुक्त नहीं था) नेपाल की राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता व सम्प्रभुता की सुरक्षा का संकल्प भी उद्घाटित हुआ। चीन–नेपाल की मैत्री का यह तत्कालिक प्रभाव ही था कि पहली बार नेपाल ने चीन के उकसाने व प्रोत्साहन के कारण ही काठमाण्डू स्थित 40 सदस्यीय भारतीय सैन्य सम्पर्क दल को भारत द्वारा वापस बुलाने की मॉग की।[46] इतना ही नहीं, नेपाल के राजा के विरुद्ध नेपाल में सक्रिय प्रजातान्त्रिक तत्वों के कारण वहॉ व्याप्त अस्थिरता का

कूटनीतिक लाभ उठाते हुए चीन ने भारत की ओर इशारा करते हुए यह इच्छा व्यक्त की कि नेपाल में सक्रिय विदेशी तत्वों को वहाँ से हट जाना चाहिए किन्तु चीन द्वारा व्यक्त इस प्रतिक्रिया का नेपाल की मीडिया व नेपाली जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा तीव्र विरोध किया गया।[47] चीन द्वारा व्यक्त उग्र प्रतिक्रिया से आन्दोलित जहॉ एक ओर नेपाली समाचार पत्रों ने वर्मा, इण्डोनिशया व मलेशिया में हुए दंगों में चीन की भूमिका को उत्तरदायी बताया वहीं नेपाल में सन 1970 में उक्त प्रतिक्रिया के फलस्वरुप नेपाल–तिब्बत सीमान्त क्षेत्र व काठमाण्डू–कोदारी मार्गों के निकट स्थापित माओ की प्रतिमाओं को हटा दिया गया। तदुपरान्त, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य सम्पन्न वार्ताओं के पश्चात द्विपक्षीय सम्बन्धों के सामान्य बनाया जा सका। उल्लेखनीय है कि इस कालावधि में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय पहचान व हैसियत की तलाश में सक्रिय चीन ने एशियाई देशों, विशेषकर नेपाल को ही अपना केन्द्र बनाकर इस देश में बढ़ रहे भारतीय प्रभाव को न्यून करने की कोशिश की जिससे धीरे–धीरे अमेरिका पूंजीवाद व सोवियत प्रभाव को शिथिल किया जा सके। क्रान्तिकारी उपायों को अपनाते हुए चीन ने अपने शत्रु के शत्रु देशों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया तथा नेपाल को भारत–विरोधी आधार बनाकर वहाँ के नवयुवकों के मन–मस्तिष्क में भारत–विरोधी विचारधाराओं को प्रत्यारोपित करने में कोई कसर न छोड़ी। सन 1970 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रों द्वारा किये गये भारत–विरोधी प्रदर्शन चीन की उक्त रणनीति का ही परिणाम थे जिसमें चीन ने भारत व नेपाल के मध्य तत्समय व्याप्त व्यापारिक गतिरोध को प्रचारित करके नेपाल में भारतीय हितों पर चोट पहुॅचाने की हर सम्भव कोशिश की।

नेपाल के तराई क्षेत्र में कपास उत्पादन हेतु चीन–नेपाल के मध्य सम्पन्न एक समझौते एवं इसकी आड़ में भारत–नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्र में चीन की संदिग्ध गतिविधियों से जहॉ एक ओर भारत–नेपाल सम्बन्धों में तनाव को बढ़ावा मिला वहीं भारतीय सुरक्षा के विरुद्ध संचालित चीनी गतिविधि को ध्यान में रखकर भारत के तत्कालीन रक्षा मन्त्री स्वर्ण सिंह ने नेपाल में सक्रिय भारत–विरोधी तत्वों पर प्रहार करते हुए इस सीमान्त क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सतर्कतापूर्ण कदम उठाने के साथ–साथ नेपाल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों

को सुदृढ़ करने की हर सम्भव कोशिश की। जनवरी 1972 में नेपाल के महाराजा महेन्द्र की मृत्यु के पश्चात शासनारुढ़ महाराजा वीरेन्द्र ने भी चीन के प्रति सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की हर सम्भव कोशिश करते हुए कृषि, उद्योग, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा आदि क्षेत्र में सहयोग यथावत जारी रखा। शीत युद्ध की इस अवधि में तृतीय विश्व के देशों के बढ़ रहे प्रभाव के कारण नेपाल के माध्यम से चीन अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता व प्रभाव–विस्तार हेतु अत्यन्त व्यग्र था। सन 1974 में सिक्किम को भारत में सम्मिलित करने सम्बन्धी गतिविधियों को न केवल चीन ने भारत की विस्तारवादी नीति का अंग माना अपितु उसने नेपाल को भी सर्तक रहने की अपील की।[48] नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के राजदूत ने जहॉ एक ओर सिक्किम सम्बन्धी चीन के बयान पर घोर आपत्ति की वहीं भारत–विरोधी प्रचार हेतु नेपाल की भूमि का प्रयोग करने सम्बन्धी चीन की गतिविधियों की तीव्र भर्त्सना भी की। सन 1974 के मध्य में नेपाल के उत्तरी भू–भाग में रह रहे तिब्बत के खम्पा शरणार्थियों (Khampa Refugees) के विरुद्ध नेपाल द्वारा चीनी दबाव में की गयी सैन्य कार्यवाही से भी नेपाल केन्द्रित भारत–चीन सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि चीन ने भारत पर यह निरर्थक आरोप लगाया कि उक्त शरणार्थियों को तिब्बत–विरोधी कार्य करने हेतु भारत उन्हें अभिप्रेरित कर रहा है। [49] परिस्थितियों की गम्भीरता को देखते हुए नेपाल के महाराजा वीरेन्द्र ने 25 फरवरी 1975 को समता, गुटनिरपेक्षता व मैत्री के मूलाधार पर भारत व चीन दोनों से सहयोगात्मक सम्बन्धों को आवश्यक बताते हुए नेपाल को 'शान्ति–क्षेत्र' घोषित करने की अपील की जिससे उसकी सम्प्रभुता व अखण्डता को अक्षुण्य रखा जा सके।[50] नेपाल के तत्कालीन विदेश मन्त्री कृष्णा राज आर्यल ने 23 मई 1975 को भारत के एक पत्रकार को दिये गये साक्षात्कार में अपनी दुविधा को स्पष्ट करते हुए यह कहा कि ''चीन हमें भारत का निकटतम सहयोगी मानता है वहीं भारत हमें चीन के पक्ष का निकट सम्बन्धी मानता है।''[51] सम्भवतः यही कारण था कि नेपाल को ''शान्ति–क्षेत्र'' घोषित करने में उसने भारत से सकारात्मक पहल का

अनुरोध करते हुए कहा कि चीन व सोवियत संघ ने नेपाल के प्रस्ताव का स्वागत किया है।[52]

सन 1976 में चीनी नेता माओत्से तुंग की मृत्यु के फलस्वरुप 1976–78 की कालावधि में वहॉ प्रारम्भ सत्ता संघर्ष के कारण चीन की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। त्वरित आर्थिक एवं आधुनिकीकरण की नीति अपनाने हेतु व्यग्र एवं वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन पर ध्यान केन्द्रित करने के बावजूद चीन–नेपाल सम्बन्ध यथावत बने रहे। जून 1976 में नेपाल के महाराजा वीरेन्द्र ने चीन यात्रा के दौरान उसके साथ अपने सम्बन्धों में प्रगाढ़ता बनाये रखने की पुनः इच्छा व्यक्त की जबकि चीनी नेता देंग सियाओपिंग ने 1978 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल के 'शान्ति–क्षेत्र प्रस्ताव' के समर्थन के साथ–साथ उसे हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया। इन यात्राओं के दौरान दोनों ही देशों ने किसी प्रकार के भारत–विरोधी बयानों से तो किनारा रखा ही साथ ही देंग ने भारत के साथ भी सम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण बनाने की भी इच्छा व्यक्त की। उधर, भारत ने क्षेत्रीय जल संसाधनों हेतु क्षेत्रीय विकास के चीनी उत्सुकता को यह कहकर खारिज कर दिया कि चीन दक्षिण एशिया का राष्ट्र नहीं है[53] इसलिए उसे इसमें पक्षकार बनने का कोई आधार नहीं है।

References:

1. Bhatt, S.C. The Triangle : India-Nepal-China, Gyan Publishing House, New Delhi, P-11.
2. Ibid.
3. Huang, Sheng-Chang, "China and Nepal", People's China, 1 May, 1956, P-8.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Chinese interest in Nepal was largely due to their religious affinity, as China also had a large Buddhist population and naturally Chinese showed great interest in getting information about the life and times of Gautam Buddha and the culture and traditions of his native place.

   -T.R.Ghoble, China-Nepal Relations and India, Deep & Deep, New Delhi, 1991, P
7. Huang Sheng Chang, No.3, P-9.
8. Leo E. Rose, Nepal : Strategy for Survival, Barkeley,1971, P.10.
9. Charles Bell; Tibet : Past and Present, Charendor Press, Oxford, 1924,P-23.
10. Radhakrishna Choudhary, "Nepal and the Karnates of mithila"(1097-1500A.D.),Journal of Indian History, xxxvi, 1 April, 1958,P-130.
11. Leo E. Rose, Nepal : Strategy for Survival, Berkeley, 1971, P-10.
12. Asad Husain, British India's Relation with the Kingdom of Nepal, 1857-1947, George Allen Ltd., London, 1970, P-257.
13. Leo E. Rose, Nepal : Strategy for Survival, P.75-79.

14. Convention signed between Great Britain and Russia on 31 August, 1907 in Dalai Lama XIV, The International Positi on of Tibet (1959), P-39.
15. The Chinese interest in Nepal began with the Tibet faction. At a minimum, these objectives are the security of Chinese interests in Tibet as that region is dependent on the neighbouring countries for border trade. Kumar Ashutosh; China Factor in Nepal, Sumit Enterprises, New Delhi, P-28.
16. "The buffer position coupled with its mountaineous topography gives it a striking resemblance to Switzerland in Europe, which has attracted the attention of Others."
17. P.P.Karan and W.H.Jenkins, Nepal : A Cultural and Physical Geography (Lexington, 1960).
18. Nepal is a sandwitch between two giant countries and is strategically located to play the role of a buffer.

    T.R.Ghoble : China-Nepal Relations and India, Deep & Deep Publicaitions, New Delhi, 1991, P-38.
19. Apart form our sympathetic interest in Nepal, we are also interested in the security of our country. From time immemorial the Himalayas have provided us with a magnificent frontier. ofcourse, they are no longer as impassable as they used to be, but they are still fairly effective. We cannot allow that barrier to be penetrated because it is also the principal barrier to India.

    J.L.Nehru : India's Foreign Policy ; Selected speeches, Sept-April 1946-April 1961, New Delhi, 1971, P-436.
20. Stuart R.Schram, The Political Thoughts of Mao Zedong, Newyork, 1963 P.266.

21. Girilal Jain, "Tibetans under Communism" in Panchsheel and After, Bombay, Asia Publishing House, New Delhi, 1960, P.54
22. The Statesman, 17 January 1952, Ministry of External Affairs Report 1953-54, P-8.
23. Amrit Bazar Patrika (Calcutta), 16 November, 1949.
24. Grishma Bahadur Devakota, Nepal ko Rajneetik Darpan (Kathmandu, 1959), P.247.
25. The Times of India, 14 November, 1954.
26. The Statesman, 7 April 1954.
27. Foreign Policy of India : Text of Documents 1947-59 (Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 1966, P.103
28. The Hindustan Times, 8 May, 1954.
29. The Hindu, 15 November, 1954.
30. George N.Patterson, Tibet in Revolt, Faber and Faber, London, 1960.
31. Nepal Samachar; 8 April 1960.
32. Beijing Review, 31 May 1960, p.4.
33. Gorkhapatra, 6 Oct. 1961.
34. Nepal Samachar 16, Oct. 1961.
35. Nehru explained that, "When he met king last, and had been asked for advice, he had told the king that India did not desire to enterfere in Nepal's affairs, but the conditions could be improved only by being conciliatory. Further he mentioned that India had made clear that she did not want the country to be made a base for operating against the Nepal Government. But, India, under her laws, couldnot prevent Nepalese in India from peacefully expressing their openions."The Hindu, 11 September, 1962.

36. S.P.Gyawali, Friendship on Trial,(The Education Press, Kathmandu, Published by the Department of Publicity and Broadcasting, Ministry of National Guidance HMG,n.d.).
37. Beijing Review, 12 Oct. 1962.
38. T.R.Ghoble, China-Nepal Relations and India, Deep & Deep Publication, New Delhi, 1991, p.51.
39. "We shall be Very glad if Nepal has better relation with India than with China"- The Motherland, 10 June 1963.
40. Beijing Review, 9 Oct. 1964, p.17.
41. The Times, London, 22 June 1968.
42. The Times of India, 18 June 1967.
43. "Mao Zedong is not the leader of China alone. To us he is the leader of all exploited people". Beijing Review, 10 March 1967, p. 28.
44. Nepal Press Digest, 2-8July 1968.
45. Beijing Review, 31 May 1968.
46. Lok Saba Debates, 21 July 1969, Cols.230-40.
47. The Times of India, 13 Sep. 1969.
48. "We would be more vigilant againt our southern border". Statement ofP.C.Lahari, Member of Nepalese Panchayat members.
49. The Hindustan Times, 24 July 1974.
50. Gorakhapatra, 26 Feb. 1975.
51. The problem is that China seems to think that Nepal is closer to India while India sees Nepal as being on the Chinese side".- Rising Nepal, 25 May, 1975.
52. Patriot, 2 June 1975.
53. The Hindustan Times, 7 Feb. 1978.

अध्याय – 4

चीन–नेपाल सम्बन्धों के आर्थिक व रणनीतिक आयाम

28 अप्रैल, 1960 को नेपाल व चीन के मध्य हस्ताक्षरित 'शान्ति व मैत्री सन्धि' के उपरान्त दोनों पड़ोसियों के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्धों को नूतन ऊर्जा प्राप्त हुई। इस सन्धि के फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य व्यापार व अन्य सम्पर्कों की स्थापना अत्यन्त दुरूह होते हुए भी दक्षिण एशिया के भू–राजनैतिक व रणनीतिक आयामों से न केवल प्रभावित हुई, अपितु 21 मार्च, 1960 के नेपाल–चीन सीमा समझौते के बाद द्विपक्षीय सम्बन्धों को नया आयाम मिला। चीन द्वारा नेपाल के 'शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव' का समर्थन व शस्त्र–आपूर्ति की शुरूआत का सिलसिला नेपाल की माओवादी इन्सरजेन्सी (1996–2006) के पश्चात त्वरित ढंग से प्रारम्भ हुआ। चीन के माओवादी विचारों से सन्निकता के कारण नेपाल में न केवल माओवादी आंदोलन सफल रहा अपितु हिन्दू राष्ट्र के पतन के पश्चात नेपाल की प्रजातान्त्रिक सत्ता के साथ चीन की आर्थिक–सामरिक निकटता से भारत–नेपाल सम्बन्ध भी अप्रभावित न रह सके। क्षेत्रीय सामरिक जटिलता का ही यह परिणाम है कि भारत–नेपाल–चीन के उभयपक्षीय सम्बन्धों में आज भी सहजता के लक्षण प्रतीत नहीं हो रहे हैं।

चीन–नेपाल आर्थिक सहयोग–

सन् 1788 एवं 1791 में नेपाल व तिब्बत के मध्य सम्पन्न दो युद्धों से नेपाल व चीन सम्बन्धों को गहरा आघात पहुँचा तथा नेपाल के महाराजा बहादुर शाह द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी से शस्त्र–आपूर्ति की अपील से स्थिति अत्यन्त ही विस्फोटक हो गयी। कालान्तर में दोनों ही देशों ने क्षेत्रीय सामरिक व राजनैतिक आयामों की विशिष्टता एवं उभयपक्षीय हितों को ध्यान में रखकर परिस्थितियों को सामान्य बनाने की गम्भीर पहल थी। परिणामस्वरूप, तिब्बत व नेपाल के व्यापारिक सम्बन्धों के महत्व को देखते हुए तिब्बत–समस्या के दूरगामी प्रभावों व परिणमों के परिप्रेक्ष्य में चीन ने संतुलन स्थापित करने का हर सम्भव प्रयत्न किया। तिब्बत में हुए विद्रोह एवं उस पर चीन द्वारा अधिपत्य स्थापित करने की पृष्ठभूमि में नेपाल व चीन के मध्य 20 सितम्बर, 1956 को

एक व्यापारिक सन्धि हुई जिससे दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों को नयी ऊर्जा प्राप्त हुई। सन् 1950 में हुए कोरियाई युद्ध में चीनी हस्तक्षेप से उस पर लगे प्रतिबन्धों का ही परिणाम था कि उसने अपनी विदेश नीति के आर्थिक पक्ष को शीर्षता पर रखकर नेपाल के माध्यम से अपने आर्थिक–व्यापारिक क्षितिज को विस्तृत करने हेतु गम्भीरता के साथ सुविचारित कदम उठाये। उल्लेखनीय है कि सन् 1960 में सोवियत तकनीशियनों की चीन से वापसी से व्यथित उसने पश्चिमी देशों से आयात नीति को प्राथमिकता देते हुए जो भी कदम उठाये उसके फलस्वरूप उसका सम्पूर्ण व्यापार सन् 1950 में 1.2 बिलियन डालर की तुलना में बढ़कर 1959 में 4.3 बिलियन डालर हो गया। गैर–साम्यवादी देशों की सहायता योजना के अन्तर्गत भी चीन ने गम्भीर कदम उठाये। 1956 से प्रारम्भ चीनी सहायता रणनीति के अन्तर्गत नेपाल के अतिरिक्त चीन ने सेण्टों व सीटों के सदस्य पाकिस्तान पर भी अपना विशेष ध्यान केन्द्रित किया। पूर्णतः भारतीय सहायता पर निर्भर व तटस्थ देश नेपाल की भू–राजनैतिक व भू–रणनीतिक विशिष्टता के कारण अपने प्रभाव–क्षेत्र में लाने की उसकी भावनाओं का ही परिणाम था कि नेपाल व चीन में मध्य व्यापारिक सम्बन्ध मधुर होने लगे। 7 अक्टूबर, 1956 व 21 मार्च 1960 को नेपाल व चीन के मध्य सम्पन्न सहायता समझौते (Aid Agreements) उक्त दृष्टि से सर्वथा उल्लेखनीय हैं। दोनों देशों ने उक्त समझौतों के आधार पर पारस्परिक व्यापारिक एजेन्सियों की स्थापना (Shigetse, Kirong and Nyalam etc) करके व्यापारिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में गम्भीर कदम उठाये।

सन् 1962 में भारत–चीन युद्ध में हुई भारत की पराजय से चीन–नेपाल सम्बन्धों में मधुरता के लक्षण दिखाई देने लगे। फलतः 19 मई, 1964 को नेपाल व चीन के मध्य काठमाण्डू में द्विवर्षीय व्यापारिक समझौता सम्पन्न हुआ जिसके अन्तर्गत दोनों देशों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 30 किमी0 के क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के मध्य होने वाले पारम्परिक व्यापार को यथावत जारी रखाने का निर्णय हुआ। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 1956 में सम्पन्न सन्धि की ही पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार व अन्य सम्बन्धों को गतिशीलता प्रदान करने हेतु काठमाण्डू व ल्हासा में वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना का

महत्वपूर्ण निर्णय तो अवश्य लिया किन्तु व्यापारिक आयात–निर्यात में अपेक्षानुकूल वृद्धि सम्भव न हो सकी। फलतः, पारस्परिक सहमति से चीन व नेपाल को व्यापारिक एजेन्सियों की गतिविधियों को बन्द करना पड़ा। तदुपरान्त मई, 1959 में चीन ने नेपाल को 80,00,00 पौण्ड मूल्य की[1] कृषि निर्माण सामग्री व उपभोक्ता सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात का निर्णय तो लिया ही साथ ही द्विपक्षीय व्यापार हेतु स्थलीय व सामुद्रिक मार्गों के प्रयोग पर भी सहमति हुई जिसके अन्तर्गत तिब्बत–कोदारी–रासुआ–यारी मार्गों (Tibet vz-kodari-Rasuwa-yari) द्वारा व्यापार को प्राथमिकता दी गयी। इस व्यवस्था के फलस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार में 1975 तक लगभग 24 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली। जहाँ तक नेपाल व चीन के मध्य आयात–निर्यात का प्रश्न है चीन नेपाल को निर्मित विविध सामान व मशीनें, कपड़े, सीमेण्ट, तेल, रसायन, सौंदर्य प्रसाधन, खेलकूद के सामान आदि निर्यात करता रहा है जबकि नेपाल चीन को जूट, चीनी, टिम्बर, चमड़े, जूते, चाय व मेडिकल वनस्पतियों आदि का निर्यात करता है। उक्त के बावजूद भारत ही नेपाल का प्रमुख व्यापारिक साझीदार है जबकि चीन का व्यापार सन् 1975 से 1978 तक मात्र 1 प्रतिशत ही रहा।[2] भौगोलिक अवरोधों के परिणामस्वरूप चीन व नेपाल के मध्य व्यापारिक गतिविधियों को भारत–नेपाल के अनुरूप न तो ऊर्जा और न ही इनमें अपेक्षित गतिशीलता ही उत्पन्न हुई। उल्लेखनीय है कि नेपाल में निहित चीन के व्यापारिक पक्षों के अतिरिक्त भारत के विरूद्ध नेपाल में उसके सामरिक हित ही प्राथमिकता में रहे क्योंकि भारत व चीन के मध्य स्थित नेपाल की भू–सामरिक अवस्थिति का सामरिक लाभ उठाना ही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। यही कारण है कि 1956 से ही चीन की अनुदान सम्बन्धी उसकी कूटनीति के अन्तर्गत नेपाल में निम्नांकित परियोजनाओं की शुरूआत करने में वह सफल रहा–

1. काठमाण्डू–कोदारी मार्ग–

आरनिका रेड (Arnica Road) नाम से चर्चित इस सड़क के निर्माण हेतु नेपाल व चीन के मध्य 15 अक्टूबर, 1961 को समझौता सम्पन्न हुआ जिसके द्वारा चीन के तिब्बत क्षेत्र व काठमाण्डू को जोड़ने का परम उद्देश्य

था। ल्हासा–काठमाण्डू को जोड़ने वाले इस मार्ग हेतु चीन ने 3.5 मिलियन पौण्ड की धनराशि प्रदान की। 26 मई, 1967 को नेपाल के तत्कालीन महाराजा महेन्द्र द्वारा उद्घाटित 104 किमी0 लम्बे इस सड़क मार्ग का सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व है। चीन द्वारा विशिष्ट अभिरूचि से निर्मित इस सड़क के सामरिक महत्व व इससे प्रभावित भारत के सुरक्षा हितों के मद्देनजर भारत व सोवियत रूस ने भी चीन के निहित मन्तव्यों की तीव्र आलोचना की थी। 13 जुलाई, 1967 को सोवियत जरनल (Literaturanaya Gazeta) में "Mao's Shadow over the Himalaya" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में इस पर विधिवत प्रकाश डाला गया।[3]

2. काठमाण्डू–भक्तापुर सड़क–

16 किमी0 लम्बा यह सड़क मार्ग भक्तापुर–कोदारी मार्ग के पश्चिम में स्थित है जिसके लिए नेपाल व चीन के मध्य 27 सितम्बर, 1968 में समझौता हुआ जिसे 1970 में पूरा कर लिया गया।[4]

3. काठमाण्डू–पोखरा राजमार्ग–

'पृथ्वी हाइवे' के नाम से विख्यात 176 किमी0 इस सड़क के निर्माण हेतु चीन व नेपाल के मध्य 29 अगस्त, 1965 में समझौता हुआ। यह त्रिशूली नदी के किनारे–किनारे पोखरा तक विस्तृत है। सन् 1974 में इसका निर्माण पूरा हो गया।

4. रिंग रोड–

चीन व नेपाल ने 20 मार्च, 1973 को भक्तापुर व पटारी को जोड़ते हुए काठमाण्डू घाटी के बाहर इस रिंग रोड को निर्मित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इस रिंग रोड द्वारा भारत व चीन द्वारा निर्मित क्रमशः त्रिभुवन राजपथ व कोदारी मार्ग को जोड़ा गया है। 30 किमी0 लम्बी यह रिंग रोड सन् 1977 में पूरी हो गयी जिससे वन्सबारी, गंगाबू, स्वयंभू व त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर को जोड़कर यातायात दबाव को कम करने की कोशिश की गयी है।

5. पोखरा–सुरखेत रोड–

90 करोड़ रू0 की लागत से 407 किमी0 लम्बे इस मार्ग को निर्मित करने हेतु चीन व नेपाल के मध्य 2 फरवरी, 1975 को एक समझौता हुआ था। इस मार्ग के निर्माण हेतु चीन ने इन्जीनियर्स व अन्य तकनीकी सहायकों को उपलब्ध कराकर इसका निर्माण कराया। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सड़क नेपाल हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

6. चमड़ा उद्योग–

नेपाल में चमड़ा व जूते के उत्पादों के विकास व उत्पादन हेतु चीन ने काठमाण्डू के निकट वान्सबारी में एक उद्योगशाला की स्थापना 1965 में की। यहाँ जूते व चमड़े की अन्य वस्तुओं को निर्माण करके उनका निर्यात भी किया जा रहा है।

7. ब्रिक व टाइल्स फैक्ट्री–

काण्माण्डू से पाँच किमी0 दूर स्थित हरिसिद्धी में चीन ने इस फैक्ट्री की स्थापना की जहाँ सन् 1969 से उत्पादन कार्य हो रहा है। इस फैक्ट्री हेतु आवश्यक कोयले की आपूर्ति भारत सरकार कर रही है। 5 जुलाई, 1974 को काण्माण्डू से 15 किमी0 दूर स्थित सूर्य विनायक नामक स्थल पर चीन के सहयोग से नेपाल में दूसरी उद्योगशाला भी प्रारम्भ की गयी।

8. जल विद्युत संयन्त्र–

नेपाल के ऊर्जा हितों की पूर्ति हेतु जल विद्युत केन्द्रों की स्थापना में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 25 मई, 1964 व 25 मई, 1967 को चीन ने नेपाल में सनकोसी (Sunkosi) जलविद्युत संयन्त्र की स्थापना हेतु एक समझौता किया तथा 10,000 किलोवाट का यह संयन्त्र 24 नवम्बर, 1972 में पूर्ण कर लिया। तदुपरान्त, 1000 किलो वाट के दूसरे संयन्त्र की स्थापना हेतु भी चीन ने नेपाल को विभिन्न तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की। यह संयन्त्र पश्चिमी नेपाल में पोखरा के निकट सेती नदी क्षेत्र में सक्रिय है।

नेपाल में बहने वाली लगभग 600 नदियों में उपलब्ध जलसंसाधनों का सदुपयोग कर जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई व पीने योग्य जल उत्पादन करना तकनीकी अकुशलता के कारण उसके लिए गम्भीर चुनौती है। यद्यपि नेपाल की

गरीबी–उन्मूलन नीतियों में जल संसाधन की निर्णायक भूमिका हो सकती है, किन्तु वाहय तकनीकी व आर्थिक सहयोग के बिना यह कार्य नेपाल के लिए दुष्कर है। इस हेतु उसने चीन व भारत का अप्रतिम सहयोग लिया है। कोसी, गण्डकी, करनाली, मेंची व महाकाली के अतिरिक्त अन्य नदियाँ नेपाल में लगभग 45,000 किमी0 लम्बाई में फैली हैं तथा ये लगभग 3,95,000 हेक्टेयर, क्षेत्रफल को आच्छादित करती हैं। सभी नदियों के जल संसाधनों के सदुपयोग हेतु नेपाल कई राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों (NGO) की सहायता व सहयोग से नेपालियों को पीने हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध करा रहा है। नेपाल में जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख संयन्त्र निम्नांकित हैं–

- Kaligandaki (144MW)
- Middle Marsyangdi (70MW)
- Marsangdi (69MW)
- Kulekhani (60MW)
- Khimti I (60MW)
- Upper Marsangdi A(50MW)
- Upper Bhote Koshi (45MW)
- Kule Khani II (32 MW)
- Chameliya(30MW)
- Trishuli (24MW)
- Chilime (22MW)
- Upper Tamakoshi (456 MW)
- Rasuwgadi (111MW)
- Middle Bhote Koshi (102 MW)
- Lower Solu (82MW)
- Trishuli 3 A(60 MW)
- Khani Khola (25 MW)
- Kule Khani III(14MW)

- Karnali Chisapani (10,800 MW)
- Pancherwor (7480 MW)
- Budhi Gandaki (1200 MW)
- Arun III(900 MW)
- West Seti (750 MW)
- Dudhkoshi (300 MW)
- Upper Karnali (300 MW)
- Kabeli A (30 MW)
- Khimti (27MW)
- Upper Modi (14MW)

नेपाल की सिंचाई परियोजनाएं–

अत्याधुनिक तकनीकी कौशल के अभाव में जलविद्युत उत्पादन एवं कृषि हेतु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में नेपाल की विवशता उसके लिए गम्भीर चुनौती है। यही कारण है कि उसने भारत व चीन से सहायता प्राप्त कर जलविद्युत उत्पादन एवं विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु गम्भीर प्रयत्न किये है। यद्यपि 83,000MW जल विद्युत उत्पादन क्षमता से सुसम्पन्न नेपाल में इस समय मात्र 22,500 मेगावाट विद्युत उत्पादक हो रहा है तथापि चीन द्वारा उक्त उत्पादन में प्रदर्शित अभिरूचि से शनैःशनैः नेपाल अपने कदम बढ़ा रहा है। पर्यटन व कृषि पर आधारित नेपाल की अर्थव्यवस्था की समृद्धि कृषि–सिंचाई पर आधारित है क्योंकि यहाँ की 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर ही अवलम्बित है। हिमालय से निकलकर नेपाल में बहने वाली नदियाँ ही सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं जिन पर बाँधों के निर्माण द्वारा सिंचाई के कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल की नदियाँ प्रति सेकेण्ड 7,124 क्यूविक मीटर जल प्रवाह से सुसम्पन्न है किन्तु नेपाल की वार्षिक जल संचय क्षमता 202,000 मिलियन क्यूविक मीटर है। नेपाल में सिंचाई का क्षेत्रफल 395,000 हेक्टेयर है तथा नदियों की लम्बाई 45,000 किमी0 है। कोशी, गण्डकी, करनाली, मेंची व महाकाली नदियाँ जल का प्रमुख स्रोत हैं जो सिंचाई, जल

विद्युत व पीने योग्य पानी उपलब्ध कराती हैं। नेपाल की निम्नांकित सिंचाई परियोजनाएँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है जिनके निर्माण में चीन ने पर्याप्त सहायता की है–

1. Surkhet Valley Irrigation Project.
2. Bagmati Irrigation Project.
3. Babai Irrigation Project.
4. Mahakali Irrigation Project.
5. Rajpur Irrigation Project.
6. Birganj Irrigation Project.
7. Sunsari Morang Irrigation Project.
8. Praganna and Badhka Irrigation Project.
9. Sikta Irrigation Project.
10. Daraudi Paluntar Irrigation Project.

उक्त के अतिरिक्त नेपाल के तराई क्षेत्र के 22 जिलों में कुओं व ट्यूबवेलों के निर्माण हेतु भी नेपाल सक्रिय है। हाइड्रोपावर व सिंचाई परियोजनाओं की तुलना में जल–आपूर्ति क्षेत्र में नेपाल को चीन का सहयोग पर्याप्त सीमित है तथापि फरवरी 2008 में चीन ने नेपाल में 'Melamchi Water Supply Project' हेतु एक महत्वपूर्ण सुरंग के निर्माण हेतु समझौता किया है जिस पर कार्य चल रहा है। SAARC व BIMSTEC का सदस्य होने के कारण नेपाल के जलविद्युत उत्पादन व सिंचाई सुविधाओं के निर्माण व विस्तार में भारत भी गम्भीर कदम उठा रहा है जिससे नेपाल पर बढ़ रहे चीनी–शिकंजे से उसे मुक्त करके अपने उत्तरी सीमान्त की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। निम्नांकित तालिका से इसकी पुष्टि होती है–

Possible future cross Border Transmission amid Nepal-India-Bangladesh:

By Year	**Nepal-India(MW)**	**India-Bangladesh (MW)**
2021-22	200	500
2026-32	6100	1500
2031-32	12500	2000
2035-36	15800	2000

उक्त तालिका से पुष्ट है कि नेपाल, भारत व बांग्लादेश की संयुक्त परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास को नवीन गति प्रदान कर सकती हैं। चीन ने उत्तरी सीमान्त क्षेत्र में शिगास्ते में उच्च क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन स्थापित की हैं जिसे वह नेपाल के केरुंग (Kerung) तक विस्तृत करने हेतु प्रयत्नशील है। चीन के स्टेट ग्रिड कारपोरेशन (SGCC) ने सन् 2017 में नेपाल के सिंचाई, जल संसाधन, ऊर्जा व विद्युत एथोरिटी के साथ गम्भीर विमर्श करते हुए रसुवागढ़ी व केरूंग को जोड़ने हेतु कदम उठाए हैं जिससे नेपाल को विद्युत सुविधा मिलने के साथ–साथ चीन के रेलवे के सम्पर्क संचालन हेतु भी अपेक्षित बिजली प्राप्त हो सकेगी जो अन्ततः उसकी 'वेल्ट व रोड' परियोजना के लिए भी हितकर होगी। उल्लेखनीय है कि नेपाल के समृद्ध जल संसाधन का दोहन कर जहाँ एक ओर चीन अपेक्षित लाभ प्राप्त करने हेतु गम्भीर है वहीं विभिन्न संयन्त्रों को आर्थिक व तकनीकी सहायता देकर वह नेपाल के इस महत्वपूर्ण संसाधन पर नियन्त्रण की कोशिश भी कर रहा है जिससे भारत–नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्धों में दरार उत्पन्न कर अपने आर्थिक व सामरिक हितों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नही, विम्सटेक की योजनानुसार नेपाल–बांग्लादेश के मध्य हुए 'विद्युत–उत्पादन व व्यापार समझौते' के अतिरिक्त भारत–नेपाल के धालकेबार–मुजफ्फरपुर (Dhalkebar-Muzafferpur) 'ट्रांसबाउण्ड्री ग्रिड' की उपलब्धियों को चीन निष्क्रिय करके नेपाल के `जल संसाधन के दोहन की जो कोशिश कर रहा है उस सन्दर्भ में भारत को आर्थिक व कूटनीतिक दृष्टि से पर्याप्त सतर्क रहकर नेपाल के साथ अपने उभयपक्षीय रिश्तों को शिथिल होने से बचाना होगा।

रेल–विस्तार सम्बन्धी सहयोग–

चीन द्वारा अपने रेलवे नेटवर्क को तिब्बत में विस्तृत करने हेतु की जा रही गतिविधियों के सन्दर्भ में जहॉ एक ओर त्वरित कदम उठाये हैं वहीं ल्हासा–खासा के 770 किमी0 लम्बे रेलवे विस्तार हेतु 2007–08 में नेपाल के साथ समझौता किया है जिससे तिब्बत व नेपाल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा सके। इतना ही नहीं, इस परियोजना को सन् 2020 तक चीन पूर्ण करने हेतु

तत्पर है तथा अगस्त 2014 में ही चीन ने ल्हासा–शिगास्ते (Lhasa-Shigaste) रेलवे सेक्शन को चालू भी कर दिया है। नेपाल में अपनी व्यापारिक व सामरिक गतिविधियों को प्रभावी बनाने हेतु चीन ने काठमाण्डू को तिब्बत के Xigaze को जोड़ने हेतु रेल निर्माण कार्ययोजना पर भी त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। सितम्बर 2018 में नेपाल के वाणिज्य मन्त्री रवि शंकर सैनजू ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने अपने Tianjin, Shezhen, Lianyungang व Zhanjiang, सामुद्रिक बन्दरगाहों के साथ–साथ स्थलीय बन्दरगाहों (Lanzhou, Lhasa व Xigaste) द्वारा नेपाल को व्यापारिक सुविधा प्रदान कर दी है। ऐसा होने से नेपाल की भारत पर निर्भरता कम हो जायेगी। 2015 में भारत द्वारा नेपाल की की गयी नाकेबन्दी की दृष्टि से चीन व नेपाल के मध्य उक्त सहयोग सामरिक–आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि तिब्बत (TAR) के सामारिक महत्व से सुपरिचित चीन ने इस क्षेत्र को चीन के शेष भागों से जोड़ने हेतु 1956 किमी0 लम्बे जिस रेलवे मार्ग का निर्माण किया है उसे काठमाण्डू तक विस्तृत कर चीन भारत के उत्तरी सीमान्त तक अपनी पहुँच को सुदृढ़ करना चाहता है जिससे नेपाल के भू–सामरिक अवस्थिति का लाभ उठाकर भारत को दक्षिण एशिया में घेरकर उसके शक्ति–प्रक्षेप को नियन्त्रित किया जा सके। 'गोल्मुड–ल्हासा रेलमार्ग' पर लगभग 45 स्टेशन हैं जिन्हें Xining से ही नियन्त्रित किया जा रहा है यह विश्व की सबसे ऊँची रेल परियोजना है जो समुद्र तल से 16,640 फिट पर स्थित है। इसी मार्ग पर विश्व की सर्वाधिक ऊची सुरंग Fenghuoshan Tunnel स्थित है जिसकी समुद्र तल से ऊचाई 16,093 फिट है।

नेपाल–चीन व्यापारिक सहयोग–

अस्थिर राजनैतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरुप नेपाल की अर्थिक विकास गति बहुत ही मन्द रही है। यद्यपि 1950 के दशक से प्रारम्भ उदारीकरण के पश्चात नेपाल की अर्थव्यवस्था शनैःशनैः विकासोन्मुख होने लगी किन्तु भ्रष्टाचार व माओवादी इन्सरजेन्सी से संत्रस्त नेपाल अपेक्षित प्रगति से

कोसों दूर ही रहा। यद्यपि आर्थिक प्रगति के त्वरित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नेपाल में प्रारम्भ पंचवर्षीय योजनाओं से वहाॅ काफी सुधार हुए किन्तु सन 2002 में नौवीं आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत उसने पूर्व की तुलना में पर्याप्त प्रगति कीं। विदेशी सहायता व पर्यटन ही नेपाल की प्रगति व विकास का आधार है जिसके बलवूते वह कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, परिवहन व शिक्षा जैसे मूलभूत सेक्टरों में अपेक्षित सुधार कर रहा है। निम्नांकित तालिका नेपाल से के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति की पुष्टि होती है। जहाँ तक चीन व नेपाल के मध्य आयात–निर्यात का प्रश्न है सन 2014–15 में नेपाल ने चीन को 2 बिलियन रुपये मूल्य के सामानों को निर्यात किया जबकि इसी अवधि में चीन द्वारा नेपाल को भेजी गयी वस्तुओं का मूल्य 99 बिलियन रहा जिसका अनुपात 48:1 था। आयात निर्यात की इसी प्रक्रिया में नेपाल को चीन से 2013–14 में–2.18 बिलियन रुपये, 2014–15 में–2.16 बिलियन रुपये, 2016–17 में–1.57 बिलियन रुपये, तथा 2018–19 में–3.00 बिलियन रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।

2017–18 में चीन द्वारा नेपाल को निर्यात की गयी वस्तुओं निम्नांकित सारिणी से समझा जा सकता है–

Nepal Export From China (Billion dollar)	**Value**	**Year**
Essential oil, Perfumes, Cosmetics, Toileteries	$3.9MM	2017
Miscellaneous articles of base metal	$3.1M	2017
Carpets and other Textile Floor Coverings	$2.28M	2017
Sugers and sugar Confectionaries	$1.18M	2017
Raw hides and skins (other than furskins) and Leather	$1.05M	2017
Articles of apparel, not knit or crocheted	$1.08M	2017
Works of art, collector's pieces and antiques	$1.05M	2017

Copper	$955.16K	2017
Cereal, Flour Starch, milk prepartions and products	$838.74K	2017
Vegetables plaiting materials, Vegtable products	$793.05K	2017

22 मार्च, 2016 को चीन व नेपाल के मध्य एक Transit and Trade सन्धि पर हस्ताक्षर किए गये जिसके अनुसार–

1. नेपाल को चीन के सामुद्रिक बन्दरगाहों द्वारा व्यापार सुविधा प्राप्त होगी।
2. इस समझौते की प्रत्येक 10 वर्षों में समीक्षा की जायेगी।
3. नेपाल के पोखरा में चीन एक क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेगा। इस हेतु उसे समस्त तकनीकी सहायता प्रदान की जायेगी।
4. चीन नेपाल में तेल व गैस के आरक्षित भण्डारों की खोज हेतु सहयोग देगा।
5. दोनों देश द्विपक्षीय 'स्वतन्त्र व्यापार समझौते' की सम्भावनाओं को मूर्त रुप प्रदान करेंगे।
6. नेपाल के हिल्सा (Hilsa) व हुमला (Humla) नदी क्षेत्र में पुलों के निर्माण व Xiarwa सीमा को सुदृढ़ करने हेतु चीन उसे सहायता व निर्माण–तकनीक उपलब्ध करायेगा।
7. दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर बौद्धिक–सम्पदा पद्धति को सुदृढ़ करेंगे।
8. दोनों देश बैंक सम्बन्धी नियमों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने हेतु सुविधाओं का विस्तार करेंगें।

संयुक्त राष्ट्र COMTRADE डेटाबेस के अनुसार चीन से नेपाल का निर्यात 2017 की अवधि में 22.33 मिलियन डालर था जिसे जी0डी0पी0 के आधार पर विकास–वृद्धि को निम्नांकित तालिका से समझा जा सकता है–

वर्ष	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GDP$ (PPP) में	28.75 Bln I	38.45 Bln I	40.97 Bln I	43.49 Bln I	47.05 Bln I	49.56 Bln I	52.58 Bln I	55.50 Bln I	59.23 Bln I	62.67 Bln I	67.62 Bln I	70.62 Bln I	71.82 Bln I	78.59 Bln I	84.37 Bln I
प्रतिव्यक्ति आयGDP$ (PPP) में	1211	1500	1579	1659	1777	1853	1946	2031	2142	2239	2387	2464	2477	2679	2842
जी0डी0 पी0 विकास (वास्तविक)	6.1 %	3.5 %	3.4 %	3.4 %	6.1 %	4.5 %	4.8 %	3.4 %	4.8 %	4.1 %	6.0 %	3.3 %	0.6 %	8.2 %	6.7 %
मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	3.4	4.5	8.0	6.2	6.7	12.6	9.6	9.6	8.3	9.9	9.0	7.2	9.9	4.5	4.2
सरकार ऋण (जी0डी0पी0 का पंचवर्षीय) प्रतिशत में	58	51	49	43	42	39	34	32	34	32	28	25	27	27	27.4

सन 1996–2017 में राजनैतिक उथल–पुथल, माओवादी विद्रोह व भूकम्प–त्रासदी के कारण आर्थिक रुप से नेपाल में व्याप्त अस्थिरता का उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। फलतः, एक दशक लम्बी शान्ति–प्रक्रिया के पश्चात 2015 में एक नये गणराज्य के संविधान की घोषणा व 2018 में बहुमत की सत्ता स्थापित होने के कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था शनैःशनैः विकसित हो रही है। नेपाल की अर्थव्यस्था धीरे–धीरे कृषि से दूर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रवास के साथ विकासोन्मुख है। मार्च 2019 में नेपाल द्वारा 'अन्तर्राष्ट्रीय निवेश शिखर सम्मेलन' के आयोजन से उसकी अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश के कारण पर्याप्त सम्बल मिल रहा है। नेपाल के साथ व्यापार में

संलग्न 5 बड़े देशों के साथ उसके व्यापारिक पक्ष (2018) को निम्नवत समझा जा सकता है।

बाजार	व्यापार (US$mil)	साथी की हिस्सेदारी (प्रतिशत)
भारत	420	56.72
संयुक्त राज्य अमेरिका	83	11.15
टर्की	48	6.42
जर्मनी	29	3.93
यूनाइटेड किंगडम	25	3
निर्यातक		
भारत	6520	64
चीन	1267	12
अनिर्दिष्ट	207	2
संयुक्त अरब अमीरात	175	1
फ्रांस	155	1

चीन–नेपाल सामरिक सहयोग–

1960 में नेपाल व चीन के मध्य सम्पन्न 'शान्ति व मैत्री सन्धि' के उपरान्त दोनों के मध्य सामरिक सम्बन्धों में नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। 5 अक्टूबर, 1960 को दोनों के मध्य न केवल सीमा समझौते की सम्पुष्टि हुई अपितु दोनों ने भारत के साथ अपने सम्बन्धों के संतुलन का भी प्रयास जारी रखा। सन 1975 में सिक्किम के भारत के विलय के उपरान्त चीन द्वारा नेपाल की सुरक्षा हेतु भारतीय चुनौती का भय दिखाकर वहॉ अपने प्रभाव–वृद्धि की हर सम्भव कोशिश की गयी। फलतः, जहाँ एक ओर चीन नेपाल हेतु एक बड़े एफ0डी0आई0 के प्रमुख स्रोत के रुप में उभरा वहीं नेपाल ने भी विविध कूटनीतिक उपायों द्वारा उसे 'सार्क' जैसे क्षेत्रीय संगठन में सदस्य बनाने की हर सम्भव कोशिशें भी की। इतना ही नहीं सिक्किम घटना के बाद नेपाल के राजा वीरेन्द्र सिंह ने नेपाल को भारत व चीन के मध्य 'शान्ति–क्षेत्र' के रुप में

प्रस्तावित किया वही 1980 के दशक से चीनी हथियारों की आपूर्ति भी प्रारम्भ कर दी। उल्लेखनीय है कि सन 1950 की भारत–नेपाल मैत्री सन्धि के अनुसार नेपाल बिना भारत की अनुमति प्राप्त किए किसी तीसरे देश से शस्त्र–आपूर्ति न करने हेतु वचनद्ध हैं किन्तु उसने 1980 के दशक व नेपाली गृह–युद्ध के दौरान (1996–2006) चीन से हथियारों की आपूर्ति की। सन 2005, 2008 व 2009 में भी नेपाल ने चीन से सैन्य–आर्थिक सहायता के अतिरिक्त विभिन्न सैन्य उपकरण भी प्राप्त किये। इस आपूर्ति के पीछे नेपाल का तर्क था कि तिब्बती शरणार्थियों के नेपाल में प्रवेश रोकने हेतु उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि ये शरणार्थियों भारत–नेपाल सीमा में छिपते हुए भारत में भी प्रवेश कर रहे थे।[5] उल्लेखनीय है कि सन 2011 में न केवल चीन ने नेपाल को 7.7 मिलियन डालर की सैन्य–आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई अपितु 2013 में सुरक्षा व रक्षा सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने सम्बन्धी एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया।[6] ये घटनाएं चीन की विदेशनीति में बढ़ रहे नेपाल के भू–सामरिक महत्व का परिणाम भी जिनमें अनावश्यक रुप से तिब्बत–प्रकरण की आड़ ली गयी। इतना ही नहीं, चीन नेपाल को परम्परागत हथियार भी उपलब्ध कराता रहा क्योंकि वास्तविक रुप से चीन के हथियार सस्ते होते हैं तथा ये अफ्रीका व दक्षिण एशियाई के विकासशील देशों की आर्थिक पहुँच की दृष्टि से उपयोगी माने जाते हैं। ध्यातव्य है कि चीन द्वारा नेपाल में संचालित गोलमुण्ड–ल्हासा–शिगास्ते रेलवे विस्तार भी चीन की सामरिक योजना ही है जिसका वह लुम्बनी व भारत के उत्तर प्रदेश की सीमा तक विस्तार कर इस सीमान्त में सामरिक सुदृढ़ता प्राप्त करना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो दक्षिण एशिया का सामरिक परिदृश्य तो प्रभावित होगा ही साथ ही भारतीय सीमाओं तक चीनी सैनिकों व सैन्य साज सामान का पहुँचाना अत्यन्त सुगम हो जायेगा। चीन के उक्त सामरिक हितों की पूर्ति में नेपाल की संलिप्तता भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से संघर्षों के नये वातावरण का सृजन करेंगी। उैत सन्दर्भ में निम्नांकित तथ्य सर्वथा उल्लेखनीय है।

" The Nepal Army (Priviously The Royal Nepalese Army) was knows to be under the direct control of Nepal's monarchy which was

reasonably friendly towoard China. Now That Nepal is a republic. China's interest in Nepal's army is growing as reflected by the visits of high-profile Chinese military delegations, Their meetings with senior army and other security officials as well as interests in the integration of the Maoist combatants."[7]

सन 1996–2006 की कालावधि में नेपाल में चली माओवादी इन्सरजेन्सी में विद्रोहियों के साथ वैचारिक साम्यता के बावजूद चीन ने विद्रोह के दमन हेतु नेपाल को चीनी हथियार भी भेजे जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, यू0के और भारत ने नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र को हथियार देने से मनाकर दिया था। सन 2008 में नेपाल में प्रारम्भ शान्ति प्रक्रिया और राष्ट्रीय चुनावों के बाद नेपाल की माओवादी सरकार ने भारत नेपाल मैत्री–सन्धि को रद्द करने की भी घोषणा कर दी। चीन व नेपाल के मध्य काठमाण्डू मे 2017 में सम्पन्न 'सागरमाथा' संयुक्त सैन्य अभ्यास यह सिद्ध करता है कि चीन की भारत विरोधी गतिविधियों में नेपाल का वह कहाँ तक उपयोग कर सकता है। भारत व नेपाल के मध्य होने वाले ''सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास'' का चीनी विरोध यह सिद्ध करता है कि चीन के भावी संकेत अशुभ हैं जबकि यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी है। नेपाल में सड़क व रेलवे विस्तार कर राणनीतिक गतिशीलता (Strategic Mobility) प्राप्त करने सम्बन्धी चीनी प्रयत्न एवं नेपाल को विकसित कर अपने वर्चस्व–वृद्धि सम्बन्धी चीन प्रयत्नों से यह पुष्ट होता है कि वह नेपाल के माध्यम से भारत के उत्तरी सीमान्त को असुरक्षित करने हेतु प्रयत्नशील है। इतना ही नहीं पाकिस्तान के माध्यम से उत्तरी–पश्चिमी सीमान्त क्षेत्र पर भी वह रणनीतिक दबाव की नीति पर चल रहा है। चीन की भारत–विरोधी गतिविधियाँ यह सिद्ध करती हैं कि वह भारत के बढ़ रहे वैश्विक–प्रभाव व रणनीतिक सामर्थ्य से क्षुब्ध है तथा उसे दक्षिण एशिया तक ही परिसीमित करने हेतु वह किसी भी कदम उठाने में संकोच नहीं होगा।

References-

1. IDSA, News Review On China, New Delhi May 1969,P-5.
2. Leo E. Rose & John T. Schulz, Nepal Profile of a Himalayan Kingdom, New Delhi, 1980 P-102.
3. Asian Recorder, 1967, P-7864
4. Ashutosh Kumar, China factor in Nepal, Sumit Enterprises, New Delhi, 2013 P-
5. Strategic Analysis, Vol.40,No.1, Jan.-Feb. 2016, p.23
6. The Hindu, July 25, 2013
7. S.D.Muni and Tan Tai Yong(eds.), A Resugent China: South Asia Perspectives, Routledge, Abingdon, U.K. 2012 p. 145

अध्याय–5

नेपाल–केन्द्रित भारत व चीन की सामरिक–आर्थिक विनियोजन नीति

एशिया के दो बड़े देशों के मध्य स्थित नेपाल की भू–स्त्रातेजिक अवस्थिति, भू–राजनीति, ऐतिहासिक धरोहर, अर्थव्यवस्था व सांस्कृतिक कारक जैसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी विदेश नीति के निर्धारण व संचालन में स्थायी रुप से परिलक्षित हो रहे हैं।[1] केन्द्रीय हिमालय, में स्थित नेपाल की स्थलवद्ध अवस्थिति तथा तीन ओर (दक्षिण, पश्चिम व पूर्व) से भारत तथा उत्तर की ओर चीन से घिरे होने का ही परिणाम है कि नेपाल सदैव 'पतले तार पर चलने के कौशल' (Tight-rope walking)[2] से निर्धारित अपनी विदेश नीति के अन्तर्गत भारत व चीन दोनों के साथ संतुलन बनाकर नीति संचालन हेतु प्रयत्नशील रहा है। नेपाल की भू–राजनीतिक स्थिति एवं उसके प्रभाव व परिणामों के सन्दर्भ में नेपाल के महाराजा पृथ्वी नरायण शाह ने कहा था कि–

" This (Nepal) country is like a gourd (or a yam) between two rocks, maintain a treaty of friendship with emperor of China, keep also a treaty of friendship with emperor of the Southern sea (i.e. The British India).[3]

एशिया के दो दिग्गज देशों के मध्य सैण्डविच के रुप में नेपाल की स्थिति (a dwarf sandwitch between two giants)[4] उसकी विदेश नीति का ऐसा स्थाई भाव है जिससे वह असुरक्षा की मनोवैज्ञानिक ग्रन्धि से सदैव पीड़ित रहा है[5] तथापि उसकी सम्प्रभुता पर कभी भी कोई आँच नहीं आयी। उल्लेखनीय है कि सन 1950 में भारत के प्रधानमन्त्री ने संसद में नेपाल के सन्दर्भ में यह कहा भी था कि भौगोलिक सन्दर्भ में नेपाल लगभग भारत का ही विस्तार है[6] तथापि भारत ने न केवल अपनी हिमालयन स्त्रातेजी में नेपाल को विशिष्ट महत्व दिया अपितु उसके सुरक्षा, विकास व स्थिरता की दृष्टि से सदैव सकारात्मक नीति ही अपनायी। ब्रिटिश भारत की सरकार ने उत्तर की ओर चीन व सोवियत रुस जैसी साम्यवादी शक्तियों की उपस्थिति के फलस्वरुप नेपाल को अन्तस्थ राज्य (Buffer State) मानकर सदैव भारतीय

सुरक्षा दृष्टि से इस हिमालयी राज्य को अपने सुरक्षा–आवृत्त में संरक्षित करने की हर सम्भव कोशिश की। 'कबूतर व अजगर' के मध्य (Between Dove and Dragon)[7] स्थित नेपाल के साथ अपने 'रोटी व बेटी' सम्बन्धों के सुदृढ़ आधार को देखते हुए भारत ने उसे अपनी विदेशनीति में विशिष्ट दर्जा (Special Status) तो अवश्य दिया किन्तु अधिकांश नेपालियों की मनोभावना भारत विरोधी ही रही।[8] भारत–नेपाल की खुली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से व्यापार, निष्कंटक आवागन, भारत में प्राप्त विशिष्ट नागरिक व सम्पत्ति अधिकार तथा विदेशी व्यापार हेतु भारत के कलकत्ता बन्दरगाह पर उसकी निर्भरता के वाबजूद नेपाल ने चीन के साथ मैत्री व्यामोह में फंसकर चीनी निकटता को प्रोत्साहन दिया। उधर, चीन के सामरिक चिन्तकों द्वारा अपनी पंचउँगली नीति (Five Finger Policy) के अन्तर्गत भूटान, लद्दाख, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश सहित नेपाल को अपने तिब्बत रुपी पंजे की उगली कहने[9] तथा सन 1951 में तिब्बत को हड़प लेने से नेपाल व भारत दोनों हतप्रभ रह गये। भारत के सहयोग से नेपाल के राणा साम्राज्य को उखाड फेंकने की घटना से नेपालियों का लगा कि ये सभी कार्य चीन के माओ–नेतृत्व की विस्तारवादी अभियान पर अंकुश लगाने हेतु ही किया गया था किन्तु चीन ने अपनी सामरिक–संस्कृति कि 'जो उसके साथ नहीं है उसके विरुद्ध रहने की नीति (Whoever is not with them being against them) का अनुपालन कर भारत के हिमालयी सीमान्त तक अपनी पहुँच बना ली। भारतीय सुरक्षा के प्रभावशली प्रहरी की भूमिका में सदैव हिमालय की केन्द्रीय भूमिका तो अवश्य रही किन्तु तिब्बत पर चीनी नियन्त्रण से भारत की पूर्व स्थापित हिमालय सम्बन्धी अवधारणा (The Himalaya has been regarded as an impenetrable barrier against any threat from the north) को गहरा आघात पहुँचा।

भारत की हिमालयी–सीमान्त सुरक्षा नीति–

1 नवम्बर, 1858 से 15 अगस्त, 1947 तक भारत में महारानी विक्टोरिया का शासन भारत की सुरक्षा, अखण्डता एवं रक्षा नीतियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण

रहा है क्योंकि इस कालावधि में जहाँ एक ओर भारत वाह्य आक्रमणों से सर्वथा मुक्त रहा वहीं भारतीय स्वाधीनता सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के फलस्वरुप भारतीयों में एकता के भाव भी विकसित हुए।[10] इस काल में भारत की विदेश नीति भी अंग्रेजों द्वारा, सन्धियों की सुरक्षा, अखण्डता एवं भारत के सीमान्त क्षेत्रों में स्थित छोटे–छोटे राज्यों को तटस्थ रखकर उनकी सुरक्षा पर केन्द्रित रहीं। ब्रिटिश–भारत के शासकों ने उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित 'रिंग फेन्स' (Ring Fence)[11] की नीति के अन्तर्गत आन्तरिक व वाहय घेरों का निर्माण करके क्रमशः हिमालयी राज्यों– नेपाल, भूटान, सिक्किम व उत्तरी पूर्वी सीमान्त के आदिवासी क्षेत्रों, उत्तरी–पश्चिमी सीमान्त तथा अफगानिस्तान, फारसखाडी से सम्बद्ध देशों, तिब्बत, ईरान (Persia) व थाईलैण्ड (Siam) को सम्मिलित कर भारतीय हितों की सुरक्षा के प्रयत्न किये गये। वाह्य रिंग घेरे (Outer Ring Fence) की नीति के अन्तर्गत शक्ति–संतुलन सम्बन्धी ब्रिटिश चातुर्य व हिन्दमहासागर पर ब्रिटिश प्रभुत्व के फलस्वरुप भारत के हित न केवल सुरक्षित रहे अपितु बड़ी शक्तियों की स्पर्धा से भी वह अप्रभावित ही रहा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सैन्य बलों को ब्रिटिश सेना में सम्मिलित कर (60,000) भारतीय सैन्य बलों (1,20,000) एवं रॉयल नेवी के माध्यम से ब्रिटिश शासकों ने पूर्वात्तर भारत व उत्तरी पश्चिमी सीमान्त की सुरक्षा को संकट से बचाने का हर सम्भव प्रयत्न किया। लार्ड कर्जन एवं लार्ड किचनर का उक्त परिप्रेक्ष्य में विशेष योगदान था।[12] स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात पं0 नेहरु ने अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य प्रारम्भ शीत युद्ध एवं हिमालयी क्षेत्र में स्थित चीन में चल रहे–सत्ता संघर्ष को भारतीय सुरक्षा हेतु न तो चुनौती मानी और न ही रक्षा सामर्थ में अभिवृद्धि पर ही ध्यान दिया। भारतीय सुरक्षा के प्रति पं0 नेहरु का अभिमत था कि– " A free India secure against attack eigther by its geostrategic position, in its size or the balance of power"[13]

भारत के उत्तरी सीमान्त में साम्यवादी चीन का अभ्युदय एवं उसकी विस्तारवादी मनोवृत्ति का पूर्वामान लगाने में उदासीन भारतीय नीतियों का ही परिणाम था कि उसने बलपूर्वक तिब्बत पर अधिकार करके नेपाल पर सामरिक–आर्थिक ध्यान केन्द्रित किया। सन 1914 में शिमला समझौते के

आधार पर भारत व चीन के मध्य निर्धारित मैकेमोहन सीमा को अस्वीकार करने से दोनों के मध्य सीमा विवाद का नया अध्याय शुरु हो गया। ध्यातव्य है कि पूर्वोत्तर भारत में चीन की आक्रामक गतिविधियों को ध्यान में रखकर भारत ने ब्रिटिशकालीन नीतियों में अपेक्षित संसोधन कर नेफा (NEFA) व अन्य दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र की सुरक्षा व विकास हेतु सन 1953 में भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा (IFAS- Indian Frontier Administrative Service) का गठन किया। इस प्रशासनिक सेवा की ईकाई भारतीय विदेशमन्त्रालय के अन्तर्गत गठित की गयी थी। इतना ही नहीं, मैकमोहन सीमा रेखा पर अपना स्पष्ट मत प्रकट करते हुए पं0 नेहरु ने 20 नवम्बर 1950 को संसद में कहा भी था कि "The Mac Mohan line is our boundary, map or no map. We will not allow anybody to come across that boundary".

इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार ने न केवल आसूचना सेवाओं को सक्रिय किया अपितु पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में संचार सेवाओं एवं यातायात व्यवस्था विकसित करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की।[14] सन 1950 के उत्तरार्ध में लद्दाख से सटे पश्चिमी क्षेत्र में किए गये चीनी अतिक्रमण पर पहले तो भारत सरकार ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई किन्तु अतिक्रमण की बारम्बारता व तीव्रता को ध्यान में रखकर चुशुल (Chusul) व देमचोक (Demchok) में चौकियाँ स्थापित कर पुलिस व सेना की टुकडियों को भारतीय क्षेत्र में तैनात किया तथा 1954 में अक्साई चिन को छोड़कर अन्य इलाकों में अतिरिक्त सीमा चौकियाँ स्थापित की गयीं। उत्तरी सीमान्त पर बढ रहे चीनी दबाव को देखते हुए भारत सरकार ने सिक्किम, भूटान व नेपाल जैसे हिमालयी राज्यों की सुरक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण कदम उठाये। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने विरासत में मिले संरक्षित राज्य सिक्किम की सुरक्षा हेतु संचार व सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश की वहीं भूटान के साथ 1865 व 1910 में ब्रिटिश भारत सरकार के मध्य हुए समझौतों के आधार पर उसकी आन्तरिक स्वायत्तता एवं जनकल्याण हेतु हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया। जहाँ तक नेपाल का सन्दर्भ है, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि नेपाल की सुरक्षा व विकास हेतु भारत प्रतिबद्ध

है।[15] 31 जुलाई, 1950 को नेपाल व भारत के मध्य सम्पन्न मैत्री सन्धि इसी सद्भावना का परिणाम है। यही सन्धि भारत व नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्धों का मूल आधार है किन्तु 21 वीं शताब्दी की नवीन भू–राजनैतिक संरचना में नेपाल इस सन्धि के संशोधन की बात करने लगा है जिसके पीछे निश्चय ही नेपाल पर बढ़ रहे चीनी प्रभाव व नेपाल की राजनीति में प्रभावी साम्यवादी विचारधारा उत्प्रेरक का कार्य कर रही है।

नेपाल में भारत की विनियोजन नीति

ऐतिहासिक, सामाजिक तथा वाणिज्य व व्यापार की दृष्टि से भारत व नेपाल के सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन व गहरे रहे हैं। यद्यपि दक्षिण एशिया का यह भारतीय पड़ोसी राष्ट्र विगत तीन दशकों से राजनैतिक अस्थिरता व आर्थिक संकटों से प्रभावित रहा है तथापि भारत ने सदैव उसके विकास, स्थायित्व व सुरक्षा के प्रति सक्रियतापूर्वक हर सम्भव सहायता पहुँचाई है। भारत, नेपाल का सबसे बड़ा निर्यातक व प्रमुख आयातक राष्ट्र है तथा प्रचुर मात्रा में सहायता व निवेश की नीतियों द्वारा सदैव नेपाल की सहायता हेतु भारत तत्पर है। भारतीय भूमि से नेपाल को होने वाले समुद्री व्यापार व पारगमन सुविधाएं दोनों देशों के आर्थिक सम्बन्धों के विस्तार में प्रमुख कारक है। सन 1971 में भारत व नेपाल के मध्य सम्पन्न व्यापार सन्धि (जिसका 1991, 1993, 1996, 2002 व 2009 में संशोधन हो चुका है) के अन्तर्गत भारत द्वारा उसे आयात शुल्क व कर सम्बन्धी विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त हैं। भारत–नेपाल सीमा से सम्पन्न होने वाले व्यापार में दोनों देशों ने पारस्परिक रुप से 16 मूलभूत वस्तुओं को निःशुल्क कर दिया है साथ ही लगभग 384 वस्तुओं पर मात्र 5 प्रतिशत व अन्य 9 प्रकार वस्तुओं पर मात्र 8 प्रतिशत का आयात–निर्यात कर लागू है। यदि भारत व नेपाल के व्यापार की प्रवृति पर प्रकाश डाला जाय तो सन 2002–03 से 2017–18 के वर्षों में भारत का नेपाल को आयात आवश्यकता से अधिक (Surplus) रहा है तथा व्यापार घाटा–वृद्धि नेपाल के लिए चिन्ताजनक है। निम्नलिखित तालिका से इसकी पुष्टि होती है–

India's Trade with Nepal (US$million)

Year	**Export to Nepal**	**Import From Nepal**	**Total Trade**	**Trade Balance**	**Trade Balance Ratio**
2002-03	350	282	632	69	11%
2003-04	669	286	955	383	40%
2004-05	473	346	1089	397	36%
2005-06	860	380	1240	480	39%
2006-07	927	306	1233	621	50%
2007-08	1507	629	2136	879	41%
2008-09	1570	496	2066	1074	52%
2009-10	1533	453	1986	1081	54%
2010-11	2168	513	2682	1655	62%
2011-12	2722	550	3272	2172	66%
2012-13	3089	543	3632	2546	70%
2013-14	3592	530	4122	3062	74%
2014-15	4559	640	5199	3919	75%
2015-16	3930	471	4401	3460	79%
2016-17	5454	445	5899	5009	85%
2017-18	5518	414	4932	5104	86%

Source: Directorate General of Foreign Trade, Ministry of commerce.

India's Top 10 Export to Nepal

Commodity	**Values in US$millon**
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minearls etc.	870
Other Products containing by Wt<0.25% of Carbon	396
Semi/wholly milled rice w/npolished/glazed	199
Light oils and preparation	197

Cement clinkers	182
Moter Cycle etc. with rciprocating internal combstion piston engines of cylinder capacity>50cc to 250cc.	176
Other in gaseous state	172
Machinery with a 360 degree, Revolving super structure	137
Electrical Energy	128
Other Medicine put up for retail sale	114

Source: Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry

Top Items Imported into India from Nepal (value in US$million)

Commoditry	**2017-18**
Sweetened Flavoured Water	59
Cardamoms: Neither crushed nor ground	47
Articles of Plastics	31
Black Tea	26
Unbleached woven fabrics of jute/other textiles bast fibers	18
Wire of iron/non alloy steel, plated/coated with zinc	17
Sacks and bags for packing, made of jute	17
Resin and racin acid	17
Oil-cake and other residues resulting from extraction of other oil-seed and oleaginous fruit	14
Corugated products, otherswise plated or coated with zinc	13

Source: Directorate General of Foreign Trade, Ministry of commerce and Industry.

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की मूलभावनाओं के अनुसार इस संगठन के सदस्य देशों के मध्य पारस्परिक व्यापार को सम्पन्न करने तथा इनमें उत्पन्न बाधाओं को समाप्त कर सीमा–पार व्यापार को सरल बनाने हेतु दिसम्बर 1995 में गठित 'साउथ एशिया प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रीमेण्ट' (SAPTA) के आधार पर भारत व नेपाल के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में

एम0एफ0एन0 भावनाओं के अनुरुप आयात–निर्यात को सरल बनाने की नीति निर्धारित की गयी तथा जनवरी 2006 में साफ्टा (South Asian Free Trade Agreement) के अन्तर्गत व्यापार प्रक्रिया को उदार व सरल बनाने का निर्णय लिया गया। भारत व नेपाल दोनों ने व्यापार उदारीकरण के आधार पर जो निर्णय लिया उसी का परिणाम है कि दोनों के व्यापारिक सम्बन्धों में नवीन ऊर्जा का संचार सम्भव हो सका। उधर नेपाली बाजारों में चीनी सामानों की व्यापाक मॉग के फलस्वरुप भारतीय सामानों के निर्यात पर असर तो अवश्य पड़ा किन्तु अभी भी (2016 तक) भारत नेपाल में निर्यात की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। निम्नांकित तालिका से इसकी पुष्टि होती है–

Nepal's Top Import Partners

Year	**2010**		**2016**	
Partner Name	**Value US$mn**	**% of Total imports**	**Value US$mn**	**% of Total imports**
India	3253	64%	5816	66%
China	561	11%	1247	14%
UAE	194	4%	210	2%
Indonesia	107	2%	111	1%
Thailand	102	2%	110	1%

भारत व नेपाल के मध्य खुली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के कारण चीन की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार पर्याप्त सरल है। पूरी सीमा पर स्थित 27 व्यापारिक स्थलों (2009 की भारत–नेपाल सन्धि के द्वारा निर्धारित) द्वारा भारत–नेपाल के मध्य व्यापार सम्पन्न हो रहा है जिसमें पानीटंकी–ककरभिटटा व रक्सौल–बीरगंज अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

नेपाल में भारत का प्रत्यक्ष निवेश–

सन 1970 व 1980 तक नेपाल में निवेश करने वाला प्रमुख देश भारत ही था जिसका औसत 0.5 मिलियन डालर वार्षिक था किन्तु 1990 के दशक में इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई। नेपाल में होने वाले प्रत्यक्ष निवेश में 3 प्रतिशत अंश

भारत का ही है। नेपाल राष्ट्र बैंक 2018 के एक आकड़े के अनुसार नेपाल 39 देशों से निवेश प्राप्त करता है जिसमें भारत का अंश सर्वाधिक है। नेपाल में भारतीय निवेश को निम्नांकित तालिका से समझा जा सकता है–

India's Cumulative FDI in Nepal (USD million)

Year	FDI Value
2007-08	4.07
2008-09	4.70
2009-10	6.39
2010-11	9.08
2011-12	14.38
2012-13	17.46
2013-14	9.76
2014-15	2.37
2015-16	5.38
2016-17	3.08
2017-18	20.92

Source; RBI Overseas Investment Data

यदि नेपाल में भारतीय निवेश का सेक्टर के आधार पर विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट है कि कुल भारतीय निवेश का 65 प्रतिशत अंश सेवा क्षेत्र में तथा 33 प्रतिशत उत्पादन क्षेत्र में होता है। निम्नांकित तालिका से इसकी पुष्टि होती है–

India's Sector wise FDI in Nepal (USD million)

Sector	Period I 2008-09 to 2012-13		Period II 2012-13 to 2017-18		Cumulative 2008-09 to 2017-18	
	FDI	Share %	FDI	Share %	FDI	Share %
Manufacturing	20	39	11	26	31	33
Wholesale, Retail Trade, Restaurent and Hotel	14	28	5	12	20	21
Financial, Insurence, Real Estate and Business	0	1	16	37	16	17

Service						
Electricity, Gas and Water	5	10	5	12	10	11
Construction	9	16	0	0	9	9
Community, Social and Personal Service	3	6	4	9	7	7
Agriculture and mining	0	0	1	3	1	1
Transport, Storage and Communication Services	0	0	0	0	0	0

Source: Overseas Investment Data, Reserve Bank of India

द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत भारत की कम्पनियॉ नेपाल में निवेश हेतु सक्रिय रही हैं तथा दोनों के मध्य पूर्व स्थापित ऐतिहासिक व सामाजिक सम्बन्धों का इन्हे पर्याप्त लाभ मिलता रहा किन्तु वहॉ की राजनैतिक अस्थिरता के कारण भारतीय निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, दोनों के मध्य एफ.डी.आई. नीति पर टैक्स की जटिलता, भ्रष्टाचार, श्रमिक संगठनों की नीतियॉ, कापीराइट का प्रश्न व ट्रेडमार्क सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धों के कारण निवेश को प्रोत्साहन मिलने में कठिनाइयॉ होने के कारण इनमें गिरावट आई। यद्यपि, सन 2011 में भारत व नेपाल की सरकारों ने निवेश को सुरक्षित रखने के साथ–साथ प्रोत्साहन देने हेतु द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन व अनुरक्षण (BIPA- Bilateral Investment Promotion and Protection) समझौते द्वारा कई उपाय भी किये किन्तु इनमें व्याप्त गतिरोध दूर नहीं किये जा सके। अपने देश में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zone) की स्थापना हेतु सन 2016 में कानून बनाने के साथ–साथ विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु कई उदार नीतियों का निर्धारण करके अपनी अर्थस्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु नेपाल प्रयत्नशील है। नेपाल में निवेश करने वाली कुछ प्रमुख भारतीय कम्पनियॉ निम्नांकित है–

1. State Bank of India
2. LIC of India
3. Pyro Telecom Soluion Pvt. Ltd.
4. Puresoftware Pvt. Ltd.
5. Care Rating Ltd.
6. Power Grid Corporation Of India Ltd.
7. Britania Industries Ltd.

8. Advance Nutritions (P) Ltd.
9. R M Chemical Pvt. Ltd.
10. Parle Biscuit Pvt. Ltd.
11. Uma Cement International
12. Miraj Multi Colour Pvt. Ltd.
13. Gmr Energy Ltd.
14. Balaji Agro Pvt. Ltd.
15. Al sameer Export Pvt. Ltd.

नेपाल के प्रति भारत की सहायता नीति–

दक्षिण एशिया में चीनी घुसपैठ की जिज्ञासा इस क्षेत्र के लिए कोई नई घटना नहीं है। तिब्बत की अन्तस्थ राज्य की स्थिति को समाप्त करने के उपरान्त 1954 के पश्चात जहाँ एक ओर उसने सन 1963 में पाकिस्तान के साथ सीमा समझौता किया वहीं नेपाल का समर्थन प्राप्त करने हेतु उसने अपनी महान स्त्रातेजी के अन्तर्गत सामरिक, राजनैतिक व आर्थिक सहायता व निवेश सम्बन्धी गतिविधियाँ तीव्र कर दी। पंचशील समझौते (29 अप्रैल, 1954) के पश्चात भारत के हिमालयी सीमान्त पर सामरिक दवाब एवं नेहरु की नीति को तार–तार कर हिन्दी–चीनी भाई–भाई सम्बन्धों को तिजांजलि देते हुए अक्टूबर 1962 में भारत पर आक्रमण कर चीन ने भारत की हिमालयी सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा व नीति को खण्ड–खण्ड कर दिया। सन 1960 के दशक में चीन ने काठमाडू–कोदारी मार्ग द्वारा नेपाल में प्रवेश कर न केवल भारत को उत्तर की ओर से घेरने की नीति का स्पष्ट संकेत दिया अपितु श्रीलंका व बांग्ला देश में अपनी उपस्थिति से यह पुष्ट कर दिया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र उसका पृष्ठ भाग (Backyard) है। चीन द्वारा सहायता (Aid) व निवेश द्वारा वाणिज्य, व्यापार, सस्ते ब्याज पर कर्ज आदि देकर नेपाल सहित भारत के अन्य पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध–विस्तार सम्बन्धी रणनीतियों के फलस्वरुप भारत को अपने सुरक्षा–आवृत्त की सुदृढ़ता हेतु निवेश व सहायता जैसे आर्थिक–उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु विवश होना पड़ा। वैश्विक शक्ति–आयाम के परिप्रेक्ष्य में भारत–चीन के सम्बन्धों की क्रिया–प्रतिक्रिया का दक्षिण एशिया पर

गम्भीर प्रभाव पड़ा तथा दोनों ही देश नये दाता के रुप में स्थापित होने लगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में निवेश व सहायता द्वारा वर्चस्व–विस्तार की रणनीति का ही परिणाम है कि भारत–चीन स्पर्धा को नयी गति प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध काल में अपने प्रभाव विस्तार हेतु सम्पन्न अमेरिका–सोवियत संघ की स्पर्धा यह पुष्ट करती है कि चीन उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर अपना वैश्विक विस्तार व प्रभाव स्थापित करने की ओर अग्रसर है जबकि भारत की न तो विस्तारवादी प्रवृति है और न ही अनावश्यक रुप से वह इस स्पर्धा में पड़ना ही चाहता है, फिर भी अपने सामरिक परिवेश को सुरक्षित रखने व अपने वैश्विक आर्थिक व सामरिक हितों की सुरक्षा हेतु अब भारत के नीति–नियन्ता भी गम्भीर विचार–विमर्श कर नीति नियोजन व संचालन में सक्रिय हैं। फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मार्शेल मॉस (Marcel Mauss) ने अपनी पुस्तक "The Gift" में स्पष्ट कहा है कि ''कोई भी उपहार बिना प्रयोजन के नहीं दिया जाता, उसके पीछे राष्ट्रों के कई निहितार्थ होते हैं। कोई भी सहायता 'बन्धन–मुक्त' नहीं होती। सहायता की नीति सही मायने में अपने शक्ति का प्रभाव निःसन्देह डालती है।'' सच कहा जाय तो ऋण, उपहार, अनुदान, कम ब्याज पर दिये जाने वाले ऋण व निवेश सही अर्थों में ऐसे प्रभावशाली हथियार हैं जिनके माध्यम से सभी राष्ट्र अपने विभिन्न हितों की पूर्ति हेतु प्रयोग करते है। इसे ही आर्थिक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। भारत व चीन की सहायता, निवेश व ऋण की प्रकृति में भी मूलभूत अन्तर है। जहॉ एक ओर भारत अपनी सहायता नीति को पारस्परिक हित व पारस्परिक–लाभ के परिप्रेक्ष्य में सहयोगी राष्ट्र की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में संचालित (Line of credit) करता है वहीं चीन की दृष्टि से उसकी सहायता निःस्वार्थ होती है। चीन की यह नीति मात्र एक स्वांग ही है क्योंकि उसकी ऋण–जाल नीति के परिणामों से विश्व अवगत होता जा रहा है। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान व थाईलैण्ड आदि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं जहाँ अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु चीन इन देशों को आर्थिक 'सहायता का इन्जेक्शन' लगाकर इन्हें अपने जाल उलझाने की गम्भीर कोशिश में है। जहाँ तक भारत का सन्दर्भ है भारतीय विकास व आर्थिक सहयोग (IDEA- Indian Development and Economic

Assistance) के नाम से पड़ोसी देशों की सहायता से भारत अपने भीतरी सुरक्षा–आवृत को सुरक्षित रखकर क्षेत्रीय स्थायित्व को सुदृढ़ करना चाहता है। विगत पाँच वर्षों में भारत ने अपने पडोसी देशों की 167 परियोजनाओं में 14,394 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है जिनमें 58 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा 109 पर कार्य प्रगति पर है। उक्त परियोजनाएं मुख्यतः कनेक्टीविटी, ऊर्जा, जल–शक्ति, राजमार्ग, कृषि व आधारभूत स्वास्थ सेवाओं से सम्बन्धित हैं। निम्नांकित तालिका से इसको सरलता से समझा जा सकता है–

Indian Aid (GA and LOC) to the Region

Aid to Country	**Grant Assistance(GA) Rs. Core/Line of Credit(LOCUS$m)**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
Afganistan	GA	585.31	732.52	880.44	263.02	365.96
Nepal	GA	381.37	303.26	309.94	332.72	376.62
	LOC	0.67	9.10	9.19	91.30	16.28
Myanmar	GA	164.86	104.34	117.07	123.62	223.55
	LOC	0	0	6.96	4.48	31.73
Sri Lanka	GA	420.80	499.70	403.80	99.16	77.89
	LOC	2.07	8.21	4.36	5.33	41.61
Maldives	GA	9.67	26.08	55.04	80.3	109.24
Bangladesh	GA	604.66	197.84	155.68	82.59	78.02
	LOC	13.12	13.68	69.63	91.30	40.11
Bhutan	GA	3926.79	4395.17	5368.46	3441.47	2475.87

Source: Ministry of External Affairs, 'Lok Sabha Question No. 3496 Projects in Neighbouring countries' August 8, 2018

चीन की ही भॉति भारत की सहायता नीति के संचालन में वित्तीय–संकट के परिणामस्वरुप परियोजनाओं के संचालन में विभिन्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार के बजट की भी अपनी सीमाएं है। निम्नांकित तालिका से इसकी पुष्टि होती है–

India's Aid to immediate neighbours in US$million

S.No.	**Country**	**BE 2016-17**	**BE 2017-18**	**BE 2018-19**
1	Afganistan	350	350	325
2	Bangladesh	125.00	65.00	175.00
3	Bhutan	2083.87	1779.07	1813.50

4	Nepal	3750.00	375.00	650.00
5	Sri Lanka	125.00	75.00	150.00
6	Maldives	75.00	125.00	125.00
7	Myanmar	225.00	225.00	280.00

Source: Lok Sabha, Parliamentry Committee on External Affairs, p.61

कूटनीतिक उपकरण के रुप में सहायता की नीति के प्रयोग का ही परिणाम है कि भारत ने 2018–19 में 27.802 बिलियन डालर के अतिरिक्त 14. 2 बिलियन डालर की 52 नई लाइन आफ क्रेडिट की घोषणा के साथ–साथ अफ्रीकी देशों हेतु 10 बिलियन डालर की कम ऋण की राशि सम्बन्धी घोषणा भी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने की है। उल्लेखनीय है कि अनुदान सम्बन्धी प्रक्रियाओं का आंकलन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा राष्ट्रों के वर्गीकरण व निर्धारित नीति द्वारा ही संचालित होता है जबकि नेपाल, भूटान व बांग्लादेश के सन्दर्भ में भारतीय विकास सहायता पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मापदण्ड लागू नहीं होते हैं। निम्नांकित तालिका से इसकी पुष्टि होती है–

Aid Criteria and percentage of interest

Country Classification	**L&LMI countries with minimum binding concessional requirment Category I**	**L&LMI countries with minimum binding concessional requirment Category II**	**Other development Countries Category III**
Rate of Interest	1.5%	1.75%	Lbor + 1.5%
Maturity	25 Years	20 Years	15 Years
Moratorium	5 Years	5 Years	5 Years
Grant Element	37.8%	31.37%	24.31%

Source: GOI, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, IDEA,

दक्षिण एशियाई देशों के प्रति चीन की बढ़ रही सामरिक आर्थिक अभिरुचि एवं अपनी 'घेरेबन्दी' से सतर्क भारत ने नेपाल, मालदीव व श्रीलंका की भेदनीयता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। इतना ही नहीं, भारत–चीन सीमा विवाद तथा नेपाल, भूटान व पाकिस्तान के साथ चीन के सम्बन्धों को

ध्यान में रखकर भारत ने इस क्षेत्र में अपनी नीतियों को सक्रियता प्रदान करते हुए सहायता नीति को प्राथमिकता दी है। भारत की अर्थव्यवस्था तीव्रता से विस्तृत हो रही है तथा उसने अपने वैश्विक आर्थिक व सामरिक हितों के रक्षार्थ हिन्दमहासागर के तटीय देशों (IOR) के अतिरिक्त सुदूर स्थित देशों में निवेश व सहायता नीति का भी विस्तार किया है। एफ0डी0आई0 के एक आकड़े के अनुसार भारत अपनी धनराशि को सन 2020–21 तक बढ़ाकर अपने जी0डी0पी0 का 3.5 प्रतिशत करने हेतु प्रयत्नशील है। यह निवेश विशेषकर आधारभूत संरचनाओं के विस्तार, साफ्टवेयर व्यापार व अन्य उच्च–तकनीकी से सम्बन्धित क्षेत्रों में की जायेगी जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें। सच कहा जाय तो भारत की उन्नतशील अर्थव्यवस्था व तकनीकी कौशल का ही परिणाम है कि आज भारत की छवि 'सांप के जादूगर देश' (Country of Snake charmers)से परिवर्तित होकर एक 'जादूगर देश' (Country of charmers) के रुप में स्थापित हो गयी है।

नेपाल की भूकम्प त्रासदी एवं भारतीय सहायता–

25 अप्रैल, 2015 को नेपाल की भीषण भूकम्प त्रासदी की पृष्ठभूमि में भारत द्वारा 'आपरेशन मैत्री' (Coperation Maitry) के माध्यम से नेपाल को प्रदत्त सहायता को एक 'राजनैतिक हथियार' की संज्ञा देते हुए चीन ने भी सहायता देकर नयी स्पर्धा को गति प्रदान की। चीन द्वारा दी गयी नेपाल को 3.3 मिलियन डालर की सहायता के अन्तर्गत अपने सैनिक, चिकित्साकर्मी व 186 टन की सामग्री उपलब्ध कराई। निम्नांकित तालिका से इसे समझा जा सकता है–

Overview of the Chinese and Indian disaster relief commitments in Nepal. [16]

	India	**China**
Relief Materials Military and Medical Personnel deployed	82 tons of blankets, food, water, 295 National Disaster task force units consisting of 100 personnels.	13 tons of medical aid, 55 military rescue team, 45 soldires, 60 medical personnels, 500 member road repairing brigade of

		the Peoples's Armed Police.
Technical support	13 military Aircraft, 3 civilian air craft and 6 helicopters.	-
Emergency Monetary releif post-reconstruction eommitment	$1 billion	$3.2 million immediate disaster relief $ 483 million

चीन द्वारा नेपाल को उपलब्ध कराई गयी आपदा–प्रबन्धन सम्बन्धी सहायता मानवीय दृष्टिकोण से पड़ोसी धर्म का पालन तो अवश्य है किन्तु नेपाल की भू–सामरिक सम्वेदना एवं यहाँ स्थापित भारतीय–प्रभाव को शिथिल करने की चीन की दूरदर्शी विदेश नीति को भी प्रकट करता है। भारत द्वारा उपलब्ध कराये गये एअरक्राफ्ट यह पुष्ट करते हैं कि भारतीय सुरक्षा नीति में भू–स्त्रातेजिक दृष्टि से नेपाल की विशिष्ट भूमिका है तथा वहॉ बढ़ रहे चीनी प्रभाव को वह गम्भीरता से लेता है।

यदि पं0 जवाहर लाल नेहरु से लेकर मोदी तक के शासनकाल तक की नेपाल–केन्द्रित नीतियों का सम्यक विश्लेषण किया जाय तो यह पुष्ट होता है कि तिब्बत पर चीनी नियन्त्रण के बाद नेपाल–केन्द्रित उसकी आर्थिक–सामरिक गतिविधियों पर भारत ने सकारात्मक नीति का संचालन तो अवश्य किया किन्तु कभी भी भारत अपने इस हिमालयी पड़ोसी के प्रति पर्याप्त सक्रिय व सतर्क नहीं रहा। यही कारण है कि भारतीय अनुदान व सहायता से नेपाल में संचालित विभिन्न सिंचाई, जलविद्युत व सड़क आदि से सम्बन्धित परियोजनाएं निर्धारित अवधि में पूरी नहीं हो पायीं। उधर नेपाल भी न तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ही सुस्थिर रख सका और न ही खुली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा प्रणाली को ही सुदृढ़ कर पाया। आई0एस0आई0 द्वारा नेपाल की भूमि का प्रयोग कर भारत में की जाने वाली गतिविधियॉ, 1999 में काठमाण्डू से भारतीय विमान का अपहरण[17], अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव व भारत–विरोधी तत्वों को शरण व प्रोत्साहन, नकली नोटों का संचालन व आर0डी0एक्स0 का भारत में प्रयोग जैसी घटनाएं भारत–नेपाल सम्बन्धों के काले अध्याय हैं।

उतार–चढ़ाव से ग्रस्त, भारत–नेपाल के सम्बन्धों का ही यह परिणाम है कि अभी तक न तो दोनों देश सीमा–विवाद व सीमा–निर्धारण की प्रक्रिया को सम्पन्न कर पाये हैं और न ही साम्यवादी शिंकजे में निरन्तर फँसता हुआ नेपाल बिना भारतीय सहयोग के विकास व स्थिरता का ही लक्ष्य प्राप्त कर सका है। सन 1950 की सन्धि में परिवर्तन की नेपाली आकांक्षा नेपाल में सक्रिय चीनी तत्वों के दबाव से यदाकदा अत्यन्त तीव्र हो जाती है। इस सन्धि की पुनर्निरीक्षण की चुनौती यथावत बनी हुई है। 'पड़ोस पहले' की विदेश नीति के अनुपालन में सन 2014 में दो बार (अगस्त व नवम्बर) यात्रा करके मोदी ने पिछले 17 वर्षों के बाद नेपाल के साथ उत्पन्न गतिरोध को न केवल समाप्त करने का कार्य किया अपितु नेपाल के सामरिक महत्व को समझते हुए द्विपक्षीय सम्बन्धों मे निवेश व सहायता की नीति को नयी ऊर्जा प्रदान की। नेपाल में चीन के बढ़ रहे प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से भारत ने विभिन्न सड़क, विद्युत व अन्य परियोजनाओं को आर्थिक सहायता का भी संकल्प प्रकट किया। यद्यपि भारत व चीन के अतिरिक्त अमेरिका, रुस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, नार्वे, स्विटजरलैण्ड, जापान व अन्य यूरोपीय देशों ने भी नेपाल में निवेश किया है[18] किन्तु नेपाल–केद्रित भारत व चीन की निवेश–स्पर्धा से नेपाल का भू–राजनीतिक महत्व बढ़ता जा रहा है। इस समय नेपाल में भारत व चीन द्वारा पोषित निम्नांकित योजनाएं चल रही है[19]–

Selected Indian and Chinese Projects in Nepal

Indian Projects	China's BRI Projects
Raxaul- Kathmandu Rail Link, Jogbani Biratnagar, Jaynagar-Baribas, Nepalganj Road-Nepalganj, Nautanwa-Bhairhwa and New Jalpaigudi-Kakarbhitta and establishment of Intigegrated Check Posts and Raxaul-Birganj, Sunauli-	Kathmandu and Kerung in North-Eastern Nepal. Kathmandu-Pokhra- Lumbini Rail Link. Pokhra International Air Port, US$ 130 Million. Cement Factory in Dhading 164 MW Nepal Kali Gandaki

Bhairhwa, Jogbani-Biratnagar and Nepal ganj Road Nepalganj. 900 MW Arun III hydropower in Tumlingtar small Project's, 6480 MW Pancheshwer Multipurpose hydro-electric Project, First transnational petroleum pipeline of 69 km pipeline from Motihari in Bihar to Amlekhganj in Nepal.	Gorge Hydropower Project, 40.27 MW Siurinyadi Power Plant, 600 MW Marshyangdi Cascade Hydropower, 75 MW Trisuli Galchhi Hydropower Project.

3–4 अगस्त, 2014 व सार्क के 18 वें शिखर सम्मलेन (26–27 नवम्बर, 2016) के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस यात्रा के दौरान मोदी ने जनकपुर, लुम्बिनी, हिमालय, गंगा, चारधाम व पशुपतिनाथ आदि के माध्यम से सुदृढ़ व सौहार्दपूर्ण भारत व नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्धों में व्याप्त सद्भावना व धार्मिक आस्था का उल्लेख किया। इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने पुष्प कमल दहल, मधेशी व अन्य दलों के प्रमुख नेताओं के साथ विचार–विमर्श करते हुए यह भी कहा कि दोनों देशों को सीमा–विवाद सहित अन्य सभी मसलों के द्विपक्षीय समाधान की कोशिश करनी चाहिए। 1950 की शान्ति व मैत्री सन्धि की समीक्षा सम्बन्धी इच्छा का सम्मान करते हुए मोदी ने ज्वलन्त वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में कहा कि इसमें भी संसोधन सम्भव है किन्तु इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।[20] दोनों देशों के सम्बन्धों को सुदृढ़ आधार देने हेतु निम्नांकित तीन विधियों (HIT) का भी प्रस्ताव मोदी ने रखा–[21]

1. Highways
2. Information ways (Information Technology)
3. Transways (Transmission Lines)

मोदी ने इस अवसर पर भारत व नेपाल सम्बन्धों को विस्तारित करते हुए 1 बिलियन डालर के 'साफ्ट–क्रेडिट' लाइन की भी घोषणाा की जिसके अन्तर्गत विकास सम्बन्धी मूलभूत परियोजनाओं, रक्सौल–अमलेखगंज,–काठमाण्डू, पेट्रोलियम लाइन का निर्माण, जनकपुर, भैरहवाँ व नेपालगंज के प्रवेश द्वारों पर वायु सुविधा प्रदान करने तथा प्रोजेक्ट डेवलपमेण्ट एग्रीमेण्ट (PDA)का गठन कर अपर करनाली व अरूणा–III इाहड्रोपावर परियोजनों को विकसित करने का भी संकल्प किया। इस अवसर पर ''भारत–मैत्री शिक्षा कार्यक्रम'' के अन्तर्गत नेपाल के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने व भारतीय विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नेपाली छात्रों के प्रवेश का भी निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि मोदी की नेपाल यात्रा के पूर्व भारत–नेपाल के मध्य 1987 में 'गठित ज्वाइण्ट–कमीशन', जो विगत 23 वर्षो से निष्क्रिय था, के तत्वावधान में 26 जुलाई, 2014 को भारत की तत्कालीन विदेशमन्त्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा संयुक्त बैठक कर भारत–नेपाल सम्बन्धों के उक्त विस्तार हेतु किये गये प्रयत्न विशषतः उल्लेखनीय हैं। भारत–नेपाल आयोग की बैठक 1991 के बाद नहीं हो सकी थी।

चीन की निवेश–सहायता नीति–

नेपाल के प्रति चीन की भावना जहाँ एक ओर उसे इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रीय–संतुलन स्थापित करने पर आधारित है वहीं दूसरी ओर भारत के साथ–बफर राज्य के रूप में स्थापित उसकी भू–राजनैतिक महत्ता का लाभ उठाकर भारत के तराई क्षेत्र से संलग्न अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक अपना प्रभाव–विस्तार करना भी है। मूलतः, सुरक्षा–उन्मुख चीन की रणनीति का ही परिणाम है कि 1 अगस्त, 1955 को कूटनीतिक सम्बन्धों के पश्चात चीन ने नेपाल के साथ अप्रैल, 1960 में 'शान्ति व मैत्री सन्धि' व 5 अक्टूबर, 1961 को सीमा सन्धि करके नेपाल के साथ व्यापारिक व सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को गतिशीलता प्रारम्भ की। चीन ने अपने व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावी बनाने हेतु न केवल सुरक्षा–व्यापार को बलपूर्वक लागू किया अपितु सन् 2010 में समझौता ज्ञापन (MOU) के आधार पर जिलांग (Jilong), झांग्यू (Zhangnu), व पुलान (Pulan) स्थित तिब्बती सीमा चेकपोस्ट व नेपाल के तातोपानी, रसुआगढ़ी व धारचूला के मध्य व्यापार की सुविधाओं का विस्तार भी किया। इतना ही नहीं, तिब्बत के

विकास हेतु प्रकाशित एक श्वेत–पत्र (22 अक्टूबर, 2013) में चीन ने यह सुस्पष्ट किया कि स्थल मार्गो द्वारा दक्षिण एशिया में प्रवेश हेतु वह व्यापारिक गलियारों (Commodity Passage) का निर्माण कर रहा है जो उसके व्यापारिक–केन्द्रों–गिरोंग (Gyirong), झांग्मू (Zhangmu), याटुण्ग (Yatung), पुलान (Pulan), एवं रिवू (Riwu), में विकसित किये गये हैं। नेपाल में चीन के मूलतः दो ही स्वार्थपरक उद्देश्य हैं–

1. नेपाल में रह रहे लगभग 20,000 तिब्बती शरणार्थियों सहित अन्य चीन–विरोधी तत्वों का कठोरपूर्ण दमन।
2. भारत–नेपाल सीमा व तराई क्षेत्र में शक्तिशाली आधारभूत तन्त्र को विस्तारित कर भारत के उत्तरी सीमान्त पर प्रभुत्व स्थापित करना।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जहाँ एक ओर चीन ने नेपाल को निवेश व सहायता प्रदान कर उसके विकास सम्बन्धी मूलभूत ढांचे के स्वरूप को परिवर्तित करने की वृहद योजना प्रारम्भ की वहीं 'नेपाल–चीन मैत्री संगठन' की स्थापना करके मीडिया व संस्कृति पर प्रभाव डालने की गतिविधियों को बढ़ावा दिया। तराई क्षेत्र में चीनी अध्ययन केन्द्र (Confucius Centre) की स्थापना, चीन में शिक्षित नेपालियों (Arnico Society)[22] के साथ नियमित सम्पर्क व सुरक्षा एजेन्सियों के साथ सम्पर्क–बैठकों के आयोजन द्वारा चीन–विरोधी तत्वों पर उसने कठोर कार्यवाहियां भी की। नेपाल की सुरक्षा एजेन्सियों से भी चीन को पर्याप्त सहायता मिलती रही।

भारत यात्रा के दौरान जिनपिंग–मोदी की ममाल्युरम में सम्पन्न वार्ता (12–13 अक्टूबर, 2019) के बाद पीकिंग लौटते समय चीनी राष्ट्रपति ने नेपाल की भी यात्रा 2019 में सम्पन्न हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री के0पी0शर्मा ओली व सी0 जिनपिंग के मध्य हुई वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने 20 सूत्रीय मेमोरेण्डन आफ अन्डरस्टैडिंग (MOU) पर हस्ताक्षर किये। चीनी प्रमुख जेनजियावाओ (2012) व 1996 में जियांग जेमिन की नेपाल यात्रा के 23 वर्षो के पश्चात जिनपिंग की इस यात्रा का उद्देश्य जहाँ नेपाल में अपने प्रभाव–विस्तार का लक्ष्य था वहीं नई दिल्ली से काठमाण्डू जाना उनकी कूटनीतिक चाल भी जिसके माध्यम से वे भारत को यह सन्देश भी देना चाहते थे कि नेपाल उनके लिए कम महत्वपूर्ण

नहीं है। नेपाल की इस यात्रा पर पुष्प कमल दहल की निम्नांकित टिप्पणी सर्वथा उद्धरणीय है–

"Nepal firmly adheres to the policy of Non-alignment, disagree with the so called Indo-Pacific strategy and opposes any attempt to contain or thwart China's development. Nepal has always believed that China's development is an opportunity for Nepal and is willing to learn China's successful experience."

स्पष्ट है कि चीन की 'बेल्ट व रोड' परियोजना का प्रबल समर्थन व अमेरिका की इण्डो–पेसिफिक स्त्रातेजी का विरोध भारत व अमेरिका–भारत के मधुर हो रहे सम्बन्धों पर कटाक्ष ही था। मई 2017 में वी0आर0आई0 पर हस्ताक्षर कर चुके नेपाल द्वारा चीन के सामरिक, आर्थिक व राजनैतिक प्रभाव को स्वीकार करने का उद्देश्य नेपाल में स्थापित भारतीय प्रभाव–विस्तार पर अंकुश लगाना तो था ही साथ ही सन् 2015 में भारत द्वारा नेपाल की की गयी आर्थिक–नाकेबन्दी से उत्पन्न गम्भीर चुनौतियों का प्रत्युत्तर भी निहित था। इस यात्रा के अवसर पर चीन ने नेपाल में बी0आर0आई0 के अन्तर्गत निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण हेतु सहायता का संकल्प लिया है–

1. नेगार कोट में व्यू टावर का निर्माण।
2. रसुआगढ़ी–काठमाण्डू रेल परियोजना।
3. कोरला–पोखरा मार्गका विस्तार।
4. किमथानका–हाइल सड़क निर्माण।
5. हुमला व सिमीकोट में हैण्डीक्राफ्ट गाँव का उच्चीकरण।
6. नेपाल के सभी सात प्रान्तों में प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना।
7. रसुआगढ़ी के सीमा बिन्दु पर बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला की स्थापना।
8. नुआकोट, पंचखाल व केब्रे में छः एकीकृत जाँच चौकियों का निर्माण।
9. करनाली गालियारा (जमुनहा–हिल्सा),गण्डकी गालियारा (बेलहैया–कोरला),थोरी–केरूंग गलियारा, कोडारी–वीरगंज गालियारा एवं कोसी गालियारा (रानी–किमथानका) का निर्माण।
10. थिटमाड–लामाबगार–लैप्चा गालियारे का निर्माण।

11. महादेवखोला में वर्षा जल–संचयन परियोजना (काठमाण्डू) का निर्माण।

12. भू–जलसम्भावना पर कार्य।

13. गाल्ची–रसुआगढ़ी–केरूल, 400 केवी ट्रान्समिशन लाइन (भेरीगंगा में) का निर्माण।

14. काठमाण्डू आउटर रिंग रोड निर्माण।

15. सनकोसी बहुउद्देश्यीय योजना का विस्तार।

16. तराई क्षेत्र में सिंचाई परियोजना का विस्तार।

17. अरनिको राजमार्ग व जलवायु परिवर्तन योजना।

उल्लेखनीय है कि भारत व नेपाल के मध्य 1950 की मैत्री सन्धि के आधार पर भारत को ही उसका रणनीतिक साझीदार माना जाता था किन्तु चीन के साथ रणनीतिक सम्बन्ध कायम कर नेपाल ने उक्त सन्धि के विरूद्ध अपनी भावनाएं स्पष्ट कर दी। सुरक्षा सम्बन्धी समझौतों के अन्तर्गत दोनों देशों की सुरक्षा एजेन्सियों (पुलिस बल, खुफिया संगठनों, सीमा प्रबंधन व कानून प्रवर्तन अधिकारियों) के मध्य सम्पर्क व सहयोग को सुदृढ़ करते हुए द्विपक्षीय रिश्तों में नवीन ऊर्जा उत्पन्न करने का संकल्प चीन व नेपाल द्वारा लिया गया है। दो असमान शक्तियों के मध्य हुए उक्त समझौतों से शायद ही नेपाल लाभान्वित होकर अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ हो सके क्योंकि इस बात की सम्भावना प्रबल है कि नेपाल भी चीन के कर्ज–जाल में फंस सकता है क्योंकि चीन द्वारा नेपाल को भारत के विरूद्ध इस्तेमाल ही किया जायेगा। नेपाल को इस पर गम्भीर विमर्श की आवश्यकता है। माओवादी गृहयुद्ध की समाप्ति एवं नेपाल में लागू नये संविधान के पश्चात नेपाल में पर्यटन, जल विद्युत, कृषि खनन व निर्माण आदि क्षेत्रों में विश्व के कई देश प्रत्यक्ष निवेदश हेतु आकर्षित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दशक के प्रारम्भिक वर्षो में नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की दृष्टि से भारत सर्वोपरि था किन्तु 2008 से इस हिमालयी राज्य में चीन के निवेश में लगातार वृद्धि हुई और 2014 में कुल निवेश के संदर्भ में चीन ने भारत को पीछे कर दिया। सन् 2015–14 में चीन ने नेपाल को कुल एफ0डी0आई0 का 42 प्रतिशत योगदान दिया। इस कालावधि में चीन का निवेश

38 मिलियन अमेरिकी डालर रहा जबकि भारत का निवेश 22 मिलियन डालर था।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में चीन ने नेपाल की 125 परियोजनाओं में 57 मिलियन डालर (6.21 बिलियन नेपाली रूपये) का निवेश किया जबकि भारत का अंश 18 मिलियन डालर था। सन् 2017 में काठमाण्डू में आयोजित 'नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन' के बाद नेपाल में चीन की आर्थिक उपस्थिति कर निरन्तर विस्तार हो रहा है तथा वित्तीय सहायता व निवेश में उसकी प्रवृत्ति आक्रामक है। सन् 2019–20 के एक आंकड़े के अनुसार नेपाल की कुल एफ0डी0आई0 का 90 प्रतिशत अंश अकेले चीन का है (88 मिलियन अमेरिकी डालर) जबकि ब्रिटेन दूसरे नम्बर पर (1.85 मिलियन अमेरिकी डालर) तथा भारत का स्थान तीसरा (1. 76 मिलियन अमेरिकी डालर) है।

यहाँ पर यह उल्लेख सर्वथा प्रांसगिक है कि नेपाल की विविध विकास योजनाओं में भारत व चीन सहायता तो अवश्य कर रहे हैं किन्तु भारतीय सेवाओं में कार्यरत लगभग 32,000 नेपाल के गोरखा सैनिकों के वेतन के अतिरिक्त उन्हें पेंशन भी भारत प्रदान करता है। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 1,25,000 गोरखा सैनिकों को प्रतिवर्ष 1974 करोड रुपये की पेंशनराशि भी भारत द्वारा दी जा रही है। इतना ही नहीं, आज भी लगभग 6 लाख नेपाली भारत में रहकर विभिन्न कार्यों में संलग्न है। चीन के साथ नेपाल के प्रधानमन्त्री के0पी0शर्मा ओली व पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहल की सन्निकटता के बावजूद नेपाल–भारत सम्बन्धों की नैसर्गिक दृढता एवं विशिष्ट–निर्भरता का उन्हें संज्ञान भी है क्योंकि भू–राजनैतिक अवस्थिति इसकों प्रगाढ़ता प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि चीन ने अपने Tiangin, Shenzhen, Lianyungang Zhanjiang बन्दरगाहों के माध्यम से नेपाल को व्यापार सुविधा तो अवश्य प्रदान की है किन्तु उसे नेपाल–चीन व्यापार की भौगोलिक व आर्थिक दुरुहता का भी ज्ञान है। यह व्यापार भारत की तुलना में अत्यधिक व्ययशील व महँगाई को प्रोत्साहित करने वाला है। सम्भवतः यही कारण है कि नेपाल के विदेश मन्त्री ने नेपाल के त्रिपक्षीय व्यापार प्रक्रिया व प्रवृत्ति के सन्दर्भ में कहा था कि–

"Supporing the deveopment of Nepal should become the consenees of China and India . Nepal hopes to give play to its geographical advantage and serve as a bridge and bond between China and India so as to benefit from the development of China and India. This wish is reasonable and justifiable, and should be jointly supported by China and India"[23]

ध्यातव्य है कि यद्यपि चीन शनैः–शनैः नेपाल में प्रत्यक्ष निवेश कर अपना प्रभाव बढ़ाते हुए भारत–नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (पोखरा) व लुम्बनी के विकास द्वारा नेपालियों के साथ धार्मिक–सन्निकटता (वौद्धधर्म) की कोशिश अवश्य कर रहा है किन्तु नेपाल में भारतीय भूमिका के निर्धारक विभिन्न तत्व उसके लक्ष्य प्राप्ति में निश्चय ही उतने सरल नहीं है जितना वह समझ रहा है।

चीन–नेपाल–पाकिस्तान सामरिक त्रिकोण एवं भारत की सुरक्षा–

एक आर्थिक व सैन्य महाशक्ति के रूप में चीन के अभ्युदय से अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। त्वरित विकास व शस्त्रों के विशालतम भण्डारण के अतिरिक्त प्रभुत्व–विस्तार हेतु चीन की आर्थिक व सामरिक विस्तारवादी नीतियों से वैश्विक शक्ति–संतुलन उथल–पुथल के दौर से गुजर रहा है। उसकी वी0आर0आई0 परियोजना, दक्षिण चीन सागर में शक्ति–प्रक्षेपण व हिन्द महासागरीय क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापना सम्बन्धी गतिविधियों का भारत की सुरक्षा पर गम्भीर प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। दक्षिण एशिया के भारत के पड़ोसी राष्ट्रों एवं अफ्रीका तक उसके विस्तार से क्षेत्रीय–संघर्षो की ज्वलन्त श्रृंखला प्रारम्भ हो गयी है। जहाँ तक भारत का संदर्भ है, उसके हिमालयी सुरक्षा–सीमान्त पर नेपाल व पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से चीनी अतिक्रमण व भारत के प्रति नेपाल व पाकिस्तान की आक्रामक मनोवृत्ति के कारण भारत की सुरक्षा के लिए गम्भीर चुनौतियाँ उत्पन्न हो गयी है। कश्मीर केन्द्रित पाकिस्तान की आक्रामक गतिविधियाँ व आतंकवाद तथा नेपाल द्वारा उत्पन्न कालापानी लिपुलेख सीमा विवाद ऐसे ज्वलन्त मुद्दे हैं जिनके पीछे

चीनी–रणनीति उत्प्रेरक का कार्य कर रही हैं। इन मुद्दों का विश्लेषण निम्नवत् है–

भारत–चीन सीमा विवाद–

यद्यपि सदियों से स्थापित भारत व चीन के सांस्कृतिक व आर्थिक सम्बन्ध मधुर रहे हैं किन्तु भारतीय स्वाधीनता के उपरान्त सन् 1959 में तिब्बत पर चीनी अधियत्व एवं तिब्बत–रूपी बफर राज्य की समाप्ति के उपरान्त दोनों के मध्य उत्पन्न सीमा–समस्याएं जटिल आयाम लेती रही हैं। सन् 1962 में हुए भारत–चीन युद्ध के पश्चात जहाँ एक ओर भारत व चीन के मध्य सीमा सम्बन्धी जटिलताएं बढ़ती गयी वहीं चीन–पाक सीमा समझौता (1963) एवं 1965 व 1971 के भारत–पाक युद्ध में चीन का पाकिस्तानी समर्थन एवं उसे भारत के विरूद्ध सामरिक व नाभिकीय हथियारों से सुसज्जित करने की चीनी रणनीति ने क्षेत्रीय–संघर्ष एवं तनाव में ऐसी उत्तेजना उत्पन्न की जिसके प्रभाव सम्पूर्ण एशियाई क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक भारत–चीन सीमा विवाद का प्रश्न है, मानचित्र, ऐतिहासिक तथ्य एवं समस्या–समाधान प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में यह पुष्ट होता है कि जटिल भू–आकृति एवं चीन के दोहरे व क्षद्मपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप इसका समाधान सम्भव नहीं हो पा रहा है। चीन ने अपनी दक्षिणी सीमान्त नीति के निर्धारण में मानचित्रों के अन्तर्गत अतिक्रमण नीतियों (Cartographical Encroachments) को सर्वथा प्राथमिकता दी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार[24] व पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना (PRC)[25] द्वारा सीमा–संरेखण (Boundary Alignment) अथवा अन्य किसी भी प्रकार के स्रोतों द्वारा प्रस्तुत साहित्यों से यह पुष्ट होता है कि पश्चिमी सेक्टर[26] लिंजीतांग (Lingzitang)व अक्साई चिन (Aksai Chin) के मध्य तथा दक्षिणी हिमालयी क्षेत्र के असम (अरूणाचल)[27] तक विस्तृत पहाड़ी भू–भागों पर चीन ने पहली बार लिखित रूप से 1959 में ही अपना दावा प्रस्तुत किया[28] जबकि चीन के मंचू साम्राज्य (1644–1912) व रिपब्लिक आफ चाइना (1912–1944) द्वारा प्रकाशित मानचित्रों में कम से कम 1922 तक भारत से संलग्न लद्दाख व पूर्वोत्तर भारत के अरूणाचल प्रदेश पर चीन के अधिकारों का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उल्लेखनीय है कि चीन की सरकार (GOC) द्वारा 1919 में अधिकारिक रूप से प्रकाशित

'चाइना पोस्टल अलबम' (China Postal Album) मानचित्र तथा 1917 में शंघाई से 'नार्थ चाइना डेली न्यूज व हेराल्ड' द्वारा प्रकाशित "New Atlas and Commercial Gazetteer of China" में भी लद्‌ाख व अरूणांचल क्षेत्रों को चीन के भू–क्षेत्रों में प्रदर्शित नहीं किया गया था जबकि इसको निर्मित करने की तकनीक उच्चस्तर की थी। इतना ही नहीं, सन् 1908 में भी शंघाई स्थित एक चीनी शिष्टमण्डल द्वारा चीन के मंचू साम्राज्य के एक एटलस (Ta Ching Ti Kuo Chuan Tu) में भी सीक्यांग के उच्च क्षेत्रों व हिमालय के दक्षिण में स्थित तवांग को तिब्बत का भू–क्षेत्र नहीं बताया। तदुपरान्त, सन् 1922 में चीन के सन्यात सेन द्वारा अपनी पुस्तक (The International Development of China) में पहली बार लद्दाख व असम को चीन के भू–क्षेत्र के रूप में उल्लेख से ही विवादों का जन्म हुआ। यह पुस्तक 1922 में उनके द्वारा निजी रूप में प्रकाशित की गयी जो सरकारी दस्तावेज नही हैं। सन्यात सेन की पुस्तक को ही आधार मानते हुए रिपब्लिक आफ चाइना ने सन् 1933 में अधिकारिक रूप से एक मानचित्र (Aka Shen-Pao Atlas-1933) प्रकाशित किया जिसमें पश्चिमी व पूर्वोत्तर के भारतीय भू–भागों (लद्दाख व अरूणाचल से सम्बन्धित) को चीनी भू–क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया। यद्यपि इस एटलस पर सरकारी मुहर न लगी होने से कुछ पश्चिमी भू–राजनीतिज्ञों व सर्वेक्षण–विशेषज्ञों ने इस पर आशंका प्रकट तो अवश्य की तथापि चीन व ब्रिटिश–भारत की सरकारों के मध्य सीमा–विवाद की आशंकाओं को बल तो अवश्य मिला। चीन द्वारा मानचित्रण–अतिक्रमण की कूटनीतिक साजिश के पश्चात पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना (PRC) ने अधिकारिक रूप से अक्टूबर 1950 में लद्दाख व असम की सीमाओं से सम्बन्धित अपना पहला मानचित्र प्रकाशित कर पश्चिमी सेक्टर (लद्दाख) में चांगचेन्मो घाटी (Changchenmo Vally) को अपना भू–भाग बताया। यह मानचित्र ऐसे अवसर पर आया जब तिब्बत–विद्रोह चरम पर था तथा तिब्बत व चीन के मध्य दिसम्बर 1953 में पीकिंग में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके थे।[29] जनवरी, 1956 में चीन द्वारा प्रकाशित प्रथम मानचित्र (Wall Map of the People's Republic of China) ही वह आधार है जिसने भारत व चीन के मध्य प्रत्यक्ष सीमा विवाद को जन्म दिया।

जहाँ तक भारत व चीन के मध्य उत्पन्न सीमा–विवाद का ऐतिहासिक संदर्भ है, पश्चिम सेक्टर में उत्तर की ओर कुनलुन पर्वत, दक्षिण की ओर काराकोरम पर्वत एवं पश्चिम की ओर से पामीर गाँठ की काश्गर रेंज के पूर्वोत्तर किनारों से घिरा यह क्षेत्र वास्तविक रूप से पूर्णतः बंजर (Barren) है तथा इसी क्षेत्र में सीक्यांग व कश्मीर के मध्य कारवाँ मार्ग के साथ–साथ यहाँ 'नो मैन्स लैण्ड' स्थित है।[30] स्त्रातेजिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण इस क्षेत्र पर 1862 तक न तो मंचू साम्राज्य और न ही ब्रिटिश–भारत सरकार का कोई दावा रहा है। किन्तु 1863 के उपरान्त इस क्षेत्र में रूस के सम्भावित प्रवेश पर नियन्त्रण हेतु कश्मीर–सीक्यांग एवं सीक्यांग–अफगानिस्तान के रिक्त क्षेत्र की सुरक्षा हेतु कैप्टन यंगहसबैण्ड के नेतृत्व में ब्रिटिश–भारत सरकार ने जल–विभाजन सिद्धान्त के आधार पर सीक्यांग व कश्मीर के मध्य विभाजन का निर्धारण किया जिसमें अक्साई चिन कश्मीर को सौंप दिया गया। उधर चीन ने कश्मीर की उत्तरी सीमा को अनिर्धारित बताते हुए ब्रिटिश मानचित्रों को संदिग्ध माना जबकि चांगचिनमों (Changchinmo)व लिंग्जीतांग (Lingzitang) पर कश्मीर के अधिकार के संदर्भ में कोई आशंका कभी भी नही रही क्योंकि ब्रिटिश–सरकार ने इसका निर्धारण कर दिया था।

जहाँ तक भारत व चीन के मध्य पूर्वी सेक्टर के सीमा विवाद का संदर्भ है, 20वीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकों तक असम के अन्दर स्थित हिमालय क्षेत्र एवं असम के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (वर्तमान अरूणाचल प्रदेश) के मध्य का भू–क्षेत्र मानचित्र में रिक्त प्रदर्शित होता रहा है तथापि न तो यह क्षेत्र गुप्त (Terra incognita) और न ही 'नो मैन्स लैण्ड' (No Man's Land) था। पी0आर0सी0 था। आज तक इस क्षेत्र पर न तो तिब्बत के स्वामित्व और न ही इस क्षेत्र के गैर तिब्बती बौद्ध निवासियों के साथ उनके सम्बन्धों का कोई उपयुक्त प्रमाण चीन प्रस्तुत कर सका है। हाँ, इतना अवश्य है कि तिब्बती लोग इस क्षेत्र के गैर–तिब्बती बौद्ध लोगों से कुछ कर की वसूली अवश्य करते थे किन्तु यह 'राजस्व' के रूप में न होकर बौद्ध मठों हेतु दान के रूप में ही एकत्रित किया जाता था।[31] इन तथ्यों को रिपब्लिक चाइना की सरकार ने भी स्वीकार किया है। यद्यपि चीन के सिचुआन प्रान्त के एक जनजातीय नागरिक अधिकारी ने वेलांग

(Welong) गाँव के उत्तर स्थित येपुक नदी (Yepuk River) के गैर तिब्बती आदिवासी क्षेत्र में चीनी झण्डे व पिलर लगाकर इस क्षेत्र पर अधिकार का प्रयत्न अवश्य किया किन्तु अंग्रेज अधिकारियों ने सन् 1914 में चीनी झण्डे व सीमा स्तम्भों को हटा दिया।[32] इसी बीच जनवरी 1912 में तिब्बत से चीनी प्रभाव ंके समाप्त होने ंके फलस्वरूप आक्रोशित चीन की सरकार द्वारा तिब्बत पर अपनी प्रभुसत्ता की एक पक्षीय घोषणा[33] से तिब्बत के ऐतिहासिकता को धक्का तो अवश्य लगा किन्तु मंगोलिया की ही भाँति अक्टूबर 1912 में तिब्बत ने भी अपने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी।[34] उल्लेखनीय है कि तिब्बत पर रूसी अधिकार की सम्भावनाओं का सम्यक आंकलन करते हुए ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत ंके स्वतन्त्रता सम्बन्धी विकल्प को अस्वीकार कर दिया तथा इसे एक स्वायत्तशासी क्षेत्र मानकर तिब्बत पर चीन को नाममात्र का अधिराज्य अधिकार (Nominal Suzerainty) प्रदान कर दिया।[35] तिब्बत प्रश्न पर उत्पन्त गतिरोध ंके समाधान हेतु सन् 1913 के पश्चात कई प्रयत्न हुए किन्तु मंगोलिया प्रश्न पर हताहत चीन ने येनप्रकारेण तिब्बत पर नियन्त्रण बनाये रखने का प्रयत्न किया। ध्यातव्य है कि यह ब्रिटिश–भारत सरकार की नीतियाँ ही थी जिसने तिब्बत के प्रतिकूल महाजाल निर्मित कर उसके स्वाधीन अस्तित्व को औचित्यहीन कर दिया तथापि शिमला सम्मेलन में चीन–तिब्बत सम्बन्धी गतिरोध यथावत बने रहे। अन्ततः 3 जुलाई, 1914 ंके शिमला सम्मेलन में भारत–तिब्बत–वर्मा सीमा निर्धारण हेतु एक समझौता सम्पन्न हुआ जिसमें मैकमोहन लाइन का निर्धारण सम्भव हो सका[36] किन्तु चाऊ एन लाई ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का परिणाम मानते हुए मैकमोहन सीमा रेखा ंके दक्षिण स्थित भारत ंके गैर–तिब्बती क्षेत्रों पर अपना दावा बताकर इसे अस्वीकार कर दिया। पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना का मत है कि तिब्बत किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते की पात्रता उस समय नही रखता था जबकि[37] चीनी तर्क निम्नांकित तथ्यों से औचित्यहीन प्रतीत होते हैं–

1. शिमला समझौते के समय तिब्बत पर चीन अधिराज्य सम्बन्धी सभी सुविधाओं से वंचित था इसलिये चीन को इसमें भाग लेने का कोई अधिकार नही था।[38]

2. सन् 1912 व 1949 की अवधि में चीन की तिब्बत में अनुपस्थिति के कारण तिब्बत पर सम्प्रभुता व अधिराज्य सम्बन्धी उसके दावे सर्वथा निराधार हैं।[39]

3. तिब्बत व पी.आर.सी. के मध्य चल रहे युद्ध में अंग्रेजों ने उनके मध्य अगस्त 1918 में चामड़ो समझौता (Chamdo Agreement) व अक्टूबर 1918 में रॉगवस्ता युद्ध–विराम सन्धि (Rongbasta Truce) के द्वारा सम्बन्धों में उत्पन्न संघर्ष पर विराम लगाया था।[40]

4. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जब चीन मित्र–राष्ट्रों के साथ युद्ध में सम्मिलित था तब तिब्बत ने तटस्थ रहते हुए भारत से होकर चीन जाने वाले शस्त्र–आपूर्ति हेतु अपनी भूमि का प्रयोग नही होने दिया।[41] तिब्बत की तटस्थ स्थिति को मित्र राष्ट्रों सहित चीन ने भी मान्यता दी थी। सन् 1943 में ब्रिटिश दूतावास से प्रकाशित एक सन्देश में कहा गया था कि–

"The Government of India has always held that Tibet is a separate country in full enjoyment of locol autonomy, entitled to exchange diplomatic representatives with other powers. The relationship between Tibet and China is not a matter which can be unilaterally decided by China."[42]

5. ब्रिटेन द्वारा सन् 1943 में सम्पन्न चुनकिंग सन्धि (Treaty of chunking) के अन्तर्गत चीन हेतु घोषित क्षेत्रीय अधिकार व्यवस्था के अन्तर्गत तिब्बत पर चीन के अधिकार की मान्यता नहीं दी थी। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिकार को 1954 में चीन के साथ सम्पन्न पंचशील समझौते के अन्तर्गत भारत ने उसे को प्रदान कर दिया जबकि अक्टूबर 2008 में ब्रिटेन ने भी तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता दे दी।

उक्त तथ्यों से सुस्पष्ट है कि सन् 1914 में सम्पन्न शिमला समझौते में ब्रिटेन के साथ मैकमोहन सीमा निर्धारण प्रक्रिया में तिब्बत का भाग लेना सर्वथा न्यायसंग था तथा उस समय तिब्बत एक स्वतन्त्र देश था न कि चीन के

अधिराज्य अधिकार में। यहाँ पर यह भी सर्वथा उल्लेखनीय है कि चाऊ एन लाई द्वारा लगाये गये आरोप, कि यह समझौता गुप्त रूप से बिना चीन को संज्ञान में लिये ही किया गया, भी निराधार हैं क्योंकि 27 अप्रैल, 1914 को चीन के एक दूत इवान चेन के संलग्न मानचित्र पर पूरे व स्पष्ट हस्ताक्षर हैं तथा तिब्बत के प्रतिनिधि लोचेन शात्रा (Lochen Shatra) ने हस्ताक्षर से पूर्व ल्हासा की अनुमति प्राप्त कर ली थी।[43] उक्त तथ्य इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं कि मैकमोहन सीमा रेखा ही वर्तमान में भारत–चीन के मध्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा है। अरूणाचल प्रदेश (पूर्व असम) पर चीन का दावा पूर्णतः तथ्यहीन, निराधार व उसकी विस्तारवादी मानसिकता का ही द्योतक है। अक्टूबर 1954, 3 दिसम्बर, 1956 व 1 जनवरी,1957 को चाऊ–नेहरू वार्ताओं के अवसर पर भी चाऊ–एन–लाई के प्रकट निम्नांकित विचारों से भी पुष्टि होती है

"……now that the (Mac Mohan Line) is an accomplished fact, we should accept it……still we feel that there is no way to better way than to recognise this Line."[44]

किन्तु तिब्बत के प्रति चीनी आक्रोश के परिणामस्वरूप अन्ततः 1959 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत में प्रवेश कर तिब्बती प्रतिक्रिया का दमनकर उसे चीन में शामिल कर लिया। इस संघर्ष में लगभग 87,000 तिब्बती मारे गये तथा भारी संख्या में उन्हें पलायन करना पड़ा।[45] इस घटना के पश्चात ही भारत–चीन सीमा विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया जिसकी परिणति थी 1962 का भारत–चीन युद्ध। इस युद्ध में चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र के 37,550 वर्ग किमी0 भूमि पर बलपूर्वक कब्जा तो किया ही साथ ही शक्सगम घाटी के लगभग 5180 किमी0 भू–भाग को पाकिस्तान से प्राप्त कर इस क्षेत्र में अपनी सामरिक श्रेष्ठता स्थापित कर ली। एक लम्बे अन्तराल तक भारत–चीन के मध्य सीमा विवाद पर तनाव बना रहा तथा 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की चीन यात्रा के बाद ही सीमा–विवाद हल करने पर दोनों देश सहमत हुए। इस यात्रा के बाद यद्यपि भारत व चीन ने संयुक्त कार्यकारी दल (J.W.G.S.) की स्थापना कर सीमा–विवाद समाधान की प्रक्रिया अवश्य प्रारम्भ की किन्तु चीन के एक मुश्त प्रस्ताव (Package Proposal) सम्बन्धी जटिलताओं के कारण कोई प्रगति न हो

सकी। तदुपरान्त सन् 1993 व 1996 में दोनों ही देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का सम्मान करते हुए सम्पूर्ण रेखा पर शान्ति व स्थिरता की स्थापना एवं बल प्रयोग न करने का निर्णय लिया। भारत व चीन के मध्य लद्दाख सेक्टर पर तनाव–शैथिल्य हेतु किये गये सभी भारतीय प्रयत्नों की अनदेखी करते हुए चीन ने इसे ऐतिहासिक धरोहर (Historical Legacy) मानकर आर्थिक व व्यापारिक सम्बन्धों को प्राथमिकता दी। सन् 2014 में भारत में सत्तारूढ़ एन.डी.ए. सरकार ने भी सीमा–समस्या के निदान हेतु कूटनीतिक व राजनैतिक स्तर पर कई प्रयत्न किए किन्तु कोई सार्थक परिणाम नही निकला। मोदी–सी जिनपिंग के मध्य बीजिंग व दिल्ली में हुई वार्ताएं व वुहान–भावना भी निष्फल रही। इस बीच कोविड–19 जैसी महामारी के स्रोत चीन ने विश्व का ध्यान इससे हटाने तथा 'क्वाड', द्वारा भारत–अमेरिकी रणनीतिक सन्निकटता एवं भारत के बढ़ रहे आर्थिक व सामरिक सामर्थ्य से चिन्तित उसने लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में (15 जून, 2020) हिंसात्मक कार्यवाही करके एक बार पुनः अपनी अविश्वनीय छवि को विश्व के समक्ष प्रकट कर दिया।

वैश्वीकरण के वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रों के मध्य निरन्तर बढ़ रही पारस्परिक निर्भरता ऐसा पक्ष है जिसमें भारत व चीन ने इस शताब्दी में प्रारम्भ से ही आर्थिक–पक्षों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। सीमा–विवाद के अतिरिक्त आतंकवाद, जलवायु नियन्त्रण, मानवाधिकार आदि मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद भारत व चीन आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त निकट आये हैं। निम्नांकित तालिका से भारत–चीन के व्यापारिक गतिविधियों के सभी पक्षों को निम्वत् समझा जा सकता है–

<u>India China Bilateral Trade in $ Bn</u>.

Year	India's Export to China	% Charge	India's Import from China	% Change	Total Imbalance	Total Trade	% Change
2014	16.41	-3.72	54.24	11.95	87.83	70.65	7.88
2015	13.39	-18.39	58.26	7.42	44.87	71.65	1.42

2016	11.75	-12.29	59.43	2.01	47.68	71.18	-0.67
2017	16.34	39.11	68.1	14.59	51.76	84.44	16.63
2018	18.83	15.21	76.87	12.89	58.04	95.7	13.34

उक्त तालिका से पुष्ट है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तो अवश्य है किन्तु व्यापार घाटा भारत के लिए चिन्ता का विषय है क्योंकि भारत चीन से अधिक सामान खरीदता है जबकि निर्यात कम है। इस शताब्दी के प्रारम्भ में दोनों देशों के मध्य व्यापार मात्र 3 अरब डालर था जो अब बढ़कर 95.7 अरब डालर का हो गया है। इस अवधि में व्यापार घटा 58.04 हो गया। 2018–19 में भारत के कुल इलेक्ट्रानिक उत्पादों का 70 प्रतिशत, टेलीकम्युनिकेशन–उपकरण का 25 प्रतिशत, टेलीविजन उद्योग का 25 प्रतिशत, घरेलू उपकरणों का 12 प्रतिशत, आटोमोबाइल बाजार का 26 प्रतिशत, सोलर इनर्जी का 90 प्रतिशत, स्टील का 20 प्रतिशत, फार्मा का 70 प्रतिशत, न्यूक्लियर व मशीनरी का 18 प्रतिशत, आर्गेनिक केमिकल का 10 प्रतिशत एवं खेल–खिलौनों के 90 प्रतिशत बाजार पर चीन का ही एकाधिकार है। भारत कच्चेमाल के रूप में भी विद्युत मशीनरी, आप्टिकल, फोटोग्राफिक उपकरण व रसायन आदि का चीन से आयात करता है। बाजार की ही भाँति मोबाइल प्लेटफार्म भी चीनी एप से भरे पड़े हैं। चीन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी आगे है। चीनी कम्पनी अलीबाबा ने स्नैपडील, पेटीएम, बिग बास्केट, जोमैटो आदि में तथा टेनसेंट ने ओला, स्विगी व हाइक आदि में पर्याप्त निवेश किया हुआ है। शाओमी, ओपो आदि चीनी कम्पनियाँ भारत में उत्पादन केन्द्र संचालित कर रही हैं। अक्षय ऊर्जा, मोटर के कलपुर्जो, स्टील, दवा, उपभोक्ता वस्तुओं और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में चीन ने भारत में आठ अरब डालर से भी अधिक निवेश किया हुआ है। स्पष्ट है कि कहने को तो भारत जी0डी0पी0 के आधार पर विश्व की पाँचवी अर्थव्यवस्था है किन्तु चीन की तुलना में पाँच गुनी कम है। भारत की अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन डालर है जबकि चीन की 14.1 ट्रिलियन डालर है। भारत व चीन के आर्थिक सम्बन्धों की प्रगाढ़ता को देखते हुए चीन न तो भारतीय बाजार को त्याग सकता है और न ही भारत पूर्णतः चीन के आर्थिक बहिष्कार की

ही स्थिति में है। सीमा विवाद में चल रहे गतिरोध के फलस्वरूप भारत की जनता द्वारा चीन ंके आर्थिक बहिष्कार की बात भावनात्मक ज्यादा है वास्तविक कम। अतएव, भारत को जहाँ एक ओर आत्मनिर्भरता हेतु ठोस व व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए वहीं चीन के साथ व्याप्त व्यापार घाटे को न्यून करने हेतु अपनी निर्यात नीति में गम्भीरतापूर्वक संसोधन करना होगा। इसी के समानान्तर भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि आर्थिक पक्षों से कही अधिक आवश्यक है अपनी सम्प्रभुता एवं अखण्डता की रक्षा।

बदल रहे भू–राजनीतिक परिदृश्य में नेपाल में भारत व चीन की बढ़ रही रणनीतिक स्पर्धा तीनों देशों के लिए चिन्ताजनक है क्योंकि नेपाल में दोनों बड़े पड़ोसियों का संघर्ष नेपाल की विदेश, आर्थिक व घरेलू नीतियों हेतु क्षतिकारक होगा। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नेपाल के महाराजा पृथ्वी नारायण शाह द्वारा 18वीं सदी में ही नेपाल को "A yam between two boulders" की संज्ञा देने के पीछे उनका यह मन्तव्य[46] था कि नेपाल की सुरक्षा एक संतुलित विदेशी नीति के निर्धारण से ही सुनिश्चित की जा सकती है। 21वीं सदी में उक्त वक्तव्य और ही प्रासंगिक प्रतीत होता है। एशिया की दोनों बड़ी शक्तियाँ अपने मार्मिक हितों का पूर्ति हेतु नेपाल में संघर्षशील हैं।[47] जिससे नेपाल की विदेश–नीति एवं उसकी आर्थिक–सामाजिक संरचना मुख्य रूप से प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि 'जॉन डब्लू गार्नर' ने 1957 में तिब्बत पर अधिकार करने ंके उपरान्त नेपाल में चीनी सक्रियता पर प्रकाश डालते हुए भारतीय चिन्ताओं को रेखांकित किया है[48] तथा नेपाल को चीन व भारत के साथ त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोगी भावनाओं को अपने विदेश–नीति में शामिल कर तदनुसार आचरण की बात की है। भारत ंके हिमालयी सीमान्त के सुरक्षा परिदृश्य पर उत्पन्न चीन–नेपाल की संयुक्त नीति नियोजन व संचालन को ही ध्यान में रखकर दक्षिण एशियाई सुरक्षा मामलों ंके विशेषज्ञ एस0डी0मुनि ने भी सहयोगी सुरक्षा ढांचे (Cooperative Security Frame Work)[48] पर विशेष बल देते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु सम्बद्ध देशों को सलाह दी किन्तु एस0एस0पटनायक व निहार नायक ने बताया है कि यह सुरक्षा तन्त्र न केवल जटित अपितु चुनौतीपूर्ण है।[50] एस0डी0 मुनि ने नेपाल को यह भी

सलाह दी है कि उच्चस्तरीय कूटनीतिक कौशल द्वारा नेपाल को चीन व भारत के मध्य संतुलन स्थापित कर त्रिपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था के सृजन हेतु गम्भीर कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसी में उसके विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हित सुरक्षित व विकसित हो सकते हैं। किन्तु वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यह सम्भव प्रतीत नहीं होता क्योंकि नेपाल की के0पी0शर्मा ओली की साम्यवादी सरकार निष्पक्ष न होकर चीन के सहयोग से भारत–विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। कालापानी, लिपुलेख व लिम्पियान्धुरा के विवाद सम्बन्धी उसकी मानचित्र कूटनीति व राम जन्मभूमि विवाद सम्बन्धी उसकी सांस्कृतिक कूटनीति इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं। उधर चीन भी भारत की बढ़ रही शक्ति, जापान व अमेरिका के साथ भारतीय निकटता को अपनी घेरेबन्दी मानकर भारत के साथ सीमा विवाद मामलों मे उग्र है। 15–16 जून, 2020 को गलवान घाटी में हुआ भारत–चीन संघर्ष एवं सम्पूर्ण वासतविक नियन्त्रण रेखा पर सामरिक दबाव सम्बन्धी उसकी कुचेष्टा उक्त सन्दर्भ में सर्वथा उल्लेखनीय है।

भारत की स्त्रातेजिक पहल–

अपनी विशिष्ट भू–राजनैतिक व स्त्रातेजिक स्थिति के कारण भारत सदैव महाशक्तियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। लगभग 32,87,240 वर्ग किमी में विस्तृत भारत विश्व का सातवाँ बड़ा देश एवं विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश व म्यांमार भारत की सीमाओं पर स्थित ऐसे देश हैं जिनमें चीन, पाकिस्तान व नेपाल के साथ सीमा–विवाद के कारण उभयपक्षीय सम्बन्ध तनावपूर्ण बने हुए हैं। कश्मीर–केन्द्रित भारत–पाक सम्बन्ध, चीन–भारत सीमा विवाद एवं नेपाल में बढ़ रहा चीन का सामरिक–आर्थिक प्रभाव 21वीं शताब्दी की ऐसी चुनौती है जिसने भारत के उत्तरी सुरक्षा–सीमान्त को असुरक्षित तो बनाया ही है साथ ही हिन्दमहासागर में चीन की घुसपैठ के कारण नवीन सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न हो गयी है। जहाँ तक नेपाल–भारत के द्विपक्षीय सम्बन्धों का प्रश्न है, अभिन्न रूप से भारतीय प्रभाव में होने के बावजूद चीन की प्रेरणा व उत्प्रेरणा से वह भारत के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है। वैसे पृथक रूप से नेपाल से भारत के समक्ष कोई गम्भीर चुनौती नहीं है तथापि चीनी–प्रभाव व भारत–नेपाल सीमा पर

उसका निरन्तर बढ़ रहा दबाव निश्चित रूप से चिन्ताजनक है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मन्त्री रहे जार्ज फर्नान्डीज ने चीन को भारत का प्रथम श्रेणी का शत्रु माना था जो आज सत्य होता लग रहा है। भारत को वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष खतरे चीन द्वारा उत्पन्न किये जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का सतत विकास, सैन्य आधुनिकीकरण एवं चीन से लगी सीमा पर भारत की विस्तृत व सुदृढ़ हो रही आधारभूत रक्षा सुविधाएं चीन को बेचैन कर रही हैं। द0पू0 एशियाई क्षेत्र में भारत की 'सक्रिय एक्ट ईस्टपालिसी', क्वाड में सहभागिता, द0 चीन सागर में भारत की सक्रिय अभिरूचि आदि ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हे चीन पसन्द नहीं करता। इतना ही नहीं, भारत की मोदी सरकार का जम्मू–कश्मीर से धारा 370 को हटाना, जम्मू–कश्मीर व लद्दाख को केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा देने एवं सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर (आक्साईचिन सहित पी0ओ0के0) को वापस लेने सम्बन्धी भारतीय संसद में प्रकट भारतीय संकल्प से इस क्षेत्र की भू–राजनीति में अद्भूत सम्वेदना व हलचल पैदा हो गयी है। इससे चीन अत्यन्त व्यवस्थित व आक्रोशित है क्योंकि अब चीन की कश्मीर–नीति एवं सी0पी0ईसी0 परियोजना के समक्ष उसे गम्भीर चुनौती मिलने की आशंका प्रबल होती जा रही है।

चीन की बी0आर0आई योजना में भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार बांग्लादेश सहित श्रीलंका व मालद्वीव के शामिल होने से इस क्षेत्र में चीन–भारत स्पर्धा में तीव्रता आई है। चीन–पाक आर्थिक गालियारा (CPEC) व बांग्लादेश–चीन–भारत–म्यांमार परियोजना (BCIM) तो भारत के लिए प्रत्यक्ष चुनौती है। यही कारण है कि अपनी सम्प्रभुता एवं अखण्डता की दृष्टि से भारत ने वी0आर0आई0 का प्रबल विरोधी किया है। 15 जून, 2020 को चीन व भारत की सेनाओं के मध्य गलवान घाटी क्षेत्र में हुआ संघर्ष एवं सम्पूर्ण 'वास्तविक नियन्त्रण रेखा' (LAC) पर व्याप्त तनाव से भारत–चीन सम्बन्धों को गहरा आघात पहुँचा है। इस संघर्ष हेतु उत्तरदायी करक निम्नवत् हैं–

1. भारत की आक्रामक कश्मीर–नीति से चीन अत्यन्त व्यथित है। 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर से धारा 370 को हटाकर जम्मू–कश्मीर व लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाने से इस क्षेत्र की

भू–राजनीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय संसद में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गयी घोषणा, कि सम्पूर्ण जम्मू–कश्मीर राज्य (पाक–अधिकृत कश्मीर व चीन–अधिकृत अक्साई चित्र क्षेत्र सहित) भारत का अभिन्न अंग है तथा वे इन सभी क्षेत्रों को वापस लेने हेतु संकल्पित हैं, से चीन व पाकिस्तान की कश्मीर केन्द्रित रणनीति को गहरा आघात पहुँचा है।

2. लद्दाख क्षेत्र में भारत की निरन्तर सुदृढ़ होती जा रही सामरिक संरचना व सियाचिन सहित दौलत बेग ओल्डी (DBO) में स्थापित रणनीतिक–वर्चस्व से काराकोरम हाईवे (KKH) व खुंजेरब दर्रे से गुजर रहे चीन–पाक आर्थिक गालियारे (CPEC) की असुरक्षा चीन के लिए गहरा सामरिक–आर्थिक आघात है।

3. वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) के निकट लद्दाख से गुटनिरपेक्षता के आदर्शवादी मोहजाल से निकलकर अपने आर्थिक व रणनीतिक हितों की पूर्ति व इसके संवर्धन हेतु भारत की सक्रिय बहुध्रुवीय–संलग्नता नीति के परिणामस्वरूप अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया तथा एशियान देशों के साथ मैत्री स्थापना सम्बन्धी भारतीय प्रयत्न चीन के एशिया–प्रशान्त क्षेत्र से जुड़े हितों के विरूद्ध होने से वह भारत की सामरिक घेरेबन्दी हेतु तत्पर है। भारत के रक्षा–सामर्थ्य में हो रही निरन्तर अभिवृद्धि व तीव्रता से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था चीन के वैश्विक व क्षेत्रीय हितों में अवरोधक सिद्ध हो रही है। उल्लेखनीय है कि आई0टी0, अन्तरिक्ष अनुसंधान, प्रक्षेपास्त्र निर्माण क्षमता, घातक विमानों, टैंक व नौ सैन्य–शक्ति से सुसज्जित भारतीय सेना पर्याप्त सक्षम है तथा वह चीन व पाकिस्तान के संयुक्त हमलों का प्रतिकार भी कर सकती है।

चीन द्वारा भारत की की जा रही सामरिक घेरेबन्दी से प्रेरित जहाँ एक ओर भारत ने (बी0आर0आई0 के परिप्रेक्ष्य में) अपनी रक्षा समाघात क्षमता में अद्भूत वृद्धि की है वहीं इजराइल, रूस, जापान, इंग्लैण्ड, जापान, आस्ट्रेलिया, अमेरिका व यूरोपीय समुदाय के देशों के साथ आर्थिक व सामरिक सम्बन्धों को पर्याप्त सदृढ़ करने की विदेश

नीति का संचालन किया है। राफेल विमान, एस–400 वायुरक्षा प्रणाली, अपाचे अटैक हेलिकाप्टर व अमेरिकी एन0एस0ए0एम0 एस–II प्रक्षेपास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली आदि की आपूर्ति यह सिद्ध करती है कि भारत–चीन–पाक संयुक्त चुनौतियों के प्रति भारत पर्याप्त सतर्क है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शीतयुद्ध काल में भारत की महान स्त्रातेजी के लक्ष्यों व रक्षा प्रवृत्ति के संदर्भ में यह उल्लेख प्रासंगिक है कि उस दौरान अपनी बाधक नीति (Moat Building) के अन्तर्गत भारत ने अपनी आर्थिक–राजनैतिक स्थिति की सुदृढ़ता पर तो ध्यान अवश्य दिया किन्तु रक्षा तैयारियों के प्रति उदासीनता बनी रही। गुटनिरपेक्षता, हरितक्रान्ति व पंचशील में ही संलग्न भारत ने सन् 1962 में चीन से हुई पराजय के पश्चात ही रक्षा को भी अपनी विदेशनीति में प्राथमिकता दी। 1990 के दशक की भू–राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत ने वैश्विक दृष्टि अपनाते हुए सैन्य व आर्थिक दृष्टि से सामर्थ्यवान देशों के साथ एफ0डी0आई0 व शस्त्र आपूर्ति की नीति को संचालित करते हुए न केवल चीन से व्यापार को प्राथमिकता दी अपितु वैश्विक सामरिक सीमान्त विस्तार सम्बन्धी प्रयत्नों को भी शीर्ष पर रखा। अरूणाचल प्रदेश तक सड़क, संचार व हवाई अड्डों के व्यापक विस्तार सम्बन्धी भारतीय प्रयत्नों से सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में चीन के वर्चस्व कों दी गयी चुनौती से न केवल वह आक्रोशित अपितु असंयमित भी हो गया है।

4. लद्दाख क्षेत्र में लेह–चुशूल–दौलत बेग ओल्डी मार्ग के निर्माण सम्बन्धी भारतीय प्रयत्नों से चीन चिन्तित है क्योंकि यह मार्ग वास्तविक नियन्त्रण रेखा के निकट से ही गुजरता है। भारत के रक्षा मन्त्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत–चीन सीमा पर चिन्हित 3812 किमी सड़क निर्माण येाजनान्तर्गत भारत ने 3418 किमी0 निर्माण का कार्य भारत के 'सीमा सड़क संगठन' ने पूरा कर लिया है जिससे सीमा पर भारत द्वारा शीघ्रता से युद्धक साजोंसामान पहुँचाए जा सकते हैं। रणनीतिक महत्व के पुलों व हवाई पट्टियों के निर्माण से इस क्षेत्र में भारत की संहारक क्षमता व रणनीतिक गतिशीलता में अद्भुत वृद्धि हुई है।

5. सन् 2016 में ही भारत ने अरूणाचल प्रदेश की सीमा पर टैंक व सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस तैनात कर दिये गये हैं साथ ही अन्य रक्षा सम्बन्धी सामानों को भी इस क्षेत्र में बढ़ा दिया गया है। सन् 2017 में ब्रह्मपुत्र की सहयोगी नदी लोहित पर 9.15 किमी0 का पुल बन जाने से ाारत के युद्धक टैंक व अन्य भारी वाहन कम से कम समय में सीमा पर भेजने में भारत सफल हो गया है।

6. भारत की बदल रही रणनीतिक–संस्कृति व आक्रामक–रक्षात्मक रक्षा संक्रियाएं चीन सहित पाकिस्तान के लिए चिन्ताजनक तो हैं ही साथ ही पाकिस्तान के विरूद्ध किए गये 'सर्जिकल स्ट्राइक' से क्षेत्रीय स्तर पर प्रकट भारत की आक्रामक–क्षमता एवं जम्मू–कश्मीर में सक्रिय पाक–समर्थित आतंकवादियों के विरूद्ध किए जा रहे निर्णायक आतंक–विरोधी प्रहार के परिणामस्वरूप चीन–पाक रणनीतिक मैत्री व उनके वृहद उद्देश्यों पर जो तुषारापात हो रहा है उससे चीन की मनोवृत्ति का आक्रामक होना स्वाभाविक है।

भू–रणनीतिक दृष्टि से भारत पर चीन द्वारा बी0आर0आई0 के माध्यम से नेपाल व पाकिस्तान के माध्यम से डाला जा रहा दबाव सर्वाधिक चिन्ता का विषय तो है ही साथ ही दोनों के मध्य व्यापारिक पक्ष में व्याप्त असंतुलन व एफ0डी0आई0 के चीनी दबाव के फलस्वरूप भारत के रण्नीतिक व आर्थिक मोर्चे दबाव में है। जहाँ तक भारत–चीन के मध्य व्यापारिक असंतुलन का प्रश्न है उसमें शनैः शनैः कमी आ रही है। सन् 2017–18 में जो व्यापार घाटा 63 अरब डालर था वह घटकर 2018–19 में 53.56 अरब डालर व 2019–20 में 48.6 अरब डालर हो गया है। इसी प्रकार चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2018–19 में 22.9 करोड़ डालर की तुलना में 2019–20 में 16.38 करोड़ डालर हो गया। भारत को व्यावहारिक व्यापारिक नीति अपनाकर इसे न्यून स्तर पर लाना होगा तभी हमारी आर्थिक–निर्भरता चीन के संदर्भ में कम हो सकेगी। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत उत्पादन क्षमता में त्वरित ढंग से कार्य करते हुए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे। यही कारण है कि भारत ने चीन की बी0आर0आई0 का न केवल विरोध किया है अपितु अपने आर्थिक व सामरिक हितों के रक्षार्थ पड़ोसी

देशों के साथ सम्पर्कों में उत्तरोत्तर समृद्धि हेतु गम्भीर कदम भी उठाये हैं। भारत सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर बांग्लादेश–भूटान–भारत–नेपाल (BBIN) पहल प्रारम्भ की है तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर उत्तर–दक्षिण यातायात गालियारे के माध्यम से रूस, केन्द्रीय एशिया, ईरान, अफगानिस्तान व यूरोप तक अपनी पहुँच को सरल बनाने का भी प्रयत्न किया है। भारत व जापान, संयुक्त रूप से अफ्रीका, ईरान, श्रीलंका व अन्य द0पू0 एशियाई देशों में मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु तत्पर हैं जिससे चीनी प्रभाव को सीमित किया जा सके। चाबहार बन्दरगाह व इससे सम्बद्ध क्षेत्र में आर्थिक–क्षेत्र को विकसित करने सम्बन्धी भारत–जापान सहयोग के अतिरिक्त श्रीलंका के ट्रिन्कोमाली बन्दरगाह तथा थाई–म्यांमार सीमा पर स्थित दाबी (Dawei) बन्दरगाह के विकास हेतु संयुक्त प्रयत्न इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। 23 मई, 2017 को गाँधी नगर में 'अफ्रीकी विकास बैंक' के सम्मेलन में भारत द्वारा एशिया–अफ्रीका ग्रोथ कोरिडर (AAGC) की स्थापना सम्बन्धी प्रयत्न इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि जापान व अमेरिका के साथ उक्त क्षेत्रों में भारत की गतिविधियाँ अफ्रीका महाद्वीप में चीनी प्रविस्तार पर अंकुश लगाने हेतु निश्चय ही महत्वपूर्ण हैं। व्यापारिक दृष्टि से ए0ए0 जी0सी0 सर्वाधिक महत्वाकाँक्षी योजना है जिसके माध्यम से जामनगर, कलकत्ता व मदुरै के भारतीय बन्दरगाह जिबुती (अदन की खाड़ी), मोम्बासा व म्यांमार के सिटवे बन्दरगाह (Sittwe) से जुड़ जाने से एशिया व अफ्रीका के कई राष्ट्रों के मध्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार एवं व्यापारिक सम्बन्धों में नयी ऊर्जा मिलेगी। उक्त परियोजना हेतु जापान ने तकनीकी सहायता एवं उत्तम स्तर के आवश्यक साज–सामान प्रदान करने का संकल्प लिया है। इतना ही नहीं, चीन के विस्तारवादी आक्रामक मनोवृत्ति पर नियन्त्रण हेतु अमेरिका ने भारत–केन्द्रित एक 'नयी सिल्क रोड' (A New Silk Road) को भी योजना बनाई हैं जो अफगानिस्तान के समस्त पड़ोसियों को जोड़ने के साथ–साथ 'इण्डो–पेसिफिक इकोनोमिक कोरिडर' को दक्षिण एशिया एवम् द0पू0 एशिया से संलग्न करेगी। उल्लेखनीय है कि भारत ने बी0आर0आई0 के प्रभाव को सीमित करने हेतु अपनी 'एक्ट ईस्ट नीति' के अन्तर्गत क्षेत्रीय सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाने हेतु मेघालय को म्यांमार व थाईलैण्ड से जोड़ने सम्बन्धी सड़क परियोजना पर त्वरित कार्य प्रारम्भ

किया है। इस योजना हेतु 5000 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। 1400 किमी0 लम्बा यह राजमार्ग व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं पर्यटन के क्षेत्र में सम्बद्ध देशों को लाभान्वित करेगा। इस क्षेत्र में बांग्लादेश व म्यांमार के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जल सम्पर्क स्थापित करने हेतु भी भारत सक्रिय है। जापान की अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (JICA) ने पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क व सम्पर्क को सुविकसित करने हेतु 610 मिलियन डालर की सहायता प्रथम चरण हेतु प्रदान की है। चीन के साथ संलग्न 3,488 किमी0 लम्बी सीमा पर जहाँ एक ओर भारत ने सड़क, पुल व अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया हैं वहीं इस सीमा पर स्थित, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम व अरूणाचल प्रदेश की सरकारों से विचार–विमर्श कर विकास गति को त्वरित करने की कार्यवाही में भी तत्पर है।

References:

1. Anand Aditya (ed.) The Political Economy of Small States, Nepal foundation for Advance Studies, 1997, p.25.
2. Ibid
3. Sharma, Nepal Democracy without Roots, Book faith India Publishers, India, p.57
4. op.cit, No. 1,p. 26
5. M.D. Dharamdasani (ed.), Nepal's Foreign Policy Anmol Publications, New Delhi, 2005, p.48
6. Nepal as, "geographically almost part of India although she is an independent country ....as an extention of India's Gangestic plain,"
7. Khadka Narayan, Foreign Aid and Foreign Policy Major Powers and Nepal, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi, 1997, p.58
8. Indian Express February 18, 2001
9. Ashutosh Kumar, China Factor in Nepal, Sumit Enterprises, New Delhi, p.1
10. "During this era, the Indian peoples lived united under one paramount rule and in unexampled security from internal disorder and external aggression."

    L.J.Kavik, India's Quest for Security : Defence Policies, 1947-1965, EBD Publishing and Distributing Co. Dehradun 1967,p.8
11. Ibid, p.9
12. Ibid p.10-11
13. Ibid p.25

14. P.C. Chakravarti; India's China Policy, Bloomington, Indian University Press, 1962,p.165
15. L.J. Kavic, op. cit. No. 10,p.56
16. Strategic Analysis, Vol. 41, No. 6, December 2017, p.542
17. Jaswant Singh, A call to Honour : In Service of Emergent India, Rupa & Co. New Delhi, 2006.
18. Strategic Analysis, Vol. 38, No. 3 May-June, 2014 p.327
19. Strategic Analysis, Vol. 43, No. 3 May-June, 2019 p.248
20. Joint Press Statement on the visit of the PM Modi to Nepal, August 4, 2014
21. P.M. Modi's Speech at Nepali Constituent Assembly.
22. Strategic Analysis, Vol. No. 2, March-April 2015, p.201
23. Hindustan Times, October 16, 2016
24. Government of India Ministry of External Affairs, Atlas of the Northern Frontier of India, New Delhi,1960
25. Report of Ministry of External Affairs, Anon, The Sino- Indian Boundary Question (Enlarged Edition) Peking, Foreign Language Press, 1962.
26. M.K. Palat (ed.); Selected works of J.L.Nehru, Second Series, Vol. 60, New Delhi, Jawahar Lal Nehru Memorial Fund, 2015, p.80, comment no.15
27. Robert Reid, History of Frontier Areas Bordering Assam from 1883-1941, Shillong Assam Government Press, 1942 consulted reprint edition, Spectrum Publications, 1997, p.295
28. B.N. Mullik, The Chinese Betrayal, New Delhi, Allied Publishers, 1971,p.196
29. T.N. Kaul, A Diplomt's Diary, (1947-99) Delhi, Macmillan, 2000, p.58-65

30. G.L. Alder, British India's Northern Frontier 1865-1895, London, Longmans, 1963 p.278
31. Parshotam Mehra, An Agreed Frontier : Ladakh and India's Northermost Border, 1846-1947, Oxford University Press, Delhi, 1992,p.10
32. Parshotam Mehra, The North-Eastern Frontier, Vol.I (1906-1914) Delhi, Oxford University Press, 1979, p.75
33. A.K.J.Singh, Himalayan Triangle, London, British Library p.65
34. Wendy Palace, The British Empire and Tibet, 1900-1922, London, Routledge Curzon, 2005,p.90
35. Ibid, p.93
36. P. Mehra, No. 32, p.118
37. Olaf Caroe, The Geography and Ethics of India's Northern Frontiers', The Geographical Journal, Vol. 126, No. 3, September 1960, p.306
38. P. Mehra No. 32, p.116
39. Wendy Palace, No. 34, p.85
40. Parshotam Mehra, The North-Eastern Frontier, Vol. II (1914-1954) Delhi, Oxford University Press, 1980, p.5-10
41. P. Mehra No. 40, p.126
42. P. Mehra No. 40, p.136
43. P.Mehra No.40, p.119
44. Mushirul Hasan (ed.), Selected Works Jawahar Lal Nehru, Second Series, Vol. 36, New Delhi, Jawahar Lal Nehru Memorial fund, 2005,p.60
45. B.K.P. Singh, China's Tibet Policy. Sumit Enterprises, New Delhi, 2009, p.2.
46. Rajeev Ranjan Chaturvedy and David M. Malone, 'A Yam Between Two Boulders : Nepal's Foreign Policy Caught

between India and China." in David M. Malone, Sebastian Von Einsledel and Suman Pradhan (eds.), Nepal in Transition : From People's war to Fragile Peace, Cambridge University Press, Cambridge, 2012p. 287-292

47. Manish Dabhade and Harsh V. Pant, 'Coping with Challenges to Sovereignty : Sino-Indian Rivalry and Nepal's Foreign Policy, Contemporary South Asia 13(2), 2004,p.159

48. John W. Garver, Protracted Contest : Sino- Indian Rivalary in the Twentieth Century, Oxford University Press, New Delhi, 2001, p-142

49. S.D. Muni, "Strategic Architecture in South Asia : Some Conceptual Parameters', in Nihar Nayak (ed.) Cooperative Security Framework for South Asia; Pentagon Press, New Delhi, 2013,p.11

50. Nihar Nayak, No. 49, p.66

अध्याय–6

चीन की एशियाई महान स्त्रातेजी एवं भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ

द्वितीय विश्व की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में स्थापित द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था एवं उनके मध्य प्रारम्भ शीत–युद्ध, नाभिकीय–शस्त्र स्पर्धा, सैन्य सन्धियों की स्थापना एवं शक्ति–स्पर्धा से वैश्विक स्तर पर सामरिक शोषण, राजनैतिक उथल–पुथल व आतंकवादी घटनाओं के अनेकों उदाहरण विश्व इतिहास में उपलब्ध हैं। हिरोशिमा व नागासाकी घटना के बाद की कालावधि में नाभिकीय युद्ध से मुक्ति हेतु यद्यपि निशस्त्रीकरण हेतु अनेकों प्रयत्न हुए किन्तु महाशक्तियों की हठधर्मिता के कारण इन विनाशक हथियारों पर समुचित व आशानुकूल नियन्त्रण स्थापित नहीं हो सका तथा पी0टी0बी0टी0, एन0पी0टी0, साल्ट व आई0एन0एफ0 आदि व्यवस्थाएं आशानुकूल परिणाम न दे सकीं। यही कारण है कि पॉच नाभिकीय देशों (P-5) के अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया व इसराइल जैसे देश आज नाभिकीय शस्त्रों से सुसम्पन्न हो चुके हैं। नाभिकीय शस्त्र–प्रसार में पाकिस्तान की नाटकीय भूमिका एवं शीत युद्ध काल में इसे चीन व अमेरिका द्वारा प्राप्त प्रश्रय, अफगान–संकट, चीन–भारत के मध्य व्याप्त अविश्वास, बाँग्ला–युद्ध में चीन–पाक–अमेरिकी गठजोड़ आदि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें शान्ति स्थापना की आड़ में वस्तुतः बड़ी शक्तियों की शक्ति–राजनीति की झलक दिखाई देती है। अफगानिस्तान युद्ध में उलझे सोवियत संघ का हुआ पतन तथा उसके पश्चात स्थापित तथाकथित नयी विश्व प्रणाली से उत्पन्न परिस्थितियों में सोवियत–स्थान प्राप्ति हेतु चीन की महत्वाकाँक्षाओं को प्राप्त नयी ऊर्जा, उत्साह व उसके वैश्विक व एशियाई रणनीतिक क्रियाकलापों से विश्व पहले की तुलना में अधिक अस्थिर व असुरक्षित हो गया।[1] वैश्वीकरण व आर्थिक उदारीकरण ने जहॉ एक ओर विकास की नयी सम्भावनाओं को प्रशस्त किया वहीं विश्व की महान शक्ति बनने की चीनी आकाँक्षाओं के फलस्वरुप चीन–अमेरिका के मध्य एक नवीन शीत युद्ध को जो प्रोत्साहन मिला उससे संघर्ष व असुरक्षा के नवीन वैश्विक परिवेश का वातावरण बनता जा रहा है।

चीन के तथाकथित शान्तिपूर्ण अभ्युदय एवं शनैःशनैः अर्थव्यवस्था व रक्षा–सामर्थ के विकास हेतु उसकी क्षेत्रीय व वैश्विक गतिविधियों का ही परिणाम है कि वह येनकेनप्रकारेण अमेरिका को पीछे छोड़कर महानतम विश्वशक्ति बनने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। संघर्ष व टकराव तथा पड़ोसी राष्ट्रों पर नियन्त्रण हेतु बल प्रयोग की धमकी के अतिरिक्त अपनी अर्थव्यवस्था को शस्त्र बनाकर वह अमेरिका की 'मार्शल योजना' जैसी नीतियों को प्रभावी ढ़ंग से संचालित करने में निःसंकोच संलग्न है।

21 वीं शताब्दी में उथल–पुथल के दौर से गुजर रही नवीन शक्ति–संरचना एवं हथियारों के साथ–साथ विदेशनीति के संचालन में अर्थव्यवस्था का प्रभावशाली उपकरण के रुप में प्रयोग आज की शक्ति–राजनीति के अनिवार्य तत्व बनते जा रहे हैं। अपने वैश्विक प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत करने के परम उद्देश्य से अफ्रीका, यूरोप, द0पू0व पूर्वी एशिया, मध्य एशिया व दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन की आर्थिक–सामरिक गतिविधियाँ इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि वह अपने सुरक्षा व आर्थिक सीमान्त को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में कोई संकोच नहीं कर रहा है। जहॉ तक एशियाई महाद्वीप का प्रश्न है, चीन की गतिविधियों के फलस्वरुप दक्षिण एशिया व हिन्दमहासागरीय क्षेत्र की रक्षा सम्वेदना सतत् गम्भीर होती जा रही है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यापार, एवं रक्षा सामर्थ की दृष्टि से इस क्षेत्र का प्रमुख देश भारत, चीन की आक्रामक व अमर्यादित गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। पाक–प्रेरित आतंकवाद चीन–पाक रणनीतिक मैत्री, एशियाई–प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से चल रही चीन–अमेरिकी प्रतिद्वन्दिता, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में चीन की उद्दण्डता, हिन्दमहासागर के माध्यम से भारत के सुरक्षा व व्यापार पर अंकुश लगाने सम्बन्धी चीनी प्रयत्न एवं नेपाल व पाकिस्तान के माध्यम से भारत पर नियन्त्रण स्थापित करने सम्बन्धी चीन की आर्थिक–सामरिक कूटनीति ने भारत की सुरक्षा व विकास के समक्ष गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर विवाद में उलझा हुआ चीन जहॉ एक ओर भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का धुर विरोधी है वहीं अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया के साथ सुधर रहे भारत के द्विपक्षीय

रिश्तों के प्रति भी वह शंकालु है। वह अमेरिका की ''एशिया की ओर वापसी नीति'' (Return Toward Asia) में भारत की उत्पन्न अभिरुचि को अपने विरुद्ध घेरेबन्दी मान रहा है। यही कारण है कि चीन अपनी ''बेल्ट व रोड' पहल योजना (Belt and Road Initiative) के माध्यम से वैश्विक प्रभुत्व स्थापना हेतु अत्यन्त व्यग्र है। वह सी0पी0ई0सी0 (C.P.E.C.) के माध्यम से सीधे अरब सागर में प्रवेश कर जहॉ एक ओर मलक्का–दुविधा' से मुक्त होकर भारत की सामुद्रिक घेरेबन्दी हेतु तत्पर है वहीं नेपाल, मालदीव, श्रीलंका आदि को भारत से पृथक कर चीन इस सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय प्रभाव को शिथिल करना चाहता है।

चीन की बेल्ट व रोड परियोजना–

चीन द्वारा संचालित 'वन बेल्ट वन रोड़' (OBOR-One Belt One Road) परियोजना उसकी सर्वाधिक विस्तृत रणनीति का अंग है जो मूलतः भू–राजनीति व भू–आर्थिक चिन्तन व प्रभुत्व–स्थापना से जुड़ी हुई है। वैश्विक स्तर पर चीन अपने आर्थिक–सामरिक–कूटनीतिक विस्तार द्वारा जहॉ एक ओर अमेरिका के महानतम शक्ति दर्जे को छीनकर स्वयं महानतम शक्ति बनना चाहता है वहीं आर्थिक दृष्टि से कमजोर देशों में अपने उत्पादित सामानों का निर्यात कर अपने आर्थिक, कूटनीतिक व रणनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने की आकांक्षा संजोये हुए है। जहॉ तक सिल्क रोड शब्दावली का प्रश्न है सर्वप्रथम इसका नामकरण जर्मनी के भूगोलवेत्ता व यात्री Ferdinand Von Richthofen[2] ने सन 1877 में किया था जो चीन के हान साम्राज्य के शासन काल में व्यापारिक मार्गों का संजाल विकसित करने पर केन्द्रित थी। 130 ई0 तक चीन द्वारा इन्हीं मार्गों से पश्चिमी विश्व के साथ सम्बन्धों की स्थापना के प्रमाण मिलते हैं। यह मार्ग भारत, मिस्र, अफ्रीका महाद्वीप, ग्रीस, रोम व ब्रिटेन तक विस्तृत था तथा चीनी सिल्क, कागज मसाले व बारुद आदि का व्यापार इसी मार्ग से सम्पन्न होता था। यहॉ पर उल्लेख समीचीन है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में चीन व पश्चिमी देशों के मध्य 'सिल्क रोड' की स्थापना का श्रेय चीन के जनरल जॉग क्विन को प्राप्त है[3] जिसे हान साम्राज्य के द्वारा

139 ई0 पूर्व में पश्चिमी देशों में एक कूटनीतिक अभियान हेतु भेजा गया था। इतना ही नहीं, आठवीं शताब्दी से ही अरब देशों से इण्डानेशिया तक चीन सामुद्रिक मार्गों से व्यापार संचालित करता था। उल्लेखनीय है कि चीन की 'बेल्ट व रोड परियोजना' का मूलध्येय व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक समृद्धि विस्तार पर तो केन्द्रित है ही साथ ही वह स्थल व सामुद्रिक मार्गों से विश्व के साथ सम्बद्ध होकर विश्व का प्रमुख शक्ति–केन्द्र बनने की भी आकांक्षा संजोए हुए है क्योंकि वर्तमान में आर्थिक–शक्ति ही शक्तिशाली राष्ट्र होने का मापदण्ड बनता जा रहा है।

चीन की बेल्ट व रोड परियोजना मूलतः सामुद्रिक शक्ति से सम्बन्धित प्रमुख सैन्य विचारक ए0टी0 महान के विश्वसनीय विचारों से अभिप्रेरित है जिसके अन्तर्गत उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था कि "किसी भी राष्ट्र की शक्ति मूलतः समुद्र से ही जुड़ी होती है"। महान के अनुसार भौगोलिक स्थिति, (Geographical Position), प्राकृतिक उत्पादन व जलवायु से संलग्न राष्ट्र की भौतिक समाकृति (Physical Configuration Connected with natural production and climate), क्षेत्र का विस्तार (Extentent of Territory), जनसंख्या (Population), समुद्र से प्रदत्त अवसरों के प्रयोग सम्बन्धी नागरिकों का सामर्थ्य (Capability of people to utilize the opportunities providede by sea) तथा समुद्र को प्रभावित करने व प्रभुत्व–स्थापना सम्बन्धी सरकार का सामर्थ्य (Ability of the government to influence and dominate the sea) आदि ऐसे तत्व हैं जो सम्यक दृष्टि से प्रयोग व उपयोग करने से राष्ट्र को सुदृढ़ शक्ति व सम्पन्नता उपलब्ध कराते हैं।[4] समुद्र ही वह तत्व है जो व्यापार को समृद्ध बनाने में निर्णायक होते है, अतएवं इन पर नियन्त्रण करना राष्ट्रों के लिए परमावश्यक है। Gerry Kearns जैसे चिन्तकों की विचारधाराओं से भी पुष्ट है कि वाणिज्य व व्यापार की सुरक्षा करके ही राष्ट्रीय शक्ति व समृद्धि की प्राप्ति सम्भव है जो सामुद्रिक व्यापारिक मार्गों पर नियन्त्रण से ही प्राप्त हो सकता है। इन्हीं के शब्दों में–

" The states that commond the Oceans will definitely commond the trade and riches of the world"[5]

किन्तु यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में सामुद्रिक शक्ति को सुद्‌ढ़ करना आवश्यक तो है किन्तु राष्ट्र व सीमाओं की रक्षा में स्थल सैन्य शक्ति की भूमिका किंचित मात्र कम नहीं है।[6] स्पष्ट है कि चीन की इस वृहद योजना (OBOR) के अन्तर्गत समुद्र व स्थलों के माध्यम से ही उसने अपने व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा, रक्षा व राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक व सामाजिक सम्बन्धों का सैन्य शक्ति के साथ संयोजन करते हुए महान स्त्रातेजी का निर्धारण किया है। मूल रुप से यदि देखा जाय तो इस योजना के अन्तर्गत चीन का उद्‌देश्य विश्व के राष्ट्रों को प्रभाव में लाकर उनकी अर्थव्यवस्था व स्त्रातेजिक संसाधनों पर नियन्त्रण स्थापित करना ही है।

7 सितम्बर, 2013 को चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिग ने कजाखस्तान में चीन को यूरोप व एशिया से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सिल्क रोड व इकोनामिक बेल्ट (SREB) व वन बेल्ट वन रोड (OBOR) की विधिवत चर्चा करते हुए इसके अन्तर्गत सड़क, रेल, जल, वायुमार्गों द्वारा विश्व के लगभग 60–65 देशों को जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रारुप प्रस्तुत किया था। इसके एकमाह पश्चात इण्डोनेशिया की यात्रा के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति ने सामुद्रिक सिल्क रोड (Maritime Silk Road) योजना की एक नयी परिकल्पना भी प्रस्तुत की जिसके अन्तर्गत दक्षिण चीन सागर से होकर चीन के पूर्वी बन्दरगाहों को भारतीय उपमहाद्वीप, बंगाल की खाड़ी व हिन्दमहासागर से जोड़ते हुए यूरोप तक विस्तृत करने की अवधारणा निहित थी। यूरोप–एशिया को जोड़ने वाली उक्त विस्तृत परियोजनाओं को चीन ने 28 मार्च, 2015 को 'वेल्ट व रोड पहल' (BRI - Belt and Road Initiative) का नाम देते हुए स्पष्ट किया कि इस परियोजना में ऐसे अनेक राष्ट्रों का सम्मिलित करने की विस्तृत योजना है जो वैश्विक जी0डी0पी0 का 30 प्रतिशत, विश्व की जनसंख्या का 62 प्रतिशत तथा ज्ञात ऊर्जा आरक्षित भण्डार के लगभग 75 अंश से सुसम्पन्न हैं।[7] इस वृहद परियोजना के अन्तर्गत निम्नांकित छः आर्थिक गलियारों को सम्मिलित किया गया है–

- चीन–मंगोलिया–रुस आर्थिक गलियारा (CMREC)
- चीन–केन्द्रीय एशिया–पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा (CWAEC)
- चीन–इण्डोचाइना–पेनिनसुला आर्थिक गलियारा (IPEC)
- चीन–पाक आर्थिक गलियारा (CPEC)
- बांग्लादेश–चीन–भारत–म्यांमार आर्थिक गलियारा (BCIMEC)
- न्यू यूरेशियन लैण्ड ब्रिज (NELB)

'वन वेल्ट वन रोड' (बी0आर0आई0) परियोजना के मुख्यतः दो भाग हैं–

1. <u>सिल्क रोड इकोनोमिक वेल्ट–</u> यह मूलतः भूमि आधारित योजना है जो चीन को मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप से जोड़ेगी।

2. <u>समुद्री रेशम मार्ग–</u> यह योजना समुद्र आधारित है जो चीन के दक्षिणी तट को भू मध्य सागर, द0पू0 एशिया व मध्य एशिया को जोड़ने का कार्य करेगी। सिंगापुर–मलेशिया, हिन्दमहासागर, अरब सागर और होर्मुज जलडमरुममध्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र इसी मार्ग योजना के अंग है।[8]

इस परियोजना के उद्देश्य निम्नवत हैं–

1. नीति–समन्वय (Policy Coordination)
2. सम्पर्क–स्थापना (Connectivity)
3. निर्वाध व्यापार (Unimpede Trade)
4. वित्तीय एकीकरण (Financial Integration)
5. जनता के मध्य मैत्री व बन्धुत्व (People-to-people bond)

वास्तव में, उक्त आर्थिक गलियारों के माध्यम से चीन अपने प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनर्जीवित करना चाहता है जिसे हान राजवंश के दौरान स्थापित किया गया था।[9] इस स्थल मार्ग से जहॉ एक ओर चीन अपने सिल्क निर्यात हेतु सक्रिय था वहीं इसी मार्ग ने पूरे क्षेत्र में बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, हिन्दू

व अन्य धर्मों के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 वीं शताब्दी के बदल रहे आर्थिक–सामरिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए चीन ने उक्त गलियारों के माध्यम से व्यापार, निवेश, तकनीक–हस्तांतरण, उत्पादन व विकास, सांस्कृतिक व अपने रणनीतिक हितों के रक्षार्थ व विस्तारार्थ जो महानस्त्रातेजी निर्धारित की है उसके अन्तर्गत रेलवे नेटवर्क, बन्दरगाह, राजमार्ग, विद्युत–उत्पादन केन्द्र, विमानन व दूरसंचार को सुविकसित करने की योजना है। इस कार्य हेतु चीन ने 40 बिलियन अमेरिकी डालर का विकास कोष निर्धारित किया है। 29 जून 2015 को हस्ताक्षरित 'एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक' (AIIB), जिसकी प्रस्तावित पूंजी 100 बिलियन डालर है, के माध्यम से बुनियादी ढ़ाँचा परियोजनाओं हेतु ऋण देने की भी व्यवस्था की गयी है। इस बैंक का प्राथमिक लक्ष्य एशिया में विकास सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करना, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाना एवं आर्थिक विकास व सामाजिक सेवाओं आदि में सुधार करना है। मास्को, अरब देश, ग्रीस, क्रोएशिया, इटली, पाकिस्तान व कई अफ्रीकी देश इस परियोजना में विशेष रुचि रख रहे हैं। यूरेशियन इकोनोमिक यूनियन (EEU) देशों (रुस, बेलारुस, कजाखस्तान, किर्गीस्तान व अरमेनिया) की भौगोलिक अवस्थिति, पूर्वी एशिया व यूरोप के मध्य व्यापार व यातायात सम्बन्धी उनकी विशिष्टता एवं इनकी आर्थिक सुदृढ़ता के कारण इस संगठन के साथ सम्बन्धों को विस्तृत करना चीन की प्राथमिकता है। स्वतन्त्र व्यापार, खुली अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग, सूचना व तकनीक के वृहत्तर प्रयोग की उपयोगिता की पृष्ठभूमि में विश्व के तमाम अविकसित देशों पर चीन की पैनी दृष्टि है। चीन ने अपनी बेल्ट व रोड परियोजना के अन्तर्गत लगभग 20 कार्ययोजनाएं निर्धारित की हैं जो आधारभूत सुविधाओं, ऊर्जा, संसाधन, उत्पादन क्षमता, वाणिज्य व विनिवेश, विज्ञान व तकनीक, पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी आदान–प्रदान पर केन्द्रित है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश चीन, इस परियोजना से सम्बद्ध देशों को आवश्यक आपूर्ति करके जहॉ एक ओर अपनी कम्पनियों का वैश्विक विस्तार चाहता है वहीं केन्द्रीय एशिया, रुस व पूर्वी एशिया के साथ संलग्न होकर अपनी ऊर्जा–सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने हेतु आशान्वित है। इतना ही नहीं, चीन

जहॉ एक ओर अपनी मुद्रा के अन्तर्राष्ट्रीय हैसियत में वृद्धि हेतु संकल्पित है वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर–विस्तार करके चीनी सामानों के उत्पादन व सेवाओं की वैश्विक मॉग को उत्प्रेरित करने हेतु भी प्रयत्नशील है। उल्लेखनीय है कि सन 2008–2009 में आए आर्थिक–संकट व ग्रुप–7 से निराश व व्यथित चीन अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रुप देने हेतु बेल्ट व रोड योजना के माध्यम से संजीवनी प्राप्त कर अपने प्रभाव व हैसियत को बढ़ाना चाहता है।[10] 14–16 मई, 2017 को चीन में सम्पन्न बी0आर0आई0 सम्मेलन में, जिसमें पाकिस्तान सहित 29 देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया था[11] चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के घोषणा की थी कि, ''उनका उद्‌देश्य विश्व की अर्थव्यवस्था को सबके लिए खोलना, वैश्वीकरण के पुनर्संतुलन, व्यापार उदारीकरण को बनाएं रखना एवं विकास को गतिप्रदान करना तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को दूर करने पर केन्द्रित है।'' यद्यपि उन्होंने इस परियोजना के संचालन के परिप्रेक्ष्य में यह घोषणा अवश्य की कि इसके अन्तर्गत सभी राष्ट्रों की सम्प्रभुता, विश्वसनीयता, समानता एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों व अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हर दृष्टि से पालन होगा किन्तु भारत सहित विश्व के कई अन्य देशों ने चीन के कूटनीतिक व सामरिक–संस्कृति के कुत्सित इरादों को देखते हुए इस योजना पर आशंका व्यक्त की है। उधर, चीन अपनी मुद्रा की वैश्विक स्वीकार्यता एवं प्रभुत्व स्थापना हेतु पर्याप्त गम्भीर है। द0 कोरिया, मलेशिया व कम्बोडिया जैसे देश चीन की मुद्रा (Renminbi) का उपयोग जहाँ एक ओर अपनी आरक्षित निधि के रुप में कर रहे हैं वहीं 2016 में चीनी मुद्रा ने लेन–देन के मामलों में विश्व में पाँचवाँ स्थान प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, चीन ने बी0आर0आई0 के विस्तार हेतु कई तरह के इक्विटी इन्वेस्टमेण्ट योजनाओं की भी शुरुआत की है जिनमें 'सिल्क रोड फण्ड' (40 बिलियन अमेरिकी डालर), 'चीन–अफ्रीका डेवलपमेण्ट फण्ड' (5 बिलियन अमेरिकी डालर) व 'मिडिल ईस्ट इन्वेस्टमेण्ट फण्ड' (10 बिलियन अमेरिकी डालर) उल्लेखनीय हैं। सन 2013 से ही चीन अपनी उक्त योजना से सम्बद्ध देशों में 50 बिलियन डालर से अधिक निवेश कर चुका है जिसे इस दशक में बढ़कर 2.5 ट्रिलियन डालर तक पहुॅचाने की उसकी योजना है। बी0आर0आई0 में सम्मिलित देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक

व शैक्षणिक आदान–प्रादान के लक्ष्य से चीन ने लगभग दस हजार सरकारी स्कालरशिप को भी प्रारम्भ किया है जिनके अन्तर्गत जन–सम्पर्क को बढ़ाना, क्षेत्रीय सम्पर्कों में वृद्धि करना, आंतकवाद, कट्टरपंथियों व अन्य विभाजनकारी तत्वों से उत्पन्न चुनौतियों का सामूहिक प्रतिकार करने का संकल्प लिया गया है।

दक्षिण एशिया में चीन का आर्थिक–रणनीतिक प्रविस्तार–

एशियाई क्षेत्र में अमेरिका की निरन्तर बढ़ रही सामरिक व आर्थिक अभिरुचि, चीन के साथ उसका शक्ति–संघर्ष व 'बेल्ट व रोड परियोजना' में निहित चीन के आर्थिक–रणनीतिक घात–प्रतिघात से दक्षिण एशिया व हिन्दमहासागरीय क्षेत्र के रक्षा–गुरुत्व में अदभुत वृद्धि के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। चीन द्वारा अपनी उक्त परियोजना के अन्तर्गत नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान व मालद्वीव आदि देशों में आर्थिक–हित विस्तार हेतु नपे तुले व दूरगामी रणनीतिक कदम उठाने से प्रत्यक्षतः भारत के क्षेत्रीय व वैश्विक हित प्रभावित हो रहे हैं। चीन का मत है कि हिन्दमहासागर ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से ही वह परियोजना से संलग्न सहयोगियों से सम्पर्क स्थापित कर सकता है। ग्वादर बन्दरगाह के साथ–साथ वहॉ अन्य आधारभूत विकास परियोजनाओं का विकास (रेल, सड़क आदि) करके जहाँ एक ओर वह भारत के पृष्ठ भाग को असुरक्षित करने हेतु संघर्षशील है वहीं अपनी 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चीन ने अपनी सीमावर्ती क्षेत्र मे लहासा–शिगास्ते (Lhasa-Shigatse) रेलवे लाईन विकसित किया है जिसे काठमाण्डू तक विस्तृत करने की उसकी योजना है। दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य एक सेतु के रुप में स्थापित बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति, खनिज संसाधन की अक्षयनिधि, जनसंख्या के आकार एवं बंगाल की खाड़ी के उत्तरीपूर्वी क्षेत्र में उसकी भू–स्त्रातेजिक स्थिति भारत व चीन दोनों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील व आकर्षण का क्षेत्र है। चीन ने खुले समुद्र की रणनीति (Open Sea Strategy) के अन्तर्गत बेल्ट व रोड परियोजना के माध्यम से हिन्दमहासागर के तटवर्ती देशों में अपने आर्थिक हितों का विस्तार करते हुए जहॉ एक ओर चीन अपने सामुद्रिक व्यापार की व्यवस्था को सुरक्षित करना

चाहता है वहीं भारत की सामरिक घेरेबन्दी कर वह भारत के हित–वर्धन विस्तार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु हर सम्भव गतिविधियों को मूर्त देने हेतु संकल्पबद्ध है। भारत के समस्त पड़ोसी देशों को आर्थिक–रणनीतिक प्रभाव में लाना तथा मनमाने ढ़ंग से शक्ति–राजनीति का संचालन ही चीन का दूरगामी ध्येय है। भारत व चीन के मध्य चल रहे भू–रणनीतिक व भू–आर्थिक विवादों के परिपेक्ष्य में यह कहना सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है कि भारत द्वारा बी0आर0आई0 का विरोध करने से आक्रोशित चीन अपनी पूरी शक्ति से दक्षिण एशिया में ही भारत की घेरबन्दी कर उलझाये रखने हेतु रणनीति–आर्थिक गतिविधियों को धीरे–धीरे सुदृढ़ व आक्रामक बना रहा है।

चीन–पाक आर्थिक गलियारा (C.P.E.C.)-

सन 1947 से भारत व पाकिस्तान के सम्बन्धों में व्याप्त शत्रु–भावनाओं के फलस्वरुप भारत का निकटस्थ पड़ोसी पाकिस्तान अपनी विशिष्ट भू–राजनीतिक व सामरिक अवस्थिति के फलस्वरुप बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा व आकर्षण का केन्द्र रहा है। भारत व पाकिस्तान के मध्य जम्मू व कश्मीर ऐसा विवाद है जिसकी पृष्ठभूमि में न केवल दक्षिण एशिया में शीतयुद्ध को सतत प्रोत्साहन मिला अपितु भारत व पाकिस्तान के मध्य हुए चार सशस्त्र–संघर्षों के कारण अमेरिका, रुस व चीन जैसी शक्तियों को भी इस क्षेत्र में प्रभाव–विस्तार हेतु सक्रिय प्रोत्साहन मिलता रहा। 1947, 1965, 1971 व 1999 के भारत –पाक युद्धों के अतिरिक्त अफगान–संकट व पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध संचालित इन्सरजेन्सी आदि ऐसे कारक हैं जिनसे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनैतिक, आर्थिक व रणनीतिक परिस्थितियॉ सदैव संतप्त रही हैं। शीत युद्ध काल में पाकिस्तान की अमेरिकी–सन्निकटता, सीटों व सेण्टों की सदस्यता व बॉग्ला मुक्ति–संघर्ष की पृष्ठभूमि में सिद्धान्तविहीन अमेरिका–चीन–पाक धुरी की स्थापना यह सिद्ध करती है कि विश्व राजनीति में स्वार्थ ही स्थायी तत्व है न किसी का कोई शाश्वत शत्रु है और न मित्र ही। उल्लेखनीय है कि भारत–सोवियत सन्धि (9 अगस्त, 1971) के तेज–विस्तार से व्यथित पाकिस्तान ने न केवल चीन व अमेरिका को एक सूत्र में बॉधने का राजनयिक कौशल दिखाया अपितु सन 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात चीन व भारत के मध्य

उत्पन्न शत्रु–भाव का कूटनीतिक लाभ उठाकर 1963 में चीन के साथ सीमा समझौता करके भारत के विरुद्ध सामरिक–आर्थिक लाभ उठाने के अवसर को भी नहीं गवाँया। जहॉ तक पाकिस्तान को प्राप्त विदेशी सहायता का प्रश्न है, अमेरिका इसमें सर्वोपरि है जिसने लगभग 70 बिलियन डालर की सहायता पाकिस्तान को दी है किन्तु शनैः शनैः पाकिस्तान की चीन के साथ प्रगाढ़ होती जा रही सन्निकटता का ही परिणाम है कि अब चीन–पाक धुरी न केवल भारत के विरुद्ध अपितु अमेरिका के विरुद्ध भी रणनीतिक–जाल बुनने हेतु सक्रिय है।

पाकिस्तान ऐसा पहला देश था जिसने सन 1950 में ताइवान से सम्बद्ध विच्छेद करके 21 मई, 1951 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (PRC) को मान्यता प्रदान की। यही कारण है कि कोरिया युद्ध में अमेरिकी समर्थन में खड़े पाकिस्तान को चीन ने न केवल सहायता का हर आश्वासन दिया अपितु 1955 के वाण्डुंग सम्मेलन के मंच से भी चीन–पाक मैत्री की भावनाएं प्रकट हुई। भारत–चीन युद्ध के पश्चात चीन व पाकिस्तान के मध्य कश्मीर–केद्रित सामरिक परिवेश में चीन सदैव पाकिस्तान का समर्थक बना तो रहा ही साथ ही उसे रक्षा–उपकरणों के अतिरिक्त उसके नाभिकीय कार्यक्रम को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई।[12] उल्लेखनीय है विगत साठ वर्षों से निरन्तर सुदृढ़ हो रहे चीन–पाक सम्बन्धों को 'हिमालय से भी उच्च' व 'समुद्र से भी गहरे' (Higher than the Highest Himalays, deeper than the deepest Ocean), 'सदाबहार मित्र' (All weather Friend), होंठ व दाँत से भी निकट (Close as lips and teeth) जैसे अलंकरणों से सुशोभित किया जाता रहा है किन्तु सी0पी0ई0सी0 से उत्पन्न चीन–पाक प्रगाढ़ता को अब 'मीठे शहद से भी अधिक मीठे' (Sweeter than the sweetest honey) सम्बन्धों की संज्ञा दी जा रही है।[13] उक्त महत्वपूर्ण अंलकरणों से विभूषित चीन–पाक सम्बन्धों के पीछे यद्यपि अनेकों निर्धारक तत्व हैं किन्तु यहॉ पर कुछ विशिष्ट उद्धरणीय पक्ष निम्नवत हैं–

1. 1971 के बांग्ला मुक्ति–संघर्ष के उपरान्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो अपनी जनसभाओं में माओ की जैकेट पहनने लगे। कहा जाता है कि कई अवसर पर भुट्टो की कैबिनेट के सभी सदस्य माओं के जैकेट में नजर

आये थे। इस सन्दर्भ में यह कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान की राजनीति में चीनी संस्कृति का टीकाकरण हो गया है।[14]

2. 1966 व 1980 के मध्य चीन द्वारा पाकिस्तान को निःशुल्क सैन्य–संयन्त्र प्रदान किये गये तथा तक्षशिला में भारी उद्योग काम्प्लेक्स की स्थापना भी चीनी सहयोग से की गयी। आज यही पाकिस्तान के विशाल योधनसंभार निर्माण उद्योग का क्षेत्र है जहाँ JF-17 थण्डर जेट फाइटर का निर्माण किया जा रहा है।

3. ऊर्जा–विकास संयन्त्रों व नाभिकीय हथियारों के निर्माण व भण्डारण हेतु चीन ने पाकिस्तान को हर सम्भव सहायता पहुचाई। चीन के सक्रिय सहयोग से ही आज पाकिस्तान नाभिकीय शस्त्र–सम्पन्न देश बना हुआ है।

4. 25 मार्च, 2019 तक चीन ने कम से कम ब्याजयुक्त 2.1 बिलियन डालर का ऋण पाकिस्तान को उपलब्ध कराया है।

5. चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। दोनों के मध्य व्यापार का आंकड़ा लगभग 10 बिलियन डालर तक पहुँच चुका है तथा 2020 तक 20 बिलियन डालर तक पहुँचने का अनुमान है। जुलाई 2015 में चीन व पाकिस्तान के मध्य 'फ्री ट्रेड एग्रीमेण्ट' सम्पन्न हुआ है जिसका लाभ पाकिस्तान को कम चीन को अधिक हो रहा है।

अप्रैल 2015 में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान 46 बिलियन डालर से निर्मित होने वाले 'चीन–पाक आर्थिक गलियारे' (CPEC) की घोषणा की गयी थी जिसे बढ़ाकर 64 बिलियन डालर कर दिया गया। सी0पी0ई0सी0 चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना का मात्र एक भाग है जिसके द्वारा चीन काश्गर को पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़कर अरब सागर व मध्य एशिया तक सामरिक व आर्थिक विस्तार करना चाहता है। यद्यपि इस योजना के सन्दर्भ में कोई अधिकारिक वक्तव्य तो नहीं आये किन्तु विभिन्न लेखों, मीडिया व इसके समर्थक व विरोधियों द्वारा यदा–कदा इससे सम्बद्ध खबरें प्रकाश में आती रही हैं। 24–25 अप्रैल 2018 को पहली बार पाकिस्तान के समाचार समूह डान (Dawn) द्वारा कराची में आयोजित 'सी0पी0ई0सी0–2018' सम्मेलन में एक समाचार पत्र के

आकार–प्रकार के एक दस्तावेज, जिसे 'दृष्टिकोण' (Perspective) की संज्ञा दी गयी, में इस परियोजना से जुड़े विभिन्न तथ्य व योजनाएं अधिकारिक रुप से प्रकाश में आईं। इसके पूर्व भी चीन के विकास बैंक द्वारा सी0पी0ई0सी0 सम्बन्धी योजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित प्रकिया को डॉन समाचार पत्र के एक संवाददाता द्वारा 15 मई, 2017 को गोपनीय रुप से प्राप्त सूचनाओं को संक्षिप्त रुप में प्रकाशित किया गया था।[15] सी0पी0ई0सी0 से सम्बन्धित दस्तावेज में इसकी दीर्घकालिक योजना (2017–2030), उद्देश्यों एवं उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इस दस्तावेज मे यह कहा गया है कि चीन व पाकिस्तान ने इस योजनान्तर्गत सामूहिक समृद्धि, पारस्परिक लाभ, औद्योगिक व आर्थिक–व्यापार सहयोग, जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान सम्बन्धित विकास गतिविधियों हेतु ऐसी धुरी निर्मित की है जिसके द्वारा समूचे क्षेत्र की सुरक्षा, समृद्धि तथा सामाजिक–आर्थिक विकास को नवीन ऊर्जा प्राप्त होगी। चीन के काश्गर को पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह से जोडने वाले इस 3218 किमी0 लम्बे मार्ग के माध्यम से जहॉ एक ओर केन्द्रीय एशिया को चीन के पूर्वी बन्दरगाहों से जोड़ना सम्भव होगा वहीं ऊर्जा संयन्त्रों, राजमार्ग, रेलवे, सौर ऊर्जा–क्षेत्र सम्बन्धी योजनाओं से सम्बद्ध यह तन्त्र पाकिस्तान के भाग्य का बदलने (Fate Changer) में सहायक सिद्ध होगी। उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नांकित परियोजनाओं व विभिन्न आर्थिक–क्षेत्रों (Economic Zone) को भी इसके अन्तर्गत विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है–

1. पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में हजारों एकड़ की कृषि योग्य भूमि चीन को बीज उत्पादन व सिंचाई तकनीक के प्रमाणीकरण परियोजनाओं हेतु लीज पर प्रदान की जायेगीं। लगभग 6500 एकड़ भूमि चीन स्वयं कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त करेगा। इस कार्य हेतु चीन ऋण व पूंजी उपलब्ध करायेगा।
2. लगभग 80000 टन उत्पादक क्षमता का एक उर्वरक संयन्त्र, सब्जी व फल सम्बन्धी प्रोसेसिंग प्लाण्ट तथा कीटनाशक दवाइयों व अन्य वैक्सीन निर्माण सम्बन्धी सुविधाओं का भी चीन विस्तार करेगा।

3. पाकिस्तान के विभिन्न खनिज संसाधनों (सोना, कॉपर, कोयला व संगमरमर) के खनन में चीन निवेश करेगा।
4. काश्गर व ग्वादर के मध्य उन्नत सम्पर्क हेतु चीन फाइबर आप्टिकल्स केबिल का जाल बिछायेगा।
5. पाकिस्तान में चीनी–संस्कृति के विस्तार हेतु वह पाकिस्तान की मीडिया का प्रयोग कर सकेगा जिससे दोनों देशों के मध्य जनसम्पर्क व पारस्परिक मैत्री को प्रोत्साहित किया जा सके।

अप्रैल 2018 के कराची सम्मेलन में पाकिस्तान स्थित चीन के राजदूत ने बताया कि सी0पी0ई0सी0 से सम्बद्ध 22 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं जबकि 43 परियोजनाओं पर तीव्रता से कार्य चल रहा है तथा लगभग 22 बिलियन डालर की धन राशि उक्त कार्यों पर व्यय हो चुकी है। सड़क व रेल विस्तार इस परियोजना की महत्वपूर्ण योजना है जिसमें अन्तर्गत काश्गर से खुंजेराब दर्रे से होकर बलूचिस्तान स्थित ग्वादर तक राजमार्ग का विकास त्वरित ढ़ग से चल रहा है। इस कार्य का पूरा अधिकार चीन की विश्वसनीय कम्पनियों के हाथों में है, पाकिस्तान को इससे पृथक रखा गया है। पाकिस्तानी सेना की महत्वपूर्ण सैन्य टुकड़ी (10000 सैनिक) इन सड़कों को उग्रवादी तोडफोड़ से बचाने हेतु लगी हुई है। ग्वादर बन्दरगाह के विकास हेतु चीन ने 140 वर्षीय समझौता भी पाकिस्तान से किया है जिसमें चीन का शेयर 91 प्रतिशत है। चीन व पाक के मध्य नई सांस्कृतिक–कूटनीति के अन्तर्गत लगभग 20000 छात्र चीन में मेडिकल, इन्जीनियरिंग व अन्य क्षेत्रों में अध्ययनरत हैं तथा पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में ही चीन की लगभग 750 छोटी–बड़ी कम्पनियॉ कार्यरत हैं। इस नवीन मैत्री के परिणामस्वरुप पंजाब में न केवल 'चीनी दिवस' धूमधाम से मनाया जा रहा है अपितु दोनों के देशों नागरिकों के मध्य विवाह के रिश्ते भी स्थापित होने लगे हैं।

चीन व पाक के मध्य सम्पन्न 'मुक्त व्यापार समझौते' का ही यह परिणाम है कि पाकिस्तान के बाजार चीनी सामानों से भरते जा रहे हैं जिनमें मोटरसाइकिलें, इलेक्ट्रानिक्स सामान व प्लास्टिक आदि प्रमुख हैं। पाकिस्तान की मोबाइल सेवा, विद्युत कम्पनियों व स्टाक एक्सचेंज पर चीन का एकाधिकार

स्थापित होता जा रहा है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शनैः शनै' चीन उसे ऋण जाल में फंसाकर अपने उपनिवेश के रुप न परिवर्तित न कर दे। ऐसा लगता है कि सी0पी0ई0सी0 योजना पाकिस्तान के बजाय कहीं चीन के लिए भाग्य परिवर्तन का कारक न बन जाय। यही कारण है कि पाकिस्तान के घरेलू मोर्चों पर अब इसके विरुद्ध आवाजें भी उठने लगी है तथा इसे 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की भी दी जा रही है। ऐसा अनुमान है कि चीन के ऋण–जाल में फंस चुके पाकिस्तान को सन 2020 के बाद प्रतिवर्ष 3 से 3.5 बिलियन डालर ऋण का भुगतान अगले तीस वर्षों तक करना होगा जो 100 बिलियन डालर तक पहुॅच सकता है। यद्यपि पाकिस्तान के अधिकारी उक्त योजना को पारदर्शी बता रहे हैं किन्तु पाकिस्तानी निवेशक चिन्तित हैं। चीन की ही शर्तों पर पाकिस्तान में प्रारम्भ इस योजना को पाकिस्तान की सेना, सरकार व कुछ अन्य संस्थाए समर्थन दे रही हैं।

चीन की ही शर्तों पर सी0पी0ई0सी0 में उलझ चुके पाकिस्तान की विवशता का ही प्रतिफल है कि वह दक्षिण एशिया को 'ग्रेटर दक्षिण एशिया' का नामकरण कर इसे न केवल अपने लिए 'भाग्य निर्धारक' योजना की संज्ञा दे रहा है अपितु सेण्ट्रल एशिया, ईरान व अफगास्तिान से जुड़कर सामरिक–आर्थिक लाभ प्राप्त करने का दिवास्वपन भी देख रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शब्दों में–

"It will (BRI) provide two- way trade routes to the world, not only for Pakistan but for Afganistan, Central Asia and Western China .... it will provide this region with access to the world through the BRI."

किन्तु पहले से ही जर्जर अर्थव्यवस्था, राजनैतिक–दिग्भ्रम, जन–असन्तोष व ऋण–जाल में उलझ चुके पाकिस्तान की 'भाग्य–परिवर्तन' करने वाली चीनी परियोजना उसे कितना सम्बल प्रदान करेगी, यह तो समय ही तय करेगा। मेरा तो अभिमत है कि शनैः शनैः चीन का आर्थिक–सामरिक उपनिवेश बनकर उसकी की गोद में बैठ चुके पाकिस्तान की राजनैतिक–अस्थिरता, सम्प्रभुता व राष्ट्रीय अखण्डता के समक्ष नवीन चुनैतियों के स्पष्ट संकेत है किन्तु

Tajikistan
(GBAO)
Afghanistan (Wakhan, Badakhshan)
CHINA
Gilgit Agency
Shaksgam Valley
XINJIANG
GILGIT-BALTISTAN
Tribal Territory
Baltistan
Siachen Glacier
Aksai Chin
PAKISTAN
Chilas
Neelam
Kupwara
Baramula
JAMMU AND KASHMIR
Kashmir
Srinagar
Ladakh
Kargil
Bagh
AZAD KASHMIR
Poonch
Anantnag
XIZANG (TIBET)
Kotli
Doda
Rajauri
Udhampur
Bhimber
Jammu
Kathua
INDIA

भारत–विरोधी भावनाओं से निरर्थक व्यथित व दिग्भ्रमित पाकिस्तान का नेतृत्व अपने अनिष्ट का अनुमान नहीं लगा पा रहा है।

पाक–अधिकृत कश्मीर में चीन की महानस्त्रातेजी–

यू0एन0सी0आई0पी0 के प्रयत्नों के फलस्वरुप भारत व पाकिस्तान के मध्य कश्मीर युद्ध में हुए युद्धविराम से सम्पूर्ण जम्मू–कश्मीर राज्य के 78,114 वर्ग किमी0 भू–क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध नियन्त्रण स्थापित हो जाना भारत के लिए रणनीतिक पराजय थी। यहॉ पर यह सुस्पष्ट कर देना समीचीन प्रतीत होता है कि वर्तमान में सम्पूर्ण जम्मू–कश्मीर राज्य निम्नांकित भू–क्षेत्रों में विभक्त है–

1. **भारत द्वारा नियन्त्रित कश्मीर (I.C.K.)-**

   यह सम्पूर्ण जम्मू–कश्मीर राज्य (जिसका क्षेत्रफल 222.236 वर्ग किमी0 था) का मात्र 48 प्रतिशत भू–भाग है जिसका क्षेत्रफल 106.567 वर्ग किमी0 है। सन 2019 में जम्मू–कश्मीर व लद्दाख को केन्द्र शासित क्षेत्र बनाकर भारत ने इस क्षेत्र की भू–राजनीति को ही परिवर्तित कर दिया है।

2. **पाक–अधिकृत कश्मीर– (POK)-**

   इस भू–भाग का क्षेत्रफल 78,114 वर्ग किमी0 है जो सम्पूर्ण कश्मीर राज्य का लगभग 35 प्रतिशत है। यद्यपि समान्यतः लोग पाक–अधिकृत को ‘आजाद कश्मीर कहकर सम्बोधित करते है किन्तु ऐसा नहीं है। पाक–अधिकृत कश्मीर दो भागों में विभक्त है–

अ. **आजाद जम्मू–कश्मीर (AJK)-**

इसके अन्तर्गत जम्मू–कश्मीर का मीरपुर, पुॅछ जागीर का कुछ भू–क्षेत्र एवं पश्चिमी कश्मीर का कुछ भू–भाग सम्मिलित है। इसमें सम्पूर्ण पाक–अधिकृत कश्मीर का मात्र 15 प्रतिशत क्षेत्र शामिल है जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। इसका क्षेत्रफल 13,297 वर्ग किमी0 है।

ब. **गिल्गिट–बाल्टिस्तान (G.B.Area)-**

पाक–अधिकृत कश्मीर के उत्तरी भू–भाग (Northern Area) के अन्तर्गत गिल्गिट व बाल्टिस्तान क्षेत्र (G.B.Area) सम्मिलित हैं

जिसकी राजधानी गिल्गिट है तथा यह 72,495 वर्ग किमी0 में फैला हुआ है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान की सरकार का सीधा नियन्त्रण है।

3. **चीन–अधिकृत कश्मीर (C.A.K.)-**

जम्मू–कश्मीर राज्य का लगभग 37,555 वर्ग किमी0 क्षेत्र, जिसे अक्साई चिन कहा जाता है, सन 1962 युद्ध के बाद से चीन के नियन्त्रण मे है। इसके अतिरिक्त सन 1963 में चीन–पाक सीमा समझौते के फलस्वरुप पाकिस्तान द्वारा दिया गये। 5180 वर्ग किमी0 भूमि पर भी चीन का कब्जा है। जहॉ एक ओर भारत आक्साईचिन को जम्मू–कश्मीर राज्य का भू–भाग कह रहा है वहीं चीन इसे तिब्बत का भाग मानता है।

यदि सम्पूर्ण पाक–अधिकृत कश्मीर पर दृष्टिपात किया जाय तो स्पष्ट है कि यद्यपि 4 अक्टूबर, 1947 को ही अनवर खॉ के नेतृत्व में यहॉ स्वतन्त्र सरकार का गठन हो गया था किन्तु इस सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान के प्रयत्नों से 24 अक्टूबर, 1947 को सरदार इब्राहीम खॉ के नेतृत्व में स्वतन्त्र आजाद कश्मीर सरकार की स्थापना हो गयी थी। यद्यपि पाकिस्तान का दावा है कि यह क्षेत्र जम्मू–कश्मीर नियन्त्रित क्षेत्र का हिस्सा नहीं था जबकि आंग्ल–सिक्ख युद्ध के पश्चात महाराजा गुलाब सिंह ने युद्ध करके राजौरी, किश्तवाड़, करगिल, लद्दाख व बाटिल्स्तान पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इस युद्ध में उनके सैनिक जनरल जोरावर सिंह की निर्णय भूमिका थी।

भू–राजनैतिक दृष्टि से पाक–अधिकृत कश्मीर की अवस्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योकि यह केन्द्रीय एशिया, दक्षिण एशिया, अफगानिस्तान के वाखान गलियारे (Wakhan Corridor), चीन के सीक्यांग व स्वायत्तशासी तिब्बत के भू–भागों व भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य से घिरा ऐसा संगम क्षेत्र है, जो इसके रणनीतिक महत्ता में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। यह भारत का दुर्भाग्य ही है कि 1839 में कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के सैन्य जनरल जोरावर सिंह द्वारा उत्तरी कश्मीर के पर्वतीय राज्य गिल्गिट व बाल्टिस्तान पर अधिकार कर पुराने सिल्क मार्ग को चालू करने के बावजूद 1947 में इसे पाकिस्तान में जाने देने के फलस्वरुप भारत के तत्कालीन शिथिल व अदूरदर्शी नेतृत्व ने काबुल–मार्ग स्वयं अवरुद्ध कर दिया। ध्यातव्य है कि भारत की

लगभग 70 किमी0 लम्बी सीमा अफगानिस्तान के सर्वाधिक अविकसित किन्तु सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण वाखान गलियारे से मिलती है तथा इसी के दक्षिणी भू–भाग में स्थित पाक–अधिकृत क्षेत्र से चीन हाईवे बना रहा है। श्रीनगर–स्कार्दू–गिल्गित मार्ग को गवॉने का ही यह दुष्परिणाम है भारत को अब विवश होकर चाबहार बन्दगाह के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु प्रयत्नशील होना पड़ रहा है जिससे मध्य व पश्चिम एशिया तक वह अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति कर सके। यह सब कुछ लार्ड माउण्टवेटन की कुत्सित योजना का ही परिणाम था जिसके अन्तर्गत उसने 1947–48 के कश्मीर–युद्ध के दौरान मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रही भारतीय सेनाओं को उड़ी में ही रोकने की नीति अपनाई तथा भारतीय सेनाओं को गिल्गिट–बाल्टिस्तान की ओर बढ़ने ही नहीं दिया। यदि भारतीय सेनाएं आगे बढ़ी होती तो आज इस सम्पूर्ण क्षेत्र पर भारत का ही नियन्त्रण होता।

अपनी सामरिक व भू–आर्थिक विशिष्टता के कारण पाक–अधिकृत कश्मीर के गिल्गिट–बाल्टिस्तान के क्षेत्र में चीन की बढ़ती सामरिक गतिविधियॉ भारत के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय हैं। ध्यातव्य है कि इस क्षेत्र के निवासियों की भाषायी व सांस्कृतिक निकटता, पाकिस्तान के साथ न होकर तिब्बतियों, कश्मीरी, उइगर, मंगोलो व कजाक जैसी नृजातीय समूहों के साथ काफी मिलती–जुलती है। गिल्गिट–बाल्टिस्तान से होकर गुजरने वाले काकारोम राजमार्ग द्वारा चीन व उसके 'सदाबाहर मित्र' पाकिस्तान के मध्य स्थलीय सम्पर्क स्थापित है। सच तो यह है कि आतंकवादी गतिविधियों से असुरक्षित व अस्थिर चीन का सीक्यांग प्रान्त तथा अशान्त पाकिस्तान के मध्य पाक–अधिकृत गिल्गिट–बाल्टिस्तान का इलाका एक प्रमुख अन्तरस्थ–क्षेत्र (Buffer Area) की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। चीन के सीक्यांग क्षेत्र में पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामी आन्दोलन (ETIM-East Turkistan Islamic Movement) की सक्रियता के फलस्वरुप हो रही हिंसा से वह अत्यधिक चिन्तित हैं। सन 2009 में यहॉ हुए दंगे एवं काश्गर में 2012 में हुए दंगों में पाकिस्तानी आतंकवादी तत्वों की संलिप्तिता से व्यथित चीन ने आतंकवाद–विरोधी अमेरिकी रणनीति के ही आधार पर उसने भी सीक्यांग प्रान्त

की रक्षा हेतु आतंकवादियों के उन्मूलन हेतु पाकिस्तान की भूमि पर ही रणनीतिक गतिविधियॉ प्रारम्भ करने की प्रक्रिया को मूर्तरुप देकर पाक–अधिकृत कश्मीर पर अपनी सामरिक पकड़ मजबूत करना प्रारम्भ कर दिया है। वांशिग्टन स्थित 'गिल्गिट–बाल्टिस्तान अध्ययन संस्थान' के प्रमुख सेंग सेरिंग का मत है कि '' चीन ने कश्मीर मामलों में रुचि लेकर पाक–अधिकृत कश्मीर के महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों पर अधिकार करने तथा पाकिस्तान, मध्य पूर्व व अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक सुदृढ़ गठबन्धन की स्थापना की दिशा में संतुलित कदम उठाया है।'' अफगानिस्तान व पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन एक पामीर समूह (Pamir Group) की स्थापना हेतु भी प्रयत्नशील है जिसकी पुष्टि चीन के सिगुंआ विश्वविद्यालय के निदेशक Li Xiguang ने करते हुए कहा है कि इससे इस क्षेत्र के आर्थिक–विकास संरचना को नयी ऊर्जा प्राप्त होगी। यही कारण है कि अपने सीक्यांग प्रान्त को आतंकवाद से बचाने एवं अफगानिस्तान व खाड़ी क्षेत्र तक अपनी सामरिक–आर्थिक भेदनीयता को प्रभावी रुप देने हेतु चीन, पाक–अधिकृत कश्मीर के गिल्गिट–बाल्टिस्तान क्षेत्र पर अपना स्त्रातेजिक नियन्त्रण कर उसे एक अन्तस्थ राज्य (Buffer State) के रुप में विकसित करने हेतु तत्पर है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में चीन की निम्नांकित गतिविधियाँ विशेषतः उल्लेखनीय है–

1. पाक–अधिकृत कश्मीर की आर्थिक समृद्धि एवं क्षेत्र की दूरगामी आर्थिक निर्भरता को सुदृढ़ आधार देने हेतु चीन इस क्षेत्र में सामरिक महत्व की विकास परियोजनाओं (रेल, सड़क, संचार, ऊर्जा आदि) के निर्माण में सक्रिय भागीदारी करके यहॉ अपनी स्थायी उपस्थिति का इच्छुक है।
2. काराकोरम हाईवे (KKH) को 10 मीटर से बढ़ाकर 30 मीटर तक चौड़ी करना तथा इसके रखरखाव हेतु 500 मिलियन डालर धनराशि की व्यवस्था, गिल्गिट–बाल्टिस्तान क्षेत्र में जगलोट–स्कार्दू मार्ग (165किमी0) एवं थाकेट –सजिन मार्ग (135किमी0) के निर्माण पर 45 बिलियन डालर धन व्यय करके चीन ने अपनी अभिरुचि प्रकट कर दी है।

3. झेलम नदी पर एक पुल के साथ–साथ मांगला डैम रिजरवायर को 60 फीट तक ऊँचा करने में चीन सक्रिय है।

4. 12.6 बिलियन डालर की लागत से 'नीलम–झेलम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट' का कार्य भी चीन प्राथमिकता के स्तर पर कर रहा है।

5. चीन, गिल्गिट–बाल्टिस्तान क्षेत्र में निम्नांकित 5 मेगा पावर प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है–

   1. दासू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट – 7.8 बिलियन डालर
   2. फण्डारे प्रोजेक्ट – 70 मिलियन डालर
   3. बासू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट – 40.1 मिलियन डालर
   4. हारपो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट – 44.608 मिलियन डालर
   5. युल्वो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट – 6 बिलियन डालर
   6. 4500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के 272 मीटर ऊँचे

Diamer Bhasma Dam के निर्माण हेतु चीन ने 12 बिलियन डालर का बजट निर्धारित किया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की विभिन्न कम्पनियां पाकिस्तान की लगभग 250 परियोजनाओं में कार्य कर रही हैं। जिसमें गिल्गिट–बाल्टिस्तान की मात्र 17 परियोजनाओं में ही चीन की 122 कम्पनियां कार्यरत हैं। Seig Harrison की 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 7000 से 11000चीनी सैनिक इस समय पाक–अधिकृत क्षेत्र के गिल्गिट–बाल्टिस्तान क्षेत्र के विभिन्न सामरिक अड्डों पर उपस्थित हैं। इतना ही नहीं, इस तथ्य के भी प्रमाण मिले हैं कि तमाम चीनी सैनिक पाक–अधिकृत कश्मीर में संचालित कई परियोजनाओं में तकनीकी कार्य में संलग्न है। पाकिस्तान की विकास परियोजनाओं में लगभग 3.3 बिलियन डालर का ऋण दे चुका चीन ऊर्जा व जल संकट की चुनौतियों के समाधान हेतु उस पर समझौते हेतु दबाव बनाने के अतिरिक्त बिना अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अपनी परियोजनाएं चीनी कम्पनियों को हस्तांतरित करने हेतु भी पाकिस्तान को विवश कर रहा है। चीन द्वारा निर्मित आर्थिक–संजाल में पूर्णतः फंस चुका पाकिस्तान अब जल ऊर्जा विकास हेतु पूर्णतः चीन पर आश्रित हो चुका है तथा वह चीन से ही

तमाम संयन्त्रों के आयात हेतु बाध्य होता जा रहा है। पाकिस्तान के 'जल व शक्ति विकास संस्थान' (WAPDA- Water and Power Development Authority) के एक रहस्योद्घाटन से इसकी पुष्टि होती है।

आर्थिक–शक्तिपात के फलस्वरुप गृह युद्ध की दिशा में बढ़ रहे पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता सम्बन्धी विवशता का लाभ उठाकर जहॉ एक ओर वह पाक–अधिकृत कश्मीर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपनी स्थाई उपस्थिति को सुदृढ़ आधार दे चुका है वहीं निरन्तर उसकी कश्मीर नीति के आयाम बदलते दिखाई दे रहे हैं। टोरेण्टो स्थित 'शान्ति व प्रजातंत्र सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान' के निदेशक मुमताज खान ने पाक–अधिकृत कश्मीर में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में कहा भी है कि ''वह पाकिस्तान को सैन्य व कूटनीतिक सहयोग प्रदान करके भविष्य में पाकिस्तान को प्रतिस्थापित (Replace) करके कश्मीर समस्या का मुख्य खिलाड़ी (Major Player) बनकर उभरेगा''। इतना ही नहीं ग्वादर के अतिरिक्त चीन पाकिस्तान के फाटा (FATA) अथवा सीक्यांग सीमा क्षेत्र से सटे उत्तरीपूर्वी क्षेत्र में एक बड़े सैन्य आधार की स्थापना हेतु भी सक्रिय है जिससे सीक्यांग क्षेत्र से संलग्न इलाके में एक आदर्श 'अन्तस्थ–क्षेत्र' की स्थापना सुनिश्चित हो सके।

बांग्लादेश–

यह सर्वथा सत्य है कि सामान्यतः भौगोलिक स्थिति, संसाधनों की अक्षय निधि, जनसंख्या का आकार तथा सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक उन्मुखीकरण सम्मिलित रूप से ही राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व हैं। जहाँ तक बांग्लादेश का प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी बिन्दु पर स्थिति यह महत्वपूर्ण देश न केवल विश्व के सर्वोत्तम सामुद्रिक मार्ग को स्पर्श करता है अपितु दक्षिण व द0पू0 एशिया के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन करता है। लगभग 165 मिलियन आबादी, तीव्रता से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था एवं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पाँच राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा) से संलग्न यह देश भारत की सुरक्षा व विकास के लिए

अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) व जमात–ए इस्लामी–(JI) के शासन काल में यह देश न केवल पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों को सहायता करता रहा अपितु पाकिस्तानी आतंकवादियों व चीन समर्थित माओवादियों के शस्त्र–आपूर्ति का मुख्य स्रोत रहा है किन्तु अवामी लीग के शासनारूढ़ होने के बाद भारत–बांग्लादेश के मध्य विकसित सहयोगी प्रवृत्ति के फलस्वरूप यहाँ आतंकवादी हिसा में पर्याप्त कमी आई है। इतना ही नहीं, भारत की विदेश नीति, आर्थिक–कूटनीति एवं एक्ट ईस्ट नीति' में बांग्लादेश की महत्वपूर्ण भूमिका का ही परिणाम है कि दोनों के मध्य स्थापित मैत्रीपूर्ण भावनाओं से चीन पर्याप्त चिन्तित व सक्रिय है। ओ0वी0ओ0आर0 के अन्तर्गत ही निर्मित बी0सी0आई0एम0 फोरम (Bangladesh, China, India and Myanmar forum) के माध्यम से बांग्लादेश में चल रही विनियोजना नीति द्वारा चीन इसे भारत से पृथक कर अपने रक्षा–आवृत्त में लाने हेतु उसे विभिन्न सेक्टरों में सहायता कर रहा है।[16]

वास्तव में, बी0सी0आई0एम0 (BCIM) की शुरूआत एक गैर सरकारी पहल द्वारा सन् 1999 में हुई जिसके अन्तर्गत चीन के यूनान प्रान्त की राजधानी कनमिंग को कलकत्ता से जोड़ने का लक्ष्य था, किन्तु 2015 में इस गलियाने को बी0आर0आई0 के अन्तर्गत चीन द्वारा सम्मिलित किये जाने के कारण भारत ने इसका प्रबल विरोध करते हुए बहिष्कार कर दिया। लगभग 2800 किमी0 लम्बे इस गलियारे द्वारा चीन मलक्का मार्ग से उत्पन्न होने वाली व्यापारिक असुरक्षा से बचते हुए केमडेला से होकर हिन्द महासागर में पहुँचना चाहता है। हालाँकि सीमापार परिवहन, ऊर्जा व दूरसंचार नेटवर्क, पूर्वोत्तर भारत के विकास एवं उसकी 'एक्ट ईस्ट पालिसी' के प्रभावी संचालन में यह गलियारा भारत के लिए उपयोगी तो अवश्य है किन्तु चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स नीति' की पृष्ठभूमि में चीन द्वारा भारत की आर्थिक व रणनीतिक घेरेबन्दी सम्बन्धी महत्वाकाँक्षाओं के कारण भारत ने इस पर सकारात्मक रूख नही अपनाया है। बांग्लादेश द्वारा चीन के बी0आर0आई0 प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा चीन द्वारा इसे प्रदान की जा रही विशाल आर्थिक सहायता से भारत चौकन्ना हो गया है।[17] जनवरी 1976 में चीन व बांग्लादेश के मध्य स्थापित

राजनयिक सम्बन्धों के पश्चात दोनों के मध्य वाणिज्यिक, सांस्कृतिक व सैन्य सम्बन्धों का निरन्तर विस्तार हो रहा है। बांग्लादेश, दक्षिण एशिया में चीन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है तथा द्विपक्षीय व्यापार सन् 2021 तक बढ़कर 30 बिलियन डालर होने का अनुमान है। सन् 2002 में चीन व बांग्लादेश के मध्य रक्षा–सहयोग सम्बन्धी समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत चीन बांग्लादेश को विमान, टैंक, मिसाइलें व अन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है। सन् 2008 में चीन की सहायता से बांग्लादेश ने चटगाँव बन्दरगाह के पास 'एण्टी शिप मिसाइल लॉच पैड' स्थापित किया तथा 12 मई, 2008 को अपनी पहली मिसाइल प्रक्षेपित की है। इस समय बांग्लादेश चीनी हथियारों का प्रमुख आयातक देश है। 'बेल्ट व रोड परियोजना' में शामिल होने के पश्चात चीन बांग्लादेश में बुनियादी ढाँचे के विकास में सक्रिय है। चीन ने न केवल चटगाँव बन्दरगाह को उन्नत किया है अपितु यहाँ एक औद्योगिक पार्क का भी निर्माण कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश में आठ मैत्री सेतु बनाये हैं तथा बेहतर द्विपक्षीय सम्पर्क हेतु 1 बिलियन डालर की 'डिजिटल परियोजना' पर कार्यरत है। यद्यपि ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, रेल व सड़क निर्माण में चीन बांगलादेश में काफी निवेश कर रहा है तथापि चीन के कर्जजाल में फँसने से बचते हुए बांग्लादेश ने सोनादिया–परियोजना को अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि अन्य चीनी परियोजनाओं हेतु चीन की प्रतिपूर्ति गति धीमी है। चीन के ऋण जाल में फँसने की आशंका से बांग्लादेश अब सतर्क हो गया है।[18]

नेपाल, श्रीलंका व मालदीव–

1. नेपाल–

भारत व चीन के मध्य एक 'बफर–राज्य' व स्थलबद्ध देश के रूप में स्थित नेपाल अपनी भू–राजनीतिक महत्ता के फलस्वरुप न केवल दोनों बड़े पड़ोसियों से लाभ उठाने की विदेश नीति का संचालन करता रहा है अपितु शनैः शनैः अब उसकी चीन–केन्द्रित महत्वाकांक्षी गतिविधियों से भारत का उत्तरी सुरक्षा सीमान्त संवदेनशील होता जा रहा है। पिछले अध्यायों में हम इसकी विस्तृत चर्चा के अन्तर्गत नेपाली विदेश–नीति के उद्देश्यों व अन्य गतिविधियों का वर्णन कर चुके है कि

सन् 1960 में दोनों देशों के मध्य सम्पन्न शान्ति व मैत्री सहयोग के आयाम किस रूप में विस्तारित होते रहे हैं। माओवादी इन्सरजेन्सी के पश्चात नेपाल की परिवर्तित विदेशनीति का चीन की ओर उन्मुख होना तथा 2015 के मधेशी समस्या को प्रत्यक्षतः भारत–प्रेरित बताना यह सिद्ध करता है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में नेपाल भारत का बहुत विश्वसनीय व भरोसेमन्द पड़ोसी नहीं रहा है। चीन के विदेश मन्त्री वॅाग यी (Wang Yi) के निम्नांकित कथन से इसकी प्रतिध्वनि को समझा जा सकता है–

"China has all along believed that countries irrespective of their size are equal. China and Nepal has always treated each other sincerely and as equal. We hope that the same policy and practices will also be adopted by India"[19]

शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के पंच सिद्धान्तों अथवा पंचशील (Panchasheel)के आधार पर स्थापित व विकसित नेपाल–चीन सम्बन्धों में तिब्बत का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। सन् 2008 में तिब्बत स्वायत्तशाली क्षेत्र (TAR) में हुए भीषण उथल–पुथल, नेपाल में रहने वाले 20,000 तिब्बती शरणार्थियों एवं नेपाल मार्ग से ही तिब्बत शरणार्थियों के भारत–प्रवेश से व्यथित चीन ने हर सम्भव आर्थिक–रणनीतिक सहायता पहुँचाकर नेपाल को अपने पक्ष में करने का ही यह परिणाम है कि उसने नेपाल में संचालित विकास सम्बन्धी 42 परियोजनाओं (सिंचाई, विद्युत–उत्पादन, कपड़ा उद्योग आदि) को प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहयोग प्रदान किया। नेपाल स्थित अपने दूतावास के माध्यम से तिब्बत–विद्रोह (2010) को शान्त करने हेतु चीन ने 10 मिलियन डालर की सहायता देकर नेपाल में उत्पन्न सम्भावित तिब्बती–आक्रोश के दमन का प्रयास किया। फलतः, नेपाल ने न केवल अपने देश में स्थित तिब्बती शरणार्थियों का निर्ममतापूर्वक दमन प्रारम्भ किया अपितु उनके सभी सांस्कृतिक उत्सवों पर प्रतिबन्ध लगाते हुए नेपाल में प्रवेश करने वाले तिब्बतियों पर कड़ा रूख अपनाया। सन्

2008 में नेपाल में रहने वाले 2000 तिब्बतियों की संख्या घटकर 2014 में मात्र 200 रह गयी। इतना ही नहीं, अपितु 2005–2013 की अवधि में चीन ने नेपाल को 7.7 मिलियन डालर की सैन्य सहायता के अन्तर्गत प्रचुर मात्रा में सैन्य साज–समान भी उपलब्ध कराये।

तिब्बत एवं भारत, नेपाल–केन्द्रित चीन की नीति के मूलाधार तो हैं ही साथ ही भारत ही चीन की दक्षिण एशियाई नीति का केन्द्रक तत्व है। चीन द्वारा संचालित बी0आर0आई0 को नेपाल द्वारा स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप भारत की हिमालयी–सीमान्त सुरक्षा में अब सम्वदेनशीलता के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। अक्टूबर, 2018 में भारत यात्रा से लौटते समय चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की अल्पकालिक नेपाल यात्रा के दौरान हुए 20 समझौतों से नेपाल व चीन की निकटता को नई दिशा मिली है। इन समझौतों के अन्तर्गत हुए महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत् हैं–

1. चीन की बी0आर0आई0 योजना को नेपाल का समर्थन।
2. वन चाइना नीति (One China Policy) को नेपाल का समर्थन।
3. राजमार्ग व रेलवे सम्पर्क मार्ग का विस्तार।
4. रणनीतिक समझौते

12 मई, 2017 को नेपाल ने बी0आर0आई0 पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किया जब इस परियोजना से सम्बन्धित आर्थिक–सामरिक पक्षों पर विश्व के कई राष्ट्रों ने आशंका प्रकट की है। हांगकांग मसले पर उलझे चीन ने दक्षिण एशिया में अपने हित–वर्धन के उद्देश्य से नेपाल को साधने हेतु 2.75 बिलियन डालर की सहायता देकर 'ट्रान्स–हिमालयन कनोक्टिविटी नेटवर्क (Trans Himalayan Connectivity Network) को सुगम बनाने की ऐसी चाल चली है जिससे ऐसा लगता है कि नेपाल को इसका लाभ कम ही मिलेगा। नेपाल–चीन सहयोग न केवल नेपाल के विभिन्न हिस्सों में चीनी उपस्थिति का एहसास कराने में सफल होगा बल्कि इसके माध्यम से भारत–नेपाल सीमा तक उसकी पहुँच सरल हो जायेगी। भारत व नेपाल के साथ त्रिपक्षीय व्यापार के माध्यम से चीन नेपाल की तराई के

Nepal's proposed railway network
CHINA
NEPAL
Kathmandu
INDIA
Janakpur
Source: Chinadialogue.net

साथ–साथ भारत की अधिक आबादी वाले राज्य बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा को व्यापारिक पारगमन हेतु उपयोग करने हेतु प्रयत्नशील है। नेपाल के साथ प्रत्यर्पण सन्धि करने के साथ ही चीन काठमाण्डू व बुटवल शहरों को मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में भी अत्याधुनिक ढंग से विकसित करना चाहता है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न कूटनीतिक उपायों के बावजूद नेपाल अपने आर्थिक हितों के संदर्भ में चीन से सौदेबाजी करने में असफल ही रहा है। सन् 2018–19 में नेपाल ने चीन को 2.1 बिलियन रूपये का सामान निर्यात किया जबकि आयात 205.52 बिलियन रूपये था। 203.4 बिलियन रूपये का व्यापारिक घाटा यह सिद्ध करता है कि चीन के खाने व दिखाने के दाँतों में पर्याप्त अन्तर है। स्पष्ट है कि सुरक्षा, रणनीतिक व आर्थिक मामलों में चीन–नेपाल सम्बन्धों व समझौतों में चीन की विशालता सम्बन्धी तत्व प्रभावी हैं तथा आशंका यह है कि भविष्य में नेपाल चीन के ऋण जाल में बुरी तरह फँस सकता है। उधर, चीन द्वारा प्रस्तावित 'चीन–नेपाल आर्थिक गालियारे' को विस्तृत कर इसे चीन–नेपाल–भारत–बाँग्लादेश गालियारे (CNIB) में परिवर्तित करने की योजना पर भी वह कार्य कर रहा है। यह तभी सम्भव है जब नेपाल–चीन के मध्य विस्तृत हो रहे रेलवे सम्पर्क भारत–नेपाल की सीमाओं तक पहुँच जाय। यह स्थिति भारत के आर्थिक विकास हेतु उपयोगी तो हो सकती है किन्तु चीन की भारत–विरोधी कुत्सित भावनाएं एवं शक्ति–प्रक्षेपण सम्बन्धी एशियाई नीति के परिणामस्वरूप यह सम्भव प्रतीत नहीं होता।

2. श्रीलंका–

मलक्का जलडमरूमध्य व स्वेज नहर के मध्य संचालित महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग पर स्थित श्रीलंका की सामरिक व भू–सामरिक स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस मार्ग से तेल टैंकर सहित लगभग 36,000 जहाजों का परिचालन श्रीलंका को हिन्दमहासागर में महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान उपलब्ध कराता है। 7 फरवरी, 1957 को चीन व श्रीलंका के मध्य स्थापित राजनयिक सम्बन्धों के पूर्व भी दोनों के

धार्मिक, आर्थिक व व्यापारिक सम्बन्धों का आधार समृद्ध रहा है। श्रीलंका चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स स्त्रातेजी' का प्रमुख देश है जिसके माध्यम से वह अपने हिन्दमहासागरीय हितों की पूर्ति व इसके अभिवर्द्धन हेतु सतत प्रयत्नशील है। चीन व श्रीलंका के मध्य मैत्री भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सन् 1981 में स्थापित श्रीलंका–चीन सोसाइटी के पश्चात 1982 व 1984 में दोनों के मध्य सम्पन्न क्रमशः "Sino-Sri Lanka Joint Trade Committee", एवं "Sino-Sri Lanka Economic and Trade Cooperation Committee" तथा 1994 में "Sri Lanka-China Business Cooperation Council" की स्थापना के फलस्वरूप उभयपक्षीयआर्थिक सम्बन्धों का आधार शनैः शनैः दृढ़ होता गया। निम्नांकित तालिका से इसकी पुष्टि होती है–

Sri Lanka Top 10 Export and Import Market, 2016 (Thousand)

No	Export		% of Export	Import		% of Import
	World	1054583	100	World	19,500,757	100
1	USA	2810220	26.6	China	4,270,756	21.9
2	UK	1045080	9.9	India	3,824,968	19.6
3	India	453481	7.1	UAE	1,067,273	5.5
4	Germany	509881	4.8	Singapore	1,030,316	5.3
5	Italy	428902	4.1	Japan	949,829	4.9
6	Belgium	337187	3.2	Malaysia	642,030	3.3
7	UAE	292867	2.8	USA	539,987	2.8
8	China	215493	2	Thailand	514,463	2.6
9	Netherland	208334	2	Taiwan	495,924	2.5
10	Japan	203819	1.9	Hong Kong	465,914	2.4

सन् 1996 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति चन्द्रिका भण्डारनाइक कुमार तुंगा ने चीन की यात्रा के दौरान आर्थिक,

सांस्कृतिक, सैन्य व तकनीकी सहायता सम्बन्धी समझौते करके चीन–श्रीलंका के द्विपक्षीय सम्बन्धों की सुदृढ़ आधारशिला रखी। सन् 2000 व 2010 के दशक में चीन ने श्रीलंका में पर्याप्त निवेश करके जो मैत्री प्रवाह विकसित किया उसी का परिणाम है कि 28 मई, 2013 को दोनों ही देशों ने स्त्रातेजिक सहयोग विस्तार हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए (National Independence, Sovereignty and Territorial Integrity) पारस्परिक राजनैतिक विचार–विमर्श एवं उपपक्षीय हितों की सुरक्षा व अभिवर्द्धन का संकल्प लिया था। इस अवसर पर श्रीलंका ने उत्कट इच्छा प्रकट करते हुए चीन के 'सामुद्रिक सिल्क परियोजना' में भाग लेकर अपनी बुनियादी सुविधाओं के विकास में उसके सहयोग का निर्णय तो लिया ही साथ ही भारत को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया था कि वह उसके जातीय मुद्दों (Ethnic Issue) पर किसी प्रकार का दबाव व हस्तक्षेप न करे। इसी समझौते के फलस्वरूप श्रीलंका ने चीन से एफ0डी0आई0 को आकर्षित कर घाटे के दबाव से प्रभावित अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ–साथ न केवल रक्षा सहयोग हेतु चीन को आकर्षित किया अपितु अपनी विकास परियोजनाओं को त्वरित गति देने की कोशिश की। श्रीलंका में हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को निम्नांकित तालिका से समझा जा सकता है–

Major Source of F.D.I in Sri Lanka (2011-2015)

	US $ Million	**% of Total**
China	989.6	15.5
Hong Kong	789.7	12.5
Mauritius	576.6	9.1
UK	571.7	9.0
India	477.2	7.5
UAE	426.8	6.7
Malaysia	415.3	6.5
Netherland	414.0	6.5

Singapore	385.7	6.0
USA	218.9	3.4
British Virgin Island	137.0	2.1
Luxemburg	124.0	2.0
Japan	114.0	1.8
Canada	113.4	1.8
Australia	95.2	1.5
Switzerland	61.1	1.0

बी0आर0आई0 की महत्वाकाँक्षी योजना के अन्तर्गत श्रीलंका की घाटे में चल रही 'हम्बनटोटा बन्दरगाह परियोजना' एवं इससे जुड़े 15000 एकड़ भू–क्षेत्र को 99 वर्ष के पट्टे पर लेकर चीन इसे विकसित कर रहा है। यद्यपि इस परियोजना पर श्रीलंका में ही सवाल उठते रहे हैं किन्तु चीन इसे श्रीलंका के हितों को पूर्ति करने वाली योजना कहकर कार्य को बढ़ावा दे तो रहा है किन्तु गतिरोध भी कायम है। श्रीलंका के मटाला हवाई अड्डे (Mattala Air Port) का भी निर्माण चीन ने ही किया है जबकि श्रीलंका की वर्तमान सरकार इन परियोजनाओं को अपने ऊपर डाले गये भार की संज्ञा देती है। चीन द्वारा संचालित 'कोलम्बो सिटी' परियोजना भी विवाद का विषय बनी हुई है। सच तो यह है कि श्रीलंका की सत्ता–राजनीति की प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी घात–प्रतिघात के कारण उक्त सभी योजनाएं निरन्तर चर्चा का विषय बनती रही हैं। दूसरी ओर, भारत अपने इस पड़ोसी को हर सम्भव सहायता देकर उसकी विकास–गति को बढ़ाने में गम्भीर कदम उठा रहा है। श्रीलंका में कोलम्बों को जाफना से जोड़ने वाले रेल मार्ग के विकास, युद्ध से विस्थापितों हेतु पचास हजार घरों का निर्माण, 'पलाली वायु आधार' (Palali Air base)व 'कनकसेन्थुराई बन्दरगाह' की मरम्मत जैसे कार्य इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इतना ही नहीं, चीन के साथ–साथ भारत भी श्रीलंका की सैन्य क्षमता की वृद्धि एवं संयुक्त सैन्य–अभ्यास के

माध्यम से उसकी लड़ाकू–क्षमता को समुन्नत व प्रभावी बनाने हेतु भी सक्रिय है। निम्नांकित तालिका से इसे समझा जा सकता है–

Indian and Chinese Projects in Sri Lanka

Indian Projects	**Chinese Projects**
- Restoration of Jaffna Library	Hambontota Port
- $ 800 million Omanthai-Jafna Railway Line	Mattala International Airport
- 45.27 Million Kanaksenthurai Port and Harbour Pallai Airport	Colombo Port City Project Roads (Colombo-Jaffna and Colombo-Gall Expressway)
50,000 Hourses for war displaced people.	Expansion of the Southern Terminal of Colombo Port

कर्ज के दबाव के फलस्वरूप श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस समय अस्थिर तो है ही वहीं चीन व भारत के मध्य यहाँ चल रही प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी राजनैतिक–मतभेद के कारण हिन्दमहासागर का यह महत्वपूर्ण देश व्यापारिक असंतुलन से पीड़ित हो रहा है। सन् 2014 में श्रीलंका पर वाह्य ऋण 44,489 मिलियन डालर था जो सन् 2016 में बढ़कर 46,586 मिलियन डालर हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गयी चेतावनी के बावजूद चीन द्वारा सन् 2019 में श्रीलंका को दिया जाने वाला 1 बिलियन 'बेल आउट' पैकेज उपलब्ध कराया तो अवश्य है किन्तु चीन के 'विकास बेंक' द्वारा इस राशि पर 5.25 प्रतिशत ब्याज लगाने से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव नही लगता। इस समय श्रीलंका की जी0डी0पी0 का 79.5 प्रतिशत अंश ऋण दबाव से ग्रसित है।

3. मालदीव–

यद्यपि भारत व मालदीव के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर व सहयोगी भावनाओं से आच्छादित रहे हैं किन्तु इसके साथ चीनी सम्बन्धों के विस्तार से

भारत–मालदीव सम्बन्धों में नकारात्मक भावनाओं का सूत्रपात हुआ है। सन् 1988 में भारत द्वारा मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल क्यूब के विरूद्ध हुए षड्यन्त्र से उनकी सुरक्षा हेतु किये गये भारतीय सामरिक प्रयास के पश्चात अब्दुल्ला यमीन के शासनकाल में द्विपक्षीय सम्बन्ध मैत्रीवत तो नही रहे किन्तु मालदीव के राष्ट्रपति मो0 नशीद के शासनकाल में भारत–मालदीव सम्बन्धों में पुनः नयी ऊर्जा की भावनाओं को बल दिया। फलतः, सन् 2016 में न केवल भारत व मालदीव के मध्य रक्षा सम्बन्धी एक 'कार्य योजना समझौते' पर हस्ताक्षर हुआ अपितु भारत–श्रीलंका व मालदीव के मध्य त्रिपक्षीय सम्वाद की भी शुरूआत हुई। मालदीव की सुरक्षा हेतु भारत ने राडार व तटीय गश्त हेतु गश्ती वाहन उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय सुरक्षा में मालदीव की भूमिका को महत्व तो अवश्य दिया किन्तु 2018 में चीन–मालदीव सम्बन्धों में आई मधुरता के कारण उसने भारतीय सहायता से इन्कार कर दिया। यह घटना 2018 में मालदीव में हुए चुनाव में पक्ष व विपक्षी दलों के मध्य हुए टकराव का ही परिणाम थी जिसमें विपक्षी दल ने भारत से प्रजातान्त्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु सहयोग की अपील की थी। भारत व मालदीव सम्बन्धों को सबसे बड़ा आघात तब पहुँचा जब भारत की प्रमुख जी0एम0आर0 समूह की 1978 में स्थापित 'इब्राहिम नासिर एअरपोर्ट' के निर्माण सम्बन्धी प्राप्त निर्माण अधिकार से उसे हटा दिया गया तथा निर्माण का यह ठेका चीन को सौंप दिया गया। यद्यपि बाद में 'सिंगापुर समझौता न्यायालय' में जी0एम0आर0कम्पनी को विजय प्राप्त हुई (227 मिलियन डालर की क्षतिपूर्ति मालदीव सरकार को देनी पड़ी) किन्तु इससे भारत–मालदीव सम्बन्धों में तनाव बढ़ गया। मालदीव व भारत के मध्य उत्पन्न विवादों को देखते हुए चीन ने मालदीव के समर्थन में पूर्वी हिन्दमहासागर क्षेत्र में फ्रिगेट्स सहित अपने नौ–सैन्य बेड़े भेजने की घोषणा भी की थी। इन्ही तनावों के कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मालदीव की यात्रा स्थगित करनी पड़ी जबकि चीनी निकटता के बावजूद मालदीव भारत से अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों की प्राथमिकता का नाटक करने में लगा रहा।

चीन के साथ अपने सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने हेतु मालदीव ने भारतीय हितों की परवाह किए बिना 1 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक मूल्य की भूमि क्रय करने का अधिकार प्रदान किया तथा दिसम्बर 2017 में 'मालदीव–चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेण्ट' पर हस्ताक्षर करके घाटे में चल रही अपनी योजनाओं को संजीवनी प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

मालदीव की उक्त गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य भारत सहित पश्चिमी शक्तियों को इस क्षेत्र में प्रभावहीन करना हैं जो चीन व राष्ट्रपति यमीन की मिली भगत का ही परिणाम है। राष्ट्रपति यमीन ने न केवल चीन की बी0आर0आई0 परियोजना का स्वागत करते हुए भारी चीनी निवेश को स्वीकार किया है अपितु भारत द्वारा वित्त–पोषित विकास योजनाओं एवं त्रिपक्षीय नौ–सैन्य अभ्यास के प्रति भी अरूचि दिखाई है तथापि मालदीव में निम्नांकित परियोजनाएं भारत व चीन के सहयोग से चल रही हैं–

Indian Projects in Maldives	**China's Projects in Maldives**
Indira Gandhi Memorial Hospital, Faculty of Engineering and Technology. India-Maldives friendship faculty of Hospitality and Tourism studies. Institute for Security and Law Enforcement Studies.	$ 800-Million expansion of the main airport by Chinese Company. China-Maldvies friendship Bridge, US $ 224.2 million 7,000 apartment housing project of Hulhumale Phase II

चीन के दबाव में मालदीव सरकार ने भारत के 'ध्रुव' हल्के हेलीकाप्टर्स को वापस लेने का निर्णय लिया है क्योंकि इससे चीन द्वारा निर्मित रक्षा–सुविधाओं की जासूसी का भय है। सन्तोष का विषय है कि मालदीव के नये राष्ट्रपति इब्राहीम मोहम्मद सोलिह ने भारत के साथ

आर्थिक सहयोग के विस्तार द्वारा घाटे में चल रही देश की अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाने की इच्छा व्यक्त की है।

हिन्द महासागरीय क्षेत्र में चीन की गतिविधियाँ–

सुविख्यात सामरिक चिन्तक ए0टी0महान के कथन कि, "Whoever control the Indian Ocean will dominate Asia .... The destiny of the world" से स्पष्ट है कि लगभग 73.6 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत हिन्दमहासागर वास्तव में सामुद्रिक सभ्यता का ऐसा सक्रिय क्षेत्र रहा है जो नवीन वैश्विक सन्दर्भ में भू–स्त्रातेजिक व भू–राजनीतिक दृष्टि से विश्व का गुरूत्व केन्द्र बनता जा रहा है। इस महासागर की तटीय रेखा लगभग 66525 किमी लम्बी है तथा यह तीन महाद्वीपों, अफ्रीका, एशिया व आस्ट्रेलिया द्वारा घिरा हुआ है। हिन्दमहासागरीय क्षेत्र (IOR) में 45 देश स्थित हैं जिनमें छः द्विपीय राष्ट्र (Island States) हैं। शीतयुद्धोत्तरकालीन राजनीति में हो रहे उथल–पुथल से गम्भीर रूप से प्रभावित यह जल क्षेत्र मलक्का, होरमुज, वेब–एल–मेण्डेव एवं केप आफ गुड होप जलडमरूमध्य द्वारा अन्य समुद्र व देशों से जुड़ा हुआ है। हिन्दमहासागर की यही भू–राजनैतिक विशिष्टता उसे सभी समुद्रों की 'कुन्जी' के अलंकरण से सुशोभित करती है। हिन्दमहासागरीय क्षेत्र निम्नाकित छः उप–क्षेत्रों में विभक्त है–

1. दक्षिण अफ्रीका
2. हार्न आफ अफ्रीका
3. पश्चिम एशिया
4. द0पू0एशिया
5. दक्षिण एशिया
6. आस्ट्रेलिया

इन क्षेत्रों में स्थित देशों में लगभग 2.5 बिलियन आबादी निवास करती है जिनकी जी0डी0पी0 इतनी सशक्त है कि उनके पास 10.131 बिलियन अमेरिकी डालर की क्रय शक्ति क्षमता है।[21] 21वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के कई देशों की अर्थव्यवस्था तीव्रता के साथ विकसित हो रही है जिनमें भारत, म्यांमार, इथियोपिया व रवाण्डा उल्लेखनीय हैं।[22] हिन्दमहासागर विश्व का तीसरा सबसे

बड़ा सामुद्रिक क्षेत्र है जो विश्व के सम्पूर्ण महासागरीय क्षेत्र का 20 प्रतिशत तथा भू–सतह का 14.4 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में विश्व के आरक्षित गैस का 35 प्रतिशत तथा आरक्षित तेल का 66 प्रतिशत अंश यहाँ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, तेल व प्राकृतिक गैस का लगभाग 80 प्रतिशत व्यापार हिन्दमहासागर द्वारा ही संचालित होता है। इस महत्वपूर्ण महासागर के 'चोक प्वाण्ट्स' सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा चीन का लगभग 80 प्रतिशत तेल, गैस का अन्य व्यापार इन्ही मार्गो से सम्पन्न होता है। चीन के व्यापार के सम्बन्ध में प्रमुख चोक–प्वाइण्ट्स व उनसे सम्बद्ध देशों की स्थिति निम्नवत् है–[23]

China, Major Choke-points and key 10RA members

Major Choke Points	Significance in China's Energy Transport	IORA Countries
Strait of Hormuz	Almost 40 percent of China's total crude oil transport from three IORA Countries though it.	Iran, UAE, Oman
Bab-el-Mandeb	China is dependent on oil transport from South of Sudan on the Red Sea.	Yemen
Strait of Malacca	Almost 37 Percent of China's LNG imports, 46 percent of gas import and 59 percent of oil imports pass through IOR and enter this strait.	Indonesia, Malaysia and Singapore

स्पष्ट है कि सुरक्षा व आर्थिक विकास में हिन्दमहासागर की महत्वपूर्ण भूमिका एवं इस क्षेत्र पर नियन्त्रण के उद्देश्य से बड़ी शक्तियों के मध्य चल रही स्पर्धा को ही केन्द्रक में रखकर शंघाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शेन दिंगली (Shen Dingli) ने बलपूर्वक यह कहा कि "आतंकवाद व सामुद्रिक डकैती चीन

के लिए वास्तविक खतरे नहीं हैं बल्कि अन्य राष्ट्रों द्वारा चीन के व्यापारिक मार्गों का अवरूद्ध करना वास्तविक चुनौती है। इसलिए उसके लिए मात्र नीले जल वाली नौ सेना ही नहीं, अपितु अपने आपूर्ति मूल्य को कम करने हेतु समुद्र पार अन्य देशों में आधारों की स्थापना करनी चाहिए।'' दिंगली का यह भी अभिमत था कि चीन की उक्त रणनीति से वैश्विक शान्ति, कूटनीति, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता का भी पथ प्रशस्त होगा। उल्लेखनीय है कि चीन की सामुद्रिक महत्वाकाँक्षाओं का उद्देश्य विश्व की महानतम शक्ति बनने हेतु अपने आर्थिक, रणनीतिक व राजनैतिक विस्तार करते हुए हिन्दमहासागर के तटीय देशों सहित इसके सभी अवरोधक–स्थलों पर नियन्त्रण हेतु शक्ति–प्रेक्षण पर आधारित तो है ही साथ ही हिन्दमहासागरीय क्षेत्र में स्थापित भारत के प्रभाव को शनैःशनैः शिथिल करना भी है। चीन का निम्नांकित दृष्टिकोण उक्त परिप्रेक्ष्य में उदरणीय है–

"We can no longer accept the Indian Ocean as only an Ocean of Indian's __We are taking armed conflict in the region into account.[24]

हिन्दमहासागरीय क्षेत्र में भारत–केन्द्रित चीन की रणनीति के अन्तर्गत मलक्का जलडमरूमध्य से 1200 समुद्री दूर दक्षिण चीन सागर में हैनान द्वीप पर सन् 2008 में पनडुब्बियों की तैनाती एवं हैनान के दक्षिण पट्टी के 'सान्या अड्डे' पर सैन्य सुविधाओं के विस्तार से चीनी इरादों की पुष्टि होती है। मलक्का, बॉव–एल–मण्डेव व हारमुज जलडमरूमध्य पर नियन्त्रण हेतु चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' नीति का विशेष सामरिक–आर्थिक महत्व है क्योंकि इस कदम से वह इस क्षेत्र में स्त्रातेजिक भेदनीयता उत्पन्न कर न केवल भारत को घेरना चाहता है अपितु भारत–अमेरिका के मध्य स्थापित हो रहे रणनीतिक सम्बन्ध को भी वह शिथिल करना चाहता है। भारत के पृष्ठ भाग (Backyard) में चीन द्वारा प्राप्त की जा रही स्त्रातेजिक गहराई (Strategic Depth) से भारत की चिन्ता बढ़ना स्वाभाविक है। चीन के 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' व बी0आर0आई0 योजना के चीनी निहितार्थ यद्यपि वैश्विक हैं तथापि यह भारत के लिए यह गम्भीर चुनौती है। उक्त योजना के अन्तर्गत चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर,

श्रीलंका में हम्बनटोटा, बांग्लादेश में चटगाँव, म्यांमार में Sittwe, Coco Island, Hianggi, Kyaukphyn, Mergui, Zaddetyki थाईलैण्ड में Leam Chabang तथा कम्बोडिया में Sihanoukville सामुद्रिक व सैन्य सुविधाएं अर्जित कर अपनी सामुंद्रिक सेना हेतु 'अग्रिम संक्रियात्मक आधार' (FOB- Forward Operating Bases) स्थापित कर लिया है जो न केवल हिन्दमहासागर में उसके व्यापारिक हितों की रक्षा करेंगे अपितु तटवर्ती क्षेत्रों में उसके राजनैतिक व रणनीतिक विस्तार में भी सहायक होंगे। जनरल वी0के0मलिक (पूर्व थल सेनाध्यक्ष) के शब्दों में "Its warships may thus be used only for naval diplomacy and geopolitical presence. PLA navy's submarine forces are however more likely to be deployed in the medium terms both during peacetime and in case of hostilities to deter its adversaries to deter its strategic imports and other operational missions."[25]

Ocean Agenda-21 के मूलाधार पर विकसित सामुद्रिक व्यापार नीति एवं वैश्विक शक्ति–संरचना में अपनी प्रभावी भूमिका तय करने हेतु चीन ने हिन्दमहासागर की भू–स्त्रातेजिक व भू–राजनैतिक महत्ता को समझते हुए उसके पूर्वी व पश्चिमी प्रवेश द्वारों, क्रमशः मलक्का स्ट्रेट एवं होरमुज स्ट्रेट से संलग्न क्षेत्रों में अपनी राजनैतिक व सामरिक उपस्थित हेतु क्षेत्रीय राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक व्यापार को तो प्राथमिकता दी ही है साथ ही इस क्षेत्र में अपने सामुद्रिक हितों के रक्षार्थ नौसैनिक सुविधाएं प्राप्त करने का सुनियोजित कार्यक्रम चलाया है। वास्तव में, चीन की सरकार ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों, विशेषकर विभिन्न क्षेत्रीय द्वीपों पर अपनी सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारों की पूर्ति हेतु नौ सेना के प्रयोग में भी किसी प्रकार का संकोच नही किया। क्षेत्रीय–सम्प्रभुता तो चीन की सुरक्षा का विशेष रोग है जिसकी पूर्ति हेतु वह सदैव आक्रामक कूटनीति हेतु तत्पर रहता है। चीन की सामुद्रिक सुरक्षा रणनीति में निम्नांकित विवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है–

1. ताइवान विवाद।
2. जापान के साथ सेनकाऊ व डायूटी द्वीप (Sankaku and Diaoyutai Island) विवाद।

© Nations Online Project
CHINA
National capital
Province capital
City, town
International airport
International boundary
Expressway
Main road
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
KYRGYZSTAN
NORTH KOREA
SOUTH KOREA
NEPAL
BHUTAN
INDIA
BANGLADESH
MYANMAR
LAOS
THAILAND
VIETNAM
CAMBODIA
PHILIPPINES
TAJ.
AFG.
PAK.
Kashmir
Aksai Chin
Indian claim
Novosibirsk
Irkutsk
Ulan-Ude
Lake Baikal
Lake Balkhash
Ulaanbaatar
Bishkek
Almaty
Yining
Altay
Karamay
Ürümqi
Turpan
Hami
Aksu
Korla
Kashgar
Hotan
Yumen
Zhangye
Yinchuan
Hohhot
Beijing
Tianjin
Dalian
Shenyang
Changchun
Jilin
Hunchun
Harbin
Jixi
Heihe
Hailar
Vladivostok
Pyongyang
Seoul
Jeju
Korea Bay
Bo Hai
Yellow Sea
Demarcation Line
Taiyuan
Shijiazhuang
Yantai
Jinan
Qingdao
Lianyungang
Xining
Lanzhou
Golmud
Xi'an
Zhengzhou
Nanjing
Hefei
Shanghai
Hangzhou
Wuhan
Chengdu
Chongqing
Changsha
Nanchang
Fuzhou
Quanzhou
Xiamen
Shantou
Taipei
Taiwan
Kaohsiung
Taiwan Strait
Guangzhou
Dongguan
Shenzhen
Hong Kong S.A.R.
Macau S.A.R.
Nanning
Zhanjiang
Haikou
Hainan
Gulf of Tonkin
Guiyang
Kunming
Lijiang
Dali
Lhasa
Shigatse
Nagqu
Qamdo
New Delhi
Kathmandu
Thimphu
Guwahati
Dhaka
Myitkyina
Mandalay
Naypyidaw (administrative capital)
Yangon
Chiang Mai
Vientiane
Hanoi
Bangkok
Da Nang
Manila
Luzon
Mindoro
Panay
East China Sea
Philippine Sea
South China Sea
PARACEL ISLANDS
Andaman Sea
Yellow
Yangtze
Mekong
Salween
Brahmaputra
Ganges
Irrawaddy
Amur
Songhua Jiang
Argun
Shilka
Lena
Angara
Yenisey
Ob'
Irtysh
0 200 400 600 800 km
0 250 500 mi
N

3. ताइवान, वियतमान, फिलीपीन्स, ब्रुनई व मलेशिया के साथ दक्षिण चीन सागर में जलक्षेत्र व स्थल आकृति सम्बन्धी विवाद।

4. वियतमान के साथ सामुद्रिक सीमा विवाद।

5. उत्तरी कोरिया, द0कोरिया, जापान, वियतमान व फिलीपीन्स के साथ मत्स्य–शिकार क्षेत्र व नियतांश सम्बन्धी विवाद।

6. जापान के साथ सामुद्रिक सीमा विवाद।

21वीं शताब्दी में हिन्द महासागर से संलग्न अपने आर्थिक–सामरिक हितों की रक्षा हेतु भारत–अमेरिका–वियतनाम–जापान–आस्ट्रेलिया के मध्य स्थापित व प्रगाढ़ हो रहे उभयपक्षीय सम्बन्धों को ध्यान में रखकर चीन ने जहाँ एक ओर दक्षिण चीन सागर व मलक्का क्षेत्र में अपने हित–रक्षण हेतु तटीय देशों को पर्याप्त सहायता देकर सैन्य आर्थिक सुविधाएं विकसित करने की हर सम्भव कोशिश की है वहीं पश्चिमी हिन्दमहासागर में भी चीन पर्याप्त सक्रिय है। सी0पी0ई0सी0 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' से जुड़ी चीन की हिन्दमहासागर केन्द्रित भारत–विरोधी रणनीति का ही परिणाम है कि उसने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका तथा मालदीव में रणनीतिक आधार विकसित कर लिए हैं तथा मालदीव पर दबाव डालकर न केवल भारत को हटने हेतु विश्व कर दिया अपितु सन् 2018 में उसने मालदीव के गाधू द्वीप (Gadhoo Island) पर बन्दरगाह सुविधाएं प्राप्त कर लीं हैं। यह घटना हिन्द महासागर में भारत के लिए प्रत्यक्ष चुनौती है।

पश्चिमी हिन्दमहासागर से सम्बद्ध देशों के साथ चीन के समृद्ध हो रहे आर्थिक, राजनैतिक व सैन्य सम्बन्ध भारत सहित अमेरिका व जापान के हिन्दमहासागरीय रणनीति के लिए चिन्ताजनक हैं। हिन्दमहासागर का दक्षिणी इलाका निम्नांकित कारणों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है–

1. यह क्षेत्र अफ्रीका के तटवर्ती व स्थल–बद्ध राज्यों (Land-Locked States) को हिन्दमहासागर, यूरोप व एटलाण्टिक महासागर से जोड़ता है तथा एशिया व ट्रान्स–अटलाण्टिक विश्व के ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख द्वार (Gateway) है। बाव–एल–मण्डेव व मोजाम्बीक चैनेल की अवस्थिति इस सम्पूर्ण क्षेत्र की व्यापार व अर्थव्यवस्थाा की दृष्टि से

महत्वपूर्ण है। 1967 के अरब–इजराइल युद्ध के दौरानन मिस्त्र द्वारा स्वेज नहर को सामुद्रिक यातायात हेतु बन्द करने से उत्पन्न संकट से इस क्षेत्र की व्यापारिक सम्वेदना को समझा जा सकता है।

2. पश्चिमी हिन्दमहासागर में बड़ी शक्तियों की उपस्थिति के फलस्वरूप इस क्षेत्र की सम्वेदनशीलता एवं भू–राजनीति की गुरूता में अभिवृद्धि हो गयी है। जिबुती में फ्रांस का सैन्य आधार होने तथा इस क्षेत्र में रियूनियन व मायोटी की स्थिति ऐसा तत्व है जिनके माध्यम से फ्रांस अपनी शक्ति व प्रक्षेपण सरलता से कर सकता है।[26] डीगोगार्सिया में अमेरिकी सैन्य आधार होने तथा यहीं से सम्पूर्ण हिन्दमहासागर व एशिया में प्रभाव–स्थापन हेतु उसकी अद्भुत क्षमता से इस क्षेत्र के सामरिक महत्व का सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है– सन् 2017 से ही चीन द्वारा जिबुती में सैन्य आधार की स्थापना सम्बन्धी प्रयत्न एवं रूस, संयुक्त अरब अमीरात एवं साउदी अरब द्वारा की गई गतिविधियों से लाल सागर से सम्बद्ध क्षेत्र के भू–आर्थिक व रणनीतिक आयाम गम्भीर रूप लेते जा रहे हैं।[27]

3. ऊर्जा विशेषज्ञों के मतानुसार सोमालिया व मोजाम्बीक के तटीय समुद्र क्षेत्रों में उपलब्ध विशाल ऊर्जा संसाधनों के फलस्वरूप यह क्षेत्र 21वीं शताब्दी में ऊर्जा का केन्द्र स्थल (Energy hub) बनता जा रहा है।[28] इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में उपलब्ध लगभग 135 बिलियन डालर का मत्स्य–उद्योग भी इसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। इस क्षेत्र में चीन का आर्थिक–विनियोजन संघर्ष को उत्प्रेरित कर रहा है।

4. अफ्रीका महाद्वीप के तटीय देशों के भारत से द्विपक्षीय सम्बन्धो के फलस्वरूप हिन्दमहासागर का पश्चिमी क्षेत्र भारत की अफ्रीकी नीति का आकर्षण स्थल व भारतीय नौ सेना के हितों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

5. द0पू0 एशिया व दक्षिण एशिया के अतिरिक्त अफ्रीका के तटीय देशों के साथ सुदृढ़ हो रहे चीन के सम्बन्धों के फलस्वरूप यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा व व्यापारिक हितों की दृष्टि से सम्वेदनशील है तथा यहाँ

चीन–भारत की स्पर्धा नवीन भू–राजनीतिक संघर्ष को उत्प्रेरित कर रही है।

हिन्दमहासागर से सम्बद्ध पश्चिमी एशिया क्षेत्र में तेल व गैस के अक्षय भण्डार के कारण चीन व भारत दोनों के लिए विकास को द्रुत गति प्रदान करने हेतु यह क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साउदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत व कतर जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश दोनों उदीयमान शक्तियों के लिए तेल संसाधन, कच्चे माल, खनिज व विभिन्न धातुओं की आपूर्ति–स्रोत हैं। अकेले साउदी अरब ही प्रतिदिन 12 मिलियन बैरेल क्रूड आयल का उत्पादन करने की क्षमता से सुसम्पन्न है। समुद्री डकैती व विभिन्न अपरम्परागत खतरों (मादक द्रव्य, छोटे हथियार, मानव तस्करी, मनी लाड्रिंग व विभिन्न अपराधिक कृत्य) से प्रभावित यह क्षेत्र (Golden Crescent-Iran, Afghanistan, Pakistan) तस्करी का प्रभावी क्षेत्र हैं। 'गोल्डेन त्रिकोण' जैसे क्षेत्र (Golden Triangle-Myanmar, Laos, Thailand) भी हिन्दमहासागर से सम्बद्ध द0पू0 एशिया में स्थित हैं। इस समय चीन अपने ऊर्जा आवश्यकताओं का 52 प्रतिशत अंश पश्चिमी एशिया से, 22 प्रतिशत अफ्रीका से तथा कुल मिलाकर प्रतिदिन 7.4 मिलियन बैरेल तेल की आपूर्ति करता है। यही कारण है कि चीन येनकेनप्रकारेण अपनी समुद्री आपूर्ति मार्ग की सुरक्षा हेतु भारत के विरूद्ध रणनीतिक–आर्थिक घेरेबन्दी कर हिन्दमहासागर पर वर्चस्व बनाये रखना चाहता है। उल्लेखनीय है कि चीन हिन्दमहासागर के तटीय देशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन्दरगाहों, राजमार्गो व रेलवे के विस्तार हेतु गम्भीर कदम उठा रहा है। केन्या में लामू बन्दरगाह (Lamu Port), तंजानिया में बगामोओ बन्दरगााह (Bagamoyo Port) ओमन में डुकम बन्दरगाह (Duqam Port) व सीमेण्ट व तेल शोधनशाला, तन्जानिया,–जाम्बिया रेल विस्तार तथा इथियोपिया व जिबुती को जोड़ने वाली 470 किमी0 लम्बी विद्युत रेलवे लाइन व मोम्बासा–नैरोबी रेलवे परियोजना को चीन विकसित कर रहा है। स्वाधीनता के पश्चात केन्या (नैरोवी) में निर्मित रेलवे परियोजना अब तक की सबसे बड़ी आधारभूत परियोजना है। केन्या की उक्त योजना को विस्तृत रूप देकर इसे द0सूडान, इथियोपिया, कांगो, यूगांडा, बुरूण्डी व रवाण्डा तक विस्तार देने हेतु चीन संकल्पबद्ध है। तजानिया में 523

किमी0 रेलवे के विस्तारीकरण द्वारा वह दार–एस–सलाम के कोयले के समृद्ध–क्षेत्र मटवारा (Mtwara) तक अपनी पहुँच बनाना चाहता है। तंजानिया रेलवे नेटवर्क को बगामोओ (Bagamoyo) से जोड़ने के साथ ही चीन द्वारा तंजानिया व जाम्बिया को रेलवे मार्ग से जोड़ने का कार्य भी प्रगति पर है। इतना ही नहीं, 1455 किमी0 लम्बे तेल पाइप लाइन द्वारा वह यूगांडा व तन्जानिया को भी जोड़ना चाहता है। चीन की उक्त महत्वाकाँक्षी परियोजनाओं से जहाँ एक ओर सम्बद्ध देशों से चीन का द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों का आधार सुदृढ़ होगा वहीं ये योजनाएं उसके रणनीतिक हितों की पूर्ति में भी सहायक होगीं। अफ्रीकी क्षेत्र में अपने सुरक्षा व रक्षा हितों के विस्तार हेतु सन् 2018 में चीन द्वारा आयोजित 'चीन–अफ्रीका सम्वाद, जिसमें 50 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया था, उक्त दृष्टिकोण से सर्वथा उल्लेखनीय है।

सन् 2017 से ही जिबुती (Djibouti) में स्थापित चीन के सैन्य आधार का उल्लेख यहाँ भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से सर्वथा उल्लेखनीय है। बीजिंग से लगभग 7000 किमी0 दूर स्थित जिबुती के दोरालेह शहर में चीन द्वारा समुद्रपार अन्य देश में अपना पहला सैन्य आधार विकसित करने से इस क्षेत्र में हलचल उत्पन्न हो गयी है। जनवरी 2016 में चीन ने लाल सागर को हिन्दमहासागर से जोड़ने वाले बाव–एल–माण्डेव क्षेत्र में स्थित जिबुती के साथ 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसमें अतिरिक्त 10 वर्षो तक विस्तृत करने की व्यवस्था है। विश्व के सबसे व्यस्ततम नौ–वहन मार्ग पर स्थित जिबुती पर सैन्य आधार विकसित करने एवं इसके रणनीतिक महत्व का ही यह परिणाम है कि उसके इस कदम से 21वीं शताब्दी की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विस्मयकारी उतार–चढ़ाव आने की सम्भावनाओं को बल मिल सकता है। हिन्द महासागर क्षेत्र में स्थित देशों में स्थापित आधारों की आड़ में चीन अपने नौ सैनिक बेड़ो को भेजकर जहाँ एक ओर वह सामरिक–राजनीति शक्ति का प्रक्षेपण कर रहा है वहीं अपने आयात–निर्यात का विस्तार करके वह अपनी शक्ति में वृद्धि हेतु प्रयत्नरत है। ग्वादर (पाकिस्तान), सलालाह (ओमन) सिचेल्स व जिबुती जैसे सैन्य आधारों की श्रृखंला उसकी महानस्त्रातेजी[29] एवं वर्चस्व–भावना को प्रकट करती है। ध्यातव्य है कि महान स्त्रातेजी के कुशल

संचालन से ही कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शक्ति का विकास व हितों का संर्वधन कर सकता है। मई 2015 में चीन द्वारा प्रकाशित श्वेत–पत्र में चीन को सन् 2049 तक एक स्थिर, सम्पन्न व शक्तिशाली देश बनाने के परिप्रेक्ष्य में चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने अपने विचारों का विस्तृत वर्णन व विश्लेषण किया है। चीन द्वारा उक्त संदर्भ में किये जा रहे सैन्य आधुनिकीकारण, शक्ति–संरचना के निर्माण, तकनीकी अनुसंधान, सैन्य अनुसंधान एवं युद्ध संचालन हेतु सैन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त अन्य उपायों को विकसित करने की प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी है। अफ्रीका के साथ 220 बिलियन डालर, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ 255 बिलियन डालर एवं एशियान देशों के [30] साथ 350 बिलियन डालर के व्यापार सम्बन्धी चिन्ताएं चीन को व्यथित कर रही हैं क्योंकि उक्त सम्बद्ध क्षेत्रों पर सामरिक–राजनीतिक–कूटनीतिक वर्चस्व के अभाव में उसके व्यापारिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि चीन ने अपनी सैन्य शक्ति की पुनर्निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत 30,000 सैनिकों को कम करने के साथ ही डी एफ–26 (Gram Killer Ballistic Missile) एवं डी एफ–21 D (Carrier Killer Missile) को अपने प्रक्षेपास्त्र–शस्त्रागार में शामिल किया है। इतना ही नही, अन्तरिक्ष व साइबर स्पेस (Cyber-Space) में अपनी लड़ाकू सामर्थ्य में अद्‌भुत विकास कर सैन्य संक्रियात्मक क्षमता में बहु–आयामी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के अतिरिक्त स्थल युद्ध सम्बन्धी परम्परागत युद्ध अवधारणाओं को अद्यतन बनने के साथ चीन प्रभावी सामुद्रिक युद्ध क्षमता अर्जित कर महानतम शक्ति बनाने की ओर अग्रसर है। चीन व अमेरिका के सामुद्रिक शक्ति–संतुलन चीन के बढ़ रहे नौ सैन्य सामर्थ्य की पुष्टि करते हैं–

China-US Naval Balance

Warship Category	China	United States
Air Craft Carriers	1	10
Destroyer	23	62
Cruisers	-	22
Frigates	52	17

Corvettes	23	-
Ballistic Missile Submarines (SSBNs)	4	14
Attack Submarines (SSN and SS)	65	55
RAS Ships	8	30
Amphibious Ships	53	31

सामुद्रिक युद्ध–केन्द्रित विचारधाराओं को विकसित करने में संलग्न चीन ने यह हृदयंगम कर लिया है कि व्यापार, सुरक्षा व विकास के अर्न्तनिहित आयामों में सुसंगत व शक्तिशाली बनकर ही वह हिन्दमहासागरीय क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया की सुगठित शक्ति को शिथिल करके ही वैश्विक श्रेष्ठता हाँसिल कर सकता है। उसकी बी0आर0आई0 योजना के सच में यही निहितार्थ भी हैं। उक्त सन्दर्भ में चीन द्वारा अर्जित संक्रियात्मक क्षमता के अन्तर्गत पुनर्भरण क्षमता व विकास (RAS-Replenishment at Sea), जनसूचना (ISR- Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), प्रवेश–विरोधी व क्षेत्र–प्रतिवाद (A2/AD-Anti-Access/Area Denial) एवं लड़ने की तैयारी तथा नियमित नौ–सैन्य अभ्यास उसकी महत्वाकाँक्षाओं की पुष्टि करते हैं।

दक्षिण–चीन सागर में भारत–चीन स्पर्धा–

दक्षिण चीन सागर, एशिया–प्रशान्त क्षेत्र का सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है जहाँ व्याप्त क्षेत्रीय–संघर्षो के फलस्वरूप सशस्त्र–टकराव की सम्भावनाएं निरन्तर प्रबल रूप ग्रहण करती जा रही हैं। एशियान संगठन के सदस्य देशों के साथ चीन के विवाद, भौगोलिक विशिष्टता तथा प्राकृतिक संसाधनों से सुसम्पन्न इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के साथ चीन के घात–प्रतिघात के कारण यह क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील होता जा रहा है। इस क्षेत्र में सामरिक व आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु सक्रिय भारत तथा मलेशिया, वियतनाम, फिलीपीन्स के साथ चीनी विवादों ने भारत को सक्रिय रहने हेतु अभिप्रेरित किया है क्योंकि स्वतन्त्र नौ–वहन सुविधा की भारतीय नीति एवं

क्षेत्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान सम्बन्धी भारतीय इच्छा के फलस्वरूप चीन–भारत संघर्ष को भी नया आयाम मिल रहा है। सिंगापुर से मलक्का जलमडमरूमध्य व उत्तर पूर्व स्थित ताइवान स्ट्रेट से घिरा दक्षिण चीन सागर विश्व का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से उत्तरी पूर्वी व पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार सम्बन्धी भारतीय– निर्भरता एवं 'एक्ट ईस्ट पालिसी' का सफल संचालन ही भारतीय सक्रियता का प्रमुख कारण है। सामुद्रिक इतिहास के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ ज्योफ्रे टिल (Geoffrey Till) के मतानुसार[31] समुद्र शक्ति के स्वतन्त्र व अन्तर्सम्बन्धित तत्वों के चार मूल तत्वों–व्यापार, संसाधन, आसूचना व सामाजिक आदान–प्रदान की दृष्टि से यह क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही एशिया–प्रशान्त क्षेत्र की शान्ति, स्थायित्व व समृद्धि की दृष्टि से भी इस जल–क्षेत्र की वैश्विक शान्ति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है। तेल व प्राकृतिक गैस की अक्षय निधि से सुसम्पन्न व महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गो का नेटवर्क होने के कारण ही क्षेत्रीय स्पर्धा को यहाँ बढ़ावा मिल रहा है। इतना ही नहीं, समुद्री जीवजन्तु, कोरल रीफ्स, समुद्री घास व वनों तथा मछली आदि की उपलब्धता की दृष्टि से दक्षिण चीन सागर अत्यन्त समृद्ध है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन का 10 प्रतिशत अंश इसी क्षेत्र से होता है। एक अनुमान के अनुसर इस समुद्र में 11 बिलियन बैरल तेल व 190 ट्रिलियन क्यूबिक प्राकृतिक गैस के आरक्षित भण्डार उपलब्ध हैं।

दक्षिण चीन सागर की भू–स्त्रातेजिक स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रशान्त व हिन्दमहासागर के मध्य नौ–वहन का यह महत्वपूर्ण जंक्शन है। Selig S.Harrison के शब्दों में–

"The sensivity of South China Sea as a Strategic waterway is apperent form its location. To the southeast, it connects with the Indian Ocean through Malacca Strait, and to the northeast, it commands access to the East China Sea. The sea lane running between the Paracel and Spratlys is used by oil tankers moving from the Persian Gulf to Japan as well as by warships in route the Indian Ocean to the Pacific."[32]

एशिया–प्रशान्त क्षेत्र से भारत के व्यापार का लगभग 55 प्रतिशत अंश दक्षिण चीन सागर के मार्ग से ही सम्पन्न होता है। यही कारण है कि भारत के कई रक्षा विशेषज्ञों व नीति निर्धारकों ने 'एक्ट ईस्ट पालिसी' के सफल क्रियान्वयन में अफ्रीका के तट से दक्षिण चीन सागर तक विस्तृत हिन्दमहासागर को भारत के विदेशी व्यापार, ऊर्जा व राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है। भारत के पूर्व विदेश सचिव रंजन मथाई के अनुसार–

"The Asia Pacific region is witnessing evolution of regional economic and security architecture. We are participating in the process of East Asia Summit, ASEAN Regional forum, A DMM Plus and other forums. An open balanced and inclusive regional architecture is in the long-term interest of the region as a whole. Our strategic partnerships with Japan, Republic of Korea and other Asia Pacific countries also serve our long.-term economic development and security interests."

सी0राजा मोहन ने भी अपनी पुस्तक ''समुद्र मन्थन' में दक्षिण चीन सागर में भारतीय हितों के निम्नांकित पाँच प्रमुख कारण बताये है[33]_

1. पूर्वी एशिया के साथ होने वाले व्यापार हेतु सामुद्रिक संचार मार्ग सुरक्षित रखना।
2. पश्चिमी प्रशान्त महासागर के देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना।
3. दक्षिण चीन सागर को 'चीनी झील'(Chinese Lake) बनाने सम्बन्धी उसकी नवीन हठधर्मिता को नियन्त्रित करना।
4. इस सामुद्रिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति द्वारा सामुद्रिक हितों की सुरक्षा।
5. अपनी नौ–सैन्य उपस्थिति के फलस्वरूप क्षेत्रीय देशों के साथ विकसित हो रहे नौ सैनिक सहयोग को सुरक्षित रखना।

वास्तव में, दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में भारत की मूलभूत स्त्रातेजी इस क्षेत्र में स्वतन्त्र नौ चालान (Freedom of Navigation), क्षेत्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान (Peaceful Resolution of disputes) एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान (Respect of International Law) पर ही केन्द्रित हैं। 22 जुलाई, 2011 को भारत के

युद्धपोत 'आई0एन0एस0 ऐरावत' को दी गयी धमकी तथा सितम्बर 2011 को वियतनाम के तट पर भारत की कम्पनी ओ0एन0जी0सी0 विदेश' द्वारा किये जा रहे तेल खनन पर चीन की आपत्ति के पश्चात भारत द्वारा तटीय क्षेत्र के राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों को प्रभावी रूप देने से चीन–भारत स्पर्धा में तीव्रता आई है।

दक्षिणी–पूर्वी एशिया में अपने आर्थिक व सामरिक हितों की रक्षा, प्रविस्तार एवं अभिवर्धन हेतु भारत ने कूटनीतिक–आर्थिक–सामरिक दृष्टिकोण से पर्याप्त महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। मलक्का की खाड़ी क्षेत्र के महत्व[34] को दृष्टिगत रखते हुए अपनी 'एक्ट ईस्ट नीति' के सफल संचालन हेतु भारत इस क्षेत्र में स्थित एशियान देशों के साथ–साथ जापान व दक्षिण कोरिया के साथ उभयपक्षीय आर्थिक व सामरिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयत्नरत है। भारतीय प्रयत्नों से जहाँ एक ओर इस क्षेत्र में भारत की सुरक्षा–व्यवहार में वृद्धि हुई है वहीं क्षेत्रीय देशों में रक्षा व व्यापार के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं में भी नयी आशा का संचार हुआ है। भारत द्वारा नई दिल्ली में स्थापित 'एशियान–भारत केन्द्र' (ASEAN-India Centre) एवं इस क्षेत्र हेतु अलग से राजदूत की नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयों से क्षेत्रीय देशों के साथ सम्बन्धों में मधुरता की भावनाओं मे सकारात्मक विस्तार सम्बन्धी लक्षण प्रतीत हुए हैं। के0एम0 पन्नीकर ने यह मत व्यक्त किया है कि 'लुक ईस्ट नीति' के विस्तारण में नौ सेना की भूमिका महत्वपूर्ण है जिनके अन्तर्गत रक्षा के अतिरिक्त व्यापार व वाणिज्य पर विशेष ध्यान केन्द्रित होना चाहिए।[35] भारत ने इस क्षेत्र के देशों के साथ नियमित प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक व रक्षा उपकरण की आपूर्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की है तथा रक्षा–संस्थान की स्थापना का भी निर्णय लिया है। मिलन अभ्यास (MILAN-Indonesia, Thailand, Malaysia and Singapore), उद्धारक संक्रियाएं (SARIEX-with Malaysia, Singapore, Indonesia) एवं 'सिंगापुर–भारत द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास' (SIMBEX) आदि उक्त दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इस क्षेत्र में भारतीय नौ सेना ने अण्डमान निकाबार द्वीप स्थित कैम्पबेल खाड़ी में –नैवेल एअर स्टेशन' (INS Baaz) को 31 जुलाई, 2012 में स्थापित करके सिंगापुर व वियमनाम को सुविधाएं देने का भी कार्य प्रारम्भ किया है जिसे 'पूर्वी व द0पू0 एशिया की खिड़की' (Window

into East and Southeast Asia) की संज्ञा दी जा रही है। 3500 फिट रनवे की क्षमता से सज्जित आई0एन0बाज से भारी व हल्के एअरकाफ्ट सक्रियता के साथ संक्रियाओं का सम्पादन करके इस क्षेत्र में विस्तृत 60,00,00 वर्ग किमी के भारतीय 'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र' की रक्षा करने में समर्थ हैं।[36] सिंगापुर, इण्डोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैण्ड, कम्बोडिया व फिलीपीन्स के साथ भारत ने सुरक्षा सहयोग समझौते करके न केवल रक्षा सहयोग को विस्तार दिया है अपितु उन्हें भारत के 'तकनीकी व आर्थिक सहयोग कार्यक्रम' (ITEC-Indian Technical and Economic Cooperation) में साझीदार बनाने के अतिरिक्त सिंगापुर व इण्डोनेशिया को 'संयुक्त रक्षा–उत्पादन' हेतु प्रस्ताव देकर अपने रक्षा–आर्थिक सीमान्त को विस्तृत व सुरक्षित करने सम्बन्धी गम्भीर प्रयत्न भी किये हैं।

एशिया–प्रशान्त से सम्बद्ध इस क्षेत्र में वियतमान का भू–रणनीतिक महत्व सर्वाधिक है। यही कारण है कि भारत ने अपनी 'एक्ट ईस्ट पालिसी' के प्रमुख स्तम्भ के रूप में उसे शक्तिशाली बनाने हेतु गम्भीर व प्रभावी कदम उठाये हैं। विशाखापत्तनम स्थित 'आई0एन0एस0 सतवाहन' में वियतनामी नाविकों को जल के अन्दर लड़ाकू कार्यवाहियों में दक्ष करने सम्बन्धी प्रशिक्षण देने, SU-30MK_2 फाइटर जेट उड़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करने एवं भारत द्वारा निर्मित गैर मानवीय हवाई वेहिकिल्स आपूर्ति करने का भी प्रयास किया है। भारत–वियतनाम सम्बन्धों को सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों का ही सुफल है कि चीन दक्षिण चीन सागर में व्यथित व परेशान है। सच कहा जाय तो इस क्षेत्र में चीन ही हठधर्मिता भारत–वियतनाम सम्बन्धों में मजबूती हेतु उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। फिलीपीन्स व इण्डोनेशिया के साथ भारत के विकसित सामरिक सम्बन्ध अब चीन को बेचैन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 'मेकांग गंगा सहयोग' (MGC), 'बिम्सटेक' (BIMSTEC) व 'इण्डियन ओशन रिम एसोसिएशन' (IORA) जैसे बहुपक्षीय मंचों की परिधि में इस सम्पूर्ण क्षेत्र में बढ़ रही भारतीय भेदनीयता से न केवल भारतीय हितों का विस्तार हो रहा है अपितु जापान व भारत के रणनीतिक सम्बन्ध नवीन भू–रणनीतिक धुरी का निर्माण करते प्रतीत हो रहे हैं।

चीन की बेल्ट व रोड योजना, स्ट्रिंग आफ पर्ल्स नीति' एशिया में भारत की सामरिक घेरेबन्दी, एवं हिन्दमहासागर व दक्षिण चीन सागर में चीन की हठधर्मिता से उत्पन्न वैश्विक भू–राजनीतिक वातावरण में चीन जहाँ एक ओर विश्व की महानतम शाक्ति का दर्जा हाँसिल करना चाहता है वहीं वह अपने एशियाई प्रतिस्पर्धी भारत को एशिया, विशेषकर दक्षिण एशिया तक ही परिसीमित कर उसकी बढ़ रही वैश्विक–क्षमता व प्रभाव तथा उसके व्यापक हितों पर अंकुश लगाना चाहता है। यही कारण है कि भारत–विरोधी चीन की सक्रियता को ध्यान में रखकर जहाँ एक भारत ने 2017 में मनीला में अमेरिका–जापान–आस्ट्रेलिया के साथ 'भारत–प्रशान्त' क्षेत्र की[37] सुरक्षा हेतु संयुक्त रूप से सक्रियता प्रारम्भ की वहीं सी.पी.ई.सी. सम्बन्धी चीन की महत्वाकांक्षाओं का पूर्वानुमान कर इस पर गहरी आपत्ति भी प्रकट की। बी0वी0आई0एन0 (BBIN-Bangladesh, Bhutan, India, Nepal) की क्षेत्रीय पहल, एशिया–अफ्रीका ग्रोथ कोरिडर योजना (AAGA-Asaia-Africa Growth Corridor), क्वाड–स्त्रातेजी तथा चीन के साथ संलग्न हिमालयी क्षेत्र में रक्षा सम्बन्धी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तथा अपने सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक, व्यापारिक व रणनीतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ आधार देने जैसे महत्वपूर्ण कदम भारत ने उठाये हैं।

References:-

1. "We have slain a large dragon, but we live now in a jungle filled with a variety of poisonous snakes and in many ways the dragon was easier to keep track of."
   - D. Banerjee; Strategic Analysis, Dec 1993, p.1145.
2. Joshua J. Malik, "Silk Road, Ancient History and Encyclopedia, March 28, 2014.
3. Strategic Analysis, Vol. 24, No. 4, July-August 2018, p.3014.
4. A. T. Mahan, The Influence of the Sea Power upon History (1660-1783), 2010, Salzwasser Verlag, p.26.
5. Gerry Kearns, "Geography, Geopolitics and Empire, Transactions of the Institute of British Geographers', New Series, 35(2), April, 2010, p.189.
6. Thengyu Wu, 'Classical Geopolitics Realism and the Balance of Power Theory,' The Journal of Strategic Studies, 2017, p.14.
7. Strategic Analysis, July-August 2019.
8. Frontline, May 1, 2015.
9. Strategic Analysis op.cit, no.7, p.315.
10. Joyeeta Bhattacharya, Observer Research Foundation, May 23, 2017.
11. Strategic Analysis, Vol. 41, No. 6, Nov-Dec 2017, p.586.
12. Pandey R.S. China-Kendra Bharat ki Surakcha Chintayen, Akriti Prakashan, New Delhi, 2017, p.73.
13. Banyan, 'Massive Chinese Investment is a boon for Pakistan,' The Economist, London, September 9, 2017.
14. Nasir Jamal, 'Mother China : A Chinese revolution sweep across Pakistan,' Herald Karachi, August 2015.
15. Khurram Husain. 'CPEC Master Plan Reserved,' Dawn, Karachi, May 15, 2017.

16. S. Singh and Z. Cuiping , (eds), BCIM : Economic Corridor : Chinese and Indian Perspectives, Adroit Publishers, New Delhi, 2017.
17. The Hindu, October 5, 2015.
18. The Daily Star, Sept. 8, 2018.
19. Indian Express, December 25, 2015
20. Xinhua, "China, Sri Lanka Upgrade Their Relationship, May 28, 2013, Cited from Strategic Analysis, May-June 2019, p.250
21. David Michel and Russel Sticklor (eds.) 'Indian Ocean Rising : Maritime Security and Policy Challenges', Stimson Centre, Washington DC. 2012, p.12
22. Dan Kopf, "The Story of Ethiopia's Incredible Economic Rise, Quart Africa, Oct. 26, 2017.
23. Strategic Analysis, Vol. 38, No. 5, Sept-Oct, 2014, p.673
24. Youssef Bodansky, "The PRC surge for the strait of Malacca and Spratly Confronts India and the U.S.," Defence and Foreign Affairs, Strategic Policy, Washington D.C, Sept. 30, 1955 p.6-13
25. Harsh V. Pant The Indian Express Dec. 16, 2011
26. Bertil Lintner, The Costliest Pearl : China's Struggle for India's Ocean, context, Chennai, 2019 p.113
27. Neil Melvin, "The Foreign Military Presence in the Horn of Africa Region," Background Paper, April, 2019
28. David Michel and Russel Sticklor (eds.) 'Indian Ocean Rising Maritime Security and Policy Challenges', Stimson Center, Washington D.C., 2012, p.12
29. A grand Strategy is the highest level of strategy of controlling and utilizing national resources, both military and non-military, promote long-term core interests.

-William C. Martel, 'Grand Strategy in Theory and Practice : The need for an Effective American foreign Policy', Cambridge University Press, Cambridge, 2015 p.25.

30. Amitav Acharya, 'ASEAN 2030 : Challenges of Building a Mature Political and Security Community, ADBI working Paper Asian Development Bank Institute, Tokyo No. 441, Oct. 2013

31. Geoffrey Till, 'Sea power : A Guide Twenty-first century', Routledge, London, 2009, p.8

32. Selig S. Harrison, 'China, Oil and Asia : Conflict Ahead', Columbia University Press, New york , 1977, p. 191

33. C.Raja Mohan, 'Samudra Manthan, 'Sino- Indian Rivalry in the Indo-Pacific', Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C. 2012, p.184-85

34. "The Gulf of Malacca is like a mouth of crocodile, the Peninsula of Malaya being the upper and the jutting end of Sumatra being the lower jaw. The entry to the Gulf can be controlled by the Nicobars and the narrow end is dominated by the island of Singapore."

    -K.M. Panikkar, 'India and the Indian Ocean : An Essay on the Influence of Sea Power on Indian History', George allen & Unwin Ltd. London, 1951, p.21

35. Ibid, p.96

36. The Times of India, July 31, 2012

37. "Broader Asia takes shape at the confluence of the two seas of Indian and Pacific Ocean.

    - Statement of H.E. Shinzo Abe, P.M. of Japan.

अध्याय–7

भारत के स्त्रातेजिक प्रयत्न व भावी सुरक्षा आयाम

एशिया के दो विशाल देशों, भारत व चीन के मध्य स्थित नेपाल अपनी भू–सामरिक विशिष्टता के कारण निर्धारित संतुलित विदेशनीति द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, विकास व सम्प्रभुता की रक्षा हेतु यद्यपि सतर्क तो रहा है तथापि समय–समय पर उसकी पक्षपाती गतिविधियॉ उसे चुनौती भी देती रही हैं। भारतीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष रुप से जुड़े नेपाल को भारत का उत्तरी द्वार भी कहा जाता है जिसकी सुरक्षा हेतु ब्रिटिश–भारत की सरकार पर्याप्त सतर्क व सचेष्ट रही है। सन 1769 में पृथ्वी नरायाण शाह द्वारा एकीकृत नेपाल की स्थापना के बाद से नेपाल व अंग्रेजों के मध्य चले दीर्घकालिक संघर्ष के स्वरुप से यह पुष्ट होता है कि विभिन्न वाणिज्यिक प्रयत्नों के बावजूद नेपाल नरेश शाह ने चीन व भारत से दूरी बनाते हुए नेपाल के स्वतन्त्र हितों की रक्षा हेतु गम्भीर प्रयत्न किये। उधर अंग्रेजों ने भी 1767 से 1816 की कालावधि में शान्तिपूर्ण वार्ताओं, मित्रवत व्यवहार एवं अपने निहित उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु सदैव एक सधी हुई कूटनीति द्वारा नेपाल के साथ सम्बन्ध–स्थापना में प्राप्त किसी भी अनुकूल सुअवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। सन 1792 व 1801 की सन्धियॉ यह सिद्ध करती हैं कि नेपाल के प्रति अंग्रेजों के कूटनीतिक चातुर्य का स्तर क्या था। सन 1814–16 में आंग्ल–नेपाली युद्ध के पश्चात दोनों के मध्य सम्पन्न 'सुगौली सन्धि' ऐसा सोपान है जिसके फलस्वरुप नेपाल व ब्रिटिश भारत के मध्य औपचारिक सम्बन्धों की स्थापना सम्भव हुई। सन 1858–1914 के मध्य नेपाल व ब्रिटेन के मध्य भौगोलिक साम्यता, नेपाल के प्रति ब्रिटिश नीति तथा गोरखा व ब्रिटिश शक्तियों के मध्य स्थापित सांमजस्य आदि ऐसे पक्ष हैं जिसने सम्मिलित रुप से नेपाल व ब्रिटिश सम्बन्धों को गतिशीलता प्रदान की। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रमुख उद्‌देश्य भारत की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए चीन तक अपने व्यापारिक–सीमान्त को विस्तृत करना तो था ही साथ ही इस क्षेत्र में चीन व रुस द्वारा प्रभाव–विस्तार हेतु सम्भावित दबाव से नेपाल को सुरक्षित करना भी था। सुगौली सन्धि ही वह

स्तम्भ है जिसने न केवल नेपाल व ब्रिटिश भारत के मध्य शान्तिपूर्ण सम्बन्ध प्रक्रिया को आगे बढ़ाया अपितु सन 1923 में ब्रिटिश शासकों द्वारा नेपाल की सम्प्रभुता व स्वतन्त्रता को मान्यता देकर यह सुनिश्चित कर लिया गया कि नेपाल की विदेशनीति इस क्षेत्र में ब्रिटिश हितों के ही अनुरुप होगी। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त शीत युद्ध के परिदृश्य को ध्यान रखकर भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष विदेशनीति के संचालन एवं वैश्विक मामलों में सक्रिय अभिरुचि के फलस्वरुप नेपाल के प्रति अत्यन्त उत्सुकता का अभाव रहा क्योंकि इस कालावधि में भारत की विदेशनीति कश्मीर–केन्द्रित पाकिस्तान की आक्रामकता, तिब्बत पर चीन का नियन्त्रण, भारत–चीन युद्ध, सोवियत संघ–अमेरिकी शीत युद्ध सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा एवं अफ्रीका व एशिया के नवोदित राष्ट्रों के साथ तालमेल कर सुरक्षा–व्यवस्था निर्माण पर ही केन्द्रित रही। नेपाल के प्रति भारत की उदासीनता ही सम्भवतः वह प्रमुख कारक था जिसके कारण तिब्बत रुपी अन्तस्थ राज्य की समाप्ति के पश्चात नेपाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रियता एवं उसके नेपाल–केन्द्रित भावी इरादों का भारत सही ढ़ग से अनुमान न लगा सका। इसके पीछे भारत की विश्व शान्ति व अहिंसा की नीति एवं रक्षा–मामलों में की गयी उदासीनता प्रमुख कारक थे।

नेपाल के साथ भारत की संलग्न लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के पॉच राज्य–उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम स्थित हैं जबकि तिब्बत के साथ उसकी 1415 किमी0 सीमा संलग्न है। 31 जुलाई, 1950 को भारत व नेपाल के मध्य सम्पन्न 'शान्ति व मैत्री सन्धि' ही वह आधार है जिससे दोनों देशों के मध्य निर्वाध आवागमन, व्यापार व अन्य सामाजिक गतिविधियाँ सम्पन्न ही होती हैं साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय खुली सीमा के कारण ही दोनों के मध्य 'रोटी व बेटी' (A relationship based on sharing hearth and marriage)[1] के सम्बन्ध सुदृढ़ हैं। बौद्ध व हिन्दू धर्म के आधार पर भारत व नेपाल के मध्य अटूट सांस्कृतिक सम्बन्धों को सतत उत्प्रेरणा भी प्राप्त होती रही है। इतना ही नहीं, लुम्बिनी व बोध गया जहॉ एक ओर दोनों देशों के मध्य बौद्ध धर्म के सूत्र को सुद्ढ़ करते हैं वही नेपाल स्थित पशुपतिनाथ व भारत के चारधाम (जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम व बद्रीनाथ)

की पवित्र यात्राएं आज भी भारत व नेपाल को एक अटूट सूत्र में बाधने का कार्य करती हैं। लगभग 40,000 गोरखा सैनिकों की भारतीय सेना में सक्रिय सेवाएं यह पुष्ट करती हैं कि पृथक राजनीतिक ईकाई होने के बावजूद दोनों देशों की पारस्परिक निकटता व सम्बन्ध–सुदृढ़ता की जड़े पर्याप्त गहरी हैं। जहॉ तक नेपाल व चीन के मध्य सीमा का प्रश्न है तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (TAR) के साथ उसकी संलग्न सीमा पूर्णतः पर्वतीय है तथा लगभग 6100 मीटर ऊँची पर्वतमालाएं एक दूसरे सम्पर्क को अत्यन्त दुरुह तो बनाती ही हैं तथापि लगभग 90 प्रतिशत चीन–नेपाल का स्थलीय सम्पर्क इन्हीं क्षेत्रों में स्थित ग्लेशियर से गुजरता है। विश्व की 10 ऊँची पर्वतमालाओं में से आठ नेपाल–तिब्बत सीमा पर ही स्थित हैं जिनमें कंचनजंगा (28,209 फिट) व एवरेस्ट (29,029 फिट) प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि तिब्बत पर नियन्त्रण हेतु नेपाल व चीन के मध्य सम्पन्न विवाद व संघर्ष से उनके द्विपक्षीय सम्बन्ध भी प्रभावित होते रहे हैं। 1789–1792 में हुए चीन–नेपाल युद्ध की पृष्ठभूमि में इस बात के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे पुष्ट होता है कि इस युद्ध के फलस्वरुप न केवल नेपाल ने चीन के क्विंग शासक के अधिराज्य अधिकार को स्वीकार कर लिया था अपितु प्रत्युत्तर में चीन ने नेपाल पर होने वाले किसी भी वाहय आक्रमण के विरुद्ध उसे सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था किन्तु 1814–1816 के आंग्ल–नेपाल युद्ध में चीन मूकदर्शक ही बना रहा। तदानन्तर, 1855–56 में पुनः हुए नेपाल–तिब्बत युद्ध के पश्चात सम्पन्न 'थपाथली सन्धि' के आधार पर नेपाल ने न केवल तिब्बत को वाहय आक्रमणों से सुरक्षा करने का संकल्प लिया अपितु ल्हासा में राजसभासद (Courtier) की नियुक्ति के बावजूद उसने 1904 में तिब्बत पर अंग्रेजों के आक्रमण का विरोध न करने के साथ–साथ 1908 में चीन को दिये जाने वाला उपहार भी बन्द कर दिया। इसी बीच 1911 में क्विंग साम्राज्य के विरुद्ध प्रारम्भ क्रान्ति में तिब्बतियों की उग्र प्रतिक्रिया के कारण चीन को न केवल तिब्बत से बाहर जाना पड़ा अपितु नेपाल ने भी चीन से अपने सम्बन्ध तोड़ लिए। उल्लेखनीय है कि साम्यवादी चीन द्वारा तिब्बत पर पुनः अधिकार करने एवं तिब्बत में नेपाल के तीर्थयात्रियों व व्यापारिक गतिविधियों पर लगाये गये प्रतिबन्धों से परिवर्तित नवीन परिदृश्य की

यर्थाथवादी परिस्थितियों से अभिप्रेरित होकर चीन व नेपाल के मध्य सन 1955 में कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना हुई तथा विगत दशकों में दोनों ही धीरे–धीरे अपने निहित हितों की पूर्ति हेतु सामरिक व आर्थिक सीमान्त को निरन्तर विस्तृत व समृद्ध कर क्षेत्रीय भू–राजनीति पर निर्णायक प्रभाव डालने हेतु सुविचारित व दीर्घकालिक संयुक्त नीतियों पर सतत अग्रसर रहे।

जहॉ तक नेपाल का सम्बन्ध है सन 1950 से ही यह देश राजशाही, प्रजातन्त्र, माओवाद एवं प्रजातान्त्रिक–संवैधानिकवाद आदि गतिविधियों से संत्रस्त रहा है। अपने अस्तित्व की संरक्षा व विकास हेतु हिमालय की विशिष्ट भूमिका से प्रभावितनेपाल के साथ जहॉ एक ओर भारत ने सदैव गैर–विस्तारवादी व अहस्तक्षेप नीति द्वारा नेपाल की भारत–निर्भरता के विरुद्ध कोई भी अनैतिक लाभ न उठाकर सदैव उसकी हर सम्भव सहायता पहुँचाई वहीं नेपाल के प्रति चीन की नीतियॉ सदैव उसकी आन्तरिक विवशता का शोषण कर अपने लाभ पर ही केन्द्रित रही हैं। राजनैतिक अस्थिरता एवं माओवादी हिंसा से संत्रस्त नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से चीन द्वारा किया जा रहा हस्तक्षेप एवं नेपाल में भारत–विरोधी तत्वों के माध्यम से नेपाल व भारत में मतभेद उत्पन्न करने सम्बन्धी उसकी विविध कोशिशों से यह सिद्ध हो रहा है कि नेपाल अपने भू–राजनीतिक स्थिति व राष्ट्रीय हितों का सही आंकलन नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र के रुप में भारत के सामरिक–आर्थिक उभार से चिन्तित चीन द्वारा नेपाल में हस्तक्षेप के जो त्वरित प्रयत्न हो रहे हैं उससे प्रभावित भारत–नेपाल की भू–राजनीति व भारतीय विनियोजन नीति संकट के दौर से गुजर रही है। यद्यपि विभिन्न गतिरोधों व उथल–पुथल के बाद नेपाल में 20 सितम्बर, 2015 को लागू नये संविधान के आधार पर अपनी सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय एकता की शपथ लेने के साथ हिन्दू राष्ट्र के स्थान पर वह अब एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना तो अवश्य है किन्तु सत्तारुढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अन्तर्विरोध एवं जटिल मधेशी समस्या के कारण अभी भी नेपाल में प्रजातन्त्र की जड़ें अस्थिर ही हैं। नेपाल की सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से वहॉ चीनी आर्थिक निवेश व बी0आर0ई0 के अन्तर्गत हो रहा इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार एवं नेपाल की सुरक्षा व

विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उसके द्वारा नजरन्दाज करने के भावी परिणामों से नेपाल सम्भवतः सचेष्ट नहीं है। भारत–नेपाल सम्बन्धों में भारत की सहायता व निवेश नीति पर दृष्टिपात से यह पुष्ट होता है कि जवाहर लाल नेहरु से गुजराल डाक्ट्रिन और अब नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा नेपाल को दी जा रही सहायता एवं निवेश से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की विदेश नीति में नेपाल को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ध्यातव्य है कि सन 1950 के दशक से ही नदियों के जल–प्रबन्धन, सम्पर्कों के विस्तृत विस्तार एवं नेपाल की क्षमता वृद्धि में भारत का उत्कृष्ट योगदान रहा है। बाढ़–प्रबन्धन से सम्बद्ध लालबकेया, बागमती, कमला व खाण्डों नदियों के तटबन्धों के निर्माण (205 करोड़ रुपये) एवं जल–विद्युत उत्पादन में भारतीय सकारात्मक सहयोग से दोनों के सम्बन्ध प्रगाढ़ता[2] को समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, पर्यटन हेतु हवाई यातायात के विस्तार, राजमार्ग निर्माण, नेपालियों को सीमापार व्यापार सुविधाएं, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना किसी दस्तावेज के स्वतन्त्र आवागमन, व्यापार–घाटे में सुधार सम्बन्धी प्रयत्न, तराई क्षेत्र में सुगम यातायात हेतु 1450 किमी0 नयी सड़कों के निर्माण, वीरगंज–रक्सौल, सोनौली–भैरहवां, जोगवनी–विराटनगर, न्यू जलपाईगुड़ी–ककरभिटटा एवं रुपइडीहा–नेपालगंज जैसी रेल परियोजनाओं का विस्तार नेपाल के प्रति भारत की सद्भावना की पुष्टि करते हैं।[3] इतना ही नहीं, नेपाल के सभी जिलों में ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, सामुदायिक केन्द्रों के विस्तार, नेपाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा आर्थिक सहायता के अन्तर्गत लाइन आफ केडिट का विस्तार, हवाई अडडों के निर्माण में सहायता एवं विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में आर्थिक सहयोग जैसे भारतीय सदप्रयास यह सिद्ध करते हैं कि भारत सही अर्थों में नेपाल के विकास–गति का त्वरित कर उसे समृद्ध व सम्पन्न राष्ट्र बनाने हेतु संकल्पित है। उधर, नेपाल ने चीनी दबाव में आकर न केवल सुगौली सन्धि की अवहेलना कर लिपुलेख–महाकाली–लिम्पियाधुरा सीमा पर नये मानचित्र का निर्माण कर सीमा विवाद को नया आयाम दे दिया है अपितु 1950 की शान्ति व मैत्री सन्धि को

भी वह समाप्त करने हेतु प्रयत्नशील है। निश्चय ही नेपाल की सरकार चीनी प्रभाव में ही उक्त भारत–विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है।

1 अगस्त, 1955 को नेपाल व चीन के मध्य स्थापित कूटनीतिक सम्बन्ध एवं अप्रैल 1960 में सम्पन्न 'शान्ति व मैत्री सन्धि' के पश्चात से ही चीन का परम लक्ष्य सुरक्षा–केन्द्रित रहने के साथ–साथ भारत को असंतुलित व शनैः–शनै महत्वहीन कर अपने वर्चस्व की स्थापना कर ही केन्द्रित रहा है। नेपाल ंके साथ सीमा–व्यापार की वृद्धि हेतु नये बन्दरगाहों की स्थापना, चुंगी पद्धति को सरल बनाना तथा सीमा सम्बन्धी कानूनों का प्रभावी बनाते हुए सुरक्षा सहयोग में सतत सुदृढ़ता चीन की नेपाल–केन्द्रित प्रमुख नीति रही है। इसके अन्तर्गत दोनों देशों ने तिब्बत के जिलॉग, झांगमऊ व पुलान तथा नेपाल ंके तातोपानी, धारचूला व रसुआगढी ंके चेक प्वाइण्ट को सुदृढ़ करने हेतु 2010 में एक समझौता तो किया ही साथ ही दक्षिण एशिया में सीधे प्रवेश हेतु चीन ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (TAR) में रसद मार्ग की स्थापना में भी नेपाल का सहयोग प्राप्त किया जिसके लिए उसने कई प्रवेश द्वारों की स्थापना की। वास्तव में, नेपाल–केन्द्रित चीन की व्यापारिक व सामरिक नीतियों के मुख्य लक्ष्य नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों का समाप्त कर नेपाल भूमि से चीन–विरोधी गतिविधियों का उन्मूलन तथा भारत–नेपाल सीमा ंके तराई क्षेत्र तक अपने प्रभाव को विस्तृत करना ही है। नेपाल–चीन मैत्री संगठन, मीडिया व सांस्कृतिक संगठन, चीनी अध्ययन केन्द्र एवं आरनिको सोसायटी आदि की तराई क्षेत्र में सक्रियता एवं इनका विस्तार करके वह नेपाली समुदाय, गुप्तचरों व अन्य सुरक्षा एजेन्सियों के मध्य सुदृढ़ नेटवर्क की स्थापना करके नेपाल ंके माध्यम से भारत ंके विरुद्ध एक वृहद संजाल–तन्त्र ंके विकास हेतु चीन निरन्तर प्रयत्नशील है। इतना ही नहीं, चीन व नेपाल ंके मध्य निरन्तर सुदृढ़ हो रहे आर्थिक–सम्बन्ध व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सतत अभिवृद्धि ंके पीछे भी चीन नेपाल को अपने प्रभाव में लेकर भारत की घेरेबन्दी में ही संलग्न है। सड़क निर्माण, हवाई सुविधाओं ंके विस्तार, संचार सुविधा को उच्चीकृत करना, जल विद्युत संयन्त्रों ंके निर्माण, शंघाई–तिब्बत रेलवे का काठमाण्डू–खासा तक विस्तार तथा नेपाल में हवाई व नेपाल टेलीकाम के मध्य सहयोग जैसी

योजनाओं से चीन नेपाल पर एकाधिकार स्थापित करके उसकी भूमि का इस्तेमाल भारत ंके विरुद्ध करने हेतु गम्भीरता से सक्रिय है[4]। पारस्परिक सम्बन्धों की सुदृढ़ता हेतु चीन ने नेपाल में चीनी बौद्ध दर्शन ंके प्रविस्तार की विभिन्न कोशिशों ंके अन्तर्गत लुम्बिनी के विकास व बौद्ध पर्यटन को भी अपनी सांस्कृतिक कूटनीति का अंग बनाया है जिससे उसकी सांस्कृतिक जड़े नेपाल में सुदृढ़ हो सकें।

नेपाल में चीन की संलिप्ता एवं प्रभुत्व स्थापना सम्बन्धी उसके सामरिक व सामाजिक प्रयत्न नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन काल में अपेक्षाकृत सरल है। नेपाल के प्रधानमंत्री के0पी0शर्मा ओली व पुष्प कमल दहल के मध्य गहराते अविश्वास एवं इसमें चीन के राजदूत की सक्रिय अभिरुचि न केवल भारत के उत्तरी सीमान्त की सुरक्षा हेतु गम्भीर चुनौती है अपितु यह नेपाल के लिए शुभ नहीं है। तिब्बत की भॉति नेपाल को भी अपने जाल में फँसाकर चीन नेपाल की अन्तस्थ राज्य की भूमिका का लाभ उठाकर उसे एक उपनिवेश के रुप में स्थापित करना चाहता है। ध्यातव्य है कि भारत के हिमालयी सीमान्त में भारत व चीन के मध्य व्याप्त सीमा विवाद एवं चीन, भूटान, अरुणांचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल व लद्दाख पर अधिकार सम्बन्धी 'फाइव फिंगर पालिसी' के फलस्वरुप 21 वीं सदी में क्षेत्रीय भू–राजनीतिक आयाम और ही जटिल स्वरुप ग्रहण कर रहा है। आर्थिक व सामरिक क्षमता में आशातीत वृद्धि के कारण चीन न केवल दक्षिण चीन सागर में आक्रामक है अपितु जून 2020 में पुनः भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में सैन्य अतिक्रमण करके यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के प्रति उसके इरादों की मनोवृत्ति का स्तर क्या है। यहाँ पर उल्लेख अत्यन्त ही प्रासंगिक है कि चीन–पाकिस्तान–नेपाल धुरी भारत ंके विरुद्ध ऐसे समय में आक्रामक है जब पूरा विश्व चीन द्वारा ही फैलाए गये केविड–19 के दुष्चक्र में उलझ कर अपने बचाव में केन्द्रित है। विश्व में अपने विरुद्ध निर्मित जनमत एवं वैश्विक कूटनीतिक दबाव से पीड़ित चीन द्वारा भारत के विरुद्ध आक्रामक होना एशियाई सुरक्षा के लिए शुभ नहीं है।

भारत–नेपाल के मध्य अन्तर्द्वन्द व दुविधा–

नेपाल में चीन के बढ़ रहे हस्तक्षेप व भारत–विरोधी उसकी आक्रामक विदेशनीति से जहॉ एक ओर भारत के हिमालयी सीमान्त की रक्षा संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है वहीं नेपाल भी दिग्भ्रमित व भावी अनिष्ट के प्रति सचेष्ट व सतर्क नहीं है। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत व चीन के मध्य गहराते विवाद में उसकी पक्षपाती भूमिका क्षेत्रीय एवं स्वयं उसकी सुरक्षा हेतु शुभ नहीं होगी। सुगौली सन्धि के उपरान्त नेपाल व भारत के मध्य 31 जुलाई, 1950 को सम्पन्न शान्ति व मैत्री सन्धि दोनों के मध्य स्त्रातेजिक, सुरक्षा, सामाजिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा, एवं मैत्रीपूर्ण भावना व परिवेश निर्माण के सन्दर्भ में विशेष महत्वपूर्ण है। रक्षा व विदेशी मामलों के अतिरिक्त दोनों देशों के नागरिकों के मध्य जनसम्पर्क, सीमापार स्वतन्त्र आवागमन व व्यापार की धुरी यही सन्धि है। इस सन्धि की धारा–5 में यह वर्णित है कि शस्त्र, गोला–बारुद, युद्ध के अन्य संयन्त्र व सामानों की आपूर्ति वह पारस्परिक सहमति से भारत के द्वारा ही आयात कर सकता है तथा किसी वाह्य खतरों के विरुद्ध दोनों देश सुरक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्वों की निरन्तरता बनाये रखेंगे। उल्लेखनीय है कि स्वाधीनता के प्रारम्भिक वर्षों में भारत व नेपाल के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बने रहे किन्तु तिब्बत पर बलपूर्वक चीनी आधिपत्य के पश्चात भारत का हिमालयी सीमान्त चीनी आक्रामक मनोवृति के कारण असुरक्षित हो गया। पं0 जवाहर लाल नेहरु के निम्नांकित कथन उक्त चिन्ता पर प्रकाश डालते हैं–

" Though from time immemorial the Himalayas have provided India with a magnificent frontier, they are also no longer as impssable as they used to be penetrated by any unfriendly power …. India could not allow the barrier to be penetrated by any unfriendly power."[5]

उक्त कथन से भारत के उत्तरी सीमान्त की सुरक्षा में नेपाल का महत्व स्वतः सिद्ध है। भारत–चीन सीमा विवाद एवं पाकिस्तान के साथ हुए भारत के संघर्षों के फलस्वरुप दक्षिण एशिया के परिवर्तित भू–राजनीति के कारण नेपाल–केन्द्रित भारत–चीन स्पर्धा से नेपाल की विदेश नीति भी प्रभावित हुई।

नेपाल की राजशाही के विरुद्ध प्रजातान्त्रिक तत्वों की आक्रामक नीति, वहाँ साम्यवादी विचारधारा आधारित दलों के प्रविस्तार एवं माओवादी आन्दोलन से नेपाल पर चीनी शिकंजा शनैः शनैः सुदृढ़ होता गया। सन 1990 के बाद नेपाल में 1950 की मैत्री सन्धि में संसोधन की मॉग तीव्र होने लगी, जिसके पीछे नेपाल के निम्नांकित तर्क उभर कर सामने आये–

(i) यह सन्धि असमान राष्ट्रों को समान अधिकार प्रदान करती है जिसमें नेपाल के साथ पक्षपात हो रहा है। यदि दोनों देशों की एक प्रतिशत आबादी ही एक दूसरे देशों की नागरिकता लेने हेतु निर्णय कर ले तो नेपाल की जनसांख्यिकी असंतुलित हो जायेगी। यदि ऐसा हुआ तो नेपाल के तराई क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़ने से न केवल विभिन्न प्रकार की सामाजिक, व्यापारिक व आर्थिक चुनौतियों को नयी ऊर्जा प्राप्त होगी अपितु भारत व नेपाल के मध्य समान व्यापारिक अवसर होने के कारण नेपाल के आर्थिक व व्यापारिक पक्ष का भावी स्वरुप व संतुलन निश्चय ही प्रभावित होगा। नेपाल की तुलना में भारत की विशाल जनसंख्या व सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के फलस्वरुप नेपाल सदैव घाटे में ही रहता है।

(ii) यदि भारत 1950 की सन्धि में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो नेपाल में वह क्षमता नहीं है कि किसी भी प्रकार से भारत को ऐसा न करने हेतु विवश किया जा सके। ऐसा होने से नेपाल का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तो प्रभावित होगा ही साथ ही भारत द्वारा लगाये जाने वाले आर्थिक–प्रतिबध से नेपाल की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है।

(iii) अपनी स्थलबद्ध प्रकृति के कारण समुद्री व्यापार पर नेपाल की भारत पर निर्भरता सर्वाधिक चिन्ता का विषय है। उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु स्थलबद्ध देशों को प्राप्त मात्र एक ही समुद्री मार्ग का उपयोग करने सम्बन्धी अधिकार से भारतीय आर्थिक–नाकेबन्दी के भय से नेपाल सदैव व्यग्र व असुरक्षित महसूस करता है।

(iv) भारत–नेपाल सन्धि की व्यवस्था के अनुसार नेपाल भारतीय भूमि से ही युद्ध सामग्री व संयन्त्रों का आयात करने हेतु प्रतिबद्ध है किन्तु सन

1988 में नेपाल द्वारा आयातित हथियारों के सन्दर्भ में नेपाल उक्त सन्धि का उल्लंघन कर चुका है। सन्धि में निम्नांकित व्यवस्था है–

"Any arms ammunition or warlike material and equipment for security of Nepal that the Government of Nepal may import through the territory of India shall be so imported with the assistance and agreement of the govenment of India."[6]

नेपाल की सरकार भारत–नेपाल मैत्री सन्धि में उल्लिखित उक्त व्यवस्था को समाप्त करके शस्त्र–व्यापार में स्वतन्त्र नीति निर्धारण हेतु प्रयत्नशील है जबकि भारत आवश्यकतानुसार शस्त्र–आपूर्ति हेतु सदैव नेपाल की सहायता करता रहा है।

(v) नेपाल का मत है कि एक सम्प्रभु राष्ट्र होने के कारण वह किसी भी देश से शस्त्र–आपूर्ति हेतु स्वतन्त्र है तथा शस्त्र आयात हेतु नेपाल को भारतीय सुझाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नेपाल व चीन के मध्य प्रगाढ़ होते रिश्तों की पृष्ठभूमि में यह समझा जा सकता है कि भारत–नेपाल मैत्री संसोधन हेतु नेपाल की व्यग्रता व दूरगामी सोच क्या है जबकि नेपाल को मिल रही भारतीय सहायता, व्यापार, पारगमन सुविधा आदि इस सन्धि के मूल तत्व हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल के बार–बार आग्रह को ध्यान में रखते हुए ही अगस्त 2014 में भारत के प्रधानमन्त्री मोदी ने नेपाल यात्रा के दौरान वहॉ की सरकार, राजनैतिक दलों व मीडिया के समक्ष यह घोषणा की थी कि वे इस सन्धि के संसोधन, सुधार, अद्यतन करने एवं अन्य द्विपक्षीय समझौतों को ठोस आधार देने हेतु सहमत हैं जिससे भावी सम्बन्धों को स्थिर व मधुर बनाया जा सके। प्रधानमन्त्री मोदी ने स्पष्ट कहा था कि–

"The issue of the 1950 treaty is being raised time to time and again, please speak frankly what you want, but refrain from politicizing it."[7]

वास्तव में, मैत्री सन्धि में वांछित संसोधन हेतु सन्धि की व्यापक समीक्षा करते हुए इसकी विभिन्न धाराओं में दोनों देशों द्वारा हुए उल्लंघन पर विचार–विमर्श कर उभयपक्षीय सुरक्षा व व्यापारिक हितों के विस्तार हेतु पारस्परिक राजनैतिक गम्भीरता का परिचय देना होगा। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया के नवीन भू–राजनैतिक परिदृश्य एवं सम्भाव्य रक्षा चुनौतियों का ध्यान रखकर दोनों ही देशों को सामूहिक हितों के रक्षार्थ तत्पर तो होना ही होगा साथ ही चीन के दबाव में आये बिना नेपाल को सम्प्रभुता के मूलभूत तत्वों के अनुरुप परिपक्वतापूर्ण कदम उठाने होंगे।

2. भारत–नेपाल की खुली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों को हर दृष्टि से प्रगाढ़ बनाने व मैत्री–सुदृढ़ता को निरन्तर गतिशील बनाये रखने में सहायक तो अवश्य रही है किन्तु कभी–कभी इसकी भौतिक प्रकृति व अवाँक्षित तत्वों द्वारा किये जा रहे दुरुपयोग से भारत–नेपाल सम्बन्धों में रोष, अविश्वास व तनाव भी उत्पन्न होते रहे हैं।[8] सीमा–पार अपराध, तस्करी व आतंकवाद जैसी गतिविधियों हेतु नेपाल की भूमि से भारत के विरुद्ध एवं पाकिस्तान की आई0एस0आई0, माओवादी व नेपाल में भारत–विरोधी दलों व अराजक तत्वों के गठजोड़ ने भारत के उत्तरी सीमान्त को असुरक्षित करने के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया है। सच कहा जाय तो नेपाल न तो अपनी आन्तरिक शान्ति को ही सुदृढ़ कर पा रहा है और न ही सीमा सुरक्षा को ही प्रभावी बनाए रखने में ही सफल हो रहा है क्योंकि हिमालय से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की न तो नेपाल में क्षमता है और न ही व्यापक दृढ़ भू–राजनैतिक संकल्प। यही कारण है कि भारत–विरोधी व पाक–समर्थित कश्मीरी तत्वों ने नेपाल को परागमन राष्ट्र (Transit Country) मानकर बार–बार सीमा पार कर भारतीय सुरक्षा को संकटापन्न करने की कोशिशे की हैं[9] जबकि 1950 की मैत्री सन्धि में यह स्पष्ट संकल्प लिया गया है कि दोनों देश अपनी भूमि का उपयोग एक दूसरे के विरुद्ध कदापि नहीं होने देंगे।

भारत नेपाल सीमा की लम्बाई 1751 किमी0 है जिसका निर्धारण सुगौली सन्धि के अन्तर्गत किया गया था तथा भारतीय स्वतन्त्रता के बाद नेपाल व भारत के बीच इसे सीमा के रुप में मान्यता दी गयी थी। भारत–नेपाल सीमा

अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण है तथा भारतीय व नेपाली नागरिकों को एक दूसरे देशों में प्रवेश हेतु बीजा अथवा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। भारत का सशस्त्र सीमा बल (SSB) व नेपाल का सशस्त्र पुलिस (APF) स्थानीय पुलिस के सहयोग से इस पर नियन्त्रण व सुरक्षा उत्तरदायित्व निभाते हैं। यद्यपि सम्पूर्ण सीमा रेखा का अधिकांशतः निर्धारण कर लिया गया है तथापि कालापानी (400 वर्ग किमी0) व सुस्ता (140 वर्ग किमी0) क्षेत्र में अभी भी विवाद है। नेपाल–चीन सीमा पर मानसरोवर क्षेत्र में स्थित कालापानी सर्वाधिक संवेदनशील सामरिक स्थल है जहाँ भारत की सुरक्षा पोस्ट स्थापित है। चीन की उत्प्रेरणा से नेपाल द्वारा जारी नवीन मानचित्र में इसे अपना भू–क्षेत्र बताने से इस क्षेत्र में भारत–नेपाल के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया है जबकि विगत कई दशकों से भारत व चीन लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार कर रहे हैं। भारत द्वारा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धारचूला–लिपुलेख मार्ग के निर्माण के बाद नेपाल की मनोवृत्ति आक्रामक हो गयी है जबकि यह मार्ग पिथौरागढ़–तवाघाट–घटीअबागढ़ का ही विस्तार है तथा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु इसको निर्मित किया गया है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने भी स्पष्ट किया है कि नेपाल ने चीन के इशारे पर ही आपत्ति दर्ज की है जो पूर्णतः निराधार है।

जैसा कि हम भारत–नेपाल सम्बन्धों से संदर्भित अध्याय में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत–नेपाल खुली सीमा स्थित 'नो मैन्स लैण्ड' पर अतिक्रमण बढ़ रहा है तथा आये दिन दोनों देशों के मध्य तनाव व संघर्ष की स्थिति बन जाती है। जून 2020 में बिहार के सीमामढ़ी क्षेत्र में सटी भारत–नेपाल सीमा पर हुई फायरिंग से स्थिति तनावपूर्ण हो गयी किन्तु ये घटनाएं ऐसे समय पर हो रही हैं जब भारत–चीन के मध्य लद्दाख में गम्भीर संघर्ष व विवाद चल रहा है। यह तो सर्वविदित है कि नेपाल में वह सामर्थ्य नहीं है कि वह भारतीय सीमा पर कोई आक्रामक रुख अपनाए किन्तु नेपाल में बढ़ता चीन का राजनैतिक, आर्थिक व रणनीतिक प्रभाव एवं भारत–नेपाल सीमा पर उसकी भारत–विरोधी गतिविधियॉ भावी अनिष्ट का संकेत है क्योंकि एशिया में भारत की रणनीतिक घेरेबन्दी सम्बन्धी महान स्त्रातेजी के अन्तर्गत उसका

बी0आर0आई0 सदस्य नेपाल एक उपकरण की भूमिका के रुप में इस्तेमाल हो रहा है। अतएव, भारत को समय रहते नेपाल के साथ सीमा व अन्य विवादों को कूटनीतिक कौशल द्वारा हल करने का प्रयत्न गम्भीरता से करना चाहिए। इतना ही नहीं, मेरा यह स्पष्ट अभिमत है कि द्विपक्षीय सामंजस्य से सम्पूर्ण सीमा पर कंटीले तार लगाने के साथ–साथ मुक्त–आवागमन हेतु कोई न कोई राष्ट्रीय दस्तावेज व पहचान पत्र को अनिवार्य रुप से लागू करना चाहिए। 'नो मैन्स लैण्ड' पर हो रहे अतिक्रमण को दोनों देशों को मिलकर खाली कराते हुए यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियन्त्रण हेतु सार्थक व प्रभावी प्रयत्न करना ही चाहिए।

3. एशिया के बदल रहे भू–राजनीतिक परिदृश्य में भारत के उत्तरी सीमान्त की सुरक्षा में नेपाल की विशिष्ट भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारत को नेपाल की विश्वसनीयता पर बहुत अधिक आशंकित न होकर बड़े भाई (Elder Brother not big brother) की भूमिका हेतु प्रयत्नशील होना होगा क्योंकि पारस्परिक व्यापार व विकास हेतु इस क्षेत्र में शान्ति, समृद्धि व स्थिरता के परिवेश के सृजन की जिम्मेदारी नेपाल की तुलना में भारत पर अधिक है। अतएवं, ऊर्जा, सड़क, सिंचाई, सामुदायिक विकास, पर्यटन व व्यापार आदि क्षेत्रों में नेपाल को सक्रिय सहयोग करते हुए वहाँ विस्तृत हो रहे चीनी–प्रभुत्व को संतुलित करने हेतु दीर्घकालिक योजनाएं बनाने, आर्थिक–सहयोग करने एवं निर्धारित समयावधि में परियोजनाओं को मूर्त रुप देने की गम्भीर कोशिश करनी चाहिए।

4. नेपाल के विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं के प्राविस्तार हेतु भारत द्वारा संचालित परियोजनाओं में आर्थिक सहयोग एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों में प्रमुख तत्व है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात बाजार व आयात का सबसे बड़ा स्रोत है किन्तु निर्यात क्षमता में कमी के कारण नेपाल तेजी से बढ़ते व्यापार घाटे की समस्या का सामना कर रहा है। नेपाल निर्मित वस्तुओं की गुणवक्ता में कमी, मूल्य, आपूर्ति–क्षमता एवं उत्पादन अयोग्यता जैसे विभिन्न कारणों से नेपाल भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में अकुशल तो है ही साथ ही द्विपक्षीय व्यापार में अनावश्यक दस्तावेज सम्बन्धी

बाधाएं, कस्टम कार्यालयों में व्याप्त प्रशासनिक बाधाएं, अतिरिक्त शुल्क व सामानों के असमान वितरण जैसी समस्याएं भी व्यापार घाटे को बढ़ाने में मुख्य कारक बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त भारत–नेपाल सीमा पर अधिकृत पारगमन मार्गों के अतिरिक्त तमाम ऐसे कई अदृश्य मार्ग भी हैं जहाँ से वस्तुओं की होने वाली तस्करी अथवा अनौपचारिक व्यापार के कारण भी यह घाटा बढ़ता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत व नेपाल के मध्य व्यापार घाटा 47,69,50,000 अमेरिकी डालर था जो कुल घाटे का लगभग 60 प्रतिशत है। इस व्यापार घाटे को चरणबद्ध ढ़ंग से कम करने हेतु निर्माण व आपूर्ति क्षमता बढ़ाते हुए नेपाल को जहॉ एक ओर प्राकृतिक संसाधनों व खनिज की खोज को त्वरित करना आवश्यक है वहीं विद्युत उत्पादन को बढ़ाते हुए इसकी निर्यात क्षमता में भी गम्भीर कदम उठाना होगा। इसके लिए नेपाल को अपनी औद्योगिक संरचना में पर्याप्त सुधार करना होगा। इतना ही नहीं, बांग्ला देश के साथ ऊर्जा व जल संसाधनों के प्रबन्धन द्वारा नेपाल अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है जिसके लिए उसे उत्तम घरेलू उत्पादन–प्रबन्धन के साथ–साथ सुदृढ़ आर्थिक–कूटनीति का संचालन आवश्यक है। नेपाल को यह कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि चीन की तुलना में भारत उसकी आर्थिक समृद्धि में अत्यन्त उपयोगी है क्योंकि उसका अधिकांश व्यापार भारत से होकर ही सम्पन्न होता है। अतएव, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति व समृद्धि हेतु भारत के साथ आदर्श सम्बन्ध स्थापित कर प्रभावी नीति–नियोजन ही उसके लिए अनुकूल होगा जबकि चीन की संलिप्तता उसे ऋण–जाल में फंसाकर हर सम्भव दोहन कर उसकी सम्प्रभुता को छिन्न–भिन्न कर देगी।

5. नेपाल की तराई में बसे मधेशी समुदाय को नेपाल के संविधान में सम्मानजनक अधिकार न मिलने से यह क्षेत्र न केवल अशान्त है अपितु आन्दोलनरत भी है। नेपाल में भारत की सीमा से सटे इस इलाके में व्याप्त उथल–पुथल और भारतीय विरोधी शक्तियों की सक्रियता भारत की सुरक्षा हेतु चिन्ताजनक है। मधेशी आन्दोलन की पृष्ठभूमि में सन 2015 में भारत द्वारा की गयी आर्थिक नाकेबन्दी के फलस्वरुप उत्पन्न आर्थिक संकट का अनुभव होने के बावजूद नेपाल ने कोई सार्थक प्रयत्न न कर चीन से ईधन आपूर्ति हेतु

समझौता तो अवश्य किया किन्तु भौगोलिक–दुरुहता के कारण वह नेपाल की कोई तत्कालिक सहायता नहीं कर सका। नेपाल को यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत–विरोधी उसकी भावनाएं सुरक्षा, स्थिरता व विकास हेतु कदापि शुभ नहीं होगी। अतएवं, नेपाल व भारत को सौहादपूर्ण वातावरण निर्मितकर मधेशी समस्या के समाधान हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए तथा यह स्वीकार करना चाहिए चीन कभी भी नेपाल के सन्दर्भ भारत की भाँति उपयोगी नहीं हो सकता।

6. चीन के मोहजाल से ग्रस्त व भारत–विरोधी विभ्रमकारी रणनीति से नेपाल को बचकर संतुलित विदेशनीति का संचालन करते हुए अपनी भू–सामरिक स्थिति, भारत पर उसकी निर्भरता एवं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सम्बन्धों के प्रगााढ़ अतीत व वर्तमान को कदापि विस्मृत नहीं करना चाहिए। यद्यपि भारत–नेपाल सम्बन्धो से सम्बन्धित अध्याय में इसपर विस्तृत विवेचन किया जा चुका है तथपि विभिन्न अवसरों पर भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमन्त्री व सचिव आदि नेपाल के प्रति भारत की मैत्री व उदार भावना को प्रकट करते रहे हैं। पं0 नेहरु के निम्नांकित उद्गार इसकी पुष्टि करते हैं–

" These relations are too deep-rooted and when the roots go deep, any happy event in our country has its effects on you and if you progress we feel elated . If we are faced with a danger, it effects you also. If you are confronted with a threat, it effects us, and in a way, becomes our danger, just as our danger would becomes yours.[10]"

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पी0वी0नरसिम्हाराव का कथन भी उक्त सन्दर्भ में उद्धरणीय है–

" Our relationship goes beyond politics, beyond governments, beyond borders. It was brought into being by shared aspirations of our two peoples. It is not by accident that the hundreds of miles of border between India and Nepal today are completely open to the flow of men, of goods, of ideas."[11]

महान राजनेता व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निम्नांकित कथन भी भारत–नेपाल सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में उद्धरणीय है–

" Ther is no other country in the entire gamut of our international relationship with which India has such ancient and deeply interwined relations as with Nepal. Indeed, there are probably no two countries in the world whose destinies are so interlinked as ours."[12]

स्पष्ट है कि भारत की विदेशनीति में प्राप्त नेपाल का महत्व यह पुष्ट करता है कि हिमालयांचल में दोनों देशों के मध्य स्थापित मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का मापदण्ड कितना महत्वपूर्ण है किन्तु नवीन वैश्विक व क्षेत्रीय भू–राजनीतिक संरचना, चीन के शान्तिपूर्ण अभ्युदय तथा उसकी विस्तावादी नीतियों के अन्तर्गत की जा रही भारत की सामरिक घेरेबन्दी से भारत–नेपाल सम्बन्धों में अविश्वास का जो वातावरण उत्पन्न हुआ है वह दोनों पड़ोसियों हेतु कदापि शुभ नहीं है। नेपाल को यथार्थवादी चिन्तन के आधार पर भारत से अपने सम्बन्धों पर पुनर्विचार कर हित–केन्द्रित विदेशनीति के संचालन में एक परिपक्व राष्ट्र के रुप में आचरण करना चाहिए।

चीन का भारत–विरोधी दुष्चक्र –

भारत के विरुद्ध निर्मित चीन–नेपाल–पाकिस्तान धुरी वर्तमान समय में भारतीय सुरक्षा व अखण्डता के समक्ष एक गम्भीर चुनौती है। पूर्व स्थापित चीन–पाक धुरी में नेपाल की सक्रिय सहभागिता तथा उसकी भूमि से संचालित भारत–विरोधी गतिविधियों से जहाँ एक ओर भारत उनके प्रतिरोध हेतु सतर्क है वहीं नेपाल अपनी अदूरदृष्टि व भारत–विरोधी भावनाओं से निरर्थक व्यथित होकर जिन घिनौने कृत्यों में संलग्न है वह उसकी राष्ट्र–राज्य स्थिति के लिए कदापि शुभ नहीं है। जहॉ तक भारत–पाक सम्बन्धों का प्रश्न है, अपनी लघु राष्ट्र मानसिकता, दिशाहीन विदेश नीति, नाभिकीय शस्त्रों से उत्प्रेरित उग्र मानसिकता, आर्थिक संकट व आतंक को नीति संचालन हेतु एक साधन के रुप में इस्तेमाल द्वारा भारत के विरुद्ध शाश्वत शत्रुता के परिणामों को देख भी चुका है। ध्यातव्य है कि कश्मीर–व्यामोह से ग्रस्त पाकिस्तान की सैन्य व शासन व्यवस्था चीन का भय उत्पन्न कर भारत को पराजित व विखण्डित करने की दिशा में जितना ही चीन के निकट जायेगी उतनी ही उसे उसकी कीमत भी

चुकानी पड़ेगी। पाक–अधिकृत कश्मीर में चीन की संलिप्तता व बी0आर0आई0 परियोजना के चीनी निहितार्थों का सही आंकलन न कर पाने के परिणाम उसे भविष्य में भुगतने ही होंगें। सच तो यह है कि भारत का विरोध करते हुए वह ऐसी संस्थिति में पहुँच चुका है जहाँ से उसका वापस लौटना अत्यन्त दुरुह है। भारत के साथ कश्मीर–केन्द्रित युद्धों में प्राप्त चीनी सहयोग व उनके परिणामों तथा कारगिल युद्ध में चीन की तटस्थता[13] से न केवल उसे शिक्षा लेनी चाहिए अपितु यह सदैव याद रखना चाहिए कि भारत,चीन व पाकिस्तान तीनों ही नाभिकीय शस्त्रों से सम्पन्न हैं। इतना ही नहीं, चीनी प्रोत्साहन के कारण भारत के साथ उलझने के बजाय पाकिस्तान को यह हृदयंगम करना चाहिए कि नवीन वैश्विक भू–राजनीतिक परिवेश में उसे विकास व सुरक्षा केन्द्रित नीति अपनाते हुए अपनी सम्प्रभुता व अखण्डता की चिन्ता व राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु आर्थिक व कूटनीतिक कौशल के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए न कि टकराव का। वैचारिक–द्रिग्भ्रम, आन्तरिक उथल–पुथल, राजनैतिक–अस्थिरता, नितान्त जर्जर होती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एवं राजनीति के धार्मिक आयाम आदि को देखते हुए प्रसिद्ध पत्रकार नज्म सेठी द्वारा पाकिस्तान को राष्ट्र–राज्य (Nation- State) के स्थान पर राज्य–राष्ट्र (State- Nation) की संज्ञा देने के निहितार्थों को उसे समझना चाहिए।

विशाल अर्थ व सैन्य तन्त्र के अहंकार व दुष्प्रेरणा से निरन्तर बढ़ रही चीन की आक्रमक व विस्तारवादी विदेशनीति से एशिया सहित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समक्ष चुनौतियॉ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका को स्थानापन्न कर विश्व की महानतम शक्ति बनने सम्बन्धी उसकी निरंकुशतापूर्ण नीतियों व व्यवहार से यद्यपि विश्व के अधिकांश देश व्यथित है तथापि दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसका अमर्यादित व अविधिक आचरण, भारत के साथ सीमा विवाद में बल प्रयोग एवं वी0आर0आई0 द्वारा विश्व बाजार पर नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयत्न उसके आर्थिक–साम्राज्यवाद की आक्रामक मनोवृत्ति की पुष्टि करते हैं। विश्व के इस नितान्त अविश्वसनीय व धोखेबाज देश द्वारा भारत के साथ सीमा समस्या समाधान में वार्ताओं का स्वांग करने के साथ–साथ जून 2020 में लद्‌दाख के पूर्वी क्षेत्र में गलवान की घाटी में जो हिंसक कृत्य किया गया

उससे उसकी रही–सही विश्वसनीयता भी समाप्त हो गयी है। भारत के साथ उत्तरी, मध्य व अरुणाचल क्षेत्र मे की जा रही सीमातिक्रमण गतिविधियों में नेपाल व पाकिस्तान को एक प्यादे के रुप में इस्तेमाल करने से यह भी पुष्ट हो गया कि सन 1988 से 2020 तक दोनों के मध्य सीमा मुद्दे पर जो भी वार्ताएं हुई वे मात्र दिखावा थीं। चीन की प्रादेशिक भूंख द्वितीय महायुद्ध काल में नाजी–नीति से प्रेरित प्रतीत होती है जबकि उसे द्वितीय महायुद्ध के परिणामों पर अपने थिंक टैंक के माध्यम से कुछ तो सार्थक विचार–विमर्श करना ही चाहिए। उल्लेखनीय है कि 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों ने सीमा–विवाद के बावजूद अपने आर्थिक–सीमान्त को विस्तृत करने हेतु एक नये सामरिक–आर्थिक समीकरण की दिशा में कदम अवश्य उठाये जिसके फलस्वरुप भारत व चीन के मध्य ब्रहमपुत्र नदी से सम्बन्धित जल विवाद, दलाई लामा प्रकरण जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य–सुरक्षा जैसे प्रकरणों के अतिरिक्त 'ब्रिक्स संगठन' व 'शंघाई संगठन के माध्यम' से इन दोनों देशों के मध्य उत्पन्न तथाकथित विश्वास का ही परिणाम था कि 'चिन्डिया' (Chindia) जैसी सम्भावनाओं को ऊर्जा मिलने के साथ–साथ इसे "A Millenium of Exceptional Synergy" [14]का नाम तक दिया गया। सितम्बर 2014 में चीन के राष्ट्रपति सी0जिनपिंग ने आई0सी0डब्लू0ए0 में दिये गये भाषण के अन्तर्गत कहा था कि–

" One who wishes to be successful seeks to help others to be successful, one who wishes to be understood, understands others"[15]

उधर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ब्राजील में सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के सन्दर्भ में यह कहने कि " China and India are like two bodies with one spirit" से यह प्रतिध्वनित होने लगा कि सीमा सम्बन्धी विवादों को किनारे रखकर दोनों ही देशों ने नवीन भू–राजनीतिक स्वरुप के बदल रहे आयामों की वास्तविकता को देखते हुए अन्य क्षेत्रों में समृद्ध सम्बन्धों के विस्तार का जो निर्णय लिया है वे न केवल ऐतिहासिक हैं अपितु बहुध्रुवीय विश्व–व्यवस्था का पथ प्रशस्त करेंगे तथापि अमेरिका की एशियाई नीति के भावी परिणामों से सर्तक चीन ने एशिया के गुरुत्व–केन्द्र की उपादेयता को न

केवल मैकाइण्डर द्वारा 'प्रतिपादित' 'हदय क्षेत्र सिद्धान्त' की कसौटी पर जॉचा–परखा अपितु उसने ए0टी0महान के सामुद्रिक शक्ति–सिद्धान्तों' का वैज्ञानिक विश्लेषण करके भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का सुविचारित स्वांग रचा तथा 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' व 'वी0आर0आई0' के संजाल को सुदृढ़ करने की सतत कोशिश की। आर्थिक–सम्बन्धों को केन्द्र में रखकर चीन ने भारत के साथ ए0आई0आई0वी0, आर0आई0सी0, ब्रिक्स डेबलपमेण्ट बैंक व जी–20 विमर्श में शामिल होने को प्राथमिकता तो अवश्य दी किन्तु उसी के सामान्तर, एन0एस0जी0, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता एवं आतंकवाद पर दोहरे आचरण व भारत का विरोध करने में उसने जरा सा भी संकोच नहीं किया। इतना ही नहीं, सार्क संगठन के विस्तार की कोशिशें एवं एशिया–पेसिफिक इकोनोमिक फोरम (APEC) के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि हेतु भारत व चीन के मध्य निर्मित सहमति भी यह पुष्ट करती है कि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ने चीन के प्रति भारत की पूर्व नीतियों से हटकर सम्बन्धों की सुदृढ़ता हेतु गम्भीर प्रयत्न किये। चीन द्वारा भारत के प्रति प्रदर्शित सहयोग सम्बन्धी नये दृष्टिकोण के प्रति सितम्बर 2015 में जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान दिया गया मोदी का निम्नांकित वक्तव्य उक्त संदर्भ में सर्वथा उद्धरणीय है– " This is a historic opportunity for the relationship between India and China, filled with vast possibilities. We can start a new era in our relation. If we are sensitive to our opportunities and challenge then I am confident that we will fulfill our resposibilities to make it a great success."[16]

मोदी ने द्विपक्षीय सम्बन्धों को प्रगाढ़ता प्रदान करने हेतु न केवल बौद्धवाद (Buddism) का सहारा लिया अपितु प्राचीन सभ्यताओं की समृद्ध पृष्ठभूमि की याद दिलाते हुए यह भी प्रकट कर दिया कि पर्यटन व सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाकर दोनों देशों के नागरिकों के मध्य उत्पन्न सद्भावनाओं से भारत–चीन सम्बन्धों में पुर्नसंतुलन स्थापित किया जा सकता है।[17] विगत छः वर्षों में मोदी व सी0 जिनपिंग, ब्रिक्स, एस0सी0ओ0 सहित कई मंचों पर 18 बार मिल चुके हैं किन्तु भारत के साथ आर्थिक सम्बन्धों पर केन्द्रित चीन

सीमा–विवाद पर निर्णायक वार्ताओं हेतु कदापि तैयार नहीं हुआ। जहॉ तक चीन के साथ आर्थिक सम्बन्धों का प्रश्न है, व्यापार से जुड़ी दूरगामी नीति के अभाव, मैन्यूफैक्चरिंग के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी, टैरिफ पालिसी का एफ0डी0आई0लिंक न होना, लाल फीताशाही का प्रभाव, करेन्सी में मजबूती व सामरिक स्थिरता कायम रखने पर व्यावहरिक स्तर पर भारतीय शिथिलता जैसे कारणों से निर्यात–आयात का संतुलन चीन के पक्ष में होता गया। इस समय चीन से भारत का कुल आयात 65.01 अरब आयात डालर है। भारत व चीन के मध्य लगभग 49 विलियन डालर का घाटा एवं भारतीय बाजार पर स्थापित चीनी नियन्त्रण सर्वाधिक चिन्ता का विषय हैं। भारत के कुल आयात का लगभग 13 प्रतिशत अंश चीन से आ रहा है जबकि हम चीन को मात्र 5 प्रतिशत ही निर्यात करते हैं। द्विपक्षीय मधुर सम्बन्धों की स्थापना सम्बन्धी विविध प्रयत्नों के बावजूद विशाल अर्थव्यवस्था एवं अत्याधुनिक हथियारों के दर्प में उन्मत्त चीन द्वारा पहले अरुणाचल, डोकलाम व अब गलवान घाटी क्षेत्र में किया गया भारत के विरुद्ध हिंसात्मक कृत्य यह सिद्ध करता है कि भारत के साथ आर्थिक सहयोग–वृद्धि के बावजूद सामरिक दबाव डालने में वह कोई संकोच नहीं करेगा। सीमा विवाद को ऐतिहासिक धरोहर (Historical Legacy) मानने वाले चीन से भारत को किसी प्रकार की सहृदयता की अपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मूलतः ''समस्त युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं'' की रणनीतिक का पोषक है।

भारत–चीन सम्बन्धों की भावी संस्थिति एवं भारतीय स्त्रातेजी–

एशिया में सामरिक–आर्थिक दृष्टि से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रुप में भारत का अभ्युदय एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल व अन्य पश्चिमी देशों के साथ निरन्तर सुदृढ़ होते उसके रिश्ते शीतयुद्धोत्तरकाल का ऐसा पक्ष है जिससे चिन्तित चीन ने भारत–विरोधी राणनीतिक कुचक्र को न केवल विस्तृत किया अपितु भारत को अपना एशियाई प्रतिस्पर्धी व अमेरिकी उपकरण मानकर उसे स्थल एवं समुद्र क्षेत्र में घेरने हेतु भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसियों को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फलतः, अपने रणनीतिक परिवेश एवं इस पर निरन्तर बढ़ रहे चीन के

सामरिक–आर्थिक दबाव के परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर भारत ने अपने रक्षा व आर्थिक विकास को प्राथमिकता देकर सभी पड़ोसियों के साथ मैत्री सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का हर सम्भव प्रयत्न किया वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा व विकास की सुदृढ़ता में वैश्विक शक्ति–संतुलन के विविध पक्षों का आंकलन करते हुए गुटनिरपेक्षता नीति से हटकर बड़ी शक्तियों के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को अपनी विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही कारण है कि सन् 1947–1999 कालावधि में जहाँ एक ओर मात्र तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों (डी0 आइजनहावर, रिचर्ड निक्सन व जिमी कार्टर) ने भारत की यात्रा की वहीं इसके बाद सम्पन्न बिल क्लिण्टन, जार्ज डब्लू ब्रुश, वराक ओबामा व डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्राएं यह पुष्ट करती हैं कि अमेरिकी दृष्टि में न केवल भारत का प्रभाव व पुरूषार्थ बढ़ा है अपितु वह अब वैश्विक मामलों में सहभागिता हेतु तत्पर सचेष्ट है। भारत व अमेरिका के मध्य निरन्तर विस्तृत व समृद्ध हो रहा स्त्रातेजिक सम्बन्ध यह पुष्ट करता है कि जापान, रूस, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व यूरोपीय समुदाय के विभिन्न देश भारत की सामर्थ्य व वैश्विक भूमिका को अब स्वीकार कर रहें है। बड़े राष्ट्रों के साथ भारत की आर्थिक–सामरिक निकटता, हिन्द महासागर व एशिया–प्रशान्त क्षेत्र में बढ़ रही सक्रियता एवं ''एक्ट ईस्ट पॉलिसी'' संचालन में उसकी गम्भीरता के कारण चीन भारत को एशिया विशेषकर द0एशिया तक ही परिसीमित करने हेतु संघर्षरत है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण–चीन सागर में चीन की संघर्षपूर्ण गैरकानूनी आक्रामक रणनीति, बी0आर0आई0 द्वारा आर्थिक–साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन, सामुद्रिक शक्ति के विस्तार, अपने एशियाई पड़ोसियों के प्रति अनावश्यक दुर्भाव एवं भारतीय सीमाओं पर पाकिस्तान–नेपाल गठजोड़ तथा अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध सहित अनेकों ऐसे कारण हैं जिसने एशिया को संवेदनशील बनाने के साथ–साथ नवीन शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। एशिया–केन्द्रित 'अमेरिकी पुनसंर्तुलन सुरक्षा स्त्रातेजी' (US Security Strategy of Asian Rebalance) में भारत की सक्रिय सहभागिता एवं वियतनाम, जापान, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया ब्रुनई एवं भारत के साथ अमेरिका द्वारा की जा रही सन्धियों, समझौतों व सैन्य सहयोग से चिन्तित चीन ने उक्त देशों को

धमकी व दबाव द्वारा डराने की कोशिशें करने के साथ–साथ भारत के विरूद्ध गम्भीर आक्रामक कदम उठाये हैं। पाकिस्तान जैसे अपने 'सदाबहार मित्र'' व नेपाल के माध्यम से वह अब भारतीय सीमाओं पर युद्धोन्माद उत्पन्न करने पर केन्द्रित तो है ही साथ ही धारा–370 की समाप्ति के बाद कश्मीर के परिवर्तित भू–राजनीतिक परिदृश्य से चिन्तित चीन ने भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद को हिंसात्मक स्वरूप प्रदान करने में जरा सा भी संकोच नही किया। सन् 1993 व 1996 में वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) पर शान्ति बनाये रखने हेतु भारत के साथ सम्पन्न समझौते का बार–बार उल्लंघन करना चीन की स्थाई प्रवृत्ति बनती जा रही है। चुमार, दमचोक व डोकलाम संघर्ष तथा गलवान घाटी में भारत के साथ हिंसक मुठभेड़ से इसकी पुष्टि होती है। भारत द्वारा ताइवान व तिब्बत को चीन का भू–क्षेत्र स्वीकारने के बावजूद न तो उसने सीमा प्रश्न पर गम्भीरता दिखाई और न ही उसकी भारत–केन्द्रित अरूणाचल–रणनीति में ही सकारात्मक प्रवृत्ति का ही कोई लक्षण प्रतीत हो रहा है।[18] अरूणाचल के निवासियों को बीजा न देना तथा भारतीय नेताओं व दलाईलामा को तवांग यात्रा न करने देने की चीनी गतिविधियाँ यह समझने के लिए पर्याप्त हैं कि वह इस क्षेत्र को भारत का अंग न मानते हुए अरूणाचल को अपनी सम्प्रभु–भूमि का दर्जा दे रहा है।[19] इतना ही नहीं, चीन द्वारा म्यांमार से संलग्न मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने तथा भारत के साथ इसी सीमा को अस्वीकार करने सम्बन्धी उसके स्वांग से उसकी कुटिलता स्पष्ट होती है।[20]

दक्षिण–चीन सागर क्षेत्र में चीन के विरूद्ध अमेरिका की सक्रियता एवं जापान के साथ उसके रक्षा–समझौते से निर्मित धुरी चीन के लिए गम्भीर चुनौती है। पूर्वी व द0पू0 एशिया में विशाल व्यापारिक सम्भावनाओं के कारण नाभिकीय सम्पन्न देशों (चीन, उ0कोरिया व भारत) के मध्य बढ़ता तनाव यह सि़द्ध करता है कि भारत के व्यापार को शिथिल कर चीन उसे 'एशियान' क्षेत्र से पृथक रखना चाहता है। एशिया में चीनी प्रधानता को शिथिल करने हेतु भारत–अमेरिकी सहयोग एवं भारत के वैश्विक उभार के संदर्भ में यह कहना नितान्त प्रासंगिक प्रतीत होता है–

"In a multipolar Asia, India is also keen to build bilateral relationship with the countries of Indian ocean, Northeast Asia, Central Asia, ASEAN, the Pacific Island and Africa. India's role as a net security provider and its willingness to shoulder great global responsibilities have also been demonstraded through its disaster relief and evacuation operations in Nepal, Yemen and Sudan, peacekeeping and maritime safety operations and participation in important global negotiations."[21]

'सुप्रसिद्ध रणनीतिक चिन्तक मोहन मलिक का कथन है कि एशिया–प्रशान्त क्षेत्र एवं अपने दक्षिणी–पश्चिमी व पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीन की हठधर्मी आक्रामक नीति के पीछे उसके उत्तरी सीमान्त क्षेत्र में दृढ़ सुरक्षा–निश्चिन्तता व भयमुक्त परिवेश मूल रुप से उत्तरदायी है जबकि कुछ विचारक चीन के आक्रामक मनोवृत्ति की पृष्ठभूमि में जापान व भारत के राष्ट्रवाद एवं अमेरिकी–अविश्वास को प्रमुख कारण मानते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि 21वीं सदी में चीन के सामरिक–आर्थिक विस्तार के पीछे अमेरिका, रूस व जापान जैसी शक्तियों द्वारा उसके प्रति प्रदर्शित उदार भावना व तटस्थता जैसे कारक उत्तरदायी अवश्य रहे हैं। वस्तुतः, चीन सही अर्थो में भारत के सामरिक–आर्थिक सामर्थ्य में हो रहे विस्तार, पूर्वी एशिया व द0पू0 एशिया में सक्रियता एवं अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया के साथ प्रगाढ़ रूप ले रही रणनीतिक व आर्थिक साझेदारी से भयभीत लगता हैं क्योंकि यह संयुक्त मोर्चा उसके वैश्विक हितों के विस्तााार पर अंकुश लगाने की क्षमता रखता है। एशिया–पेसिफिक इकोनोमिक कोआपरेशन फोरम (APEC), ट्रान्स–पेसिफिक पार्टनरशिप (TPP), एशियान देशों का रीजनल क्राम्प्रेहेन्सिव इकोनामिक पार्टनरशिप (RCEP), यूस–जापान–साउथ कोरिया स्ट्रेटजिक कोआपरेशन आदि ऐसे फोरम हैं जो अमेरिकी सहयोग से पूर्वी व द0पू0 एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम पर प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं। इनके प्रत्युत्तर में ही ए0आई0आई0बी0 (AIIB), पी0सी0ई0 एवं नौ–सैन्य आधुनिकीकरण सम्बन्धी चीनी परियोजनाएं भारत के प्रति संघर्ष, अविश्वास व हित–संघर्ष को प्रेरित कर रही हैं। सच कहा जाय तो एशिया–प्रशान्त क्षेत्र पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर

विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु सन्नद्ध चीन उक्त गतिविधियों से पर्याप्त क्षुब्ध है। परिणामस्वरूप, वैश्विक राजनीति में हो रहे घात–प्रतिघातों से चिन्तित चीन ने जहाँ एक ओर रूस व यूरेशियन इकोनोमिक यूनियन (EEU) के देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना का प्रयत्न करते हुए अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश प्रारम्भ की है वहीं अमेरिका ने भारत सहित अपने सभी परम्परागत मित्र देशों के साथ मैत्री, सहयोग व गठबन्धन बनाते हुए चीन की हठधर्मिता को रोकने हेतु गम्भीर प्रयास प्रारम्भ किये है। एशिया में चीन–अमेरिकी स्पर्धा शनैः शनैः नया स्वरूप ग्रहण कर रही है किन्तु चीन की वैश्विक अविश्वनीयता एवं पड़ोसी देशों के साथ अनावश्यक टकराव उसकी भावी नीतियों में अवरोधक सिद्ध हो सकते हैं। फिर भी सभी देशों को यह ध्यान रखना चाहिए कि संघर्ष के बजाय सहयोग की नीति ही (Cooperation is better than conflict) सदैव सर्वोत्तम शन्तिमूलक होती है।[22]

यद्यपि नेपाल के माध्यम से चीन शनैः शनैः भारतीय सीमाओं तक अपना विस्तार तो अवश्य कर रहा है किन्तु उसके द्वारा नेपाल–भारत के मध्य सदियों से स्थापित सांस्कृतिक व सामाजिक सम्बन्धों में निहित प्रगाढ़ता की ग्रन्थि को शिथिल व दूषित करने की कुचेष्टा अत्यन्त घातक है। पहले लिपुलेख–विवाद तथा अब अयोध्या–प्रकरण पर नेपाल की कूटनीतिक चाल से ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल का ओली शासन पूर्णतः चीनी बन्धक बनता जा रहा है। यही नही, चीनी से लगी भारतीय सीमाओं पर स्थित भूटान जैसे देशों के विरूद्ध उसकी सीमातिक्रमण गतिविधियाँ निश्चय ही अपरोक्ष रूप से भारत पर आक्रमण ही है। अतएव, क्षेत्रीय व वैश्विक भू–राजनैतिक परिदृश्य में अपनी सुदृढ़ सुरक्षा हेतु भारत को निम्नांकित पथ प्रदर्शन पक्षों पर गम्भीरतापूर्वक नीति–निर्धारण आवश्यक है–

1. पूर्वी लद्दाख की गलबान घाटी में चीन की कायरतापूर्ण सैन्य कार्यवाही उसके सामरिक व भू–राजनीतिक उद्देश्यों, भय और उसके रक्षा–सिद्धान्त का ही परिणाम है। चीन की उक्त आक्रामक गतिविधियों की तैयारी सही अर्थो में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में भारतीय सेना की कार्यवाही एवं धारा 370 की समाप्ति के बाद लद्दाख को

केन्द्रशासित क्षेत्र बनाये जाने के बाद ही प्रारम्भ हो गयी थी क्योंकि भारत की सशक्त होती राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य–शक्ति एवं सीमा पर मजबूत, होते इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण चीन को भारतीय दबाव का अनुमान होने लगा। इतना ही नहीं, लद्दाख क्षेत्र में बार–बार होने वाले सीमातिक्रमण को रोकने हेतु भारत द्वारा एक 'आक्रामक माउण्टेन स्ट्राइक कोर' के गठन व 2019 में इस कोर द्वारा सम्पादित 'आपरेशन हिमविजय' से चीन को गम्भीर चिन्ता हुई। उल्लेखनीय है कि सम्भवतः लद्दाख जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में चीन ने नया सैन्य मोर्चा इसलिए खोला कि यदि भारत, पाक–अधिकृत कश्मीर या गिल्गिट–बाल्टिस्तान में पाकिस्तााान के विरूद्ध कोई आक्रामक कदम उठाये तो लद्दाख में उसे उलझाकर ऐसा न करने दिया जाय क्योंकि उसे पाकिस्तान से अधिक चिन्ता सी0पी0ई0सी0 के सुरक्षा की है। इस क्षेत्र में काराकोरम हाईवे की रक्षा करने में भी भारत की तुलना में वह कमजोर हैं क्योंकि 'दौलत बेग ओल्डी' व पूरे सब–नार्थ सेक्टर में भारत रणनीतिक रूप से चीन से श्रेष्ठ स्थिति में है। सियाचिन पर नियन्त्रण व डी.वी.ओ. में भारत की श्रेष्ठ स्थिति के कारण भारत, चीन व पाकिस्तान दोनों की सेनाओं पर भारी पड़ सकता है। चीन यह आभास दिलाने की भी कोशिश हैं कि कोविड–19 के कारण विश्व के ध्रुवीकरण के बावजूद उसकी शक्ति–प्रक्षेपण क्षमता में कोई कमी नहीं आयी है। सम्भवतः, इसीलिए वह अमेरिका, जापान, भारत, व आस्ट्रेलिया आदि के विरूद्ध आक्रामक है। चीन का यह व्यवहार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उस रक्षा व्यवहार के अनुरूप ही है जिसके अनुसार ''प्रतिद्वन्दी देशों के विरूद्ध कार्यवाही तब करनी चाहिए जब वे आपको कमजोर समझते हों।'' इतना ही नहीं, वैश्विक संकटों का लाभ उठाना भी चीनी रणनीति का हिस्सा है। 1950 में कोरिया युद्ध में अमेरिकी सेना से संघर्ष करना तथा 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय भारत पर चीनी आक्रमण से इसे समझा जा सकता है। कोविड–19 काल में चीनी गतिविधियों के वैश्विक आयामों के परिप्रेक्ष्य में भारत के रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने स्पष्ट

कहा है कि ''अब चीन के व्यापारिक वर्चस्व को तोड़ने की आवश्यकता है, इसके लिए चीन छोड़ने वाली कम्पनियों को राहत–रियायत देन की जरूरत है। यदि ऐसा न किया गया तो जोखिम बढ़ता जायेगा। चीनी साम्राज्यवाद की काट के लिए यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली व स्पेन में नये नियम बनाये जा रहे हैं। जापान ने भी चीन से पलायन करने वाली कम्पनियों के लिए 2.2 अरब डालर का कोष बनाया है। चीन के वैश्विक बहिष्कार करते हुए चीन की घेरेबन्दी आवश्यक है।'' अतएव, भारत के लिए नितान्त आवश्यक है कि रणनीतिक तैयारी के साथ–साथ चीन के आर्थिक–जाल को शिथिल करने हेतु वह अपनी आर्थिक–कूटनीति के गम्भीर संचालन व आत्मनिर्भरता हेतु सक्रियतापूर्वक दूरगामी नीति–नियोजन करे।

2. लद्दाख के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश से लगी मैकमोहन सीमा से संलग्न भू–क्षेत्र में भारत ने अपनी सामरिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सामरिक महत्व के सड़कों का निर्माण किया है जिनमें तिनसुखिया जिले में ढोला–सादिया पुल (Dhola-Sadiya Bridge) विशेष रुप से उल्लेखनीय है। इस पुल द्वारा असम व अरुणांचल प्रदेश के मध्य सेना व नागरिकों के आवागमन में सरलता आयी है तथा सीमा पर सेनाओं का पहुँचना अपेक्षाकृत सहज हो गया है। भारत सरकार चीन से संलग्न क्षेत्रों में स्कूल, सड़क, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ सेवाओं का विस्तार कर रही है जिससे नागरिकों में सुरक्षा व राष्ट्रीय भावनाओं को सुदृढ़ किया जा सके। 378 किमी0 लम्बी मिसामारी–टेंगा–तवांग रेलवे परियोजना पर भी भारत सरकार कार्य कर रही है।

3. यदि भारत की रक्षा चुनौतियों का आंकलन किया जाय तो यह स्पष्ट है कि समुद्र की तुलना में भारत के स्थलीय सीमान्तों पर रक्षा चुनौतियाँ अधिक हैं। (Border Pressure is greater on its land frontiers than sea frontiers)[23] अतएव, चीन, नेपाल, बांग्लादेश व पाकिस्तान के साथ पारस्परिक सम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण बनाते हुए सम्बद्ध पक्षों के साथ विचार–विमर्श कर सीमा–प्रबन्धन को सुदृढ़ करने की अत्यन्त

आवश्यकता है। ऐसा होने से न केवल क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि होगी अपितु शन्ति–प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान के साथ खोखरापार–मुनावाओं रेल–सम्पर्क व श्रीनगर–मुजफ्फराबाद सड़क सम्पर्क, म्यांमार के साथ 'कलादान प्रोजेक्ट' एवं भारत–नेपाल व बांग्लादेश के मध्य क्रमशः 'ककरबिट्टा–पानी टंकी–फुलवारी–बांग्लाबन्धा सड़क' व अगरतल्ला–आखुरा–चटगाँव रेल परियोजनाएं निश्चय ही महत्वपूर्ण हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता एवं सीमापारगमन हेतु भारत द्वारा नेपाल को दी जा रही आधुनिक सुविधाएं पड़ोसियों के प्रति भारत की सद्भावना व संकल्प को इंगित करती हैं। पड़ोसी देशों के साथ व्यापार व नागरिकों के सहज, तीव्र व बाधारहित आवागमन हेतु भारत को 'स्मार्ट वार्डर' (Smart Border) के सिद्धान्त पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सीमा–प्रबन्धन, सीमाओं की रक्षा, अपराध व आतंकवाद के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही एवं अन्य उभयपक्षीय चुनौतियों का सम्यक निष्पादन सम्भव हो सके।

4. तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग आदि के अतिरिक्त नेपाल, भूटान व भारत के विरूद्ध चीन की आक्रामक मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए भारत को कूटनीतिक आदर्शवाद से ऊपर उठकर तिब्बत, हांगकांग व ताइवान के मसलों में वास्तविक राजनैतिक सिद्धान्तों (Real Politik) का पालन करना होगा। 'वन चाइना नीति' (One China Policy) के ही आधार पर चीन को एक भारत की नीति (One India's Policy) की नीति हेतु चीन को विवश करते हुए अब भारत को तिब्बत की स्वतन्त्रता व ताइवान को कूटनीतिक मान्यता देकर पारस्परिक सम्बन्धों को विस्तृत करना तथा हांगकांग मुद्दे पर स्पष्ट नीति निर्देशक तथ्यों पर बल देना चाहिए। तिब्बत की स्वाधीनता सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धित 1959–60 व 1965 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के साथ–साथ अमेरिका (बिल नं0 HR-4331) सहित अन्य पश्चिमी देशों की तिब्बत की स्वतन्त्रता सम्बन्धी नीतियों का पक्ष लेना अब भारत के लिए अपरिहार्य है अन्यथा भारत के धर्मशाला में तिब्बत

की निर्वासित सरकार को शरण देने का औचित्य ही क्या है। ध्यातव्य है कि चीन की मनोवृत्ति से यह पुष्ट है कि वर्तमान दलाईलामा की मृत्यु के बाद अगले अवतारी बच्चे का चुनाव कर तिब्बत की धार्मिक मान्यताओं को वह समाप्त करना चाहता है। चीन की इन्हीं चालों का पूर्वानुमान कर दलाईलामा ने 2012 में ही अपने सभी राजनैतिक अधिकार तिब्बत के निर्वाचित सिक्योंग (प्रधानमंत्री) को देकर अपने पद को केवल आध्यात्मिक मामलों तक सीमित करके तिब्बत की निर्वासित सरकार व उसके अधिकारों को अनन्तकालीन विस्तार दे दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत को तिब्बत–दुविधा से मुक्त होकर पंचशील भावनाओं को तिलांजलि देने का अब सही समय आ गया है। यदि सरकार इसमें संकोच करती है तो भारत के विविध सामाजिक व गैर राजनीतिक संगठन तो तिब्बत की स्वतन्त्रता हेतु आवाज तो उठा ही सकते हैं जैसे हांगकांग की स्वायत्तता हेतु विश्व के कई संगठन सक्रिय हैं। तिब्बतियों को अपना शान्तिपूर्ण वैचारिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक अभियान चलाने में हम सहायता तो उसे दे ही सकते हैं क्योंकि उन्हे इससे वंचित रखना हमारी मानवीय व संवैधानिक प्रतिज्ञा के पूर्णतः विरूद्ध है। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों द्वारा तिब्बत के संदर्भ में किये जा रहे कूटनीतिक प्रयत्नों में भारत की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाकर भारत को अब कूटनीतिक–कौशल द्वारा आगे बढ़ने हेतु संकल्पित होना होगा।

5. भारत की सामरिक घेरेबन्दी सम्बन्धी चीनी गतिविधियों का विधिवत विश्लेषण करते हुए अब उसे पंचशील व उदारवाद[24] जैसी आदर्शवादी नीति के व्यामोह से बाहर निकल कर कौटिल्य द्वारा वर्णित सिद्धान्तों के आधार पर चीन से पीड़ित व रूष्ट देशों से मैत्री पहल को सुदृढ़ता प्रदान करनी होगी। वियतनाम के साथ सामरिक, आर्थिक व सैटेलाइट आदि क्षेत्र में बढ़ रहा भारत का सहयोग इसका उदाहरण है। भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी के प्रमुख स्तम्भ के रूप में वियतनाम[25] के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए चीन के विरूद्ध भारत के लिए पाकिस्तान

(India"s Pakistan)[26] की, भूमिका हेतु चीन के विरुद्ध हेतु तैयार करने की गम्भीर कोशिश करनी चाहिए। इसी के समानान्तर एशियान देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को विश्वनीय बनाकर भारत न केवल दक्षिण–चीन सागर में चीनी हितों को अवरूद्ध कर सकता है अपितु उसकी 'मलक्का–निर्भरता' को भी असुरक्षित किया जाना भारतीय नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 'मालाबार अभ्यास' में जापान के सम्मिलित होने तथा दक्षिण चीन सागर को भारत द्वारा 'पश्चिमी फिलीपीन्स सागर' की संज्ञा देने से[27] चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना उक्त संदर्भ में उल्लेखनीय हैं।

6. 2017 में सार्क शिखर सम्मेलन के रद्द होने के बाद गोआ के 'ब्रिक्स–सम्मेलन' में 'बिम्सटेक' के सदस्य देशों के सम्मिलित होने से यह ध्वनित हुआ कि पाकिस्तान व भारत के मध्य व्याप्त गहरे मतभेदों के कारण सार्क की प्रासंगिकता अपेक्षाकृत कम हो गयी है। पूर्वी एशिया के अधिकांश देशों ने विम्सटेक के माध्यम से व्यापार–सम्पर्क, ऊर्जा सहयोग, आतंकवाद व सीमापार अपराध सहित लगभग 14 क्षेत्रों में पारस्परिक सम्बन्धों को विस्तृत करके शान्ति–स्थापना, स्थायित्व व क्षेत्रीय समृद्धि की दिशा में जो पहल की उसमें भारतीय कूटनीति की शीर्ष व विशिष्ट भूमिका है। इस संगठन के दशों की भौगोलिक सन्निकटता, प्राकृतिक व मानव संसाधन की प्रचुरता, समृद्ध ऐतिहासिक सम्पर्क–सूत्र एवं सांस्कृतिक धरोहर आदि ऐसे पक़्ष हैं जो इस संगठन को सार्क की तुलना में नया व प्रभावशाली नूतन परिवेश प्रदान करते हैं। यही कारण है कि सार्क मंच की तुलना में पाकिस्तान–मुक्त इस मंच के माध्यम से जहाँ एक ओर भारत ने भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, जैसे अपने निकटस्थ पड़ोसियों के साथ नवीन सम्बन्धों को सुदृढ़ आधार देने की कोशिश प्रारम्भ की है वहीं अपनी 'एक्ट ईस्ट पालिसी' के सफल संचालन से सम्बद्ध केन्द्रित नीतियों की सफलता हेतु मोदी के शासनकाल में गम्भीर कूटनीति प्रयत्न किये जा रहे हैं। द0पू0 एशियाई व अपने अन्य पड़ोसियों में बढ़ रहे चीन के आर्थिक–रणनीतिक प्रभाव

को शिथिल करने के लक्ष्य से भारत ने ऊर्जा–ग्रिड के विस्तार एवं व्यापार–सम्पर्क को प्राथमिकता देकर इस संगठन के सदस्यों के मध्य अन्तरव्यापार को भी उच्चस्तरीय प्राथमिकता दी है । सन् 2009 में भारत द्वारा 'एशियान' के साथ हस्ताक्षरित 'स्वतन्त्र व्यापार समझौता' (FTA), श्रीलंका के साथ भी 'आर्थिक व तकनीकी सहयोग समझौते' (ETCA) तथा बांग्लादेश व नेपाल के साथ 'द्वपक्षीय निवेश, सुरक्षा व वृद्धि' (BIPA) हेतु एवं इण्डिया–एशियान एफ0टी0ए0 (India-ASEAN FTA) आदि समझौते यह पुष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, निवेश व व्यापार हेतु भारत सतत प्रयत्नशील है। राजनीति से पूर्णतः मुक्त उक्त प्रयत्नों में सभी देशों के हितों, बाजार सुलभता एवं चुंगी आदि मुद्दों पर सहमति से समृद्धि व विकास–केन्द्रित प्रयत्न किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत की 'कलादान परियोजना' (Kaladan Port Project) तथा म्यांमार होते हुए भारत के मोरे (Moreh) व थाईलैण्ड के 'में सॉट' (Mae Sot) तक विस्तृत 1400 किमी लम्बी त्रिभुजीय सड़क परियोजना को कम्बोडिया व वियतनाम तक विस्तृत करने का कार्य भी प्राथमिकता में है। लगभग 6000 करोड़ की लागत से आइजॉल–टुइपांग फोरलेन मार्ग (Aizawl-Tuipang Four-Lane Highway) का कार्य भी प्रगति पर है जिससे सिटवे (Sittwe) व आइजाल के मध्य व्यापार व आवागमन को नया आयाम प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, विम्सटेक देशों के मध्य सम्पर्क–विधाओं को सरल बनाते हुए व्यापारिक गतिविधियों को सुदृढ़ आधार देने हेतु भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में Paletwa-Kaletwa-Zorimpuri सड़कों का निर्माण कर इन्हें म्यांमार तक विस्तृत कर रहा है। विम्सटेक देशों के साथ विमर्श करते हुए भारत ने लगभग 165 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को विकसित करने का निर्णय भी लिया है जिनमें 35 परियोजनाएं सड़क, 12 परियोजनाएं रेलवे तथा 9 वायु अड्डों के विस्तार से सम्बन्धित हैं। शेष परियोजनाएं गहरे जल में बन्दरगाहों से जुड़ी हैं जिनके माध्यम से कलकत्ता (भारत), थिलावा (म्यांमार), चटगाँव

(बांग्लादेश) को जोड़ते हुए इस क्षेत्र में सामुद्रिक व्यापार का नेटवर्क विस्तृत किया जायेगा।[28]

बिम्सटेक देशों के मध्य ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करके व्यापार में तीव्रता लाना भारत का मुख्य ध्येय है। नेपाल व बांग्लादेश के साथ भारत द्वारा ग्रिड कनेक्टीविटी की स्थापना व विस्तार भारत प्राथमिकता के स्तर पर कर रहा है। भूटान की विभिन्न विद्युत परियोजनाएं (Chukha, Kurichu, Dagachu, Basachhu, Tala) भारत के आर्थिक सहयोग से निर्मित हुई हैं जिनसे 1116 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। भारत व नेपाल के मध्य भी विद्युत–उत्पादन में अद्भुत सहयोग है जिसके अन्तर्गत भारत Dhalkebar-Muzaffarpur, Raxaul-Parwanipur व Kataiya-Kushaha परियोजनाओं को भारत आर्थिक सहयोग कर रहा है। नेपाल को विद्युत आपूर्ति करने के साथ–साथ वुटबल–गोरखपुर, डुहाबी–पुर्णिया, लम्की–बरेली व अनारमनी–सिलीगुड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को भी नेपाल के साथ निर्मित करने हेतु भारत प्रयत्नरत है। आतंकवाद व सीमापार अपराधों पर सामूहिक नियन्त्रण हेतु बिम्सटेक देशों के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत ने गम्भीर कदम उठाये हैं। भारत व श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास (Mitra Shakti) नेपाल के साथ 'सूर्य किरण अभ्यास' (Surya Kiran), तथा म्यांमार, थाईलैण्ड व बांग्लादेश के मध्य आतंकवाद, तस्करी व अपराध नियन्त्रण हेतु सहमति तथा 2017 में बिम्सटेक देशों के मध्य आई0डी0एस0ए0 नई दिल्ली में सम्पन्न सुरक्षा–सहयोग सम्बन्धी सम्मेलन उक्त दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। भारत की उक्त नीतियाँ उसके आर्थिक–रणनीति प्रयत्नों की सक्रियता एवं चीन से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों की गम्भीरता को प्रकट करती हैं। इस क्षेत्र में भारत को अपने दीर्घकालीन हितों की रक्षा में 'क्वाड' जैसे संगठन को विस्तृत करते हुए चीन के विरूद्ध एक विस्तृत व प्रभावी तन्त्र विकसित करने की आवश्यकता है।

7. प्रत्यक्षतः, हिन्दमहासागर से जुड़ी भारतीय सुरक्षा को ध्यान रखते हुए भारत अपने सामुद्रिक हितों के रक्षार्थ सदैव सक्रिय रहा है। चीन की 'सामुद्रिक सिल्क मार्ग परियोजना' के निहित भारत–विरोधी उद्देश्यों एवं इस क्षेत्र के परिवर्तित भू–राजनीतिक आयामों को ध्यान में रखते हुए जहाँ एक ओर भारत ने अपने सामुद्रिक व नौ–सैन्य बल को अत्याधुनिक बनाने का प्रयत्न है वही अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया व हिन्दमहासागरीय क्षेत्र के देशों (IORA) के साथ साामरिक–आर्थिक व कूटनीतिक सम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण बनाने की हर सम्भव कोशिशे की हैं। इस संगठन में निम्नांकित देश सम्मिलित हैं–

IORA States:

1. African States- Comoros, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles, Somalia, South Africa, Tanzania,.
2. Non-African States- Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, United Arab Emirates, Oman, Yemen.
3. IORA Dialogue Partners- Japan, Germany, China, United Kingdom, U.S.A, France, Egypt.
4. Potential IORA States- Bahrain, Brunei, Maldives, Myanmar, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan.

बड़ी शक्तियों के साथ सामरिक–आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में उक्त अधिकांश देशों की सहभागिता तो अवश्य है किन्तु भारत भी सक्रियता से द्विपक्षीय सम्पर्को को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयत्नशील है। आतंकवाद, सामुद्रिक डकैती, माद्रक द्रव्यों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध मत्स्य–व्यापार, सामुद्रिक प्रदूषण, सामुंद्रिक संसाधनों का भीषण दोहन व अवैध आव्रजन आदि ऐसे पक्ष हैं जिनमें सहयोगी भावना से प्रेरित होकर भारत अपने सीमान्त को विस्तृत कर सुरक्षा व विकास के वातावरण को समृद्ध कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत को अपने

अण्डमान निकोबार कमान (ANC) को सुविकसित कर उसे चीन द्वारा उत्पन्न की जाने वाली हिन्दमहासागरीय असुरक्षा हेतु प्रभावी–केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहिए।

8. इस्लामिक आतंकवाद के उन्मूलन, सामुद्रिक व साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा–स्वच्छता जैसे तत्वों की पृष्ठभूमि में बढ़ रही

भारत–अमेरिकी निकटता से व्यथित चीन के वैश्विक हितों को परिसीमित करने हेतु एशिया–प्रशान्त क्षेत्र में भारत को अपने व्यापारिक हितों के रक्षार्थ क्षेत्रीय सहयोग को विस्तृत करने की परम आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि चीन–पाक धुरी व आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अमेरिकी विश्वसनीयता व भारत के प्रति उसके इरादों पर शंकालु होना स्वाभाविक तो है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में चीनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने सम्बन्धी अमेरिकी कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में भारत को अपनी स्वतन्त्र व हित–केन्द्रित नीति के परिप्रेक्ष्य में यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी होगी। वैसे राजनीति में कुछ भी असम्भव न होने के मूलभूत सिद्धान्त पर सतर्क रहने तथा समयानुकूल रणनीति का निर्धारण करना सर्वथा उचित होता है क्योंकि राष्ट्रों के मध्य सम्बन्धों में उतार–चढ़ाव परिस्थतिजन्य ही होते हैं। सी0 राजा मोहन के शब्दों में–

"To be more reasonable toward India as China begins to focus on the US military challenge from the east India cannot merely rely on internal balancing to cope with China's rise, rather the US and its Asian allies must be central of any Indian strategy of external balancing."[29]

9. रक्षा–उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु भारत को अमेरिका के साथ सन् 2012 में सम्पन्न डिफेन्स टेक्नोलाजी एण्ड ट्रेड इनीसीएटिव (DTTI) सहमति पर सक्रियता बढ़ानी चाहिए जिससे संयुक्त रूप से हथियार व अन्य उपकरणों का उत्पादन सुनिश्चित हो सके। इस समझौते की पृष्ठभूमि में 2015 में रक्षा–साझेदारी हेतु भारत–अमेरिका के मध्य गैरमानवीय हवाई वाहन (UAVc), C-130J सुपर हरक्युलिस

एअरक्राफ्ट, जैविक व रसायनिक युद्ध में सैनिकों के बचाव हेतु वर्दी निर्माण एवं 'तेजस' को इंजन आपूर्ति पर सहमति बनी। संयुक्त सैन्य अभ्यासों विशेषकर 'युद्ध अभ्यास', 'कोप इण्डिया', मालाबार व 'बज्र प्रहार' तथा अगस्त 2016 में सम्पन्न नौ सैन्य समझौता (LEMOA-Logistics Exchange Memorandum of Agreement) तथा अमेरिका के NDAA (National Defence Authorisation Act-2017) द्वारा भारत को अमेरिकी का 'बड़ा रक्षा साझेदार' (Major Defence Partner) बनने से यह सिद्ध होता है कि अब भारत ने अपने रक्षा–सामर्थ्य को उन्नत करने को प्राथमिकता दी है। अमेरिका के अतिरिक्त रूस, इजराइल व फ्रांस के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग से यह पुष्ट है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के रक्षार्थ अमेरिका व रूस के साथ संतुलन बनाकर दूरदर्शी नीति का परिचय दिया है। भारत को चाहिए कि वह चीन के विस्तारवादी आक्रामक रूख को देखते हुए अमेरिका व रूस के मध्य आदर्श सम्बन्ध बनाते हुए अपने आर्थिक, सामरिक व अन्य हितों की पूर्ति हेतु अपेक्षित नीति का अनुपालन करे।

चीन पर भारत की व्यापारिक निर्भरता एवं विशाल आर्थिक घाटा व असंतुलन भारत के समक्ष गम्भीर चुनौती है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश की तीस में से अठ्ारह यूनीकार्न कम्पनियाँ चीन द्वारा वित्त–पोषित हैं तथा एक अनुमान के अनुसार भारतीय स्टार्टअप्स में चीनी तकनीकी निवेशकों ने लगभाग चार अरब डालर का निवेश किया है। दुर्भाग्य यह है कि चीन के विनिर्माण क्षेत्र को भारत कच्चा माल व सामग्री का निर्यात करता हैं जबकि उससे उच्च मूल्य की निर्मित सामग्री का अधिक आयात, ही मुख्यतः व्याापार–असंतुलन का मूल कारण है। चीन ने उत्पादन और रोजगार वृद्धि के माध्यम से वैश्विक बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है जबकि भारतीय कम्पनियाँ चीन के सस्ते उत्पादों के विकल्प हेतु सक्षम नहीं दिखाई दे रही हैं। भारत के पास आज भी चीन को भारतीय बाजार से हटाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा, तकनीक व वैकल्पिक निवेश की सम्भावनाएं नहीं है। कोविड–19 से उत्पन्न स्वास्थ्य व सुरक्षा क्षेत्र के संकटों ने भारत के समक्ष चीन पर निर्भरता शिथिल करने की सम्भावनाओं को

जन्म तो अवश्य दिया हैं किन्तु इसके लिए घरेलू व निर्यातोन्मुखी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रणनीतिक व व्यवस्थित निवेश हेतु प्रभावी मांग और रोजगार सृजन हेतु तकनीक व बुनियादी ढ़ाँचों की आवश्यकता है। थ्री ई (3E-Electronics, Engineering, Electricals) के बलबूते चीन ने जो अर्थव्यवस्था खड़ी की उससे न केवल चीन आत्मनिर्भर होता गया अपितु भारत की चीनी–निर्भरता भी बढ़ती गयी। आज जहाँ चीन का सकल घरेलू उत्पादन (GDP) 132 अरब अमेरिकी डालर हैं वही भारत की जी0डी0पी0 मात्र 28 अरब डालर ही है। भारत की प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 2500 अमेरिकी डालर है जबकि चीन की उक्त आय 10 हजार डालर है। अर्थव्यवस्था का यह विशाल अन्तर ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, भारत के शीर्ष व्यापारिक देशों अमेरिका, रूस, जापान, आस्ट्रेलिया व ब्रिटेन आदि के साथ व्यापार समझौते भी नहीं हैं। अतएव, भारत को जहाँ एक ओर संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, व विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिलाकर एक नयी विश्व व्यवस्था निर्मित करने की आवश्यकता है वहीं हाइपरसोनिक्स, 5 जी इंटरनेट, जेनटिक्स, आर्टिफिसियल–इन्टेलीजेन्स, व थ्री डी सम्बन्धी तकनीक पर शोध–अनुसंधान को प्राथमिकता देने के साथ–साथ भारत को अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु गम्भीर प्रयत्न करने होंगे। डीग्लोब्लाइजेशन के स्थान पर भारत को मिलकर 'ग्लोबल एलाइन्स' के निर्माण द्वारा भारत–विरोधी चीन की रणनीतिक गतिविधियों एवं उसके विस्तारवादी नीतियों को ध्यान में रखते हेतु भारत द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतिबन्ध लगाना वर्तमान तकनीकी परिवेश में महत्वपूर्ण कदम है। वैसे यह कार्य तो बहुत पहले ही होना चाहिए किन्तु देर से ही सही यह निर्णय सुरक्षा, रणनीति व अन्य कारणों से स्वागतयोग्य है। नई तकनीक व विभिन्न एप्स ऐसे चीनी हथियार हैं जिनके द्वारा बिना गोली फायर किये वह अपने प्रतिद्वन्दी को घुटनों के बल ला सकता है। आस्ट्रेलिया पर हुआ साइबर हमला इसका उदाहरण है। युद्धों में बढ़ रही तकनीक का महत्व यह पुष्ट करता है कि भावी युद्ध तकनीकी मोर्चों पर ही लड़ा जायेगा जिसमें शत्रु के विमानों की उड़ान, शस्त्र व सैन्य–रसद–आपूर्ति व बिजली व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करने में एप्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

यद्यपि भारतीय सेना व अन्य महत्वपूर्ण विभागों में तमाम एप्स प्रतिबन्धित हैं किन्तु उनके मित्रों व स्वजनों के एप्स में सेंधमारी करके शत्रु को पर्याप्त क्षति तो पहुँचाई ही जा सकती है। इन कार्यों में चीन को विशेषता हाँसिल होने के कारण भारत को बहुत ही सावधान रहना तो होगा ही साथ ही चीनी जबाव हेतु उनके विकल्प तैयार कर स्वदेशी उद्यमियों के माध्यम से अनुसंधान–आत्मनिर्भरता की दिशा में गम्भीर प्रयत्न अपेक्षित है। व्यापारिक–नीति में भी भारत को मूलभूत परिवर्तन करना होगा तभी चीन के वर्चस्व को शिथिल किया जा सकता है।

भारत के उत्तरी सीमान्त पर नेपाल व पाकिस्तान के संयुक्त मोर्चे के माध्यम से चीन द्वारा निर्मित युद्ध सदृश स्थिति एवं वैश्विक स्तर पर उसकी विस्तारवादी नीतियों से यह पुष्ट है कि मोदी द्वारा चीन के प्रति प्रदर्शित सदाशयता व उनकी 'इंन्च टुवर्ड माइल्स' (Inch-India and China; Miles-Millennium of Exceptional Synergy) भावनाएं क्षत–विक्षत हो गयी हैं। आश्चर्य व धोखा चीन की मूल संस्कृति है जिसपर अंकुश लगाने हेतु भारत को उसी की भाषा में प्रभावी प्रतिकार हेतु संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। यह न केवल सही सबक सीखने अपितु विदेश नीति में व्यापक परिवर्तन का समय है। यद्यपि आर0आई0सी0 (RIC) मंच से भारत के विदेश मन्त्री एस0 जयशंकर ने दृढ़तापूर्वक यह स्पष्ट कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान, साझेदारों के उचित हितों को मान्यता, बहुपक्षीयता को प्रोत्साहन तथा सभी के लिए समान लाभ का अवसर देकर ही एक विश्वसनीय वैश्विक–संरचना का निर्माण सम्भव है तथापि चीन को उक्त तथ्यों पर न तो विश्वास है और न ही कोई गम्भीर चिन्तन। वैश्विक राजनैतिक की वास्तविकताएं जिस तरह तेजी से बदल रही हैं उसमें भारत को समान सोच वाले व विश्वसनीय देशों के साथ एक बहुपक्षीय ढांचे के निर्माण में गम्भीर पहल करनी चाहिए। चीन के विरूद्ध अमेरिका व उसके अन्य सहयोगी देशों द्वारा किए जा रहे आर्थिक–रणनीतिक घेरेबन्दी के परिप्रेक्ष्य में भारत को चीन के साथ अपने सम्बन्धों के पुनर्संयोजन को तार्किक परिणति प्रदान करने के साथ–साथ चीन के विरुद्ध शक्ति –संतुलन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता की सीमाएं अब तय करनी ही होंगी

अथवा डोकलाम व गलवान की पुनरावृत्ति का सामना करना पड़ सकता है। भारत का यह परम दायित्व है कि वह अपने नेपाल जैसे पड़ोसी के प्रति आक्रामक आर्थिक व कूटनीति कौशल द्वारा उसे उसके उत्तरदायित्व व क्षेत्रीय भू–राजनीतिक संरचना के अनुरूप व्यवहार करने हेतु विवश करे। नेपाल के हित में भी यह आवश्यक है कि चीन से प्रेरित होकर वह भारत–विरोधी गतिविधियों का परित्याग कर भारत व चीन के साथ मिलकर 'त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग' का संतुलित वातावरण बनाते हुए अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को राष्ट्र–हित केन्द्रित करने में तत्पर हो, अन्यथा दो बड़े राष्ट्रों के बीच उसकी स्थिति निरन्तर कमजोर व दयनीय ही होती जायेगी। इतना ही नही, क्षेत्रीय व वैश्विक शक्ति–संरचना की प्रकृति एवं उसमें भारत की भूमिका को देखते हुए यह परम आवश्यक है कि वह अपने हित–रक्षण व अभिवर्द्धन हेतु एक दीर्घकालीन व यथार्थ रणनीति का निर्धारण करने में गम्भीरतापूर्वक नियोजन करे। हमें यह स्वीकार करके, कि चीन–भारत सम्बन्धों में टकराव व संघर्ष–भावनाएं सदैव बनी ही रहेंगी, चीन के प्रति भावनात्मक सम्बन्धों के बचते हुए यथार्थ नीति (Real Politik) का अनुसरण करना तो होगा ही साथ ही दलीय घात–प्रतिघातों व घृणा–भाव से ऊपर उठकर भारत के सभी राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय सुरक्षा, अखण्डता व सम्प्रभुता पर अनावश्यक टकराव को त्यागकर राष्ट्र–रक्षा का संकल्प लेना चााहिए।

References

1. Strategic Analysis, Vol. No.2, March-April, 2015, p.197
2. Ibid.
3. Ibid p.201
4. Ibid
5. Jawaharlal Nehru; India's Foreign Policy : Selected Speeches (Sept 1946-April 1961) Government of India Publication Division, New Delhi, 1971 p.436.
6. Buddhi Narayan Shrestha, Border Management of Nepal, Bhoomichitra Co.Pvt. Ltd. Kathmandu, 2003, p.268.
7. Strategic Analysis July-August, 2015,p.403
8. V.T.Patil and Nalini K.Jha (eds.) India in a Turbulent World: Perpective on Foreign and Security Policies, South Asian Publishers, New Delhi, 2003, p.74
9. India Today, June 19, 2000
10. A.S. Bhasin (ed.) Nepal's Relation with India and China, Vol. I(Delhi : SIBA Exim Pvt. Ltd. 1994) p.71
11. Ibid. p.535
12. Speech of External Affairs Minister Atal Bihari Vajpayee at a dinner in Kathmandu, July 14, 1977 quoted in Bhasin, Ibid, p. 326
13. Strategic Analysis, October 1999, Vol. XXXIII, No.7 p.1087-90
14. Strategic Analysis, Nov-Dec, 2015, p.696
15. The Indian Express, September 24, 2014
16. Ram Madav, 'Two suns in the East' The Indian Express, May 14, 2015

17. Arvinder Lamba, "India-China Relations; The "Mo-XI" Dynamics, Viewpoint, Ananta Aspen Centre, September 18, 2014
18. Sujit Dutta, 'China's High Risk India Gamble', IDSA Comment Sept. 2010
19. Abanti Bhattacharya, "Sixty years of India-China Relations, Strategic Analysis 34(5) September-October 2010, p.678
20. Deepatiman Tiwari,' Ajit Doval Slams Beijing's Mc Mohan Hypocrisy', The Times of India, May, 23, 2015
21. Dr.S. Jaishankar, India the US and China, IISS-Fullerton Lecture Singapore, July 20, 2015
22. Mohan Malik, 'China and Strategic Imbalance, The Diplomat, July 14, 2014
23. Ely Ratner, 'Rebalaning to Asia with an Insecure China, The Washington Quarterly 36(2), Spring 2013, p.22
24. Strategic Analysis 41(i), Jan-Feb 2017, p.26
25. Indian Defence Review, Sept. 4, 2016
26. Brig. (Retd.) Gurmeet kanwal; Developing Leverages to Counter China's Strategic Encirclement; India Strategic, May, 2012
27. The Times of India, Nov. 4, 2015
28. Strategic Analysis, Vol. 42, No.4, July-August 2018, p.426
29. Strategic Analysis, Vol. 41, No.1, Jan-Feb. 2017, p.28.

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रन्थ सूची

APPENDIX-I

TREATY OF 1815
(The Treaty of Sugauli)

Treaty of Peace between the Honorable East India Company and Maharajah Bikram Sah. Rajah of Nipal, settled between Lieut Colonel Bradshaw on the part of the Honorable Company, in virtue of the full powers vested in him by His Excellency the Right Honorable Francis, Earl of Moira, Knight of the Most Noble Order of the Greater, one of His Majesty's Most Honorable Privy Council, appointed by the Court of Directors of the said Honorable Company to direct and control all the affairs in the East Indies, and by Sree Gooroo Gujraj Misser and Chunder Seekur Opedeea on the part of Maharajah Girmaun Jode Biram Sah Behauder Shum-sheer Jung. in virtue of the powers to that effect vested in them by the said Rajah of Nipal.

Whereas war has arisen between the Honorable East India Company and the Rajah of Nipal, and whereas the parties are mutually disposed to restore the relations of peace and amity which, previously to the occurrence of the late differences, had long subsisted between the two States, the following terms of peace have been agreed upon.

Article 1st:

There shall be perpetua peace and friendship between the Honorable East India Company and the Rajah of Nipal.

Article 2nd:

The Rajah of Nipal renounces all claim to the lands which were the subject of discussion between the two States before the war and acknowledge the right of the Honorable Company to the sovereignty of those lands.

Article 3rd:

The Rajah of Nipal hereby cedes to the Honorable the East India Company in perpetuity all the under mentioned territories, viz.

First- The whole of the lands between the Rivers Kali and Rapti.

Secondly- The whole of the low land (with the exception of Bootwul Khass) lying between the Rapti and the Gunduck.

Thirdly-The whole of the low lands between the Gunduck and Coosah, in which the authority of the Birth Government has been introduced, or is in actual course of introduction.

Fourthly- All the low lands between the rivers Mitchee and the Teestah.

Fifthly- All the territories within the hills eastward of the River Mitchee, including the fort and lands of Nagree and the pass of Nagarcote, leading from Morung into the hills, together with the territory lying between that Pass and Nagree. The aforesaid territory shall be evacuated by the Goorkha troops within forty days from this date.

Article - IV

With a view to indemnify the Chiefs and Barahdars of the State of Nipal, whose interests will suffer by the alienation of the lands ceded by the foregoing Article, the British Government agrees to settle pensions to the aggregate amount of two lakhs of rupees per annum on such Chiefs as may be selected by the Rajah of Nipal, and in the proportions which the Rajah may fix. As soon as the selection is made, Sunnuds shall be granted under the seal and signature of the Governor General for the pensions respectively.

Article - V

The Rajah of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connextion with the countries lying to the

west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants there of.

Article - VI

The Rajah of Nipal engages never to molest to disturb the Rajah of Sikkim in the possession of his territories; but agrees, if any difference shall arise between the State of Nipal and the Rajah of Sikkim, or the subjects of either, that such differences shall be referred to the arbitration of the British Government by which award the Rajah of Nipal engages to abide.

Article - VII

The Rajah of Nipal hereby engages never to take or retain in his service any British subject, nor the subject of any European or American State, without the consent of the British Government.

Article - VIII

In order to secure and improve the relations of amity and peace hereby established between the two States, it is agreed that accredited Ministers from each shall reside at the Court of the other.

Article - IX

This treaty, consisting of nine Articles, shall be ratified by the Rajah of Nipal within fifteen days from this date, and the ratification shall be delivered to Lieutenant-Colonel Bradshaw, who engages to obtain and deliver the ratification of the Governor-General within twenty days, or sooner, if practicable.

Done at Segowlee, on the 2nd day of December 1815.

PARIS BRADSHAW, Lt. Col., P.A.

Received this treaty from Chunder Seekur Opedeea, Agent on the part of the Rajah Nipal, in the valley of Muckwaunpoor, at half-past two

o'clock p.m. on the 4th of March 1816, and delivered to him the Counterpart Treaty on behalf of the British Government.

(Singned) DD.Ochterlony,

Agent, Governor-Gerneral

Memorandum for the approval and acceptance of the Raja of Nipal.

Presented on the 8th December 1816.

1. Adeverting to the amity and confidence subsisting with the Rajah of Nepal, the British Government proposes to suppress, as much as it is possible, the execution of certain Articles in the Treaty of Segowlee, which bear hard upon the Rajah, as follows:
2. With a view to gratify the Rajah in a point which he has much at heart, the British Government is willing to restore the Terai ceded to it by the Rajah in the Treaty, to wit, the whole Terai lands lying between the Rivers Coosa and Gunduck ***[nullifies Article-3 point three]***, such as appertained to the Rajah before the late disagreement; excepting the disputed lands in the Zillahs of Tirhoot and Sarun, and excepting such portions of territory as may occur on both sides for the purpose of settling a frontier, upon investigation by the respective commissioners; and excepting such lands as may have been given in possession to any one by the British Government upon ascertainment of his rights subsequent to the cession of Terai to that Government. In case the Rajah is desirous of retaining the lands of such ascertained proprietors, they may be exchanged for others, and let it be clearly understood that notwithstanding the considerable extent of the lands in the Zillah of Tirhoot, which have for a long time

been a subject of dispute, the settlement made in the year of 1812 of Christ, corresponding with the year 1869 of Bikramajeet, shall be taken, and everything else relinquished, that is to say, that the settlement and negotiations, such as occurred at that period shall in the present case hold good and be established.

3. The British Government is willing likewise to restore the Terai lying between the Rivers Gunduk and Rapti, that is to say, from the River Gunduk to the western limits of the Zillah of Goruckpore, together with Bootwul and Sheeraj [nullifies Article-3 point two], such as appertained to Nepal previous to the disagreements, complete, with the exception of the disputed places in the Terai, and such quantity of ground as may be considered mutually to be requisite for the new boundary.

4. As it is impossible to established desirable limits between the two States without the survey, it will be expedient that Commissioners be appointed on both sides for the purpose of arranging in concert a well defined boundary on the basis of the preceding terms, and of establishing a straight line of frontier, with a view to the distinct separation of the respective territories of the British Government to the south and of Nepal to the north; and in case any indentations occur to destroy the even tenor of the line, the Commissioners should effect and exchange of lands so interfering on principles of clear reciprocity.

5. And should it occur that the proprietors of lands situated on the mutual frontier, as it may be rectified, whether holding of the British Government or of the Rajah of Nipal, should be placed

in the condition of subjects of both Government, with a view to prevent continual dispute and discussion between the two Governments, the respective Commissioners should effect in mutual concurrence and co-operation the exchange of such lands, so as to tender them subject to one dominion alone.

6. Whensoever the Terai should be restored, the Rajah of Nipal will cease to require the sum of 2 lakhs of Rupees per annum, which the British Government. agreed the advance for the maintenance of certain Barahdars of his Government.

7. Moreover, the Rajah of Nipal agrees to refrain from prosecuting any inhabitants of the Terai, after its revertance to his rule, on account of having favored the cause of the British Government during the war, and should any of those persons, excepting the cultivators of the soil, the desirous quitting their estates, and for retiring within the Company's territories, he shall not be liable to hindrance.

8. In the event of the Rajah's approving the foregoing terms, the proposed arrangement for the survey and establishment of boundary marks shall be carried into execution, and after the determination in concert of the boundary line, Sunnuds conformable to the foregoing stipulations, drawn out and sealed by the two States, shall be delivered and accepted on both sides.

(Signed) Edward Gardner seal
Resident
(A true translation) (Signed) G.
Wellcsley,
Assistant.

SUBSTANCE of a LETTER under the Seal of the RAJAH OF NIPAL, received on the 11th December 1816.

After compliments;

I have comprehended the document under date the 8th of December 1816, or 4th of poos 1873 sumbut, which you transmitted relative to the restoration, with a view to my friendship and satisfaction, of the Terai between the Rivers Coosa and Rapti to the southern boundary complete, such as appertained to my estate previous to the war. It mentioned that, in the event of my accepting the terms contained in that document, the southern boundary of the Terai should be established as it was held by the Government. I have accordingly agreed to the terms laid down by you, and herewith enclose an instrument of agreement, which may be satisfactory to you. Moreover, it was written in the document transmitted by you, that it should be restored, with the exception of the disputed lands and such portion of land as should, in the opinion of the Commissioners on both sides, occur for the purpose of settling a boundary: and excepting the lands which, after the cessions of the Terai to the Honorable Company, may have been transferred by it to the ascertained proprietors. My friend, all these matters rest with you, and since it was also written that a view was had to my friendship and satisfaction with respect to certain Articles of the Treaty of Segowlee, which bore hard upon me, and which could be remitted, I am well assured that you have at heart the removal of whatever may tend to my distress, and that you will act in a manner corresponding to the advantage of this State and the increase of the friendly relations subsisting between the two Government.

Moreover I have to acknowledge the receipt of the orders under the red seal of this State, addressed to the officers of Terai between the Rivers Gunduk and Rapti, for the surrender of that Terai, and their retiring from thence, which was given to you at Thankote, according to your request, and which you have now returned for my satisfaction.

(A true translation)

(Sd.) G Wellesley

Seal

Assistant

SUBSTANCE of a DOCUMENT under the Red Seal, received from the DURBAR on Dec 11, 1816

Doorga Bowanee.

With a regard to friendship and amity, the Government of "Nepal agrees to the tenor of the document under the 8th December 1816 or 4th Poos 1873 Sumbut, which was received by the Durbar from the Honorable Edward Gardner on the part of the Honorable Company, respecting the revertance of the Terai between the Rivers Coosa and Rapti to the former southern boundary, such as appertained to Nipal previous to the war with exception of the disputed lands.

Dated the 7th of Poos 1873 Sumbut.

(A true translation)

(Signed) G.

WELLESLEY. Assistant

APPENDIX-II

TREATY OF PEACE AND FRIENDSHIP, KATHMANDU, JULY 31, 1950

The Government of India and the Government of Nepal, recognising the ancient ties which have happily existed between the two countries for centuries;

DESIRING still further to strengthen and develop these ties and to perpetuate peace between the two countries;

HAVE resolved therefore to enter into a Treaty of Peace and Friendship with each other and have, for this purpose, appointed as their plenipotentiaries the following persons, namely,

The Government of India

His EXCELLENCY SHRI CHANDRESHWAR PRASAD NARAIN SINGH, Ambassador of India in Nepal.

The Goverment of Nepal

Maharaja Mohun Shamsher Jang Bahadur Rana.

Prime Minister and Supreme Commander-in-Chief of Nepal,

WHO, having examined each other's credentials and found them good and in due form have agreed as follows :

Article I

There shall be everlasting peace and friendship between the Government of India and the Government of Nepal. The two Governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other,

Article II

The two Governments hereby undertake to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighboring State likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the two Governments.

Article III

In order to establish and maintain the relations referred to in Article I the two Governments agree to continue diplomatic relations with each other by means of representatives with such staff as is necessary for the due performance of their functions.

The representatives and such of their staff as may be agreed upon shall enjoy such diplomatic privileges and immunities as are customarily granted by international law on a reciprocal basis:

Provided that in no case shall these be less than those granted to persons of a similar status of any other State having diplomatic relations with either Government.

Article IV

The two Governments agree to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and other consular agents, who shall reside in towns, ports and other places in each other's territory as may be agreed to.

Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and consular agents shall be provided with exequaturs or other valid authorization of their appointment. Such exequatur or authorization is liable to be withdrawn by the country which issued it, if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible.

The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis all the rights, privileges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of any other State.

Article V

The Government of Nepal shall be *free to* import, from or through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement **shall be worked out** by the two Governments acting in consultation.

Article VI

Each Government undertakes, in token of the neighbourly friendship between India and Nepal, to give to the nationals of the other, in its territory,

national treatment with regard *to* participation in industrial and economic development of such territory and to the grant of concessions and contracts, relating to such development.

Article VII

The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same

privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.

Article VIII

So far as matters dealt with herein are concerned, this treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements

entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.

Article IX

This Treaty shall come into force from the date of signature by both Government.

Article X

This Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year's notice.

DONE in duplicate at Kathmandu this 31st day of July 1950.

Sd/ (Signed)

CHANDRESHWAR PRASAD NARAIN Government of India

MOHUN SHAMSHER, JANG SINGH RANA For the Government of Nepal

Letter enclosed with 1950 Treaty of Peace of Friendship Letter from the Ambassador of India to the Prime Minister of Nepal.

Kathmandu

31st July, 1950

YOUR HIGHNESS

In the course of our discussion of the Treaties of Peace and Friendship and of Trade and Commerce which have been happily concluded between the Government of India and the Government of Nepal, we agreed that certain matters of details be regulated by an exchange of letters. In pursuance of this understanding, it is hereby agreed between the two Governments:

(1) Neither Government shall tolerate any threat to the security of the other by a foreign, aggressor. To deal with any such threat, the two Governments shall consult with each other and devise effective countermeasures.

(2) Any arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal that the Government of Nepal may import through the territory of India shall be so imported with the assistance and agreement of the Government of India. The Government of India will take steps for the smooth and expeditious transport of such arms and ammunition through India.

(3) In regard to Article 6 of the Treaty of Peace and Friendship which provides for national treatment, the Government of India recognize that it may be necessary for some time come to afford the Nepalese nationals in Nepal protection from unrestricted competition. The nature and extent to this protection will be determined as and when required by mutual agreement between the two Governments.

(4) If the Government of Nepal should decide to seek foreign assistance in regard to the development of the natural resources of, or of any industrial project in Nepal, the Government of Nepal shall give first preference to the Government or the nationals of India, as the case may be, provided that the terms offered by the Government of India or Indian nationals, as the case may be, are not less favorable to Nepal than the terms offered by any other Foreign Government or by other foreign nationals. Nothing in the foregoing provision shall apply to assistance that the Government of Nepal may seek from the United Nations Organization or any of its specialized agencies.

(5) Both Governments agree not to employ any foreigners whose activity may be prejudicial to the security of the other. Either Government may make representations to the other in this behalf, as and when occasion requires.

Please accept Excellency, the assurances of my highest consideration.

Sd/-

CHANDRESHWAR PRASAD NARAIN SINGH

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of India at the Court of Nepal.

APPENDIX-III

FRIENDSHIP AGREEMENT

(CHINA NEPAL)

September 20, 1956

(Ratified on January 17, 1958)

The Government of the People's Republic of China and the Government of the Kingdom of Nepal,

Being desirous developing the friendly relations between the two countries as good neighbours on the basis of the long-standing friendship between the two people.

Reaffirm that the five priniciples (Panch Shila) of:

(i) Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty;

(ii) Non-aggression;

(iii) Non-interference in each other's internal affairs for any reasons of an economic, political or ideological character;

(iv) Equality and mutal benefit; and

(v) Peaceful co-existence.

Should be the fundamental principles guiding the relations between the two countries.

The two parties have resolved to conclude the present agreement in accordance with the above-mentioned principal and have, for this purpose, appointed as their respective plenipotentiaries :

The Government of the people's Republic of China, His Excellency Pan Tzu-li, Ambassador Extraordinary and of Nepal; the Government of the Kingdom of Nepal, His Excellency Chuda Prasad Sharma, Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Nepal, who, having examined each other's credentials and finding them in good and due from, have agreed upon the following :

Article One

The high contracting Parties declare that peace and friendship shall be maintained between the People's Republic of China and the Kingdom of Nepal.

Article Two

The high contracting parties hereby reaffirm their decision to mutually exchange diplomatic represntatives on ambassadorial level.

Article Three

All treaties and documents which existed in the past between China and Nepal including those between the Tibet Region of China and Nepal are hereby abrogated.

Article Four

In order to maintain and develop the traditional contacts between the people of the Tibet Region of China and Nepal, the high contracting parties that the nationals of both parties may trade, travel and make pilgrimage in those places in each other's territory as agreed by both parties, and the two parties agree to safeguard the proper interests of the nationals of the other party in the territory in accordance with the laws of the country of residence, and for this purpose the high contracting parties agree to do as follows :

Paragraph One- The high contracting parties mutually trade agencies :

(i) The Chinese Government agrees that the Government of Nepal may establish trade agencies at Shigatse, Kyerong and Nyalam;

(ii) The Government of Nepal agrees that the Chinese Government may establish an equal number of trade agencies in Nepal the specific locations of which will be discussed and determined at a later date by both parties;

(iii) The trade agencies of both parties shall be accorded the same status and same treatment. The trade agents of both parties shall enjoy freedom from arrests of excising their functions, and shall enjoy in respect of themselves, their wives and their children who are dependent on them for livelihood freedom from search.

The trade agencies of both parties shall enjoy the privileges and immunities for couriers, mailbags and communication in code.

Paragraph Two-The high contracting parties agree that traders of both countries may trade at the following places :

(i) The Chinese Government agrees to specify (1) Lhasa, (2) Shigatse, (3) Gyantse, and (4) Yatung as markets for trade;

(ii) The Government of Nepal agrees that when with the development of Chinese trade in Nepal, it has become necessary to specify markets for trade in Nepal, the Government of Nepal specify an equal number of markets for trade in Nepal;

(iii) Traders of both countries known to be customarily and specially engaged in border trade between the Tibet Region of

China and Nepal may continue trade at the traditional markets for such trade.

Paragraph Three- The high contracting parties agree that pilgrimage by religious of either country to the other may continue according to religious customs. Personal baggages and articles used for pilgrimage carried by the pilgrims of either party shall be exempted from taxation by such trade, by the other party.

Paragraph Four- For travelling across the border between the Tibet Region of China and Nepal, the high contracting parties agree that the nationals of both countries shall use the customary routes.

Paragraph Five- For travelling across the border by the nationals of the countries, the high contracting parties agree to following provisions:

(i) Diplomatic personnel and officials of the two countries expect those provided by sub-paragraphs two, three and four, who travel across the border between the Tibet Region of China and Nepal, shall hold passports issued by their respective countries and visited by the other party. National of two countries who enter the Tibet Region of China or Nepal through a third countries and visited by the other party.

(ii) Traders of the two countries known to be customarily and specifically engaged in trade between the Tibet Region of China and Nepal, their wives and children dependent on them for livelihood and their attendants, not covered by sub-paragraph, who enter into the Tibet Region of China or Nepal as the case may be for the

purposes of trade, shall hold passports issued by their respective countries and visited by the other party or certificates issued by their respective governments or by organs authorized by their respective governments.

(iii) Inhabitants of the border districts of the two countries who cross the border to carry on petty trade to visit friends or relatives, or for seasonal changes of residence, may do so as they have customarily done heretofore and need not hold passports, visas or other documents of certification.

(iv) Pilgrims of either party who travel across the border between the Tibet Region of China and Nepal for the purposes of pilgrimages need not passports, visas or other documents of certification, but shall register at the border check posts or the first authorized government office of the other party, and obtain permits for pilgrimage therefrom.

(v) Notwithstanding the provisions of the foregoing sub-paragraphs of this paragraph, either government may refuse entry to any particular persons.

(vi) Nationals of either country who enter the territory of the other party in accordance with the foregoing sub-paragraphs of this paragraph may stay with the procedures specified by the other party.

Article Five

This agreement shall be ratified. It shall come into effect after mutual notice of ratifications, and remain in force for eight (8) years. Extension of the present agreement may be negotiated by the two

parties if either party requests for it six (6) months prior to the expiry of the agreement and request is agreed to by the other party.

Done in Katmandu on the 20th day of September 1956, in duplicate in the Chinese, Nepalese and English languages, all texts being equally authentic.

Sd/- PAN TZU-LI
Plenipotentiary of the Government
of the People's Requblic of China

Sd/- CHUDA PRSAD SHARMA
Plenipotentiary of the Government of the Kingdom of Nepal.

Bibliography

A Primary Sources :

1. Annual Report- 2006-2007, Ministry of External Affairs, New Delhi.
2. Annual Report (Part-II), Department of culture , Ministry of Human Resource Development, Govt. Of India, Various Issues.
3. India: Bilateral Treaties and Agreements Volumes, From I-X, Ministry of External Affairs, New Delhi.
4. Ministry of Commerce Annual Report (2010-11) Government of India, New Delhi.
5. Ministry of Defence Annual Reports, 2009-10,20014-15, 2015-16, 2016-17 Government of India, New Delhi.
6. Ministry of External Affairs, Annual Report, 2009-2010 Government of India, New Delhi.

(B) Books-

1. Ambekar, G.V. and Divekar V.D.(ed),"Document of China: Relations with South and South-East Asia, 1949-1962, Allied, Bombay, 1964.
2 Anand R.P., Cultural Factors in International Relations, Abhinav Publications, New Delhi, 1981.
3. A.K.J. Singh, Himalayan Tringli, British Library London, 1988.
4. Asad Husain, "British India's Relations with Kingdom of Nepal 1857-1947: A Diplomatic History of Nepal, London, George Allen and Unwin, 1970.
5. Baral, Lok Raj,"Oppositional Politics in Nepal", Abhinav Publications, New Delhi, 1977.
6. Bennett, Gordon(ed), China's Finance and Trade, The Macmillan Press Ltd. London, 1978.
7. Bhasin A.S., Documents on Nepal's Relation with India and China(1949-1966), Academic Book, Boombay, 1970.
8. Boyed R.G., Communist China's Foreign Policy, Praeger, New York, 1962.

9. Burrard, Col. S.G., and Hayden H.H., A sketch of the Geography and Geology of Himalaya Mountains and Tibet, Government of India, Calculta, 1907.
10. Chatterji Bhola, A Study of Recent Nepalese Politics, world press, Calcutta, 1967.
11. Chaudhary Swati Ranjan, Indo-Nepal Relations, Anamika Publishers, New Delhi, 2015.
12. Dutt V.P., China's Foreign Policy, 1958-1962, Allied Publishers, New Delhi, 1981.
13. Dutt, Gargi and Dutt, Vidya Prakash, China's Cultural Revolution, Asia Publishing House, Bombay, 1970.
14. Dharmadasani M.D., Nepal's Foreign Policy, Annual Publications , New Delhi, 2005.
15. Eric Hyer, The Pragmatic Dragon: China's Grand Strategy and Boundary Settlements, University of British Columbia Press, Vancouver, 2015.
16. Fisher , M.W., Rose, L.E. and Huttenback, R.A., Himalaya Battle Ground : Sino-Indian Rivalary in Ladakh, Prager, New York , 1963.
17. Gulshan Dietl, India and the Global Game of Gas Pipelines, Routledge, New York, 2017.
18. Harun ur-Rashid, Bangaladesh Foreign Policy: Realities, Priorities and Challenges, Academic Press and Publishers Library, Dhaka, 2010.
19. Jain Giri Lal, India Meets China in Nepal, Asia Publishing House, Bombay, 1959.
20. Jayant Kumar Ray, India's Foreign Policy, 1947- 2007, Routledge, New Delhi, 2011.
21. Karan P.P., The Himalayan Kingdoms: Bhutan, Sikkim and Nepal, Princeton D.Van Votirand, Newyork, 1963.
22. Karan and Jenkins W.M. Jr., Nepal: A Cultural and Physical Geography, University of Kentueky Press Lexingtion, 1960.
23. Kavic, L.J., India's Quest for Securty: defence Policies 1947-1965, University of California Press Berkeley, 1697.
24. Kumar Ashutosh, China Factor in Nepal, Sumit Entirprises, New Delhi, 2013.

25. Khanal, Yadu nath, Background of Nepal's Foreign Policy, Department of Publicity and Broadcasting, Kathmandu, 1964.
26. Kumar , D.P., Nepal: Year of Dicisions, Vikas Publishing House , New Delhi, 1980.
27. Lamb, Alastair, Britain and Chinese Central Asia; The Road to Lhasa, 1767-1905, Routledge and Kegan Paul, London, 1960.
28. Lohia, Ram Manohar, India, China and Northern Frontiers, Navhind Prakashan, Hyderabad, 1963.
29. Malik V.P.General, Kargil: From Surprise to Victory, Hasper Collins Publishers, Delhi, 2010.
30. M.Kauland A. Chakraborty, India's Look East to Act East Policy : Tracking the opportunties and Challenges in the Indo-Pacific, Pantagon Press, New Delhi, 2016.
31. M.L.Bosh, History of Arunachal Pradesh, Concept Publishing Co. New Delhi, 1997.
32. Mullik, B.N., The Chinese Betrayal: My Years with Nehru, Allied Publications, New Delhi, 1971.
33. Muni, S.D., Foreign Policy of Nepal, National, New Delhi, 1973.
34. Muni, S.D.(ed), An Assertive Monarchy, Chetna Publication New Delhi, 1977.
35. Mandal Monika(ed), Indo-Nepal Relations, KW Publishers, New Delhi, 2014.
36. M.K. Palat(ed), Selected Work of J.L.Nehru,Second Series, Vol.60, New Delhi, Jawaharlal Nehru Memorial Fund, 2015.
37. Nehru, J.L., India's Foreign Policy: Selected Speeches, Sept. 1946-April 1961, The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi, 1961.
38. Nari Rustomgi, Enchanted Frontiers, Oxford University Press, New Delhi, 1972.
39. Nihar Nayak(ed), Cooperative Security Framework for South Asia, Pentagon Press, New Delhi, 2013.
40. Panikkar K.M.; In Two China's: Memoirs of a Diplomats, George Allen & Unwin, London, 1955.

41. Permanand; The Nepal Congress in Exil, Delhi University Book House, Delhi, 1978.
42. Pershotam Mehra, An Agreed Fronteir:Ladakh and India's Northernmost Border, 1846-1947, Oxford University press Delhi, 1992.
43. Ramakant, Nepal-China and India, Abhinav Publications, New Delhi, 1976.
44. Rose, Leo B., Nepal: A Strategy of Survival, University Press, California, 1971.
45. Samual Huntingtion, Politial Order in Changing Socities, Yale University, New Haven, USA, 1968.
46. Sen Debarata, Basic Principles of Geopolitics and History, Concept Publishing House, Delhi, 1975.
47. Singh Jasjeet, Reshaping Asian Security, K.W. New Delhi, 2001.
48. Sanwal K.N., Reseing India-Nepal Ties and China, Sumit Enterprises, New Delhi, 2016.
49. Singh B.D., Indian Subcontinent And China's New Defence Strategy, Sumit Enterprises, New Delhi, 2016.
50. Singh B.K.P., China's Tibet policy, Sumit Enterprises, New Delhi, 2009.
51. Subir Bhaumik, Insurgent Crossfire:North East India, Lancer Publishers, New Delhi, 1996.
52. Tiwari V.K., Indo-Nepal Trade Relations, Gyan Publishing House, New Delhi, 2013.
53. Pushpesh Pant, Bharat Ki Videsh Neeti, Tata MC Graw hill, New Delhi, 2010.
54. Pandey Anshu, Bharat Nepal Sambandh, Natraj Prakashan, Delhi, 2007.
55. P.R. Chari (ed), Perspectives on National Security in South Asia; In Search of a New Paradigm, Manohar publications , New Delhi, 1999.
56. Vishal Chandra (ed), India's Neighbourhood: The Armies of South Asia, Pentagon Press, New Delhi, 2013.
57. Wendy Palace, The British Empire and Tibet, 1900-1922, Routledge CurZon, London, 2005.

C. Journals/Magzines-

1. Strategic Analysis, New Delhi
2. Mainstream, New Delhi
3. South Asia Journal, New Delhi
4. Strategic Digest, New Delhi
5. Nepal Press Digest, Kathmandu
6. India Today
7. Outlook

D. News Papers-

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. The Hindustan Times
4. New Bharat Times
5. Nepal Sandesh
6. The Satatesman
7. Economic Times
8. The Pioneer
9. Jansatta